राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 266

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 3 मार्च 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

ज्यादा आक्रामक होने के सवाल पर बिफरे कप्तान कोहली

>> 14

सरोकार

16 एकड़ के उसी खेत से अब कमा रहे 45 लाख

जींद : हरियाणा के जींद निवासी 'बेर वाले अंकल' की कहानी लोगों को जागरूक कर रही है। छोटी सी जमीन पर लगाए गए बाग ने किस्मत बदल दी।

उसी खेत से अब सालाना 45 लाख रुपये से ज्यादा कमा रहे हैं। दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। (पेज-11)

जागरण विशेष

खुलेंगे सिनेमाघर, कश्मीर में गूंजेगा लाइट-कैमरा-एक्शन...

श्रीनगर : कश्मीर को बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग का हब बनाने के सरकारी प्रयास तेज हो चुके हैं। श्रीनगर के बंद पड़े सिनेमाघरों को भी जल्द खोले जाने की उम्मीद है।

माना जा रहा है कि इसी साल यह प्रयास रंग लाते दिखेंगे। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

पंजाब में मुख्यमंत्री भी लोकपाल के दायरे में

चंडीगढ़ : विधानसभा चुनाव के दौरान नए और सशक्त लोकपाल का वादा कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सरकार ने शर्त के साथ पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर की अध्यक्षता में सोमवार को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में नए लोकपाल बिल को मंजूरी मिल गई। मुख्यमंत्री, मंत्री व विधायक इसके दायरे में होंगे।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के 11 दोषियों को ताउम्र जेल

रांची : झारखंड की राजधानी रांची में लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। रांची सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने घटना को जघन्य मानते हुए कहा कि दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

बंदरगाहों पर सड़ रहा करोड़ों रुपये का आयातित प्याज

नई दिल्ली : पहले प्याज की कमी ने उपभोक्ताओं को परेशान किया, तो अब आयातित प्याज की हजारों टन की खेप सरकारी खजाने को प्रभावित कर सकती है। तुर्की समेत कई और देशों से आयातित प्याज की बड़ी खेप विभिन्न बंदरगाहों पर सड़ रही है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

तालिबान-गनी सरकार के बीच बातचीत सबसे अहम : भारत

नई दिल्ली : अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान की तरफ से अमेरिका से किए गए समझौते से पीछे हटने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में भारत ने कहा है कि वह पूरे हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है। भारत ने यह भी कहा है कि अमेरिका-तालिबान समझौते के बाद तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच होने वाली बातचीत सबसे महत्वपूर्ण है।

...तो क्या सोशल मीडिया को 'अनफ्रेंड' करेंगे मोदी!

जेएनएन, नई दिल्ली

- पीएम ने ट्वीट कर रविवार से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम को छोड़ने का दिया संकेत
- हर ओर अटकलों का दौर, भाजपा आइटी सेल ने कहा- रविवार तक इंतजार करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। ट्विटर

अपने संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का कुशलता से उपयोग करने वाले धुरंधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात इसी फोरम से यह एलान कर सबको चौंका दिया कि वह अगले रविवार से सभी सोशल मीडिया से हटने की सोच रहे हैं। करोड़ों फॉलोअर्स वाले इस मंच से हटने के फैसले के पीछे क्या कारण है, यह कोई बताने की स्थिति में नहीं है। माना जा रहा है कि वह एक साथ कई संदेश देना चाहते हैं। इसमें सोशल मीडिया में हाल के दिनों में आ रही नकारात्मकता, इन फोरम में दिखते रहे पक्षपातपूर्ण रवैये, समाज को इसकी लत से बचाने की कोशिश जैसी कई सोच हो सकती है।

मोदी ने सोमवार को ट्विटर पर अपने मन की बात जाहिर करते हुए कहा, 'इस रविवार से मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर अपने सभी खातों को छोड़ने के बारे में विचार कर रहा हूं। इस बारे में जानकारी दूंगा।' इस बीच भाजपा के आइटी सेल ने लोगों से रविवार तक इंतजार करने को कहा है। मोदी के ट्वीट के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि सोशल मीडिया पर अफवाहों के फैलने से वह निराश हैं। ध्यान रहे कि सोशल मीडिया को लेकर अक्सर यह सवाल भी उठता रहा है कि इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और इसीलिए अराजक हो जाता है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि भारत अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लांच कर सकता है।

बहुत लोकप्रिय हैं मोदी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय हैं। ट्विटर पर उनके 5.33 करोड़ फॉलोअर हैं। फेसबुक पर 4.47 करोड़ लोग और इंस्टाग्राम पर 3.52 करोड़ लोग उन्हें फॉलो करते हैं।

करते रहे हैं पैरवी

यह ट्वीट बहुत चौंकाने वाला इसलिए भी माना जा रहा क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर मोदी अपनी केंद्रीय योजनाओं और सामाजिक सरोकारों को भी सोशल मीडिया के जरिये खासा प्रचारित-प्रसारित करते रहे हैं। वह कई बार सोशल मीडिया को सरकार और जनता के बीच की सबसे बड़ी कड़ी भी बता चुके हैं और इसके उपयोग को लेकर लोगों को प्रोत्साहित भी किया है।

ट्रेंड करने लगा 'नो सर'

मोदी के ट्वीट करते ही सोशल मीडिया पर हैशटैग 'नो सर' ट्रेंड करने लगा। लोग प्रधानमंत्री मोदी से सोशल मीडिया नहीं छोड़ने की अपील करने लगे। दो घंटे के भीतर ही मोदी के ट्वीट पर 68 हजार लोगों ने कमेंट कर दिया।

कांग्रेस ने साधा निशाना

मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया देने में देरी नहीं की। राहुल ने ट्वीट किया, 'नफरत को छोड़िए, सोशल मीडिया नहीं।' कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी को सलाह देते हुए लिखा, 'आदरणीय मोदी जी, दिल से चाहता हूं कि आप यह सुझाव अपनी ट्रोल सेना को दीजिए, जो दिन-रात लोगों को गालियां देते रहते हैं।'

दिल्ली दंगों पर संसद में हाथापाई की नौबत

मर्यादा तार-तार ▶ लोकसभा में कांग्रेस-भाजपा सदस्यों की झड़प धक्का-मुक्की तक पहुंची

दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर किया हंगामा, गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली हिंसा मामले पर सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा किया। प्रेट्र

दिल्ली दंगों को लेकर सोमवार को संसद के दोनों सदनों में सरकार और विपक्ष के बीच जबर्दस्त दंगल हुआ। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन कांग्रेस की अगुआई में विपक्षी दलों ने दंगों के लिए केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठाई। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी झड़प से हाथापाई तक की नौबत आ गई। सदन की गरिमा तब तार-तार हो गई, जब लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों के बीच धक्का-मुक्की होने लगी। इस सियासी जंग की वजह से पहले दिन दोनों सदनों की कार्यवाही ठप हो गई।

लोकसभा की बैठक शुरू होते ही जदयू सांसद वैद्यनाथ महतो को श्रद्धांजलि दी गई। इसके तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों के दिल्ली दंगों का मामला उठाने से पहले ही स्पीकर ओम बिरला ने सदन को दो बजे तक स्थगित कर दिया। दो बजे सदन शुरू होने के बाद विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करने लगे। कांग्रेस के कुछ सदस्य गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग वाला काला बैनर लिए सत्ता पक्ष की तरफ वेल में पहुंच गए। कांग्रेस के गौरव गोगोई और रवनीत बिट्टू के बैनर लेकर आने का संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी व भाजपा सांसदों ने विरोध किया और देखते-देखते हंगामा बढ़ गया।

हंगामे के बीच 'विवाद से विश्वास' बिल पर शुरू हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए जोशी ने कहा कि 1984 के दंगे भड़का कर तीन हजार लोगों को मारने वाले नसीहत न दें। दिल्ली में सबसे पहला काम है शांति बहाली। इस बीच गोगोई और बिट्टू को रोकने के लिए भाजपा के रमेश विधूड़ी और निशिकांत दूबे समेत भाजपा के कुछ सदस्य भी वेल में पहुंच गए। धीरे-धीरे दोनों पक्षों के सांसद एक दूसरे को पीछे धकेलते हुए भिड़ गए। सांसदों के बीच खींचतान को थामने के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी ने उग्र हुए विधूड़ी को थामने का प्रयास किया। हालात बेकाबू होता देख स्पीकर ने सदन को तीन बजे तक स्थगित कर दिया। कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी करीब दस मिनट तक दोनों पक्षों में जबर्दस्त तनाव बना रहा। विधूड़ी के साथ केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे भी उग्र होकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते देखे गए। रविशंकर और स्मृति ने फिर बचाव का मोर्चा संभाला।

लोकसभा जब तीन बजे बैठी तब विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू किया और सदस्य वेल की ओर बढ़ने लगे। इस बार भाजपा की महिला सांसदों ने पहले ही वेल में कतारबद्ध होकर विपक्षी सदस्यों का रास्ता रोक दिया। रम्या हरिदास समेत कांग्रेस की कुछ महिला सदस्य भी इस दौरान वेल में पहुंच गईं। इस बीच भाजपा सांसद जसकौर मीणा ने रम्या हरिदास को धक्का दिया। इसको लेकर हंगामा बढ़ा तो सदन को चार बजे और फिर साढ़े चार बजे तक स्थगित किया गया। हंगामा और गतिरोध खत्म होता न देख साढ़े चार बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही को मंगलवार तक स्थगित कर दिया।

स्मृति ईरानी ने सदन को शर्मसार होने से बचाया पेज>>3
संसदीय समितियों की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहे 95 सदस्य पेज>>3
दंगों पर सियासी दंगल (विचार) पेज>>8

कांग्रेस सांसद राम्या हरिदास ने लगाया मारपीट का आरोप

कांग्रेस की सांसद राम्या हरिदास ने भाजपा की जसकौर मीणा पर मारपीट का आरोप लगाया। राम्या हरिदास को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी स्पीकर के चैंबर में पहुंचे और राम्या ने लिखित तौर पर जसकौर मीणा के खिलाफ शिकायत की। साथ ही कहा कि महिला और दलित होने के नाते उनके साथ सदन में बार-बार ऐसा सलूक किया जा रहा। राम्या की शिकायत के बाद भाजपा ने भी अपनी महिला सांसदों के साथ कांग्रेस सदस्यों के दुर्व्यवहार की शिकायत स्पीकर से की।

राज्यसभा में भी नहीं हो पाई चर्चा

राज्यसभा में भी शून्यकाल शुरू होते ही विपक्ष ने दिल्ली दंगों और भाजपा के कुछ नेताओं के नफरत भरे बयानों का मुद्दा उठाने का प्रयास किया। सभापति वेंकैया नायडू ने मुद्दे की गंभीरता को स्वीकार किया मगर कहा कि सबसे पहला काम शांति बहाली का है। गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री की नाकामी की बात उठाई ही थी कि नायडू ने सदन दो बजे तक स्थगित कर दिया। दो बजे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंधित बिल पर उपसभापति हरिबंस ने चर्चा शुरू कराई, मगर कांग्रेस के साथ-साथ सपा, एनसीपी, द्रमुक, आप, टीएमसी आदि सभी दल दिल्ली के भयावह दंगों में हुई मौतों का मामला उठाते हुए गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे। कांग्रेस के कुछ सदस्य तो बिल पर बोल रहे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के माइक के पास जाकर जोरदार नारेबाजी करने लगे। इसकी वजह से निशंक को तीसरी पंक्ति में अपने कागजात लेकर भागना पड़ा। हंगामा थमता नहीं देख उपसभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। इस बीच कांग्रेस ने राज्यसभा में अपने सभी सदस्यों को मंगलवार को मौजूद रहने को कहा है।

बड़ी पीठ में नहीं भेजा जाएगा अनुच्छेद 370 का मामला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ही सुनवाई करेगी। कोर्ट ने मामले को विचार के लिए सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को भेजने की मांग खारिज कर दी है। पांच न्यायाधीशों की पीठ ने मांग खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि जिन दो पूर्व फैसलों को एक दूसरे का विरोधाभासी बताते हुए मामले को बड़ी पीठ को भेजने की मांग की जा रही है वे फैसले विरोधाभासी नहीं हैं। इसलिए मामले को बड़ी पीठ को भेजने की जरूरत नहीं है।

यह आदेश जस्टिस एनवी रमना, संजय किशन कौल, आर. सुभाष रेड्डी, बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली तीन याचिकाकर्ताओं की मांग खारिज करते हुए सुनाया। वैसे तो अनुच्छेद 370 को बहुत सी याचिकाओं में चुनौती दी गई है और सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, लेकिन तीन याचिकाकर्ताओं गैरसरकारी संस्था पीयूसीएल (पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज), जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और एक हस्तक्षेप अर्जीकर्ता ने मांग की थी कि पूर्व में दिए गए फैसले प्रेमनाथ कौल बनाम जम्मू एवं कश्मीर (1959) और संपत प्रकाश बनाम जम्मू एवं कश्मीर (1970) एक दूसरे के विरोधाभासी हैं।

दोनों फैसलों को विरोधाभासी बताया पेज>>3

निर्भया के गुनहगारों की एक बार फिर टली फांसी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- आज होनी थी फांसी, कोर्ट ने अगले आदेश तक टाली
- पवन के दया याचिका दायर करने के बाद कोर्ट ने दिया आदेश

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में चारों दोषियों के खिलाफ जारी डेथ वारंट अदालत ने अगले आदेश तक टाल दिया है। लिहाजा मंगलवार (3 मार्च) को फांसी नहीं दी जा सकेगी। इस मामले में अदालतों में सुनवाई के कारण सोमवार को दिनभर संशय बना रहा। पटियाला हाउस की एक अदालत ने पहले सत्र में डेथ वारंट पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी थी। इसके तुरंत बाद पवन की तरफ से दया याचिका दायर कर दी गई, जिसके बाद अदालत के दूसरे सत्र में अतिरिक्ति सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने डेथ वारंट टालने का आदेश दिया।

दोषी पवन और अक्षय ने अर्जी दायर कर मांग की थी कि 3 मार्च के लिए जारी डेथ वारंट पर रोक लगाई जाए, क्योंकि उनकी याचिकाएं विचाराधीन हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने इस पर तिहाड़ प्रशासन से जवाब मांगा था। बहस के दौरान लोक अभियोजक ने दलील दी कि जब एक बार अक्षय की दया याचिका खारिज हो चुकी है, तो उसने फिर से क्यों दायर की? पवन ने भी अब क्यूरेटिव याचिका दायर की है, जबकि हाई कोर्ट से दिया गया समय भी पूरा हो चुका है। इस पर जज ने एपी सिंह से जवाब मांगा।

लंच के बाद सुनाया अदालत ने फैसला पेज>>6

कोरोना वायरस ने दिल्ली में भी दी दस्तक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- राजस्थान और तेलंगाना में भी एक-एक व्यक्ति घातक वायरस से संक्रमित
- दिल्ली, जयपुर के मरीज इटली से जबकि तेलंगाना का मरीज दुबई से लौटा

तेलंगाना के हैराबाद स्थित गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस के आइसोलेशन वार्ड के बाहर चिकित्सक। प्रेट्र

घातक रूप से संक्रामक कोरोना वायरस ने राजधानी दिल्ली में दस्तक दे दी है। इटली से लौटने वाला एक व्यक्ति जांच में कोरोना वायरस से ग्रसित पाया गया है। इसके साथ ही एक दूसरा व्यक्ति तेलंगाना में कोरोना वायरस से पीड़ित मिला है, जो दुबई से लौटा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि दोनों का अस्पताल में अलग-थलग कर इलाज शुरू कर दिया गया है। जबकि कोरोना से संक्रमित तीसरे व्यक्ति की पहचान राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक इटली के नागरिक के रूप में हुई है। दूसरी बार की जांच में उसे पॉजिटिव यानी संक्रमित पाया गया।

कोराना वायरस से ग्रसित दो नए मरीजों की जानकारी देते हुए सोमवार को हर्षवर्धन ने बताया कि दिल्ली और तेलंगाना के मरीजों ने खुद ही आगे आकर कोरोना वायरस की जांच के लिए कहा। जांच में वायरस से ग्रसित पाए जाने के बाद सरकारी अस्पताल में अलग-थलग रखकर इलाज शुरू कर दिया गया है।

दूसरी ओर, आइएएनएस समाचार एजेंसी के अनुसार तेलंगाना के पहले कोरोना से पीड़ित मरीज की उम्र 24 साल है और उसका इलाज सरकारी गांधी अस्पताल में चल रहा है। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ई.राजेंदर ने बताया कि सॉफ्टवेयर टेकी अपनी कंपनी के काम से दुबई गया था और वहां हांगकांग के कुछ लोगों के संपर्क में आ गया। वह 22 फरवरी को बेंगलुरु से हैदराबाद आया और बुखार से पीड़ित था। उसने पहले सिकंदराबाद के अपोलो अस्पताल में पांच दिन इलाज कराया। वहां आराम न मिलने पर उसे गांधी अस्पताल के लिए रेफर किया गया। उसके नमूने जांच के लिए पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए। प्रशासन उन 80 लोगों की पहचान कर रहा है, जो अब तक उसके संपर्क में आ चुके हैं।

हालांकि इससे पहले, संक्रमित व्यक्तियों की गोपनीयता का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने उनकी पहचान और उनके अस्पताल के बारे में कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया। लेकिन भारत आने के बाद घर, दफ्तर और अन्य जगहों पर उनके संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान का काम शुरू कर दिया गया है। हर्षवर्धन ने कहा कि इन लोगों की पहचान कर उन्हें 28 दिनों तक निगरानी में रखा जाएगा। दरअसल कोरोना वायरस व्यक्ति से व्यक्ति के बीच फैलता है। ऐसे में ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों में इसके फैलने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। (पेज-7 भी देखें)

बड़ी परेशानी

इंडिया रेटिंग्स ने जताई एनपीए बढ़ने की आशंका, एक-चौथाई कर्ज डूब जाने का डर

आर्थिक सुस्ती से 10 लाख करोड़ रुपये के कर्ज दांव पर

मुंबई, प्रेट्र : सरकार पिछले कुछ समय से सुस्त चल रही इकोनॉमी को रफ्तार देने की हरसंभव कोशिश कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) और सरकार दोनों की कोशिश है कि बैंक कर्ज बांटने में सतर्कता भले बरतें, लेकिन जरूरतमंद उद्योग को बिना किसी परेशानी के कर्ज मिले। ऐसे माहौल में रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स की एक रिपोर्ट कहती है कि इकोनॉमी की पहले से सुस्त रफ्तार को कोरोना वायरस का फैलता असर और सुस्त कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके चलते कॉरपोरेट जगत के 10.5 लाख करोड़ रुपये पर एनपीए में तब्दील होने का संकट मंडराने लगा है। इंडिया रेटिंग्स ने कहा है कि आर्थिक सुस्ती के चलते कंपनियां अगले तीन वर्ष के दौरान 10.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने में चूक सकती हैं।

इंडिया रेटिंग्स का कहना है कि आर्थिक सुस्ती के चलते कंपनियां इस वक्त जिन दबावों का सामना कर रही हैं, उसके अगले कुछ समय तक जारी रहने की आशंका है। एजेंसी ने का कहना है कि कॉरपोरेट जगत पर इस वक्त जितना कर्ज है, उसमें से 10.5 लाख करोड़ रुपये के डिफॉल्ट होने की आशंका है। यह रकम उद्योग जगत के कुल कर्ज का लगभग 16 प्रतिशत हिस्सा है।

इंडिया रेटिंग्सर के मुताबिक अगर जीडीपी ग्रोथ रेट में और गिरावट आती है तो डूबने वाला कर्ज 5.59 परसेंट तक पहुंच सकता है। हालांकि रिपोर्ट कहती है कि ग्रोथ रेट सुधरकर सात परसेंट तक रहने की स्थिति में डूबने वाला कर्ज 3.13 परसेंट के स्तर तक नीचे आ सकता है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष (2019-20) की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ रेट 4.7 परसेंट रही थी, जो सात वर्षों का निम्न स्तर है। एनएसओ ने चालू वित्त वर्ष के दौरान पांच परसेंट ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। सोमवार को ही अग्रणी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक विकास दर का अनुमान घटा दिया है। फिच को इस महीने के आखिर में खत्म होने वाले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 4.9 प्रतिशत पर सिमटने का अंदेशा है।

ऐसे लगाया अनुमान : एजेंसी ने कंपनियों के असेट का मूल्यांकन करने के बाद शीर्ष 500 कर्जदाताओं के विश्लेषण के जरिये यह रिपोर्ट तैयार की है। इसके लिए एजेंसी ने 11 सेक्टर्स की असेट गुणवत्ता को परखने की कोशिश की है। इनमें रियल एस्टेट, पावर, ऑटो और इसका सहायक क्षेत्र, टेलीकॉम सेक्टर शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान करीब 25 परसेंट कर्ज डूबने की आशंका है। इससे वित्त वर्ष 2021-22 तक सिस्टम में मौजूद कुल कर्ज का चार परसेंट हिस्सा डूब सकता है।

मुसीबत

- पहले से सुस्त घरेलू इकोनॉमी पर पड़ी है कोरोना की मार
- तीसरी तिमाही के दौरान ग्रोथ रेट सात वर्षों के निचले स्तर पर

प्रतीकात्मक फोटो

अफवाह फैलाने वालों पर भी शिकंजा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- उपद्रव की अफवाह फैलाने के मामले में 40 लोग पकड़े गए
- गृह मंत्री शाह से मिले बैजल, हिंसाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया

राजधानी में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने उपद्रवियों के साथ ही अब अफवाह फैलाने वालों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर, सोमवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव के साथ दंगे में सबसे ज्यादा प्रभावित शिव विहार का जायजा लिया। बाद में उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि बैजल ने शाह को मौजूदा हालात की जानकारी दी।

रविवार शाम को दिल्ली के हर कोने में अचानक दंगा फैलने की अफवाह फैल गई थी। संवेदनशील जगहों पर मेट्रो स्टेशनों को बंद करना पड़ा था। इस दौरान पुलिस के पास हिंसा से जुड़ीं 18 सौ काल आई थीं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमे दर्ज किए हैं। वहीं गिरफ्तार लोगों पर शांति भंग, अफवाह फैलाने, साइबर क्राइम जैसी धाराओं में कार्रवाई की गई है।

तेजी से सुधार रहे हालात : दंगा प्रभावित इलाके में हालात तेजी से सामान्य होने लगे हैं। शिव विहार, उस्मानपुर के गढ़ी मेंडू, ब्रह्मपुरी के गली नंबर एक, भजनपुरा, करावल नगर, खजूरीखास व घोंडा आदि कुछ इलाकों को छोड़ बाकी इलाके में रहने वाले लोगों की जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी है। दंगों के मामले में अब तक 369 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें 40 केस हत्या व 44 आर्म्स एक्ट के शामिल हैं। 1284 को हिरासत में लिया गया है।

हिंसा में मारे गए लोगों के शव मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। सोमवार को भी गोकलपुरी नाले से एक शव और बरामद हुआ है।

हेड कांस्टेबल रतन लाल के हत्यारोपित का मिला सुराग पेज>>2

205 दर्ज किया गया सोमवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स। फरीदाबाद का एयर इंडेक्स 240, गाजियाबाद का 256, ग्रेटर नोएडा का 172, गुरुग्राम का 125 और नोएडा का 213 दर्ज किया गया।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 3 मार्च 2020

पुलिस लोगों के दिलों से डर निकाले : बैजल

सुधरते हालात ▶ उपराज्यपाल ने दंगा प्रभावित इलाकों में पीड़ितों से सुना उनका दर्द, सभी को सुरक्षा का दिलाया विश्वास

लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने को कहा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सोमवार को दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उपराज्यपाल के साथ पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव व पूर्वी दिल्ली नगर निगम की निगमायुक्त दिलराज कौर व कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उपराज्यपाल शिव विहार, करावल नगर, बृजपुरी, चांदबाग गए और दंगा पीड़ितों से उनका दर्द सुना। इसके साथ ही उन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह सुरक्षित हैं, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में हालात पूरी तरह से समान्य हैं। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें।

शिव विहार में पीड़ितों ने उपराज्यपाल को बताया कि किस तरह से दंगाइयों ने उनके घरों व दुकानों के साथ ही वाहनों को आग के हवाले कर दिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, कई तरफ से दंगाइयों से घिरे हुए थे। दंगों की वजह से वे बर्बाद हो गए हैं। उनकी सारी जमा पूंजी चली गई। सबसे ज्यादा नुकसान शिव विहार में हुआ है। पुलिस अगर नहीं आती तो शायद वे बच भी नहीं पाते।

दंगा प्रभावित क्षेत्र शिव विहार में उपराज्यपाल अनिल बैजल को जानकारी देते पुलिस अधिकारी। साथ में पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव (मध्य)। जागरण

उपराज्यपाल ने पुलिस को निर्देश दिए किए वह अमन कमेटियों के साथ मिलकर लोगों के दिलों से डर को निकाले। जो दूरियां समुदायों के बीच है, उन्हें पाटने का काम किया जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करना हमारी प्राथमिकता है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च करे। उन्होंने निगम को आदेश दिया कि वह क्षेत्र में बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाए। उपराज्यपाल से शिव विहार तिराहे पर मिली अवैध तेजाब फैक्ट्री के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा वह जांच का विषय है। उन्होंने अफवाह पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी।

पुलिस सुरक्षा में विद्यार्थियों ने दी परीक्षा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दंगा प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य होने पर एक सप्ताह के बाद सोमवार को सीबीएसइ बोर्ड की 12वीं की भौतिकी की परीक्षा हुई। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही पुलिस और अर्धसैनिक बलों का कड़ा पहरा था। परीक्षार्थी अभिभावकों के साथ परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। उनके चेहरों पर भी तनाव व दहशत साफ झलक रही थी। जब तक परीक्षा खत्म नहीं हो गई, अभिभावक केंद्र के बाहर डटे रहे। खजूरी खास के राजकीय कन्या विद्यालय केंद्र पर खजूरी खास के एसीपी हरीश कुककैती और थानाध्यक्ष पवन कुमार ने परीक्षार्थियों का स्वागत गुलाब का फूल देकर किया। इससे विद्यार्थी काफी खुश दिखे। बता दें कि गत सोमवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं थी, उसी दौरान दंगे भड़क गए थे। विद्यार्थी दंगों में बुरी तरह से फंस गए थे। वजीराबाद रोड स्थित विक्टोरिया स्कूल में भी परीक्षा का केंद्र था। दंगाइयों ने स्कूल के बाहर खड़े स्कूल के वाहनों को आग लगा दी थी। उस दंगे के बाद अब इस सोमवार को विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। उनके चेहरे पर डर झलक रहा था। जाफराबाद, शिव विहार, वेलकम, कर्दमपुरी, यमुना विहार, करावल नगर सहित अन्य इलाकों में माहौल शांत रहा। परीक्षा खत्म होते ही परीक्षार्थी तुंरत अपने घरों को निकल गए। भौतिकी की परीक्षा देकर बाहर आए विद्यार्थियों ने पेपर बहुत ही लंबा और कठिन बताया।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, चीजों को होने से नहीं रोक सकते

भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआइआर की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई

नई दिल्ली, एजेंसियां : 'हम यह नहीं कह रहे हैं कि लोगों को मरना चाहिए। इस तरह के दबाव से निपटने में हम सक्षम नहीं हैं। हम चीजों को होने से नहीं रोक सकते।' सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कथित भड़काऊ भाषणों के लिए भाजपा नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और अन्य के खिलाफ तत्काल एफआइआर दर्ज करने की मांग संबंधी याचिका पर चार मार्च को सुनवाई के लिए सहमति देते हुए की। दिल्ली हिंसा के 10 पीड़ितों के एक समूह की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि कथित रूप से इन नेताओं के भाषणों की वजह से ही उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़की थी।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के समक्ष हिंसा प्रभावितों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंसाल्विस ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते इस मामले की सुनवाई छह हफ्ते के लिए स्थगित कर दी, जबकि हर दिन लोग मर रहे हैं। यह बहुत ही अहम मसला है और शीर्ष अदालत को इस पर आज-कल में ही सुनवाई करनी चाहिए। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'हम एहतियाती राहत नहीं दे सकते। हम खुद पर एक तरह का दबाव महसूस करते हैं। हम हालात से तभी निपट सकते हैं जब वह घटित हो जाए। हम पर जिस तरह का दबाव है, उससे हम नहीं निपट सकते... यह ऐसा है कि जैसे अदालत जिम्मेदार है। हम अखबारों को पढ़ते हैं। हमें पता है कि किस तरह के बयान दिए गए हैं। अदालत तभी परिदृश्य में आती है जब चीजें घटित हो चुकी हों और अदालतें ऐसी चीज को रोक नहीं पातीं। हम शांति की कामना करते हैं...'

आइबी अधिकारी की हत्या की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग : सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके दिल्ली हिंसा, आइबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या, धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ और सीआरपीएफ पर एसिड हमले की जांच अदालत की निगरानी में एसआइटी से कराने की मांग की है। साथ ही याचिका में बीएसएफ जवान के घर तोड़फोड़ और हिंसा रोकने में पुलिस अधिकारियों की नाकामी की जांच भी एसआइटी से कराने की मांग की गई है।

केजरीवाल ने कहा, साझा करें हिंसा पीड़ितों की जानकारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली हिंसा से पीड़ित परिवारों की तत्काल मदद के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से ऐसे पीड़ित परिवारों की जानकारी हैशटैग दिल्ली रिलीफ के साथ ट्विटर पर साझा करने की अपील की है। इसमें पीड़ित का पता व मोबाइल नंबर साझा करने की अपील की गई है, जिससे हिंसा पीड़ित को तत्काल मदद पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने यह अपील ट्वीट करके की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपील की कि अगर आप हिंसा पीड़ित किसी व्यक्ति को जानते हैं, जिसे मदद की आवश्यकता है तो आप हमें उसकी जानकारी दे सकते हैं। लोगों से जरूरतमंदों का सही पता और मोबाइल नंबर समेत अन्य जानकारी साझा करने की अपील की है, जिससे उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। अरविंद केजरीवाल ने आश्वस्त किया कि ऐसे लोगों को तत्काल मदद दी जाएगी।

नुकसान का आकलन करने में जुटे अधिकारी : केजरीवाल ने हिंसा से पीड़ित परिवारों के लिए राहत व पुनर्वास कार्य तेज करने का निर्देश प्रशासन को भी दे रखा है। लगातार 24 घंटे इस पर नजर भी रख रहे हैं, जिससे पीड़ितों को मदद मिलने में कोई

अरविंद केजरीवाल। (फाइल)

- मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर पता व मोबाइल नंबर साझा करने की अपील की
- कहा, हिंसा पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कर रही 24 घंटे प्रयास

परेशानी न हो। जिनके घर जल गए हैं, उन्हें तत्काल 25 हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। हालांकि अधिकारी उनके नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं। यह कार्य लगभग पूरा होने वाला है और जल्द ही पीड़ित लोगों को घोषित मुआवजे का लाभ दिया जाएगा। साथ ही हिंसा पीड़ितों के रहने के लिए राहत शिविर बनाए गए हैं। सरकार की तरफ से लोगों को लगातार खाना पहुंचाया जा रहा है। हिंसा के बाद अपना घर छोड़कर जा चुके लोगों से भी लौटने की मुख्यमंत्री अपील कर चुके हैं।

फर्जी खबरें पोस्ट करने वालों को होगी जेल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति की बैठक में फैसला
- शिकायत के लिए आज जारी होगा मोबाइल नंबर और ई मेल आइडी
- फर्जी खबरें पोस्ट करने वालों की जानकारी देने वाले होंगे पुरस्कृत

सोशल मीडिया पर फर्जी और अफवाहें फैलाने वाली पोस्ट डालने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसा करने वालों को तीन साल की जेल काटनी पड़ सकती है। सोमवार को विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति की बैठक यह फैसला लिया गया।

समिति ने दिल्ली में हुए दंगों के मद्देनजर यह फैसला लिया है। यह समिति एक एजेंसी की मदद से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फर्जी खबरों की जांच कराएगी और आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कराएगी। साथ ही समिति ने सोशल मीडिया पर ऐसी फर्जी खबरें फैलाने वालों की जानकारी देने वालों को पुरस्कृत करने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए मंगलवार को एक ईमेल आइडी और मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा। पुरस्कार की राशि अभी तय नहीं है। हालांकि समिति के कुछ सदस्यों ने 10 हजार रुपये इनाम देने की सिफारिश की है।

गौरतलब है कि विधानसभा ने दिल्ली में हुए दंगों की वजह जानने और उस पर रोकथाम के लिए दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज को बनाया गया है, जबकि विधायक अब्दुल रहमान, अजय कुमार महावर, अतिशी, बीएस जून, जरनैल सिंह, दिलीप पांडेय, कुलदीप कुमार और राघव चड्ढा को सदस्य बनाया गया है।

समिति लेगी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की मदद

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सौरभ ने बताया कि समिति ने यह भी फैसला लिया है कि कुछ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की मदद ली जाएगी क्योंकि उनके पास कानून का अच्छा अनुभव होता है। सेवानिवृत्त अधिकारी समिति को राय देंगे कि जो लोग गड़बड़ी व घृणा फैला रहे हैं, उनको किस तरह से सजा दी जाए।

वाट्सएप, फेसबुक के अफसरों से भी ली जाएगी सहायता

इसके अलावा समिति के पास एक और प्रस्ताव आया है कि वाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर आदि के वरिष्ठ अधिकारियों से मदद ली जाएगी। उनसे बात की जाएगी कि समिति की वे कैसे मदद कर सकते हैं।

भाजपा की मांग, दंगाइयों की संपत्ति से हो नुकसान की भरपाई

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

भाजपा विधायकों ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करते हुए दंगे के दौरान हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों की संपत्ति से करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के समय एक साजिश के तहत दिल्ली में हिंसा कराकर देश की छवि खराब करने की कोशिश की गई। माहौल बिगाड़ने के लिए अभी भी अफवाह फैलाई जा रही है, जिसकी जांच जरूरी है।

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों के शिष्टमंडल ने राजनिवास जाकर उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। बिधूड़ी ने कहा कि हिंसाग्रस्त इलाके में पहले से हथियार जमा किए गए थे। अभी भी वहां हथियार हो सकते हैं, इसलिए प्रत्येक घर की तलाशी लेकर अवैध रूप से हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने हिंसा में संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से करने की मांग की। रविवार शाम को राजधानी के कई हिस्से में दंगे की अफवाह फैलाई गई। दंगों के दौरान लोगों की संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई दंगाइयों से की जानी चाहिए। कहा कि उकसावे के बावजूद दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने धैर्य व संयम का परिचय दिया। गृह मंत्री अमित शाह के सक्षम नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया।

उन्होंने कहा कि सड़क को घेरकर प्रदर्शन करना गलत परंपरा है। इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर जैसी जगह सुनिश्चित है। अगर किसी को विरोध प्रकट करना है तो वहीं आकर करना चाहिए। शिष्टमंडल में विधायक मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, ओमप्रकाश शर्मा, अनिल वाजपेयी, जितेंद्र महाजन तथा अभय वर्मा शामिल थे।

बीमा दावों के त्वरित निपटारे के लिए पीएमओ ने बुलाई बैठक

नई दिल्ली, आइएएनएस : उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों से आ रहे बीमा दावों के त्वरित और परेशानी रहित निपटारे के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सरकारी बीमा कंपनियों की एक बैठक बुलाई है।

हालांकि ये अभी शुरुआती दिन हैं, लेकिन प्रारंभिक अनुमान बताते हैं कि 10 से 15 करोड़ रुपये के बीमा दावे पेश किए जा सकते हैं। हालात सामान्य होने के बाद जब सर्वेयर मूल्यांकन शुरू करेंगे तब बीमा दावों की राशि बढ़ सकती है। सूत्रों ने बताया कि संभावित हालात और दावों की स्थिति की पीएमओ पहले ही समीक्षा कर चुका है। उन्होंने बताया कि सरकारी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम (एलआइसी) रिकॉर्ड समय में दिल्ली पुलिस के मारे गए हेड कांस्टेबल की बीमा राशि का भुगतान कर चुका है। अभी तक पेश किए गए बीमा दावों में ज्यादातर मोटर वाहनों को हुए नुकसान और कारोबार को हुए नुकसान से संबंधित हैं। एक निजी बीमा कंपनी के एक एक्जीक्यूटिव ने बताया कि भारत में संपत्ति, कारोबार, दुकानों और घरों का सामान्य तौर पर बीमा नहीं कराया जाता। चूंकि मोटर वाहनों का बीमा कराना अनिवार्य है इसलिए ज्यादातर दावों में वाहनों को हुए नुकसान ही शामिल हैं, लेकिन स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।

हेड कांस्टेबल रतन लाल के हत्यारोपित का मिला सुराग

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

24 फरवरी को वजीराबाद रोड पर दंगे के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल को सामने से गोली मारने वाले दंगाई के बारे में क्राइम ब्रांच को अहम सुराग मिला है। डीसीपी शाहदरा अमित शर्मा को बचाने के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी।

जामिया इलाके में छिपा है ताहिर : आइबी के सिपाही अंकित शर्मा की हत्या का आरोपित आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन व हवलदार दीपक दहिया पर पिस्टल तानने वाले शाहरुख को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस को शक है कि ताहिर जामिया इलाके में छिपा है। वहां उसके कई रिश्तेदार रहते हैं। वहीं, शाहरुख की तलाश में दिल्ली, पंजाब व उत्तर प्रदेश में स्पेशल सेल छापेमारी कर रही है।

अंकित के परिजन को भी एक करोड़ देगी दिल्ली सरकार : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आइबी जवान अंकित शर्मा के परिवार को एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।

पुलिस जांच के बाद सील होगी तेजाब फैक्ट्री : शिव विहार के गोविंद विहार स्थित तेजाब फैक्ट्री को पुलिस जांच के बाद सील किया जाएगा। यह वही तेजाब फैक्ट्री है जहां से दंगा प्रभावित इलाकों में तेजाब पहुंचाया गया था। इसकी वजह से भारी तबाही हुई थी। यहां तक कि पुलिसकर्मियों पर भी तेजाब से हमला किया गया था।

दंगों से पहले भी तेजाब आपूर्ति हुई थी। यहां जब पुलिस पहुंची तब भी 60 हजार लीटर तेजाब मिला। गंगा जल लिखे टंकियों में तेजाब जमा किया जाता था। यह फैक्ट्री इस इलाके में अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। नगर निगम शाहदरा उत्तरी जोन के चेयरमैन प्रवेश शर्मा ने इस फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से सील करने का आदेश दिया था लेकिन यह अभी तक सील नहीं हो पाया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि अभी यहां पुलिस जांच चल रही है। इस कारण इसे सील नहीं किया जा सकता है।

योगी ने दी गौतमबुद्ध नगर को 2821 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

जागरण संवाददाता, नोएडा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा प्रवास के दूसरे दिन जिले को 2821 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी। सेक्टर 38ए के बोटेनिकल गार्डन में उन्होंने दस परियोजनाओं का लोकार्पण और दस परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा में शासन स्तर पर विश्वस्तरीय सुविधाएं दी जा रही हैं। ये दोनों शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी के संकल्प को पूरा करने के लिए तेजी से बढ़ रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण पूरा होने के बाद आने वाले समय में गौतमबुद्ध नगर विश्वस्तरीय सुविधाओं वाला शहर होगा और यहां लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे।

प्रदेश में जिला स्तर पर खोलेंगे युवा हब : मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है। प्रदेश में हम हर जिला स्तर युवा हब के नाम से स्टार्टअप खोलने जा रहे हैं। प्रत्येक युवा हब में पांच हजार युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। ऐसे युवाओं को 2500 रुपये मासिक मानदेय भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास के जिस मॉडल को हमें दुनिया के सामने रखना चाहिए था, उसकी हमने पिछले तीन साल में नींव रख दी है। नोएडा विकास प्राधिकरण की मल्टीलेवल पार्किंग का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पार्किंग में 7500 वाहन एक साथ पार्क हो सकते हैं। यह देश की सबसे बड़ी मल्टीलेवल पार्किंग है। इससे लोगों को सुविधा होगी।

योगी आदित्यनाथ। (फाइल)

जेवर में निवेश के लिए लाइन में बड़ी कंपनियां

जेवर एयरपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हम विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं। वर्ष 2015 से 2017 के बीच जिस भट्ठा पारसौल में दिन में भी लोग जाने से डरते थे, तीन साल में वहां सब कुछ बदल चुका है। अब विश्व की बड़ी कंपनियां यहां निवेश के लिए हमसे संपर्क कर रही हैं। यहां के युवाओं को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया है कि रोजगार के लिए कहीं और नहीं जाना होगा। विकास परियोजनाओं को समय पर शुरू करने के लिए उन्होंने नोएडा-ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की सराहना की, साथ ही ईमानदारी से काम करने की नसीहत भी दी।

5,000 फ्लैटों की डीडीए की नई आवासीय योजना जुलाई में

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की नई आवासीय योजना जुलाई में आएगी। इस योजना में पांच हजार फ्लैट शामिल रहेंगे। पहली बार सुपर एचआइजी फ्लैट भी इसका हिस्सा होंगे। फिलहाल आला अधिकारी इस योजना का प्रारूप तैयार करने में लगे हैं। इसके बाद उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए इस प्रारूप को डीडीए बोर्ड की बैठक में लाया जाएगा।

2014 से 2019 के बीच आई डीडीए की तीन स्कीमों को अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया। बड़ी संख्या में आवंटियों ने अपने फ्लैट वापस भी कर दिए। ज्यादातर की शिकायत फ्लैटों का आकार छोटा होने से जुड़ी थी। इसके बाद डीडीए ने नए फ्लैट बनाने से भी तौबा कर ली। लेकिन जो फ्लैट बनने शुरू हो गए थे, वे जैसे-जैसे तैयार होते जाएंगे, डीडीए कुछ- कुछ हजार फ्लैटों की आवासीय योजना लाता रहेगा। हर योजना में पहले की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सुधार होगा। इसी कड़ी में अगली योजना जुलाई में लाने की तैयारी है। नई योजना के सभी फ्लैट द्वारका, जसोला, रोहिणी और नरेला में होंगे। इस बार फ्लैट पूर्णतया तैयार हो जाने के बाद ही योजना लाई जाएगी। इन फ्लैटों में बिजली-पानी, परिवहन, रंग- रोगन, पार्क और अन्य सभी सुविधाएं भी पहले से ही मुहैया करा दी जाएंगी, ताकि बाद में सफल आवंटियों को कोई शिकायत न रहे।

इसमें एचआइजी, एमआइजी, एलआइजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैट तो शामिल रहेंगे ही, करीब छह दशक से भी अधिक लंबे इतिहास में डीडीए सुपर एचआइजी फ्लैट भी ऑफर करेगा। इन फ्लैटों को पेंट हाउस भी कहा जा रहा है। यह फ्लैट द्वारका में टॉप फ्लोर पर होंगे। जगह अधिक होने के चलते इनकी कीमत दो से तीन करोड़ रुपये के बीच रहेगी।

> नई आवासीय योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। जल्द ही सभी औपचारिकताएं पूरी करके योजना का पूरा प्रारूप उपराज्यपाल और डीडीए अध्यक्ष की स्वीकृति के लिए बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
>
> -तरुण कपूर, उपाध्यक्ष, डीडीए

तलाशी राह

आइआइटी दिल्ली की केमिकल इंजीनियरिंग की एसोसिएट प्रोफेसर शालिनी गुप्ता को नई तकनीक विकसित करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर चुके हैं सम्मानित

खून में बैक्टीरिया के संक्रमण का दस मिनट में लग जाएगा पता

राहुल मानव, नई दिल्ली

खून में बैक्टीरिया का संक्रमण है या नहीं यह अब सिर्फ दस मिनट में ही पता लग जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली की केमिकल इंजीनियरिंग की एसोसिएट प्रोफेसर शालिनी गुप्ता ने ऐसी ही एक तकनीक को विकसित किया है। इस तकनीक को विकसित करने के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान स्थापना दिवस के मौके पर विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सामाजिक लाभ के लिए प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से उत्कृष्टता दिखाने वाली युवतियों को इस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उन्हें वर्ष 2019 के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया है। इस पुरस्कार को भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीक विभाग (डीएसटी) के सौजन्य से प्रदान किया गया है। डॉ. शालिनी बैक्टीरिया संक्रमण का तेजी से इलाज करने की प्रणाली पर काम कर रही हैं। उन्होंने एक ऐसी डिवाइस को तैयार की है जिससे सिर्फ दस मिनट में खून की जांच करते हुए बैक्टीरिया के संक्रमण के बारे में पता लगाया जा सकता है। साथ ही उसकी क्षमता की भी जानकारी मिल सकेगी। डॉ. शालिनी ने इस तकनीक का पेटेंट भी करा लिया है।

आइआइटी दिल्ली की एसोसिएट प्रोफेसर शालिनी गुप्ता डिवाइस दिखाते हुए। जागरण

डिवाइस में पिंक रंग आने से पता लग जाता है कि खून में बैक्टीरिया का संक्रमण है या नहीं। सौ. प्रो. शालिनी

डॉ. शालिनी ने वर्ष 2002 में आइआइटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी से केमिकल एंड बॉयोमॉलिक्यूलर में पीएचडी की डिग्री हासिल की है। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ आइआइटी दिल्ली में नैनोडेक्स स्टार्ट-अप कंपनी भी स्थापित की है।

कैसे काम करती है यह तकनीक

डॉ. शालिनी ने बताया है कि पांच साल की मेहनत के बाद यह तकनीक विकसित की गई है। इसमें डिवाइस के अंदर दो माइक्रोलीटर खून की बूंद डालनी होती है और इसके बाद कुछ रासायनिक (कैमिकल सॉल्यूशन) पदार्थ डालने होते हैं। इसके बाद खून का रंग अगर बहुत ज्यादा घना गुलाबी रंग का होता है तो इसका अर्थ है कि खून में बैक्टीरिया का संक्रमण है। अगर गुलाबी रंग बिल्कुल भी नहीं आता है तो इसका अर्थ है कि खून में बैक्टीरिया का संक्रमण नहीं है।

क्या होता है असर

डॉ. शालिनी ने कहा कि खून में बैक्टीरिया का संक्रमण पाया जाता है तो इससे शरीर में सैप्टिसीमिया बीमारी होने की आशंका रहती है। बैक्टीरिया का संक्रमण खून के जरिये पूरे शरीर में फैल जाता है जो जीवन के लिए खतरनाक हो जाता है। इस तरह का संक्रमण दिल की धड़कनें तेज कर सकता है, श्वसन क्रिया को भी तेज कर सकता है। इससे निमोनिया और किडनी का संक्रमण भी हो सकता है।

क्या हैं फायदे

डॉ. शालिनी ने बताया कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के क्लिनिक में इस तकनीक को पिछले दो वर्षों में 300 मरीजों पर आजमाया गया है। आमतौर पर लैब में खून की जांच कराने में एक दिन का समय लग जाता है। डीएनए के जरिये मशीनी उपकरणों से टेस्ट कराते हैं तो तीन घंटे लगते हैं। इस तकनीक से दस मिनट में खून की सफलतापूर्वक जांच हो जाती है।

लगातार तीन दिन बारिश के आसार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : फिलहाल भले ही मौसम में गर्मी का एहसास बढ़ रहा हो, लेकिन एक-दो दिन में ही फिर से फिजा बदलने के आसार हैं। हिमालय क्षेत्र में सक्रिय होने जा रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली में लगातार तीन दिन तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना है। हालांकि बुधवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक चले जाने की उम्मीद है।

सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। शुक्रवार को हवा की गति बढ़कर 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तेज बारिश और ओलावृष्टि होने का अनुमान है। शनिवार को भी बारिश होने की संभावना है।

चुनावों की सरकारी फंडिंग के पक्ष में नहीं आयोग

नई दिल्ली, प्रेट्र : चुनाव आयोग चुनावों की सरकारी फंडिंग के पक्ष में नहीं है। आयोग का कहना है कि ऐसा होने से यह तय कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि उम्मीदवारों ने कितना खर्च किया है। इससे उम्मीदवारों के खर्च पर नियंत्रण भी मुश्किल हो जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने और नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने की दिशा में सरकार के कदमों का भी जिक्र किया। सरकार ने इसके लिए आयकर कानून में बदलाव किया है और अज्ञात स्रोत से मिलने वाले नकद चंदे की सीमा 2000 रुपये तय कर दी है। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता के लिए सरकार 'चुनावी बांड स्कीम 2018' लाई है। इससे चंदे का ऑडिट आसान होता है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश में आयकर रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या पिछले तीन साल से लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक, असेसमेंट ईयर 2016-17 में 5.18 करोड़ लोगों ने ई-रिटर्न दाखिल किया था।

रिटर्न नहीं फाइल करने वालों पर नजर

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि रिटर्न फाइल नहीं करने वालों पर भी सरकार की नजर है। इसके लिए नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएस) लागू किया गया है। इसके तहत अन्य स्रोतों से ऐसे लोगों की जानकारी जुटाई जाती है, जिन्होंने बड़ा वित्तीय लेनदेन किया है लेकिन रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। पिछले तीन साल में ऐसे क्रमशः 33 लाख, 38 .81 लाख और 15 .58 लाख लोगों की पहचान की गई।

असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए 15 फरवरी तक यह संख्या 6.35 करोड़ हो चुकी है। असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए अभी 31 मार्च तक रिटर्न फाइल किए जा सकते हैं, इसलिए यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।

सरकारी खर्च पर चुनाव!

चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए समय-समय पर चिंताएं जाहिर की गईं, लेकिन इसके तहत गठित समितियों की सिफारिशों पर अमल नहीं हो सका।

इंद्रजीत गुप्त समिति

भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने चुनावी प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के तहत जून, 1998 में इंद्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में संसदीय समिति का गठन किया। राजनीतिक दलों से विस्तृत सलाह मशविरा के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को सौंपी।

अहम सिफारिशें

- समिति ने सरकारी खर्च पर चुनाव का समर्थन करते हुए कहा कि कम धन वाले दलों के लिए बराबरी का मौका वाले हालात स्थापित करने के लिए यह पूरा न्यायोचित, संवैधानिक और विधिसम्मत के साथ-साथ जनहित में भी है।
- केंद्र सरकार द्वारा सालाना 600 करोड़ रुपये योगदान वाले एक अलग चुनाव कोष का निर्माण किया जाए (10 रुपये प्रति मतदाता के हिसाब से 60 करोड़ मतदाताओं के लिए)। इस कोष में यथोचित भागीदारी सभी राज्य सरकारों की भी होगी।
- सरकारी खर्च पर चुनाव कराने की दो सीमाएं हों। पहला यह कि चुनाव खर्च उन्हीं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों को दिया जाए जिनको चुनाव चिह्न आवंटित किया गया हो। निर्दलीय उम्मीदवारों को यह खर्च न दिया जाए। दूसरा यह कि अल्प कालीन स्टेट फंडिंग के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को यह मदद अन्य सुविधाओं के रूप में दी जाए।
- रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय चूंकि देश की माली हालत इस लायक नहीं थी कि चुनाव खर्च सरकार उठा सके, इसलिए आंशिक खर्च वहन करने का सुझाव दिया।

प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट

2008 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी अनैतिक और अनावश्यक फंडिंग को कम करने के उद्देश्य से आंशिक रूप में सरकारी खर्च पर चुनाव कराने की बात कही।

लॉ कमीशन की रिपोर्ट

1999 में कहा कि सरकारी खर्च पर चुनावों को संपन्न कराना तभी वांछनीय है जब तक राजनीतिक दलों को अन्य स्रोतों से धन लेने पर पाबंदी हो। आंशिक स्टेट फंडिंग की वकालत की।

संविधान समीक्षा आयोग

2001 में सरकारी खर्च पर चुनाव के विचार को खारिज किया। 1999 में लॉ कमीशन की उस सिफारिश की वकालत की जिसमें स्टेट फंडिंग पर विचार करने से पहले राजनीतिक दलों को उपयुक्त नियामक तंत्र के दायरे में लाए जाने का प्रावधान था।

परदेस में प्रावधान

दुनिया के कई देशों में राजनीतिक दलों को चंदा देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं। यहां पर चंदा देने वाले कारपोरेट, ट्रेड यूनियन और वैयक्तिक स्तर पर वैधानिक सीमा लागू कर दी गई है। विदेश में चंदा लेने-देने की प्रक्रिया पर पेश है एक नजर :

ब्रिटेन : प्रमुख रूप से चंदा देने के तीन प्रमुख स्रोत हैं- सदस्यता, चंदा और सरकारी खर्चे पर चुनाव (स्टेट फंडिंग)। विवाद की मुख्य वजह यह है कि देश के राजनीतिक दलों पर आरोप है कि वे कुछ विशेष धनी दाताओं पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हैं।

आयरलैंड : एक व्यक्ति सालाना 4,500 पौंड से अधिक की राशि चंदे के रूप में नहीं दे सकता। राजनीतिक दलों को 3,600 पौंड से अधिक का चंदा प्राप्त करने पर ब्योरा देना होता है।

फ्रांस : 1995 से व्यापारिक समुदाय से चंदे लेने पर पाबंदी लगा दी गई है। यहां सरकारी खर्चे पर चुनाव होते हैं। चुनाव के दौरान एक व्यक्ति 4600-7500 यूरो के बीच चंदा दे सकता है। इस पर टैक्स में छूट भी मिलती है।

अमेरिका : हर नागरिक प्रत्येक चुनाव अभियान में एक हजार डॉलर से अधिक की राशि नहीं दे सकता। इसी तरह एक नागरिक साल भर में चुनावी अभियानों के लिए 25 हजार डॉलर से अधिक नहीं दे सकता। प्रत्याशियों की कमेटियों, राजनीतिक दलों की कमेटियों ओर राजनीतिक कार्यवाही कमेटियों (पीएसी) को प्राप्ति और खर्च के विषय में नियमित अंतराल पर रिपोर्ट देनी होती है। इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्शन सिस्टम के अनुसार प्रत्याशियों के पास उनको वित्तीय समर्थन देने वाले पीएसी और पार्टी कमेटियों की सूची होनी चाहिए। इसके साथ ही उनको सालाना 200 डॉलर से अधिक का चंदा देने वाले व्यक्तियों का नाम भी बताना होता है।

ऑस्ट्रेलिया : निर्वाचन आयोग को चंदे का ब्योरा देना अनिवार्य है। किसी प्रत्याशी को यदि कोई नागरिक या संगठन 125 डॉलर से अधिक या किसी सीनेट समूह को 625 डॉलर से अधिक देता है तो उसके नाम और पते को घोषित करना होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी पंजीकृत दल को 935 डॉलर से अधिक का चंदा देता है तो उसको आयकर रिटर्न में दिखाना होता है।

जर्मनी : 6700 पौंड से अधिक दिए जाने वाले सभी चंदे का ब्योरा देना आवश्यक है। यूरोपीय यूनियन या किसी कंपनी में एक जर्मन नागरिक की हिस्सेदारी यदि 50 प्रतिशत से ज्यादा है तो वह 336 पौंड का चंदा दे सकता है। प्रमुख रूप से सरकारी खर्चे पर चुनाव होते हैं।

संसदीय समितियों की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहे 95 सदस्य : नायडू

घटती उपस्थिति ▶ अनुदान मांगों पर विचार के लिए गठित इन समितियों में हैं 244 सदस्य

नई दिल्ली, प्रेट्र : राज्यसभा सभापति एम. वेंकैया नायडू ने संसद की स्थायी समितियों की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति पर चिंता जताई है। नायडू के अनुसार 95 सांसदों ने तो संसद की स्थायी समितियों की एक भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। ये समितियां मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर विचार करती हैं।

बजट के बाद तीन हफ्तों के अवकाश के दौरान विभिन्न विभागों से संबंद्ध संसद की 24 स्थायी समितियों ने मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर विचार किया। इन समितियों में लोकसभा और राज्यसभा के 244 सदस्य शामिल हैं। अवकाश के बाद शुरू हुए बजट सत्र के पहले दिन नायडू ने राज्यसभा में बताया, 'कुल 244 में से 95 सदस्यों यानी 39 फीसद ने अनुदान मांगों की किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। पिछली बार केवल 28 सदस्यों की अनुपस्थिति शून्य रही थी।' इन समितियों में शामिल राज्यसभा के 78 सदस्यों में से 23 यानी 29 फीसद सभी बैठकों में अनुपस्थित रहे। पिछली बार ऐसे सदस्यों की संख्या 11 थी। लोकसभा के 166 सदस्यों में से 78 यानी 47 फीसद सभी बैठकों में नदारद रहे। पिछली समीक्षा में इनकी संख्या 72 थी।'

इन समितियों की बैठकें संसद की करीब 30 बैठकों की भरपाई करती हैं। पहले संसद 100 दिनों तक चलती थी, जिसकी संख्या अब घटकर 60-70 दिन हो गई है। बजट सत्र के दौरान तीन सप्ताह की छुट्टियां इसलिए की गई थीं, ताकि एक फरवरी को बजट के दौरान प्रस्तुत मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर 24 स्थायी समितियां विचार कर सकें।

नायडू ने कहा, 'समितियों की लगातार दो बैठकों में गायब रहने वाले सदस्यों की संख्या इस बार 106 हो गई, जो पिछली बार 100 थी। इनमें राज्यसभा के 28 व लोकसभा के 78 सदस्य शामिल हैं।' उन्होंने कहा कि विभागों से संबंद्ध इन समितियों में से आठ राज्यसभा से संबंधित थीं, जिनकी 20 बैठकों के दौरान 45.35 फीसद उपस्थिति रही। यह संतोषजनक नहीं है। हालांकि, चार समितियों में सदस्यों की उपस्थिति 50 फीसद से अधिक रही। राज्यसभा के सदस्यों की उपस्थित 52.57 फीसद रही जो लोकसभा सदस्यों की 46.37 फीसद उपस्थिति से ज्यादा थी।

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण की बैठकों में उपस्थिति सबसे ज्यादा : नायडू ने बताया स्वास्थ्य व परिवार कल्याण समिति की बैठकों में सबसे ज्यादा 65.51 फीसद उपस्थिति रही। इसके 29 में से 19 सदस्य तीनों बैठकों में उपस्थित रहे। वाणिज्य विभाग से संबद्ध समिति में सदस्यों की उपस्थिति सबसे कम 32.25 फीसद रही।

भाजपा-कांग्रेस सदस्यों की हाजिरी दूसरे दलों से ज्यादा : समितियों में भाजपा व कांग्रेस के कुल 142 सदस्य शामिल थे, जिनकी उपस्थिति 50 फीसद रही। जबकि, इसमें शामिल दूसरे दलों के 102 सदस्यों की उपस्थिति 40 फीसद थी।

रेलवे के आंतरिक संसाधनों में कमी पर जताई चिंता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संसद की स्थायी समिति ने रेलवे की खराब माली हालत पर चिंता जाहिर की है और रेल मंत्रालय से अपने आंतरिक संसाधनों में बढ़ोतरी के प्रयास तेज करने को कहा है।

लोकसभा सदस्य राधामोहन सिंह की अध्यक्षता वाली संसद की रेल मंत्रालय से संबद्ध स्थायी समिति ने रेलवे की अनुदान मांगों से संबंधित अपनी रिपोर्ट सोमवार को संसद के दोनों सदनों में पेश की। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कई वर्षों के दौरान रेलवे के आंतरिक संसाधानों में तीव्र गिरावट देखने में आई है। इससे बजटीय सहायता तथा बाजार से लिए जाने वाले ऋणों पर रेलवे की निर्भरता बढ़ गई है। परिणामस्वरूप पूंजीगत परिव्यय में कमी आ रही है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि जहां वर्ष 2016-17 में कुल बजट में आंतरिक संसाधनों का योगदान 12,125 करोड़ रुपये यानी 11.3 फीसद था, वहीं 2017-18 में यह घटकर मात्र 3,070 करोड़ यानी 3.1 फीसद रह गया। वर्ष 2018-19 में भी यही हालत रही और आंतरिक संसाधनों से रेलवे केवल 4,663 करोड़ रुपये यानी 3.5 फीसद धन जुटा पाया। यही नहीं, वर्ष 2019-20 में हालत और भी खराब मानी जाएगी, क्योंकि रेलवे ने आंतरिक संसाधनों से केवल 5,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। और तो और वर्ष 2020-21 के लिए भी आंतरिक संसाधन से राजस्व जुटाने का रेलवे का लक्ष्य मात्र 7,500 करोड़ का है। आंतरिक संसाधनों में कमी के लिए रेलवे ने यात्री, माल यातायात तथा विविध आय से होने वाली आमदनी में कमी के अलावा सातवें वेतन आयोग के असर को मुख्य वजह बताया है।

पानी की हिस्सेदारी पर उप्र और मप्र में नहीं बनी बात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- दोनों राज्य ज्यादा पानी के दावे पर डटे, संसद में भी उठा सवाल
- डीपीआर तैयार, पर्यावरण मंत्रालय भी दे चुका मंजूरी

केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच अभी भी पानी की हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में दोनों ही राज्यों के बीच सभी मुद्दों पर जल्द समाधान की जानकारी दी है। इस बीच दोनों राज्यों के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए बैठकें चल रही हैं। बीती 26 फरवरी को भी दोनों के बीच मुद्दों के समाधान को लेकर चर्चा हुई है। इसमें दोनों राज्यों के जल और राजस्व विभाग के सचिवों ने हिस्सा लिया था।

नदियों को जोड़ने की इस मुहिम को 2002 में तत्कालीन अटल बिहारी बाजपेयी सरकार ने शुरू किया था। इसमें सबसे पहले केन-बेतवा पर काम शुरू किया है। साथ ही इन नदियों के पानी से बुंदेलखंड की जल्द ही प्यास बुझाने का सपना भी बुना गया, लेकिन तब से आज तक यह परियोजना विवादों में ही उलझी हुई है। हालांकि इस बीच मौजूदा सरकार ने केन-बेतवा के नदी जोड़ परियोजना के पहले और दूसरे चरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसे पर्यावरण मंत्रालय की भी मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में जब परियोजना पर काम शुरू होने की बारी आई, तो दोनों राज्यों ने पानी की हिस्सेदारी को लेकर अपने अलग-अलग दावे ठोक दिए। केंद्र के दखल के बाद दोनों राज्यों में थोड़ी बात बनी, लेकिन अब भी दोनों राज्य इसे लेकर पूरी तरह सहमत नहीं है। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जल की हिस्सेदारी सहित दूसरे कई मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के साथ इसे लेकर गठित कार्यबल काम कर रहा है।

प्रकाश जावडेकर। फाइल

केन-बेतवा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र में नदियों की जलधारा को रोककर बालू व अन्य खनिजों के अवैध खनन को लेकर संसद में किए गए सवाल को पर्यावरण मंत्रालय ने गलत बताया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने इससे जुड़े सवाल के जवाब में बताया कि अवैध खनन, ढुलाई, भंडारण रोकने का विषय राज्य सरकारों का है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक नदियों की जलधारा को रोककर बुंदेलखंड में कहीं भी अवैध खनन नहीं हो रहा है।

पुरातात्विक महत्व के सभी स्थलों की अब होगी जियो मैपिंग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पुरातात्विक महत्व के स्थलों को संरक्षित करने के साथ ही उन्हें अवैध कब्जों से बचाने के लिए सरकार ने बड़ी मुहिम छेड़ दी है। इसके तहत देश के ऐसे सभी स्थलों को अब इसरो की मदद से जियो मैपिंग कराने का फैसला लिया गया है। मौजूदा समय में देश में पुरातात्विक महत्व के 36 सौ से ज्यादा स्थल हैं, लेकिन अभी इनमें से सिर्फ पांच सौ स्थलों की ही जियो मैपिंग हुई है।

संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक, जियो मैपिंग के साथ ही इसमें उस स्थल से जुड़ी सारी जानकारी भी मिलेगी। इसके साथ ही स्थल पर मौजूदा भवन और इमारत को देखा जा सकेगा। वहीं इस प्रोजेक्ट से ऐसे स्थलों के आस-पास होने वाले निर्माणों पर भी नजर रखी जा सकेगी। मौजूदा समय में पुरातात्विक स्थलों के आसपास काफी बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा हटाने के लिए सरकार जहां एक तरफ मुहिम जारी रखे हुए है, वहीं कोई नया कब्जा न हो इसे लेकर सतर्क भी है। फिलहाल विस्तृत क्षेत्र में फैले इन पुरातात्विक महत्व के स्थलों पर निगाह रखना काफी कठिन काम है। ऐसे में सरकार ने इसके लिए तकनीक का सराहा लिया है, जिसमें इसरो से मदद ली जा रही है। पुरातात्विक महत्व के स्थलों को सहेजने का सरकार का यह कोई पहला प्रयास नहीं है। इसके अलावा सरकार ने उन स्थलों को दुनिया की नजरों में सामने लाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। इसके तहत देश भर में फैले ऐसे स्थलों की नए सिरे सर्वे कराने का फैसला लिया है।

स्मृति ने सदन को शर्मसार होने से बचाया

नई दिल्ली, आइएएनएस : लोकसभा में सोमवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का अलग चेहरा देखने को मिला। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन दिल्ली दंगे को लेकर हुए हंगामे के बीच स्मृति ईरानी की तत्परता ने सदन को शर्मसार होने से बचा लिया। इससे पहले कि पक्ष-विपक्ष की धक्का-मुक्की कोई और रंग लेती, स्मृति ईरानी ने मजबूती से हालात को संभाल लिया।

दिल्ली दंगों को सरकार की विफलता बताते हुए विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा था। इसी बीच कांग्रेस के गौरव गोगोई और गुरजीत सिंह ने हाथ में बैनर लेकर भाजपा के संजय जयसवाल को बोलने से रोकने की कोशिश की। इस पर रमेश विधूड़ी समेत कुछ भाजपा नेता आगे आए और बैनर छीनने की कोशिश करने लगे। नौबत धक्का-मुक्की तक पहुंच गई। तभी हालात को भांपते हुए स्मृति ईरानी दोनों पक्षों के बीच पहुंच गईं। उनके साथ कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी जुड़ गए। दोनों नेताओं ने समझ-बूझ के साथ दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की। इसके बाद कांग्रेस के अधीर रंजन भी आगे आए और अपने साथियों को शांत किया। कुछ देर बाद सदन में फिर ऐसी ही स्थिति बनती दिखी, लेकिन स्मृति ईरानी ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और हाथ जोड़कर सदस्यों को शांत किया। बसपा सांसद ने कहा, 'सदन में नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और रामविलास पासवान जैसे नेताओं की अनुपस्थिति ने सदन में स्थिति को बिगाड़ा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नहीं होने से भी स्थिति बिगड़ी। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि स्मृति ईरानी ने सदन को शर्मसार होने से बचा लिया। दोनों पक्ष के सदस्यों का गुस्सा देखते हुए कुछ भी हो सकता था, लेकिन स्मृति ईरानी ने स्थिति को संभाल लिया।'

सांसदों के आचरण से बिरला आहत : लोकसभा में सांसदों के कृत्यों से तार-तार हुई मर्यादा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को व्यथित कर दिया। जिस तरह लोकसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच न सिर्फ धक्का-मुक्की हुई बल्कि अपशब्द भी कहे गए, उसने बिरला को इतना असहज कर दिया कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसी परिस्थिति में वह सदन संचालित नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने अपील की कि सभी दल के वरिष्ठ नेता एक साथ बैठें और हमेशा के लिए एक एक दिशा तय करें ताकि फिर कभी ऐसी परिस्थिति न बने।

दिल्ली हिंसा पर संसद में विपक्ष का हंगामा, आंखों पर काली पट्टी और मुंह पर अंगुली

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होते ही विपक्षी दलों ने दिल्ली हिंसा पर सोमवार को खूब हंगामा मचाया। हिंसा का ठीकरा मोदी सरकार, खासकर गृहमंत्री अमित शाह पर फोड़ते हुए उनके इस्तीफे की मांग की गई। इस दौरान टीएमसी सांसदों की आंखों पर काली पट्टी और मुंह पर अंगुली थी।

देखें, संसद में विपक्षी दलों का हंगामा ऊपर छपी तस्वीर को Google Lens से स्कैन करके

वीडियो देखने के लिए

1. अपने मोबाइल पर Google Lens App डाउनलोड करके OPEN करें. Go to goo.gle/lens, or use the Google Lens App on Android/Google App on iOS
2. ऊपर छपी तस्वीर को Google Lens के साथ स्कैन करें
3. छपी तस्वीर पर आधारित विश्लेषणात्मक वीडियो देखें

गर्भपात की ऊपरी सीमा बढ़ाने का बिल लोस में पेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा में सोमवार को गर्भपात की मंजूर सीमा को वर्तमान 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने के लिए गर्भ चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 पेश किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने यह बिल पेश किया।

राइफल व कारतूस गायब होने के मामले की सीबीआइ जांच नहीं : विजयन

तिरुअनंतपुरम, एजेंसियां : केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोमवार को एसएपीबी से राइफल व जिंदा कारतूस गायब होने संबंधी सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर मामले की सीबीआइ जांच कराने की विपक्ष की मांग खारिज कर दी है। उन्होंने विधानसभा में कहा, स्पेशल आर्म्ड पुलिस बटालियन (एसएपीबी) की कोई राइफल गायब नहीं हुई है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में जितनी संख्या में जिंदा कारतूसों के गायब होने की बात कही है, उनमें ज्यादातर कांग्रेस की नेतृत्व वाली राज्य की पूर्ववर्ती यूडीएफ सरकार के दौरान गायब हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के दौरान एसएजीबी के मालखाना में तैनात एसआइ को 350 कारतूस कम मिले थे।

कोर्ट ने दोनों फैसलों को विरोधाभासी बताया

प्रथम पृष्ठ से आगे

ये दोनों ही फैसले पांच न्यायाधीशों की पीठ के थे ऐसे में अब अनुच्छेद 370 के मामले की सुनवाई सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजी जानी चाहिए। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि प्रेमनाथ कौल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 370 का प्रावधान अस्थायी प्रकृति का है जबकि संपत प्रकाश के फैसले में कोर्ट ने इस व्यवस्था को पलटते हुए अनुच्छेद 370 को स्थायी प्रकृति का माना था।

कोर्ट ने मामले को बड़ी पीठ को भेजने की मांग ठुकराते हुए कहा कि दोनों फैसले एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं हैं। किसी भी फैसले के चुने हुए अंश नहीं देखे जा सकते और न ही उनका कोई विशिष्ट मतलब निकाला जा सकता है। किसी भी फैसले को उसके तथ्यों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि प्रेमनाथ कौल के फैसले में जम्मू कश्मीर के युवराज की वैधानिक सक्षमता का मुद्दा था। युवराज ने उस समय एक कानून पारित किया था और तब जम्मू कश्मीर का संविधान लागू नहीं हुआ था जबकि भारत का संविधान लागू हो चुका था। इसीलिए प्रेमनाथ कौल के फैसले में कोर्ट ने कहा था अनुच्छेद 370(2) के तहत राज्य की संविधान सभा का निर्णय अंतिम होगा। आदेश में कोर्ट ने कहा है कि इस फाइनेलिटी की बात को अनुच्छेद 370(2) की भाषा को देखते हुए उन सीमित संदर्भों में लिया जाना चाहिए जो निर्णय अनुच्छेद 370 के तहत राज्य सरकार ने राज्य की संविधान सभा की बैठक से पहले लिए थे। कोर्ट ने कहा कि प्रेमनाथ कौल के फैसले में राज्य की संविधान सभा भंग होने के बाद अनुच्छेद 370 के जारी रहने या समाप्त किए जाने का मुद्दा विचार के लिए नहीं था। जैसा कि संपत प्रकाश के केस में हुआ था जिसमें विशेषतौर पर ये दलीलें कोर्ट में दी गई थीं और कोर्ट ने खारिज की थीं। कोर्ट ने कहा कि इसलिए दोनों फैसलों में कोई विरोधाभास नहीं है और उन्हें मामला बड़ी पीठ को भेजने का आधार नजर नहीं आता।

राष्ट्रपति ने गत वर्ष पांच अगस्त को दो आदेश जारी किए थे जिसमें जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए समाप्त कर दिया था। राष्ट्रपति के इस आदेश को बहुत सी याचिकाओं में कोर्ट में चुनौती दी गई है।

विदेशी निवेशकों के मामले में देरी से बचे न्यायपालिका : सीजेआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेशी निवेशकों और मध्यस्थता वाले मामलों में न्यायपालिका को देरी से बचना चाहिए। इससे द्विपक्षीय निवेश संधियों (बीआइटी) के तहत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश को दावों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) एसए बोबडे ने सोमवार को यह बात कही। सीजेआइ बोबडे मध्यस्थता कानूनों पर लिखी सुप्रीम कोर्ट की जज इंदु मल्होत्रा की किताब के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे।

सीजेआइ ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका की गतिविधियों के कारण बीआइटी के तहत अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को कई दावों का सामना करना पड़ा है। यह अप्रत्याशित है। न्यायपालिका यह कर सकती है कि इस तरह के मामलों में होने वाली देरी से बचे।

सीजेआइ ने चिंता जताते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय दावों के ज्यादातर मामले

- देरी के कारण देश को अंतरराष्ट्रीय मंच पर कई दावों का सामना करना पड़ता है

भारत में चल रही आपराधिक जांच की कार्यवाहियों में अड़ंगा डालने के लिए होते हैं। उन्होंने इन्वेस्टर-स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में सुधार की पैरवी भी की। बीआइटी के मामले इसी मैकेनिज्म के तहत आते हैं। सीजेआइ ने कहा कि जजों को विदेशी इकाइयों से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान हर पहलू पर विचार करना चाहिए।

इसी कार्यक्रम में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात पर चिंता जताई कि ऐसे मामलों में अक्सर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप को बड़ा हर्जाना नहीं भरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत संस्थागत मध्यस्थता का केंद्र बनना चाहता है और विदेशी मामलों की सुनवाई को भी यहां अनुमति दी जाएगी।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

17 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां वे बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्मशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 'मुजीब वर्ष' समारोह में हिस्सा लेंगे और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 3 मार्च 2020

गुजरात का 'दंगा मॉडल' देश में लागू करना चाहती है भाजपा : ममता बनर्जी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- बंगाल की मुख्यमंत्री का आरोप-दिल्ली हिंसा सुनियोजित नरसंहार
- तृणमूल प्रमुख ने केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाने का किया आह्वान

बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया कि भाजपा बंगाल सहित पूरे देश में गुजरात के 'दंगा मॉडल' को लागू करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि दिल्ली की हिंसा सुनियोजित नरसंहार है। निर्दोष लोगों की हत्या से मैं अत्यंत दुखी हूं। उन्होंने इसकी कड़ी निंदा भी की है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाने का आह्वान भी किया। राज्य में जल्द निकाय और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित तृणमूल कर्मी सम्मेलन में पार्टी के जनसंपर्क अभियान 'बांग्लार गोर्बो ममता' (बंगाल की गौरव ममता) की लांचिंग के मौके पर बोलते हुए उन्होंने उक्त बातें कहीं।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि मैं दिल्ली की घटना से बहुत दुखी और उदास हूं। यह एक सुनियोजित नरसंहार है। रविवार को भी वहां चार शव मिले हैं। रोज नालों से शव मिल रहे हैं। मुझे पता चला है कि करीब 700 लोग अब भी लापता हैं। उन्होंने दावा कि सीएए के कारण दिल्ली में इतने लोग मारे गए। यह बात अमित शाह को ध्यान में

ममता बनर्जी। फाइल फोटो

रखना चाहिए। ममता ने सवाल उठाया कि दिल्ली में नरसंहार के बावजूद भाजपा ने अभी तक इसके लिए माफी नहीं मांगी है। ऊपर से यहां आकर कहते हैं कि वे बंगाल लेकर जाएंगे। सवाल किया कि दिल्ली में इतनी मौतें हुई हैं, लेकिन भाजपा नेताओं को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, जो भड़काऊ बयान दे रहे थे। तृणमूल सुप्रीमो ने इस दौरान केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम आज संकल्प लेते हैं कि जब तक तानाशाह सरकार को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकते हैं तब तक हम नहीं रूकेंगे।

उत्तर प्रदेश में बोलने तक की आजादी नहीं : ममता ने कहा कि उत्तर प्रदेश जाकर देखिए, लोगों को वहां बोलने तक की आजादी नहीं है। वहां अगर महिलाएं शिकायत दर्ज कराती हैं तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।

सीएए के कारण अब तक 400 की मौत : ममता ने यह भी आरोप लगाया कि सीएए के कारण दिल्ली सहित असम व उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 400 लोगों की जानें जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जहां भी शासन कर रही है, वहां सिर्फ दंगे करा रही है।

हिंसा पीड़ितों को आर्थिक मदद देगी तृणमूल : ममता बनर्जी ने यह भी एलान किया कि दिल्ली हिंसा पीड़ितों के लिए उनकी पार्टी फंड जुटाकर जो भी संभव होगा, आर्थिक मदद करेगी। यह भी कहा कि बंगाल के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। यदि कोई हिंसा पीड़ित यहां आकर रहना चाहता है तो आ सकता है। हमारे प्रदेश में सभी को आने की छूट है। हम किसी को भी आने से नहीं रोकते। यही तो बंगाल की सादगी है और अब तक यही संस्कृति रही है।

भाजपा से मुकाबले को अब तृणमूल का नया अभियान 'बंगाल की गौरव ममता'

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- ममता बनर्जी को बंगाली अस्मिता से जोड़कर भाजपा को घेरने की रणनीति
- चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तृणमूल के इस नवीनतम अभियान को दिया है आकार

बंगाल में भाजपा से मिल रही जबर्दस्त चुनौती से पार पाने के लिए सत्तारुढ़ दल तृणमूल कांग्रेस ने आगामी नगर निकाय चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को 'बांग्लार गर्बो ममता' (बंगाल की गौरव ममता) नाम से नए जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित पार्टी के कर्मचारी सम्मेलन में मुख्यमंत्री व पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इसको लांच किया। इस दौरान पार्टी की ओर से कहा गया कि इस अभियान के तहत तृणमूल के 75 हजार से ज्यादा नेता व जमीनी कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि ममता बनर्जी बंगाल के विकास एवं प्रगति के लिए तथा राज्य के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए कितनी जरूरी हैं।

यह अभियान तीन चरणों में 10 मई तक चलेगा और करीब ढाई करोड़ लोगों तक पार्टी इसके जरिये सीधे तौर पर पहुंचेगी। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने नेताओं व कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे निम्न से निम्न स्तर के लोगों के पास जाएं और अपनी सरकार के विकास कार्यों को बताने के साथ भाजपा की नफरत की राजनीति से उन्हें अवगत कराएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अभियान राज्य सरकार के सुशासन पर केंद्रित होगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह अभियान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के दिमाग की उपज है। ममता ने इससे पहले पिछले साल उनकी सलाह पर 'दीदी के बोलो' अभियान की शुरुआत की थी। इसमें एक हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट शुरू की गई थी, जिसमें शुरुआत में ही जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिली थी और लगभग 10 लाख लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई थीं।

बंगाल में चुनाव की कमान खुद संभालेंगे अमित शाह

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- अप्रैल से तीन व अक्टूबर से महीने में सात दिन बंगाल में रहेंगे केंद्रीय गृहमंत्री
- निकाय और 2021 के विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रियता बढ़ी

बंगाल की सियासी धरती पर कमल खिलाने के लिए भाजपा नेतृत्व काफी तत्पर है। इसीलिए आगामी निकाय चुनाव हो या फिर 2021 का विधानसभा चुनाव, भाजपा का चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने खुद ही बंगाल में चुनावी कमान संभालने की तैयारी कर ली है। यही नहीं कभी तृणमूल कांग्रेस का चाणक्य कहे जाने वाल मुकुल रॉय पर निकाय व विधानसभा चुनाव को लेकर भी शाह ने भरोसा जताया है।

आगामी अप्रैल माह से शाह हर महीने तीन दिन बंगाल में रहेंगे। यह सिलसिला सितंबर तक चलेगा और इसके बाद अक्टूबर से वह आगामी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव तक हर माह सात दिन बंगाल में बिताएंगे। यही नहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार बंगाल का दौरा करते रहेंगे।

गौरतलब है कि रविवार को कोलकाता में आयोजित रैली के बाद शाह ने नड्डा की मौजूदगी में बंगाल भाजपा नेतृत्व के साथ संगठन की बंद कमरे में बैठक ली। इसमें उन्होंने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव, जिसे सेमीफाइनल माना जा रहा है, उसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरतनी है।

रैली से निकाय चुनाव को लेकर शाह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस सांगठनिक बैठक में प्रदेश नेतृत्व को साफ कहा कि निकाय चुनाव में उम्मीदवार चुनने में किसी तरह की गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य के पार्टी सांसदों पर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चुनने से लेकर प्रचार की रणनीति बनाने तक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हावड़ा व कोलकाता नगर निगम समेत किसी नगर निकाय की जिम्मेदारी किन सांसदों की होगी, यह शाह खुद तय करेंगे।

न्यूज गैलरी

पूर्व भाजपा सांसद आरपी सरमा कांग्रेस में शामिल

गुवाहाटी : असम में भाजपा के पूर्व सांसद राम प्रसाद सरमा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लोकसभा में राज्य की तेजपुर सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके सरमा के अलावा वरिष्ठ पत्रकार जमशेर अली एवं अन्य भी रविवार को कांग्रेस में शामिल हुए है। गोरखा समुदाय से आने वाले सरमा 2014 के लोकसभा चुनाव में तेजपुर से विजयी हुए थे। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची में नाम शामिल नहीं होने के बाद 2019 में सरमा ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने दावा किया कि असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 126 में से कम से कम 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। असम कांग्रेस मुख्यालय में सरमा ने कहा, 'मेरा कोई धर्म नहीं है। मुझे जब भी अच्छा खाने की इच्छा होती है मैं कहीं भी खा सकता हूं।' (प्रेट्र)

सदन के बाहर सरकार से वादों का हिसाब मांगेंगे हुड्डा

चंडीगढ़ : हरियाणा के कांग्रेस विधायक मंगलवार को विधानसभा के बाहर भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार की घेराबंदी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विस तक विरोध मार्च निकालने का निर्णय लिया है। भाजपा-जजपा गठबंधन से उनके चुनावी वादों का हिसाब मांगते हुए कांग्रेस विधायक पहले ही विधानसभा के भीतर सरकार की घेराबंदी कर चुके हैं। पूर्व सीएम हुड्डा लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। (राब्यू)

अब पंजाब में मुख्यमंत्री भी आएंगे लोकपाल के दायरे में

फैसला ▶ सीएम के खिलाफ मुकदमे के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी

मंत्री, विधायक व सभी सरकारी मुलाजिमों पर चल सकेगा केस

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

विधानसभा चुनाव के दौरान नए और सशक्त लोकपाल का वादा कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सरकार ने शर्त के साथ पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर की अध्यक्षता में सोमवार को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में नए लोकपाल बिल को मंजूरी मिल गई। मुख्यमंत्री, मंत्री व विधायक इसके दायरे में होंगे, लेकिन उन पर तभी मुकदमा दर्ज कराया जा सकेगा, जब सदन इसे दो तिहाई बहुमत से पास कर देगा।

पंजाब कैबिनेट के इस फैसले से मौजूदा पंजाब लोकपाल एक्ट-1996 रद हो गया है। नया कानून मुख्यमंत्री, मंत्री, सभी सरकारी अधिकारियों पर लागू होगा। इससे राज्य सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त बेहतर प्रशासन मुहैया करवाने का उद्देश्य पूरा होगा। कैबिनेट की बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभागों में भ्रष्ट कर्मचारियों की पहचान करके उनकी छुट्टी करें। उन्होंने यह निर्देश कैबिनेट की बैठक में दिए। कैबिनेट ने 58 वर्ष के बाद दो साल की ऐच्छिक सेवा वृद्धि के नियम को खत्म करने पर भी मोहर लगा दी है। अब 58 वर्ष तक ही सरकारी मुलाजिम सेवाएं दे सकेंगे।

मुख्यमंत्री होंगे चयन समिति के अध्यक्ष

- चयन समिति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। इसमें विधानसभा के स्पीकर, विपक्ष के नेता, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और पंजाब सरकार से मनोनीत एक प्रख्यात कानूनी माहिर सदस्य होगा।
- लोकायुक्त वह होगा, जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज हो या रह चुका हो।
- सदस्यों की संख्या चार से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सरकार की तरफ से नियुक्त किए जाएंगे।
- लोकायुक्त के सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणी, अल्पसंख्यक या महिला जरूर होना चाहिए।
- लोकायुक्त के सदस्य प्रतिष्ठावान होने चाहिए, जिन पर कोई भी दोष न हो।
- चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के बहुमत के आधार पर राज्यपाल करेंगे।

ला कायुक्त के अधिकार

- लोकायुक्त के पास सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत सिविल कोर्ट के सभी अधिकार होंगे।
- वह झूठी शिकायत के मामले में भी मुकदमा चला सकेगा।
- विधानसभा की ओर से मुकदमा चलाने की आज्ञा दी जाती है या नहीं, इसके लिए लोकपाल पाबंद होगा।

कैसे करेगा काम

- नोटिस जारी करने से पहले सभी शिकायतों की पड़ताल लोकपाल की स्क्रीनिंग कमेटी करेगी।
- स्क्रीनिंग कमेटी इस बारे में सरकार की राय भी लेगी।
- लोकपाल मामले की जांच कर रहा है, तो यह कानून किसी भी अधिकारी व सार्वजनिक पद पर काम करने वालों के खिलाफ शिकायत के समानान्तर पड़ताल को रोक सकता है।

मरांडी के मुद्दे पर दूसरे दिन भी झारखंड विधानसभा में हंगामा

राज्य ब्यूरो, रांची

गतिरोध

- हंगामे और शोरगुल के बीच निपटाए गए विधायी कार्य
- पटल पर रखी गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग को लेकर भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। पहली पाली में दो बार सदन की कार्यवाही स्थगित की गई और शोरगुल के बीच ही जरूरी विधायी कार्य निपटाए गए। सरकार ने सदन के पटल पर 2019-20 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट रखी और राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र भी पेश किया। दूसरी पाली में हंगामे के बीच 1216 करोड़ का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित किया गया।

सोमवार सुबह 11.11 बजे स्पीकर रवींद्र नाथ महतो के आसन पर बैठते ही भाजपा के विधायक बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे और वेल में आ गए। स्पीकर के समझने के बावजूद भाजपा विधायक अपने स्थान पर नहीं गए। इस दौरान जयश्री राम के नारे भी लगे। स्पीकर ने भरोसा दिलाया कि न्याय होगा, लेकिन यह दबाव में नहीं होता। स्पीकर की अपील के बावजूद भाजपा विधायक अपनी सीट पर नहीं गए। इस दौरान बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह, नीलकंठ सिंह मुंडा और रामचंद्र चंद्रवंशी जैसे भाजपा के वरिष्ठ विधायक शांत भाव से अपनी सीट पर बैठे रहे। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 12.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

सत्ता पक्ष के विधायक भी वेल में आए : सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी रही। भाजपा विधायक एक बार फिर प्ले कार्ड लेकर वेल में उतर गए। मौके पर मौजूद मार्शल ने उनके हाथ से पोस्टर छीने।

पहले बनाएंगे पार्टी, बाद में बनेगा मोर्चा : चंद्रशेखर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने 15 मार्च को नई पार्टी का गठन करने और समान विचारों वाले दलों से मिलकर 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। सोमवार को लखनऊ के डाली बाग स्थित वीआइपी गेस्ट हाउस में चंद्रशेखर ने केंद्र व प्रदेश सरकारों पर निशाना साधा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर से बंद कमरे में मुलाकात भी की। चंद्रशेखर और राजभर में निकटता से बसपा में बेचैनी बढ़ी है।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओमप्रकाश राजभर से आधा घंटे चली मुलाकात पर चंद्रशेखर ने बताया कि दोनों में मित्रता के नाते मुलाकात हुई। इसको राजनीतिक गठबंधन में भी बदला जाएगा लेकिन भीम आर्मी अपनी राजनीतिक विंग का गठन (15 मार्च) कांशीराम जयंती के मौके पर करेगी।

सज्जन कुमार के खिलाफ मामले की जल्द सुनवाई से इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को शीर्ष कोर्ट ने राहत देने इन्कार कर दिया। कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे से संबंधित मामलों में सज्जन कुमार को 2018 में अग्रिम जमानत देने के खिलाफ विशेष जांच दल (एसआइटी) की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा, 'एसआइटी का शीघ्र सुनवाई का आवेदन खारिज किया जाता है।' पीठ ने याचिका खारिज करते हुए एसआइटी से सवाल किया कि 'क्या वह (सज्जन कुमार) जेल के अंदर हैं या नहीं।' पीठ उस मामले का जिक्र कर रही थी जिसमें कुमार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई और वह इस समय जेल में हैं। बता दें कि एसआइटी ने सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों से जुड़े दो मामलों में अग्रिम जमानत देने का निचली अदालत का 21 दिसंबर, 2016 का आदेश बरकरार रखने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के 22 फरवरी, 2018 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी।

क्या था मामला : सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों से संबंधित दो मामलों में हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये मामले एक और दो नवंबर, 1984 को दिल्ली छावनी के राजनगर पार्ट-1 इलाके में पांच सिखों की हत्या और राजनगर पार्ट-2 में एक गुरुद्वारा जलाने से संबंधित हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता ने हाई कोर्ट के पिछले साल 17 दिसंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

फिर नाराज हुए गुजरात सरकार में नंबर दो नितिन पटेल!

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल के एक बयान ने सियासी हलकों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सभी लोग एक तरफ हैं और वह दूसरी तरफ अकेले खड़े हैं। उधर, कांग्रेस को राज्य सरकार पर हमले का एक मौका मिल गया।

पाटीदार समाज की कुलदेवी मां उमिया के शिलान्यास समारोह के दौरान रविवार की रात उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल के बयान ने लोगों को अचंभित कर दिया। हालांकि, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से उनकी नाराजगी की चर्चा पहले भी कई मौकों पर होती रही है। लेकिन, कड़वा पाटीदार समुदाय के लोगों की बड़ी उपस्थिति के बीच उनके बयान ने सियासी

नितिन पटेल। फाइल

सरगर्मी पैदा कर दी। उन्होंने सिर्फ अकेले होने की बात ही नहीं की, बल्कि यह भी कहा, 'कई लोग मुझे नापसंद करते हैं। मुझे अकेला करने की कोशिशें होती रहती हैं, लेकिन मां उमिया के आशीर्वाद से यहां खड़ा हूं।'

नितिन पटेल ने कहा, 'कुछ लोग मुझे भुला देना चाहते हैं। लेकिन, याद रखें कि मैं किसी को नहीं भूलता।' वह किसे चेतावनी दे रहे थे यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह साफ हो गया है कि गुजरात सरकार में नंबर दो का रुतबा रखने वाले नितिन पटेल इन दिनों नाराज चल रहे हैं।

वर्ष 2017 में सरकार गठन के बाद नितिन पटेल को वित्त मंत्रालय नहीं दिया गया था। इससे नाराज नितिन पटेल तब तक अपने कार्यालय नहीं गए थे, जब तक उन्हें वित्त मंत्रालय का प्रभार नहीं मिल गया था।

मूलरूप से उत्तर गुजरात के कड़ी मेहसाणा निवासी नितिन पटेल की पाटीदार समुदाय में जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। संघ से भी उनकी करीबी है। अगस्त 2016 में तत्कालीन सीएम आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद नितिन पटेल को ही मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन विजय रूपाणी बाजी मार गए थे।

नितिन पटेल के बयान पर विधानसभा गलियारे में भी खूब चर्चा हुई। कांग्रेस विधायक ब्रजेश मिर्जा व बलदेवजी ठाकोर ने जहां इस बहाने राज्य सरकार पर निशाना साधा, वहीं निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने उन्हें 15-20 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ने का ऑफर तक दे डाला।

उधर, गुजरात भाजपा अध्यक्ष जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि नितिन पटेल के बयान का गलत अर्थ निकालकर कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा था कि समूचा विपक्ष एकजुट होकर जब आरोप-प्रत्यारोप करता है, तब वे अकेले ही भाजपा की ओर से जवाब देने में सक्षम होते हैं। कांग्रेस सत्ता में आने का सपना देख रही है।

शरद यादव की नई पार्टी पर जदयू नेता की याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जदयू नेता ने शरद यादव द्वारा नई पार्टी बनाए जाने के दावे को चुनौती दी है।

जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा, 'दलील सुनी गई। लिखित दलील तीन दिनों के भीतर सौंपी जाएगी।' शीर्ष अदालत ने वर्ष 2018 में रामचंद्र प्रसाद सिंह की याचिका पर सुनवाई करने का फैसला लिया था। उन्होंने यादव द्वारा नई पार्टी गठित करने के दावे को रिकार्ड पर लेने की मांग की थी। जदयू नेता ने दिल्ली हाई कोर्ट के 11 सितंबर 2018 के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

नोएडा-ग्रेनो में हजारों करोड़ के घोटाले की फाइलें गायब

जितेंद्र शर्मा, लखनऊ

- शासन स्तर पर ठिकाने लगा दी गईं सपा-बसपा काल में हुए खेल की पत्रावलियां
- ऑडिट के लिए सीएजी ने मांगे थे 45 अभिलेख और सौंपे मात्र तीन, अब शुरू हुई तलाश

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) और ग्रेटर नोएडा में हुए हजारों करोड़ रुपये के घोटाले ने शासन स्तर तक खलबली मचा दी है। उस दौर में प्रभावशाली पदों पर रहते हुए सरकारी धन की लूट मचाने वालों की जड़ें औद्योगिक विकास विभाग में इतनी गहरी हैं कि घोटाले की पत्रावलियां ही यहां से गायब करा दी गईं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने ऑडिट के लिए 45 अभिलेख मांगे थे, जिसमें से मात्र तीन ही उपलब्ध कराए गए हैं।

योगी सरकार नोएडा और ग्रेटर नोएडा का ऑडिट सीएजी से करा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में स्पष्ट कह चुके हैं कि 2007 से 2017 तक के नोएडा के ऑडिट में तीस हजार करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। वहीं, औद्योगिक विकास विभाग में सीएजी ने प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी है। जहां सीएजी को गड़बड़ियां मिली हैं, उनसे संबंधित दस्तावेज विभाग से मांगे हैं।

इसी जांच-पड़ताल में पर्दाफाश हुआ है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण और संपत्ति आवंटन से संबंधित फाइलें गायब कर दी गई हैं। अब खलबली मची है तो तलाश शुरू हुई है। गौरतलब है कि जिन दस सालों के कार्यों की ऑडिट हो रही है, उनमें 2007 से 2012 तक बसपा और 2012 से 2017 तक सपा की सरकार रही।

छुट्टी में खुलवाया सचिवालय, खंगाली फाइलें : 28 फरवरी को औद्योगिक विकास अनुभाग-3 के स्टाफ को इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया। इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ऑडिट टीम द्वारा 45 अभिलेखों की मांग की गई थी, जिसमें से मात्र तीन अभिलेख उपलब्ध कराए गए हैं। इस संबंध में उच्च स्तर पर हुई बैठक में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा ऑडिट में सहयोग नहीं दिए जाने की बात कही गई। साथ ही प्रमुख सचिव का हवाला देते हुए कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि पत्रावलियां 'ट्रेस' करने के लिए 29 फरवरी (शनिवार) को कार्यालय खोला जाएगा। कर्मचारियों ने बताया कि कार्यालय खोलकर शाम तक फाइलें खंगाली भी गईं।

कई आइएएस-पीसीएस अफसरों की गर्दन पर तलवार : माना जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण और संपत्ति आवंटन से जुड़े रहे उस वक्त के आइएएस और पीसीएस अधिकारियों की गर्दन इसमें फंस सकती है। शासन स्तर पर बैठे कर्मियों की संलिप्तता की भी आशंका है, जिसके चलते पत्रावलियां गायब कर दी गई हैं। हालांकि योगी सरकार इसे लेकर जल्द कुछ बड़ा फैसला कर सकती है।

> अभी फाइलें नहीं मिली हैं। फिर से रिव्यू करेंगे और फाइलें नहीं मिलती हैं तो जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
> -आलोक कुमार प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास

आरटीआइ में मिली जानकारी

मंत्रिमंडल में नौ सदस्य, 58 नेताओं को मिला है मंत्री पद का दर्जा, दर्जा प्राप्त मंत्रियों में आठ कैबिनेट स्तर के, बाकी 50 के पास स्तर है राज्य मंत्री का, मानदेय व भत्तों के रूप में दर्जा प्राप्त मंत्रियों को मिलते हैं 1.25 लाख रुपये प्रतिमाह

उत्तराखंड में विधायक 71 और मंत्री बन गए 67

विकास धूलिया, देहरादून

खबर का शीर्षक देख हैरान रह गए न आप कि यह कैसे मुमकिन है, लेकिन है यह सौ फीसद सच। उत्तराखंड में मंत्रियों का आंकड़ा 67 तक पहुंच गया है। अब यह बात दीगर है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत मंत्रिमंडल में महज नौ ही सदस्य हैं। शेष 58 वे भाजपा नेता हैं, जिन्हें सरकार ने अहम पदों पर मनोनीत कर मंत्री पद के दर्जे से नवाजा है। इनमें आठ कैबिनेट मंत्री के दर्जे के ओहदेदार हैं और बाकी 50 राज्य मंत्री स्तर के। दिलचस्प बात यह कि इन 58 में से कोई भी विधायक नहीं है। मंत्री पद का दर्जा हासिल प्रत्येक ओहदेदार को सरकार हर महीने 1.25 लाख रुपये की धनराशि मानदेय और भत्तों के रूप में दे रही है।

यूं तो उत्तराखंड विधानसभा का आकार 70 सदस्यीय है, लेकिन इनके अलावा एक विधायक एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि के रूप में

त्रिवेंद्र सिंह रावत फाइल फोटो

नामित किए गए हैं। यानी 70 निर्वाचित और एक नामित, कुल 71 सदस्य हैं उत्तराखंड विधानसभा में। संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक यहां मंत्रिमंडल में अधिकतम 12 सदस्य ही हो सकते हैं। फिलहाल मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के अलावा छह कैबिनेट और दो राज्य मंत्री शामिल हैं। मंत्रिमंडल के तीन स्थान रिक्त चल रहे हैं।

सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना में दर्जा प्राप्त मंत्रियों की संख्या की जानकारी मिली है। दरअसल, सत्ता में आने पर पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह के पद बांटती हैं। अलग-अलग विभागों के अंतर्गत गठित परिषदों, निगमों, आयोगों और समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। भाजपा सरकार ने ऐसे पदों पर नियुक्त किए अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्वधारी नाम दिया है। ज्यादातर में इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को मंत्री पद के दर्जे के साथ सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती है। कई समितियों, आयोगों, निगमों में मनोनीत सदस्यों को मंत्री पद का दर्जा तो नहीं मिलता, लेकिन मानदेय और भत्ते जरूर भरपूर मिलते हैं।मसलन, श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। इसी तर्ज पर गढवाल मंडल विकास निगम में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को राज्यमंत्री का दर्जा हासिल है, जबकि निदेशक मंडल के सात सदस्य भी दायित्वधारी हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष राज्यमंत्री के दर्जे के ओहदेदार हैं और चार सदस्य भी दायित्वधारी हैं। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष को कैबिनेट तथा उपाध्यक्ष को राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है, जबकि इनके अलावा सात सदस्य दायित्वधारी के रूप में मनोनीत हैं।

कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल नेताओं को हर महीने 45 हजार तो राज्य मंत्री के दर्जे वालों को 40 हजार रुपये मानदेय मिलता है। बगैर मंत्री पद के दर्जे के अन्य दायित्वधारियों का मानदेय 35 हजार रुपये है। वाहन किराए के रूप में हर महीने प्रत्येक दायित्वधारी को 60 हजार की धनराशि की अनुमति है। कार्यालय सह आवास भत्ते की धनराशि है 25 हजार रुपये महीना। यानी, कैबिनेट दर्जे वाले दायित्वधारी पर हर महीने 1.30 लाख तो राज्यमंत्री के दर्जे व गैर मंत्री के दर्जे के दायित्वधारी पर सरकार हर महीने 1.25 लाख की धनराशि खर्च करती है।

8,591 मामले 2019 में राजस्थान पुलिस ने अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज किए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार यह संख्या पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक है।

शाह की सभा के बाद बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले

हिंसा ▶ पार्टी ने तृणमूल पर लगाया आरोप, सत्तापक्ष ने किया खारिज

गृह मंत्री की सभा में नारेबाजी को लेकर तीन कार्यकर्ता किए गए गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

अदालत ने दो को पुलिस हिरासत में भेजा, तीसरे की जमानत मंजूर

शाह की रैली में जाते समय कथित रूप से 'देश के गद्दारों को, गोली मारो...' नारे लगाने वाले भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने ध्रुव बसु, पंकज प्रसाद और सुरेंद्र कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया। उन्हें सोमवार को बैंकशाल अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पंकज और सुरेंद्र को पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया, जबकि ध्रुव बसु की जमानत मंजूर कर ली।

सिर्फ नारेबाजी के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। यह सब तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की थी, न कि गोली चलाई थी।

-दिलीप घोष, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष

यह दिल्ली नहीं, बंगाल है। इस तरह की भड़काऊ नारेबाजी करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी।

-ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री व तृणमूल सुप्रीमो

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में रविवार को कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा के बाद 24 घंटे में ही बंगाल में चार जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं। इसमें कई कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। पार्टी कार्यालय पर भी हमला किया गया है। उधर, शाह की सभा में 'देश के गद्दारों को...' जैसे नारे लगाने के आरोप में कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस पर भाजपा ने जहां तीखी प्रतिक्रिया दी है, वहीं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि यह दिल्ली नहीं, बंगाल है। यहां भड़काऊ नारेबाजी करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी।

जानकारी के मुताबिक, पहली घटना सोमवार सुबह उत्तर 24 परगना जिले में हुई, जहां बदमाशों ने भाजपा की एक महिला नेता के घर पर गोली चलाई। अर्चना विश्वास के घर पर दो राउंड फायरिंग की गई। भाजपा का दावा है कि शाह की बैठक में वह शामिल हुईं थी, इसीलिए सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के उपद्रवियों ने उनके घर पर हमला किया। दूसरी ओर तृणमूल का कहना है कि यह भाजपा के अंदरूनी कलह का नतीजा है। इस मामले में पुलिस ने राजू विश्वास नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। उधर, शाह की सभा से लौट रहे भाजपा कार्यकताओं पर कोलकाता व हुगली में हमले हुए। भाजपा का आरोप है कि तृणमूल के उपद्रवियों ने ही ये हमला किए। इनमें दर्जनभर कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। इस मामले में भाजपा की ओर से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

वीरभूम में कार्यालय जलाया : वीरभूम के सुनबुनी गांव में रविवार देररात भाजपा के पार्टी कार्यालय को जला दिया गया। भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के उपद्रवियों ने ऐसा किया, क्योंकि गांव में उनकी संगठनात्मक शक्ति बढ़ने से तृणमूल भयभीत थी। हालांकि, तृणमूल की ओर से आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया।

भाजपा शासित निकाय में सीएए, एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित

औरंगाबाद, प्रेट्र : महाराष्ट्र के परभणी जिले में भाजपा शासित सेलू नगरपालिका परिषद ने सर्वसम्मति से नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। परिषद के चेयरमैन विनोद बोराडे ने सोमवार को कहा कि नगर परिषद में तीन मनोनीत सदस्य समेत 27 पार्षद हैं।

बोराडे ने कहा कि बिना किसी विरोध के 28 फरवरी को बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि भी इस कदम के समर्थन में हैं। चेयरमैन ने कहा कि दो दिनों पहले उन्होंने बैठक बुलाई थी। राकांपा, कांग्रेस और मुस्लिम समुदाय के सात पार्षदों ने मांग की थी इसलिए प्रस्ताव पारित किया गया। पिछले साल दिसंबर में संसद ने सीएए पर मुहर लगाई थी। नागरिकता संशोधन कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इस कानून के लागू होते ही देश के कई हिस्सों में इसका विरोध शुरू हो गया। केंद्र की भाजपा की अगुआई वाली सरकार के बार-बार दोहराए जाने के बाद कि इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है।

बांग्लादेश पर एनआरसी का असर नहीं होगा : शृंगला

- विदेश सचिव ने कहा, यह पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला
- बोले-रोहिंग्या शरणार्थियों की म्यांमार वापसी का आपसी सहयोग से होगा हल

ढाका, प्रेट्र : भारत ने बांग्लादेश को आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के नए प्रारूप से उनके यहां के लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि इसकी प्रक्रिया पूरी तरह से देश का आंतरिक मामला है। साथ ही विस्थापित रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश में शरण दिए जाने को लेकर भारत ने स्पष्ट किया है कि वह इस मुद्दे का आपसी सहयोग से समाधान चाहता है, ताकि म्यामांर के रखाइन राज्य के शरणार्थी अपने मूल स्थान को वापस लौट सकें व सम्मानपूर्वक जी सकें।

बांग्लादेश दौरे पर गए भारत के विदेश सचिव हर्ष वर्धन शृंगला ने सोमवार को कहा कि एनआरसी के नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने ढाका में हुए सेमिनार 'भारत-बांग्लादेश : एक सुरक्षित भविष्य' में कहा कि भारत बांग्लादेश को इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि बांग्लादेश और उसके लोगों पर एनआरसी का कोई असर नहीं पड़ेगा। विदेश सचिव शृंगला ने कहा कि मानवता के नाते वह बांग्लादेश के इस रुख का स्वागत करते हैं कि उसने करीब दस लाख विस्थापित लोगों को अपने यहां शरण देने की पेशकश की है।

उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश के इस रुख से सहानुभूति रखते हैं और उन पर आने वाले अतिरिक्त भार को समझते हैं। इसके लिए हम उन्हें पूरा समर्थन देते हुए इसका आपसी समाधान निकालने के इच्छुक हैं। ताकि जल्द से जल्द यह लोग अपने मूल स्थान म्यांमार के रखाइन राज्य में वापस जा सकें। यह सब सुरक्षित तरीके से और स्थाई तौर पर किया जाएगा। शृंगला ने बताया कि भारत ने पांच चरणों में राहत सामग्री बांग्लादेश के कॉक्स बाजार स्थित शरणार्थी शिविरों में पहुंचाई है। साथ ही और मदद देने को तत्पर है। कॉक्स बाजार वह क्षेत्र है जहां करीब दस लाख रोहिंग्या म्यांमार से भागने के बाद बांग्लादेश के शिविरों में रह रहे हैं। ध्यान रहे कि बांग्लादेश में 7.40 लाख रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं जो म्यांमार के रखाइन राज्य में सैन्य शासन के दमन के बाद भागकर अगस्त, 2017 में बांग्लादेश आ गए थे। ढाका में भारतीय उच्चायोग में कार्यरत रह चुके शृंगला इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री मोमेन से भी मुलाकात करेंगे। उल्लेखनीय है कि दिसंबर में नए नागरिकता विधेयक को लेकर बांग्लादेश विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन और गृह मंत्री असदुज्जमान खान ने अपने भारत दौरे रद कर दिए थे। बांग्लादेश ने असम में एनआरसी को लेकर भी खिन्नता जताई थी जबकि भारत यह स्पष्ट कर चुका था कि यह उसका आंतरिक मामला है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एनआरसी के मुद्दे को सितंबर में न्यूयार्क में द्विपक्षीय बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष उठाया था।

मेघालय में युवक को किया घायल, दुकानों में आगजनी

शिलांग, एजेंसियां : सीएए के खिलाफ मेघालय में शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। उपद्रवियों ने मावप्रेम इलाके में एक युवक को टूटी बोतल मारकर घायल कर दिया तो साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के फोटोक्रोह शहर में चार दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। करीब आधा दर्जन से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त कर डाले। शुक्रवार से जारी हिंसा में अब तक तीन लोग मारे जा चुके हैं, जबकि कई घायल बताए जाते हैं। आठ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक गैब्रिएल इंगराई ने बताया, 'रविवार की शाम एक 28 वर्षीय युवक को कांच की टूटी बोतल मारकर घायल कर दिया गया। ईस्ट खासी हिल्स जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजराने वाले वाहनों पर पथराव की भी सूचना है। हालांकि, स्थिति नियंत्रण में है और हिंसा प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल भेजा जा रहा है।' ईस्ट खासी हिल्स के जिलाधिकारी एमडब्ल्यू नोंगब्री ने बताया कि छात्रों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए सोमवार सुबह छह बजे से कर्फ्यू में ढील दी गई। हालांकि, परीक्षा की समाप्ति के बाद कर्फ्यू लागू कर दिया गया। खासी और जयंतिया हिल्स क्षेत्र के छह जिलों में मोबाइल इंटरनेट और मैसेजिंग सेवा पर लागू प्रतिबंध जारी है। अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर दुकानें, बैंक और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। सरकारी दफ्तरों में भी नाममात्र की उपस्थिति देखी जा रही है। उल्लेखनीय है कि खासी स्टूडेंट्स यूनियन (केएसयू) ने शुक्रवार को ईचामाटी में सीएए के विरोध में रैली का आयोजन किया था। इसके बाद ही राज्य में हिंसा भड़क गई थी।

पिस्तौलबाज दंगाई शाहरुख की तलाश में दौड़ी पुलिस

जागरण संवाददाता, बरेली

जानकारी जुटाने के लिए क्राइम ब्रांच व अन्य टीमें लगाई गई है। अभी तक शाहरुख के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिली है।

-रमेश भारतीय, एसपी क्राइम, बरेली

शाहरुख के बरेली में होने की आशंका पर पुलिस टीमों को अलर्ट किया गया। कुछ जगह टीमें लगी हुई हैं।

- शैलेश पांडेय, एसएसपी, बरेली

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपुर चौक में हिंसा के दौरान खुलेआम पिस्टल लहराने के आरोपित शाहरुख के बरेली जिले में छिपे होने की सूचना पर पुलिस ने कई क्षेत्रों में दबिश दी। हालांकि, उसके बारे में सुराग नहीं मिल सके। जानकारी जुटाने के लिए खुफिया टीमें भी लगाई गई हैं। शाहरुख का पिता साबिर ड्रग्स की तस्करी करता है। दिल्ली पुलिस का मानना है कि उसका उत्तर प्रदेश के रामपुर व बरेली में भी नेटवर्क है। आशंका जताई जा रही कि वह बरेली में कहीं छिपा हो सकता है।

सोमवार को दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित हुई तो एसपी क्राइम रमेश भारतीय ने क्राइम ब्रांच व थाना पुलिस की टीमों को जानकारी जुटाने के लिए लगाया। स्मैक तस्करी के बड़े अड्डे फतेहगंज पश्चिमी, उससे जुड़े गांव धंतिया में कई जगह सुराग तलाशे गए। मीरगंज और फरीदपुर में स्मैक तस्करी से जुड़े लोगों की सूचनाएं इकट्ठी की गईं। हालांकि सोमवार शाम तक शाहरुख के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका। साथ ही पुलिस टीमें बरेली शहर में उन लोगों के बारे में ब्योरा जुटा रहीं हैं, जो दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन करने गए थे।

हिंदू नाम रख फर्जी पासपोर्ट से विदेश जा रहीं दो रोहिंग्या महिलाएं गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- बैंकॉक जाने के दौरान कोलकाता एयरपोर्ट पर इमीग्रेशन विभाग ने दबोचा
- उनके फर्जी पासपोर्ट पर उत्तर 24 परगना जिले के सीमावर्ती क्षेत्र का पता दर्ज

दो रोहिंग्या महिलाओं को हिंदू नाम रखकर फर्जी पासपोर्ट के जरिये विदेश जाते समय कोलकाता के नेताजी सुभाषचंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इमीग्रेशन विभाग के अधिकारियों ने रविवार की आधी रात को बैंकॉक जाने वाले विमान में सवार होने से पहले उन्हें दबोच लिया।

रविवार की रात लगभग 12.50 बजे कोलकाता से बैंकॉक जाने वाली थाई एयरवेज की उड़ान की दो यात्रियों पर इमीग्रेशन विभाग को संदेह हुआ। उनके पासपोर्ट की जांच की गई तो पता चला कि एक का नाम रीना साहा और दूसरे का तान्या बिस्वास है। हालांकि, दस्तावेज की सावधानीपूर्वक जांच करने पर पता चला कि दोनों के पासपोर्ट फर्जी हैं। तान्या का असली नाम तस्लीमा है, जबकि रीना का नाम रुखसाना अख्तर है। दोनों म्यांमार के तंगसुरिया की निवासी हैं। उनसे पूछताछ करने के बाद इमीग्रेशन विभाग ने दोनों को पुलिस को सौंप दिया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों महिलाओं के पासपोर्ट पर उत्तर 24 परगना जिले का पता लिखा है। उन्होंने भारतीय पासपोर्ट कैसे बनवाया, किसने फर्जी पोस्टपोर्ट तैयार किया, क्या उनके साथ और भी रोहिंग्या हैं, इन सभी सवालों के जवाब के लिए दोनों से पूछताछ की गई। इसके अलावा यह भी पता किया जा रहा है कि कहीं इस मामले के तार किसी बड़े रैकेट से तो नहीं जुड़े हैं। सूत्रों के अनुसार, कुछ दिनों पहले बांग्लादेश से लगभग 30 रोहिंग्याओं का एक समूह देश में प्रवेश किया था। उनके उत्तर 24 परगना जिले में घोजाडांगा सीमा से प्रवेश करने की सूचना है। वहां घुसपैठिए विभिन्न दलालों के माध्यम से फर्जी पासपोर्ट की जुगाड़ कर लेते हैं। संदेह से बचने के लिए हिंदू नाम रख लेते हैं। उक्त दोनों महिलाओं की इंडोनेशिया जाने की योजना थी, क्योंकि उनमें से एक का पति वहां काम करता है, लेकिन खुफिया विभाग के लिए चिंता का विषय यह है कि अन्य 28 रोहिंग्या कहां हैं।

जिहादी भाषण देने वालों के खिलाफ आरोप पत्र दायर

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- लेक्चरार से आतंकी बने रफी के जनाजे में दिए थे देश विरोधी भाषण

कश्मीर विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य छोड़ आतंकी बनने वाले मोहम्मद रफी बट के जनाजे में जिहादी भाषण देने और आतंकवाद को सही ठहराने वाले मौलवी सहित दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने अदालत में सोमवार को आरोप पत्र दायर कर दिया। दोनों आरोपित प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी से संबंध रखते हैं।

कश्मीर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का लेक्चरार गांदरबल निवासी मोहम्मद रफी बट पांच मई 2018 को आतंकी बन गया था। वहीं, अगले ही दिन वह शोपियां में सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में दो अन्य आतंकियों के साथ मारा गया था। उसके जनाजे में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी संगठन के नेता बशीर अहमद लोन और तहरीक-ए-हुर्रियत कश्मीर के नेता मोहम्मद रफीक शाह ने कथित तौर पर जिहादी भाषण दिए थे। रफीक शाह भी जमात के पुराने नेताओं में से एक है। इन दोनों ने लोगों को अपने भाषण के जरिए भारत के खिलाफ भड़काने का प्रयास करते हुए कश्मीर में जिहाद का आह्वान किया था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बशीर अहमद लोन और मोहम्मद रफीक को पीएसए के तहत गिरफ्तार कर जांच शुरू की थी। इन दोनों के खिलाफ पुलिस ने गांदरबल में एक मामला दर्ज किया था। जांच में दोनों के खिलाफ सभी आरोप सही साबित हुए। पुलिस ने जांच में सभी आवश्यक तथ्य व सुबूत जमा करने के बाद ही जम्मू-कश्मीर प्रशासन से आगे की कार्रवाई के लिए आग्रह किया था।

मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को तीन घंटे की हिरासत में भेजा

जागरण संवाददाता, नैनीताल

- छात्रों को बढ़ी हुई फीस नहीं लौटाने पर सख्त हुआ हाई कोर्ट, कॉलेज निदेशक तलब
- बढ़ी फीस नहीं लौटाने पर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका की थी दायर

हाई कोर्ट ने आदेश का अनुपालन नहीं करने व विरोधाभासी बयान पर सख्त रुख अपनाते हुए देहरादून के हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल झा को हिरासत में भेज दिया गया। ऐसे में उन्हें करीब तीन घंटे न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। अब कोर्ट ने मंगलवार को कॉलेज के निदेशक को तलब किया है।

सरकार ने 14 अक्टूबर 2015 को आदेश जारी कर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की सालाना फीस 80 हजार से बढ़ाकर 2.15 लाख कर दी थी। नौ जुलाई 2018 को हाई कोर्ट ने कॉलेज के छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए फीस बढ़ोतरी के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कॉलेजों को छात्रों से वसूली गई बढ़ी फीस लौटाने का आदेश भी दिया।

इस पर मेडिकल कॉलेजों की एसोसिएशन ने एकलपीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी आदेश बरकरार रखते हुए विशेष अपील निरस्त कर दी। इसके बाद हाई कोर्ट ने कालेजों की विशेष अपील भी खारिज कर दी।

इस बीच फीस नहीं लौटाने पर मेडिकल कॉलेज के छात्र मनीष कुमार और 15 अन्य ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी। इस पर कोर्ट ने देहरादून के हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को व्यक्ति रूप से पेश होने का निर्देश दिया।

सोमवार को न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य अनिल झा पेश हुए। सुनवाई के दौरान विरोधाभासी बयान को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने प्रधानाचार्य को हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। सुबह साढ़े दस बजे से दोपहर करीब सवा एक बजे तक प्रधानाचार्य अनिल झा को हिरासत में रहना पड़ा। कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को कॉलेज के निदेशक को पेश होने के आदेश दिए है।

आर्थिक सहायता...

बीएसएफ के आइजी डीके उपाध्याय ने सोमवार को बीएसएफ के जवान मोहम्मद अनीस को 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। उत्तरी दिल्ली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में अनीस के घर को उपद्रवियों ने जला दिया था। प्रेट्र

'धरने में भेजते थे पति कहते थे खाना मिलेगा'

जागरण संवाददाता, अलीगढ़

धरने का सच

पुरानी चुंगी पर रोजाना धरने में शामिल हो रही बुजुर्ग महिला सरबरी को चिह्नित किया गया था। महिला के घर पहुंचे तो उसने पति शब्बीर के दबाव में धरने में जाने की बात कही। पति को नोटिस जारी किया गया है।

-अनिल समानिया, सीओ, तृतीय

अलीगढ़ में पुरानी चुंगी गेट के बाहर चल रहे धरने को हटवाने के बाद पुलिस ने सोमवार को उन इलाकों का दौरा किया, जहां से महिलाएं धरने में आ रही थीं। फिरदौस नगर में 65 वर्षीय सरबरी नाम की महिला ने धरने की पोल खोल दी। महिला ने पुलिस को बताया कि पति ही उसे खाने-पीने का लालच देकर धरने में भेजते थे। कहते थे, शाहजमाल में धरना चल रहा है, वहां जाओ। पति रोज जान खाते थे, इसलिए धरने पर जाती थी। महिला व पुलिस की बातचीत का वीडियो भी वायरल हुआ है।

23 दिसंबर को ऊपरकोट पर हुए बवाल के बाद से एएमयू के पुरानी चुंगी गेट पर छात्र व आसपास क्षेत्र की महिलाएं धरने पर बैठ गई थीं। शनिवार को जीवनगढ़ का धरना समाप्त कराने के बाद पुलिस ने पुरानी चुंगी गेट पर भी महिलाओं को समझाया, लेकिन वे नहीं हटीं। यहां धरने में एक बुजुर्ग महिला प्रतिदिन शामिल हो रही थी। पुलिस ने उसे चिह्नित किया। सोमवार सुबह पहले पुलिस ने पुरानी चुंगी गेट से धरना समाप्त कराया, फिर दोपहर एक बजे एसीएम द्वितीय रंजीत सिंह और सीओ तृतीय अनिल समानिया फिरदौस नगर स्थित बुजुर्ग महिला के घर पहुंचे। सीओ ने महिला के पति से पूछा कि आपकी पत्नी रोजाना धरने में शामिल हो जाती हैं। बुजुर्ग ने कहा कि साहब इतना समझाया, पर क्या करें। इसी बीच अंदर से भागती हुई बुजुर्ग महिला भी आ गई और पति की बात को काटते हुए बोली, 'तुमने कहा था कि धरने में जाओ।' सीओ से महिला ने कहा कि वह झूठ नहीं बोल रही हैं। इन्होंने (पति ने) ही कहा था कि शाहजमाल में धरना लग रहा है, चली जाओ। रोज जान खाते हैं। इस पर सीओ ने कहा कि अब मत जाना अम्मा, हाथ जोड़ रहे हैं। इसके बाद सीओ ने पति को नोटिस देने की बात कही।

कर्नाटक में पाकिस्तान समर्थक नारा लगाने वाला गिरफ्तार

मंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुर में मिनी विधानसभा के सामने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने कहा कि मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति सोमवार सुबह 10 बजे विधान सौध के सामने आया और उसने कई बार पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। इसके बाद वह गलियारे में चला गया और नारे लगाता रहा।

स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और कुछ ही मिनटों के भीतर यह वायरल हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा सचेत करने के बाद पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और उसे गिरफ्तार कर लिया। कुंडापुर के तहसीलदार ने भी पुलिस को लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने कहा कि तहसीलदार की शिकायत पर एफआइआर दर्ज की गई है और देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। पूछताछ में आरोपित के बयान में कोई तालमेल नहीं पाया गया। उडुपी के एएसपी कुमारचंद्रन ने कहा कि पुलिस आरोपित की मानसिक स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहेगी। एक बार चिकित्सकीय रिपोर्ट तैयार हो जाए, विस्तृत जांच की जाएगी। मानसिक रूप से अस्थिर इस व्यक्ति का इलाज चल रहा है। वह शिक्षक था और बीमारी के कारण आठ साल पहले उसकी नौकरी जा चुकी है। आरोपित के घरवालों का कहना है कि वह लगातार टीवी देखता रहता है और हो सकता है कि किसी समाचार से प्रभावित होकर उसने ऐसा किया हो।

दीवार पर 'फ्री कश्मीर' नारा लिखा मिला: कर्नाटक में दीवार पर 'फ्री कश्मीर' लिखे होने की घटना एक बार फिर सामने आई है। इस बार शिवाजीनगर इलाके में डिफेंस कॉलोनी की चहारदीवारी पर सोमवार को यह नारा लिखा पाया गया। पुलिस ने कहा कि रंग पोत कर नारे को मिटा दिया गया है। पुलिस उपायुक्त एसडी शरनप्पा ने कहा कि इस संबंध में एक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। दोषी जल्दी ही पकड़ा जाएगा।

हनी ट्रैप मामला

सोमवार को अलग-अलग याचिकाओं की हुई सुनवाई, कोर्ट ने कहा-बिना केस डायरी के चले आते हैं अधिकारी

हाई कोर्ट नाराज, कहा-केस की गंभीरता समझने को कोई तैयार नहीं

नईदुनिया, इंदौर

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि कोई भी मामले की गंभीरता को समझने को तैयार नहीं है। स्पष्ट आदेश के बावजूद विशेष जांच दल (एसआइटी) आयकर विभाग को मामले से जुड़े दस्तावेज नहीं सौंप रहा है। जांच अधिकारी बगैर केस डायरी कोर्ट में चले आते हैं। सीबीआइ का जवाब तो दूर उनकी तरफ से न वकील उपस्थित होते हैं, न अधिकारी। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर सीबीआइ के एसपी को उपस्थित रहने का आदेश दिया। कोर्ट अब इस मामले में 16 मार्च को सुनवाई करेगी। उसी दिन प्रकरण से जुड़े तमाम दस्तावेज बंद लिफाफे में कोर्ट में प्रस्तुत भी करने होंगे।

दरअसल, हाई कोर्ट में मामले की अलग-अलग याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई पहले एसआइटी को आदेश दिया था कि वह 10 दिन के भीतर मामले से जुड़े तमाम दस्तावेज आयकर विभाग को सौंपे। इसके बावजूद आयकर विभाग को दस्तावेज नहीं सौंपे गए। सोमवार को आयकर विभाग ने कोर्ट को बताया कि दस्तावेज अब भी पूरे नहीं मिले हैं।

कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और आदेश दिया कि अगली सुनवाई के पहले तमाम दस्तावेज नहीं सौंपे गए तो एसआइटी के प्रमुख को खुद कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि सीबीआइ की तरफ से कौन है। वहां उपस्थित एडवोकेट ने कोर्ट को बताया कि जो वकील साहब मामले में पैरवी कर रहे हैं, वे उपस्थित नहीं हैं। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आदेश दिया कि अगली सुनवाई पर सीबीआइ के एसपी खुद कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब दें।

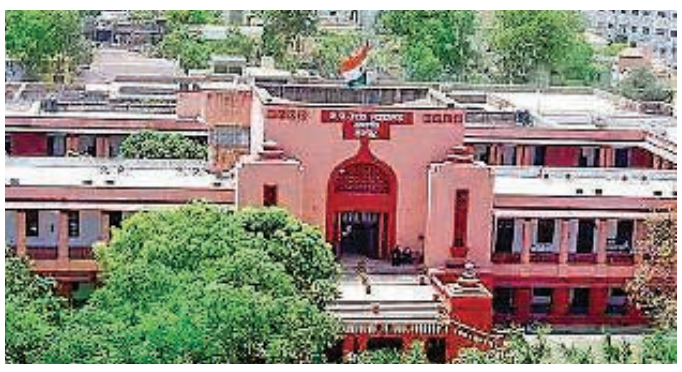

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ। (फाइल)

यह था मामला

इंदौर नगर निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसे कुछ महिलाएं रुपयों के लिए ब्लैकमेल कर रही हैं। पुलिस ने शिकायत के बाद गिरोह की सरगना श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन, बरखा सोनी, मोनिका सहित अन्य को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में जानकारी मिली थी कि आरोपितों ने रसूखदार लोगों के वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर मोटी रकम वसूली है। इसी मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है।

जांच अधिकारी से पूछा-किसके कहने पर आए : सुनवाई के दौरान आयकर विभाग के वकील ने कोर्ट को बताया कि एसआइटी ने चालान सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अब तक नहीं सौंपे हैं। इस पर कोर्ट ने वहां मौजूद जांच अधिकारी अवधेश गोस्वामी (आइपीएस) से पूछा कि क्या आप केस डायरी के साथ आए हैं। जैसे ही उन्होंने इन्कार किया कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि आप यहां किसके कहने पर आए हैं।

अगली सुनवाई पर केस डायरी और इस मामले से जुड़े तमाम दस्तावेज बंद लिफाफे में लेकर उपस्थित हों। कोर्ट ने यह भी कहा कि तीन दिन में मामले से जुड़े तमाम दस्तावेज आयकर विभाग को नहीं सौंपे गए तो एसआइटी प्रमुख को खुद उपस्थित होना पड़ेगा। अब शासन को अगली सुनवाई से पहले मामले से जुड़े तमाम दस्तावेज आयकर विभाग को सौंपने ही होंगे। साथ ही ये दस्तावेज बंद लिफाफे में कोर्ट में भी पेश करने होंगे।

न्यूज गैलरी

सेना ने अरुणाचल में फंसे 111 नागरिकों को बचाया

ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश में 29 फरवरी को सेना ने बड़ा मानवीय बचाव अभियान चलाया। इसमें सेना ने करीब 14 हजार फीट की ऊंचाई पर फंसे 111 स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया। अपने चिकित्सकीय कर्मचारी और रिकवरी वाहन के साथ सेना की दो टीमों ने एक मार्च की पूरी रात काम किया। फंसे हुए लोगों में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे। सेला दर्रे में भारी बर्फबारी के बाद अरुणाचल प्रदेश में तापमान शून्य के आसपास पहुंच गया। सभी लोग अपनी गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। संकट में फंसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को चाय, स्नैक्स और खाद्य सामग्री मुहैया कराई गई। स्थिति की निगरानी कर रहे मुख्यमंत्री कार्यालय ने सेना के इस प्रयास की सराहना की है। समय पर प्रभावी रूप से अभियान चलाकर सेना ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया। (एएनआइ)

पाक सेना ने गांवों में मोर्टार दागे, मकान क्षतिग्रस्त

पुंछ : सीमावर्ती जिले में पाकिस्तानी सेना कई महीनों से रुक-रुक कर गोलाबारी कर रही है। सोमवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे पाक सैनिकों ने जम्मू संभाग के पुंछ जिला की मेंढर तहसील में नियंत्रण रेखा पर बसूनी व डराना गांव में मोर्टार दागे। गोलाबारी से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। भारतीय सेना ने भी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। स्थानीयवासी मुहम्मद फारूक पुत्र वलायत हुसैन निवासी बसूनी ने बताया कि गोलाबारी के समय परिवार के सदस्य मकान में सोए हुए थे। तभी अचानक गोलाबारी से उनकी नींद टूट गई। हम जब तक कुछ समझ पाते हमारे घर की छत पर मोर्टार आ गिरा, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद महिलाएं और बच्चे चिल्लाने लगे। किसी तरह उन्हें संभाल कर नजदीक के घर में शरण ली। बाद में कई मोर्टार हमारे गांव में गिरे। फारूक ने बताया कि काफी समय से पाक सेना फायरिंग रेंज बढ़ाकर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। (जासं)

संदिग्ध परिस्थितियों में प्रतियोगी छात्र की मौत

प्रयागराज : सतना से आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले 22 वर्षीय छात्र विष्णु द्विवेदी की रविवार रात संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। कीडगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मझिगवां थाना क्षेत्र स्थित पिंडरा गांव निवासी सुरेंद्र द्विवेदी बिजली विभाग में तैनात हैं। उनके तीन बेटों में सबसे छोटा विष्णु कीडगंज थाना क्षेत्र के बैरहना मोहल्ले में दीपक कुमार के घर में किराए पर कमरा लेकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता था। कुछ दिन पहले शंकरगढ़ का अवनीश मिश्रा उसका रूम पार्टनर बनकर रहने लगा। पुलिस के मुताबिक, अवनीश ने बताया कि शनिवार शाम विष्णु अपने दोस्तों के साथ सिविल लाइंस में पार्टी करने गया था। (जासं)

लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के 11 दोषियों को ताउम्र जेल

फैसला ▶ वारदात के 92वें दिन दोषी करार, 97वें दिन सुनाई सजा

50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, पीड़िता को मिलेगा पैसा

जागरण संवाददाता, रांची

झारखंड की राजधानी रांची में लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। रांची सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने घटना को जघन्य मानते हुए कहा कि दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। उन पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगा है, जो पीड़िता को दिया जाएगा। जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बचाव पक्ष ने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की बात कही है। दोषियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया।

सोमवार दोपहर खचाखच भरी न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में करीब 15 मिनट की सुनवाई के बाद सजा सुना दी। इससे पूर्व बचाव पक्ष के वकील एनसी दास ने दोषियों की कम उम्र और कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने के आधार पर कम से कम सजा की मांग की। इस पर न्यायायुक्त ने पूछा, आप ही बताइए कितनी सजा मिलनी चाहिए...। जो कानून में लिखा है उसी अनुरूप सजा सुनाई जाएगी। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में रियायत का कोई विकल्प ही नहीं है। पीड़िता के अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने अदालत से कहा कि यह सामान्य घटना नहीं है। उम्र कोई मायने नहीं रखता है। दोषियों के लिए फांसी की सजा भी कम है।

दो घंटे तक पीड़िता ने जहन्नुम की यातना सही : अभियोजन ने बताया कि दो घंटे तक पीड़िता ने जहन्नुम की यातना सही। वह पूरी तरह दोषियों के कब्जे में थी और दोषी जो चाह रहे थे वही किया। सभी एक खिलौने की भांति पीड़िता पर टूट पड़े। मनमर्जी की। 25 साल की युवती जो कानून पढ़कर दूसरों की मदद करना चाहती थी उसका जीवन खाक कर दिया गया। पीड़िता को न्याय और समाज को संदेश देने के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए।

अदालत ने कहा, सोसाइटी को झकझोरने वाली घटना है : फैसले में अदालत ने कहा कि लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म समाज की चेतना को झकझोरने वाली घटना है। पीड़िता जिस वेदना, जिस मानसिक प्रताड़ना से गुजरी इसको बयां करना मुश्किल है। घटना पूरी मानवता के खिलाफ है। दोषियों ने खुद तो अपराध किया ही, दूसरों को भी अपराध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। एक भी दोषी रहम के हकदार नहीं हैं।

इन्हें मिली सजा : कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा एवं ऋषि उरांव। एक आरोपित नाबालिग निकला है, जिस पर अलग से मामला चलेगा।

निर्भया केस की दलील पर गरमा-गरमी

अभियोजन पक्ष ने घटना को दिल्ली के निर्भया केस से जोड़ा। दलील दी गई कि दोनों घटनाओं में काफी समानता है। अगर पीड़िता का दोस्त जान बचाकर नहीं भागता तो न तो वह बचता, न ही पीड़िता। दोषियों पर किसी प्रकार की रहम नहीं होनी चाहिए।

> घटना सोसाइटी को झकझोरने वाली है। पीड़िता ने जो यातनाएं सहीं, उसे बयां करना मुश्किल।
> **-अदालत की टिप्पणी**

> अभियोजन पक्ष और पुलिस इस तरह मिलकर काम करेगी तो आरोपित बच नहीं पाएंगे। अभियोजन पक्ष के बेहतर कार्य का ही नतीजा है कि इतनी जल्दी आरोपित को सजा दिलवाई जा सकी।
> **-कमल नयन चौबे, डीजीपी।**

चिन्मयानंद दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई से किया इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को लॉ की एक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दो याचिकाओं पर सुनवाई से इन्कार कर दिया। पहली याचिका आरोपित भाजपा नेता के खिलाफ दुष्कर्म के मामले को उत्तर प्रदेश से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने के संबंध में थी। दूसरी में पीड़ित पक्ष ने आरोपित चिन्मयानंद को जमानत मिलने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

जस्टिस आर. भानुमति और एएस बोपन्ना की खंडपीठ ने सोमवार को दिए अपने आदेश में कहा कि इन दोनों मामलों को किसी और खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध कराएं, जहां वह दोनों जज सदस्य न हों।

इससे पहले, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने खंडपीठ को बताया कि इन मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। इस पर खंडपीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इन दोनों मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से उपयुक्त आदेश ले लें।

विगत तीन फरवरी को हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद की जमानत मंजूर कर दी थी। उन पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अपने ट्रस्ट की ओर से चलाए जा रहे कालेज में लॉ की पढ़ाई कर रही एक छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। हाई कोर्ट ने चिन्मयानंद की जमानत मंजूर करते हुए कहा था कि दोनों पक्षों ने ही अपनी सीमाएं लांघी हैं। और अब इस समय यह तय करना मुश्किल है कि किसने किसका उत्पीड़न किया।

- **मामले के दिल्ली स्थानांतरण और जमानत को चुनौती पर सुनवाई से किया इन्कार**
- **जस्टिस भानुमती व बोपन्ना बोले-दोनों मामले किसी और खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध कराएं**

चिन्मयानंद फाइल

पिछले साल 20 सितंबर को चिन्मयानंद को पीड़ित छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में आइपीसी की धारा 376 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। जबकि पीड़ित छात्रा पर आरोप था कि उसने चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करके मोटी रकम वसूली है। और इसी आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। दिसंबर, 2019 में वह जमानत पर छूट गई थी।

10वीं के छात्र पढ़ेंगे जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का पाठ

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू-कश्मीर के विद्यार्थी अब अपनी किताबों में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 और जम्मू-कश्मीर के विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के बारे में भी पढ़ेंगे। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून और पूर्व जम्मू कश्मीर के आधुनिकीकरण के अध्याय जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (शिक्षा बोर्ड) के सोशल साइंस के विषय के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए हैं। साल 2020-21 के पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को नए चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। दसवीं कक्षा के सोशल साइंस के विषय में विद्यार्थियों का जम्मू-कश्मीर के विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ाने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून को शामिल किया गया है। इसमें विद्यार्थियों को उक्त कानून के विभिन्न प्रावधान पढ़ाए जाएंगे। यह चैप्टर सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक विज्ञान के हिस्से में शामिल होगा। सोशल साइंस के इतिहास के हिस्से में पूर्व जम्मू कश्मीर का आधुनिकीकरण, जम्मू-कश्मीर का आधुनिक रास्ते पर आगे बढ़ने, नया कश्मीर घोषणापत्र जैसे चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। बोर्ड ने पाठ्यक्रम में इन चैप्टर को लागू करते हुए पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया है। गौरतलब है कि पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की घोषणा कर दी गई थी।

निर्भया के दोषी पवन की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई मुहर

जागरण ब्यूरो, नयी दिल्ली

- **क्यूरेटिव याचिका खारिज, राष्ट्रपति के समक्ष दाखिल की दया याचिका**

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता की फांसी की सजा पर एक बार फिर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार को पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने क्यूरेटिव याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करने और फांसी पर रोक लगाने की मांग भी ठुकरा दी।

निर्भया के तीन दोषियों मुकेश, अक्षय और विनय की क्यूरेटिव याचिकाएं पहले ही सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं। सोमवार को पवन की भी क्यूरेटिव याचिका खारिज हो गई। अब पवन ने आखिरी उपाय के तहत राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाया है। उसने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल की है।

सोमवार को जस्टिस एनवी रमना, अरुण मिश्रा, आरएफ नरीमन, आर भानुमति और अशोक भूषण की पीठ ने पवन की क्यूरेटिव याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि उन्होंने याचिका और उससे संबंधित दस्तावेज देखे और मामले पर विचार करने के बाद पाया कि यह मामला क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई के लिए रूपा अशोक हुर्रा फैसले में तय मानकों में नहीं आता।

मालूम हो कि दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को पैरामेडिकल की छात्रा से चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। छात्रा से इस कदर दरिंदगी हुई थी कि बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से चारों दोषियों मुकेश, अक्षय, विनय और पवन को फांसी की सजा सुनाई गई है। हालांकि दोषी फांसी से बचने के लिए लगातार देरी के हथकंडे अपना रहे हैं और एक-एक कर याचिकाएं दाखिल करते हैं ताकि फांसी की तारीख आगे बढ़ जाए।

लंच के बाद सुनाया अदालत ने फैसला

प्रथम पृष्ठ से आगे

उनसे पूछा, हाई कोर्ट से मिला समय भी गुजर गया और अब जाकर क्यूरेटिव याचिका दायर की। इस दौरान कुछ देर के लिए सुनवाई रोक दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव याचिका पर विचार कर रहा था। कुछ देर बाद अदालत को सूचित किया गया कि याचिका खारिज हो गई है। इस पर अदालत ने अक्षय और पवन की अर्जी को खारिज करते हुए डेथ वारंट पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। जज ने कहा कि अगर अब इसे टाल दिया गया तो यह पीड़ित को न्याय के अधिकार का हनन करना होगा। इसके बाद एपी सिंह ने बताया कि पवन की तरफ से दया याचिका दायर कर दी गई है। लिहाजा अदालत को फैसले पर विचार करना चाहिए। इस पर जज ने अदालत को लंच के लिए स्थगित करते हुए निर्देश दिया कि दूसरे सत्र में विस्तृत जानकारी के साथ आएं। दूसरे सत्र में भी कुछ देर बहस हुई। लोक अभियोजक ने कहा कि अब इस अदालत के पास डेथ वारंट पर रोक लगाने की शक्ति नहीं है। हाई कोर्ट ही इस पर फैसला ले सकता है। इस पर एपी सिंह ने कहा कि दिल्ली जेल नियमावली के अनुसार एक अपराध के सभी दोषियों को एक साथ ही फांसी दी जा सकती है। तिहाड़ प्रशासन की तरफ से कहा गया कि दया याचिका दायर होने के बाद गेंद सरकार के पाले में है। अब जज की कोई भूमिका नहीं रह जाती।

जज ने वकील से कहा, आप आग से खेल रहे हैं : इस पर जज ने वकील से कहा कि आप आग से खेल रहे हैं, आपको सतर्क रहना चाहिए। किसी के एक गलत कदम का क्या दुष्परिणाम हो सकता है, यह आपको पता होना चाहिए। पहले सत्र में भी तीखी बहस हुई। जज ने एपी सिंह से कहा कि आपके पास इतना समय था, लेकिन क्यूरेटिव और दया याचिका दायर करने की बात अब क्यों कही जा रही है? अब आप अदालत से क्या चाहते हैं? क्या कानून का कोई प्रावधान बचा है? इस पर एपी सिंह ने कहा कि अभी विकल्प हैं।

जज ने कहा कि यह अदालत आपके लिए क्या कर सकती है? मुझे लगता है कि या तो आप मेरी सहायता नहीं करना चाहते या फिर आपके पास कोई जवाब नहीं है। इस पर एपी सिंह ने कहा कि मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि अदालत की मदद कर सकूं। अदालत जो आदेश देगी, उसे माना जाएगा, क्योंकि मैं अदालत से ऊपर नहीं हूं। इसके कुछ देर बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया। काफी देर तक इंतजार के बाद दोषियों को राहत देने वाला फैसला आया।

> दोषी पवन की दया याचिका विचाराधीन है। मौत की कगार पर खड़ा दोषी जब भगवान से मिले तो उसके मन में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए।
> **-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की टिप्पणी**

> हमारा सिस्टम अपराधियों की मदद कर रहा है। अदालत को अपना ही आदेश लागू कराने में इतना समय क्यों लग रहा है? बार-बार फांसी टलना हमारी कार्यप्रणाली की विफलता को दर्शाता है।
> **निर्भया की मां, कोर्ट के बाहर**

दोषियों के परिजनों ने मांगी दया : दोषी पवन गुप्ता, विनय शर्मा, अक्षय सिंह और मुकेश सिंह के परिजनों ने अदालत परिसर के बाहर बैनर लगाए और उनके लिए दया मांगी। काफी देर तक उनके परिजन परिसर के बाहर बैठे रहे और जब दूसरे सत्र की सुनवाई हुई तो फिर अदालत में चले गए।

जेल में रोक दिया गया ट्रायल : सुबह से शाम तक तिहाड़ जेल संख्या तीन में जिस तरह से फांसी को लेकर ट्रायल का दौर चला। शाम करीब पांच बजे कोर्ट द्वारा फांसी टालने की सूचना मिलते ही जल्लाद ने फांसी का ट्रायल रोक दिया। इसके बाद जल्लाद की मौजूदगी में ही डमी को एक कमरे व फंदों को बक्से में रख दिया गया। जल्लाद मंगलवार को अपने शहर के लिए रवाना हो जाएगा।

आजम, तजीन व अब्दुल्ला की जमानत अर्जी पर नहीं हो सकी सुनवाई

जागरण संवाददाता, रामपुर

बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में जेल गए सांसद आजम खां, उनकी पत्नी विधायक तजीन फात्मा और बेटे विधायक अब्दुल्ला की जमानत अर्जी पर सोमवार को वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत अब मंगलवार को सुनवाई करेगी। इसी मामले में तीनों ने 26 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर किया था, तब से तीनों जेल में हैं। रामपुर की गंज कोतवाली पुलिस ने चार जनवरी 2019 को तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए गए हैं। मामले में पुलिस ने सांसद सहित उनकी पत्नी विधायक और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तीनों के खिलाफ अप्रैल 2019 में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी।

चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने सुनवाई शुरू की, तब से तीनों कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। मुकदमे की सुनवाई कर रही एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को तीनों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किए थे। इसके बाद ही तीनों ने कोर्ट में सरेंडर किया था।

आजम खां फाइल

जेल शिफ्टिंग मामले में भी आज होगी सुनवाई

सांसद आजम, पत्नी तजीन फात्मा और बेटे को रामपुर से सीतापुर जेल में शिफ्ट किए जाने के मामले में भी कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। आजम के अधिवक्ता खलील उल्ला खां ने जेल शिफ्टिंग को लेकर आपत्ति दाखिल की थी, जिस पर बहस होगी। सुनवाई के दौरान तीनों भी कोर्ट में पेश हो सकते हैं।

आजम खां के बहनोई ने कहा सपा ने नहीं दिया साथ

जागरण संवाददाता, सीतापुर

- **कहा, अब सपा के बड़े नेताओं से नहीं मिलेंगे आजम खां**
- **एमएलसी ने दी सफाई, पार्टी हमेशा आजम के साथ**

जेल में बंद सांसद आजम खां से मिलकर आए उनके बहनोई जमीर अहमद ने सोमवार को समाजवादी पार्टी को कठघरे में खड़ा कर दिया। उनका आरोप है कि सपा ने आजम खां का साथ सही ढंग से नहीं दिया। उनका कहना है कि पहले दिन से उनके साथ ज्यादती हुई थी, तब पार्टी ने साथ नहीं दिया था। अब जब इतने मुकदमे हो गए, तब लोग आ रहे हैं। जमीर ने यह भी दावा किया कि आजम ने पार्टी के किसी भी बड़े नेता से मिलने इन्कार कर दिया है। उन्हें अपनों से भी शिकायत है।

सोमवार को आजम की बहन सबीहा खां और बहनोई जमीर ने उनसे मुलाकात की। आजम की साली तनवीर फात्मा भी मुलाकात के लिए जिला जेल पहुंचीं। मुलाकात के बाद उनकी बहन ने कुछ भी बोलने से इन्कार किया। लेकिन जमीर ने कहा कि उत्पीड़न का आलम यह है कि उन पर मुर्गी चोरी से लेकर जेब काटने तक का मुकदमा है। ये सब झूठे इल्जाम है। उन्होंने रामपुर के एसपी के ट्रांसफर पर भी सवाल उठाए हैं। जमीर के आरोपों का खंडन करते हुए सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने कहा, मैं तो उन्हें नहीं जानता, लेकिन सपा पहले दिन से आजम खां के साथ खड़ी है। विधानसभा में भी इसकी आवाज उठाई जा चुकी है। सीतापुर जेल में शिफ्टिंग के पहले दिन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की।

सीबीआइ ने कर्नाटक के भाजपा नेता की हत्या में छह को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने कर्नाटक के भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। धारवाड़ निवासी योगेश जिला पंचायत सदस्य थे।

अधिकारियों ने बताया कि योगेश की हत्या के मामले में दिनेश, सुनील, नूतन, अश्वथ, शाहनवाज और नजीर अहमद को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआइ ने पिछले साल सितंबर में इस मामले की जांच शुरू की थी। आरोपितों को सोमवार को विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पांच दिनों की सीबीआइ हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआइ के प्रवक्ता ने एक बयान में बताया, 'एजेंसी ने 20 नवंबर 2019 को एक आरोपित को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के बाद 29 फरवरी 2020 को छह आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं।' कर्नाटक पुलिस इस मामले में छह आरोपितों के खिलाफ नौ सितंबर 2016 को आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। योगेश सप्तपुरा में जिम का संचालन करते थे। वहीं 15 जून 2016 को उनकी हत्या कर दी गई थी।

उप्र में अपहृत छात्रा आरोपितों को चकमा देकर भागी निकली

नईदुनिया, ग्वालियर

- **एटा के व्यापारी की बेटी का अपहरण आरोपित फरार**
- **ग्वालियर में कार से भागी, पुलिस ने परिजनों को सौंपा**

उत्तर प्रदेश के एटा के एक व्यापारी की 17 वर्षीय बेटी को कार सवार युवकों ने पता पूछने के बहाने रोका और बेहोशी की दवा सुंघाकर अपहरण कर लिया। घटना रविवार रात 7.45 बजे एटा के विजय नगर इलाके में हुई। रात दो बजे ग्वालियर के पड़ाव रेलवे ओवरब्रिज पर छात्रा को होश आया तो उसने साहस और समझदारी से काम लिया और सीट पर लेटी रही। कुछ देर बाद जब बदमाशों ने कार रोकी और उतरे तभी छात्रा ने कार से उतरकर दौड़ लगा दी। बदमाश भी पीछे भागे, लेकिन छात्रा के शोर मचाने पर वह कार लेकर फरार हो गए। रात्रि गश्त कर रहे पड़ाव थाने के एसआइ बलवीर सिंह ने छात्रा को निगरानी में लिया। सोमवार सुबह स्वजन छात्रा को एटा ले गए।

एटा के कोतवाली थाना स्थित विजय नगर निवासी प्रेमचंद्र जैन सुपारी कारोबारी हैं। उनकी 17 वर्षीय बेटी रिया जैन कक्षा 12वीं की छात्रा है। रविवार रात 7.45 बजे वह घर से पास ही चाट मार्केट से मोमोज खरीदने निकली थी। वह घर से कुछ दूरी पर पहुंची थी तभी सुनसान रास्ते पर एक सफेद रंग की कार पास आकर रुकी। कार से उतरे एक युवक ने छात्रा से पता पूछा। छात्रा पता बताने लगी तभी उसने रूमाल निकालकर उसकी नाक पर रखकर कुछ सूंघाया। उसके बाद छात्रा बेहोश हो गई और उसे कुछ याद नहीं रहा। कुछ घंटों बाद जब उसको होश आया तो वह कार में थी। कार में चालक सहित चार युवक थे। दो आगे बैठे थे दो पीछे वाली सीट पर।

होश में आने दिखाई समझदारी-

छात्रा ने होश में आने के बाद समझदारी दिखाते हुए कोई हरकत नहीं की। वह लेटी रही। छात्रा को यह भी नहीं पता था कि वह कहां है। कुछ देर बाद एक पुल पर सुनसान इलाके में अपहर्ताओं ने कार को खड़ा किया। उन्हें लगा कि छात्रा बेहोश है। इस पर पीछे बैठे दोनों युवक भी बाथरूम करने उतर गए। तभी छात्रा ने बहादुरी का परिचय दिया और गाड़ी से उतरकर दौड़ लगा दी।

> उत्तर प्रदेश के एटा से अपहृत नाबालिग पड़ाव पुल पर बदमाशों को चकमा देकर भागी थी। बाद में पुलिस ने उसकी मदद करते हुए आरोपितों को भी तलाशा, लेकिन वह हाथ नहीं आए। नाबालिग को परिजन के सुपुर्द कर दिया है।
> **-नवनीत भसीन, एसपी ग्वालियर, मप्र**

गिरी, उठी फिर भागी, लेकिन नहीं हारी हिम्मत : कार से कूदने के बाद छात्रा जब पड़ाव ओवरब्रिज पर भाग रही थी तो अपहरणकर्ता उसका पीछा कर रहे थे। एक बार वह हड़बड़ाहट में गिरी भी, लेकिन उठकर फिर भागी। यहां भी भागते समय छात्रा ने शोर मचाते हुए समझदारी दिखाई।

राहगीर वकील ने की मदद : शोर होने पर वहां से गुजर रहे पुलिस लाइन निवासी वकील अमित भदौरिया ने छात्रा को देखा तो मदद करने रुक गए। यह देख पीछा कर रहे बदमाश वापस भाग गए। अमित ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। रात्रि गश्त पर निकले पड़ाव थाने के सब इंस्पेक्टर बलवीर सिंह मावई मौके पर पहुंचे। छात्रा को निगरानी में लिया। उनको ने पूरी घटना बताई। फिर उसके स्वजनों को पुलिस ने सूचना दी।

साथ गया पुलिसकर्मी : घटना की सूचना मिलते ही सोमवार सुबह छात्रा के स्वजन ग्वालियर पहुंचे और उसे अपनी सुपुर्दगी में लिया। पड़ाव थाना पुलिस ने भी एक एएसआइ स्वजनों के साथ एटा भेजा, ताकि रास्ते में उन्हें कोई परेशानी न हो। छात्रा ने बताया है बदमाशों की उम्र 25 से 30 साल के करीब थी।

संभावना

आतंकियों के वीपीएन के दुरुपयोग करने पर मोबाइल कंपनियों का फैसला, सुरक्षा एजेंसियों से लेकर पुलिस भी वीपीएन के तेजी से इस्तेमाल पर थी परेशान

कश्मीर में वीपीएन बंद, 4जी शुरू होने की उम्मीद

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) की सेवा बंद कर दी गई है। बीएसएनएल समेत इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों ने अपने सर्वर में वीपीएन को निष्क्रिय बनाने वाले अत्याधुनिक फायरवॉल स्थापित कर दिए हैं। इसके साथ ही घाटी में इंटरनेट ब्राडबैंड सेवा और 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा के जल्द बहाल होने की उम्मीद बढ़ी है।

पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की घोषणा के साथ ही प्रशासन ने पूरे जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। जम्मू में इंटरनेट ब्राडबैंड सेवा को अगले दो दिनों में ही सामान्य रूप से बहाल कर दिया था। कश्मीर में यह उपभोक्ताओं के लिए बंद है। सरकारी अनुमति से कुछ संस्थान इस सेवा का सशर्त लाभ ले रहे हैं। मोबाइल इंटरनेट सेवा को जनवरी 2020 में बहाल किया, लेकिन वह भी टू-जी इंटरनेट सेवा को।

प्रशासन ने वादी में वाट्सएस, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी सोशल साइटों और कुछ अन्य वेबसाइट को प्रतिबंधित करते हुए 480 वेबसाइट की श्वेत सूची जारी की। प्रशासनिक पाबंदियों के बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने मोबाइल फोन पर वीपीएन एप के जरिए सोशल मीडिया की प्रतिबंधित साइटों का इस्तेमाल कर रहे थे। आतंकियों और अलगाववादियों ने वीपीएन के जरिए फिर अपने नेटवर्क को सक्रिय करना शुरू कर दिया। आतंकी सरगना और उनका कैडर वीपीएन के जरिए ही संपर्क में थे। नगरोटा, कश्मीर के त्राल और अन्य जगहों पर मारे गए आतंकियों के पास जो फोन मिले उनसे भी इस तथ्य की पुष्टि हुई थी।

एजेंसियों ने कई बार किया आग्रह : सुरक्षा एजेंसियों को इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों से आग्रह करना पड़ा कि वह वीपीएन के इस्तेमाल को रोकें। पुलिस ने भी वीपीएन के जरिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पूरी वादी में कंपनियां वीपीएन को रोकने में समर्थ फायरवॉल स्थापित करने में कामयाब रही हैं।

एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि सुबह कुछ समय के लिए जब 4जी सेवा बहाल हुई तो लगा था कि प्रतिबंध हट गया है। अब तो वीपीएन काम नहीं कर रहा है। कश्मीर के एक प्रतिष्ठित होटल व्यावसायी ने कहा कि मैंने मोबाइल फोन पर चार वीपीएन इंस्टाल किए थे, अब एक भी नहीं चल रहा है। यह सब बंद कर दिए गए हैं।

प्रतीकात्मक

हालात का आकलन होगा

राज्य गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मोबाइल इंटरनेट सेवा की बहाली की अनुमति चार मार्च तक है। इसे हालात के आकलन के बाद बढ़ाया जा सकता है। सुनने में आया है कि वीपीएन पूरी तरह बंद हो गए हैं। उम्मीद है कि ब्राडबैंड इंटरनेट और 4 जी मोबाइल इंटरनेट सेवा जल्द ही बहाल होगी।

कोरोना वायरस से निपटने को कितने तैयार हैं हम!

चीन के साथ दुनिया के दूसरे हिस्सों तक कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अभी तक भारत में कोरोना वायरस के ज्यादा मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के सामने खतरा मंडरा रहा है। इसे लेकर भी सवाल हैं कि क्या भारत की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं इससे मुकाबले करने के लिए पर्याप्त हैं।

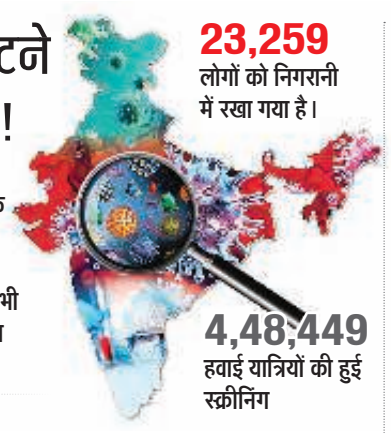

23,259 लोगों को निगरानी में रखा गया है।

4,48,449 हवाई यात्रियों की हुई स्क्रीनिंग

शुरुआत में नहीं था उल्लेख

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जैविक और स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने के लिए नोडल मंत्रालय है। आपदा प्रबंधन एजेंसियों, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के अंतर्गत भी ऐसे मामले आते हैं। भारत में लंबे समय तक आपदा प्रबंधन के लिए कोई निश्चित रास्ता नहीं था और यह अनौपचारिक रूप से राज्य का विषय बना रहा। 1943 के बंगाल अकाल के बाद यह माना गया कि भारत में खाद्य से संबंधित आपदा ही आ सकती है। संविधान में राज्य या केंद्र के विषयों में आपदा प्रबंधन का कोई उल्लेख नहीं था।

तैयार हुआ तंत्र

आजादी के बाद कई बड़ी आपदाएं आई लेकिन आजादी के करीब पचास साल बाद 2001 में गुजरात के भुज में आए भीषण भूकंप के बाद 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की स्थापना के बाद ही आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल और नीतियों को विकसित किया जा सका। कोरोना वायरस का प्रकोप एक प्रकार की जैविक आपदा है। यह केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजी एंड न्यूक्लियर (सीबीआरएन) डिफेंस का हिस्सा होगा। अतिरिक्त सहायता के लिए राज्य या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एनडीआरएफ) और यहां तक की सैन्य बलों से आग्रह किया जा सकता है।

धीमी शुरुआत के बाद रफ्तार

अन्य देशों की तुलना में भारत की शुरुआती प्रतिक्रिया धीमी थी। वुहान में जनवरी की शुरुआत में ही कोरोना वायरस के लक्षण नजर आने लगे थे। यूरोपीय देशों, सिंगापुर, जापान और अमेरिका ने लगभग उसी समय चीन से लौटने वालों को अलग करना शुरू कर दिया। वहीं भारत में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) ने महज सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नजर रखी। हालांकि जनवरी के अंत तक भारतीय स्वास्थ्य तंत्र हरकत में आया। 30 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर मंत्रियों का समूह गठित किया गया और 3 फरवरी को पहली बैठक हुई।

उठाए गए यह कदम

मंत्री समूह की पहली बैठक में रिस्क एडवाइजरी जारी करने, यात्रियों की स्क्रीनिंग कराने, प्रयोगशाला जांच और अलग से रखने की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ। स्क्रीनिंग के लिए 21 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और 12 प्रमुख बंदरगाहों पर व्यवस्था की गई। 2014 में इबोला के प्रकोप के बाद इन प्रवेश मार्गों पर कर्मचारियों को संभावित संक्रमणों की जांच के लिए प्रशिक्षित किया गया था।

तंत्र की ताकत

संदिग्ध मार्गों से आने वाले यात्रियों की जांच की गई। करीब 4,214 उड़ानों और 4,48,449 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है। वहीं 23,259 लोगों को सामुदायिक निगरानी में रखा गया है। सभी राज्यों को रैपिड रेस्पोंस टीम और सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों को चिह्नित किया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दुनिया की 15 वैश्विक प्रयोगशालाओं में पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वाइरोलॉजी (एनआइवी) को भी संदर्भ परीक्षण के लिए चिह्नित किया गया है। इसे भी अलर्ट पर रखा गया है। एनआइवी आवश्यकता पड़ने पर देश की 105 प्रयोगशालाओं की मदद ले सकता है।

वुहान से निकाला

वुहान से 600 से ज्यादा लोगों को जनवरी 30 और 1 फरवरी को निकाला गया जिन्हें 19 फरवरी को कोरोना वायरस के परीक्षण के नकारात्मक आने के बाद छोड़ा गया।

एजेंसियों की तैयारी

सभी राज्यों में रोग निगरानी कार्यक्रम है जो कि एनसीएमसी और एनडीएमए को दैनिक रिपोर्ट भेजता है। इसके जरिए आवश्यता होने पर राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय परिप्रेक्ष्य में संकट की गंभीरता को परखा जाता है। जब सभी सामुदायिक संसाधन समाप्त हो जाते हैं तभी एनडीआरएफ से सहायता का अनुरोध किया जाता है, जैसा 2018 में निपाह के प्रकोप के समय हुआ था। इसके बाद में सेना को भी बुलाया जा सकता है।

राम मंदिर के समानांतर विकसित होगी अयोध्या

तैयारी ▶ 2023 तक विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस होगी राम नगरी

जागरण संवाददाता, अयोध्या

राम जन्मभूमि मंदिर पर निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही रामनगरी को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करने का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। विश्वस्तरीय सड़कें, सीवर, शौचालय, धर्मशाला, प्रवेश द्वारों पर रामायण कालीन दृश्यों का अंकन नगर की गरिमा को भव्य बनाएगा। मंदिर के साथ ही अयोध्या को भी विकसित करने का खाका तैयार किया जा रहा है। 2023 तक अलौकिक अयोध्या फलक पर होगी। अपने हिस्से का कार्य नगर निगम ने शुरू भी कर दिया है।

विकास के 10 बिंदु : स्मार्ट अयोध्या को 10 बिंदुओं पर विकसित किया जाएगा। इनमें राम नगरी का सुंदरीकरण, सार्वजनिक परिवहन, नगर के प्रवेश स्थलों का सुंदरीकरण, वाई फाई युक्त पार्क, फूड हब, लेजर शो, हेरिटेज वॉक व सिटी वॉक सहित दस प्वाइंट हैं। राम नगरी को स्मार्ट बनाने के लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिसमें नगर निगम को प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपये मिलेंगे।

मंदिर निर्माण के बाद भी चलती रहेगी नक्काशी : रामजन्मभूमि पर प्रस्तावित मॉडल के अनुरूप दो तिहाई शिलाओं की तराशी तो पूरी की जा चुकी है, पर कुछ बारीक नक्काशी यथास्थान मंदिर निर्माण के बाद भी होती रहेगी। विहिप के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्रस्ट में भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्र को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त होने और तराशी गई शिलाओं को गंतव्य तक पहुंचाए जाने की प्रकिया में नुकसान पहुंचने की आशंका से कुछ बारीक नक्काशी नहीं की गई है और यह नक्काशी तब की जाएगी, जब तराशे गए पत्थर यथास्थान शिफ्ट हो जाएंगे। इनमें सर्वाधिक अहम यक्ष-यक्षिणियों की वे मूर्तियां हैं, जो प्रस्तावित मंदिर के स्तंभों पर उत्कीर्ण की गई हैं। प्रस्तावित मंदिर में 212 स्तंभ लगने हैं। 106 भूतल पर और इतने ही प्रथम तल पर। प्रथम तल के स्तंभ 16 फीट छह इंच ऊंचे और दूसरे तल के स्तंभ 15 फीट तीन इंच ऊंचे हैं। तीन फीट व्यास वाले सभी 212 स्तंभों में यक्ष-यक्षिणियों की 16-16 मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। इन पर हुई नक्काशी इतनी बारीक है कि जरा सी चूक वर्षों के श्रम और भव्यता के पर्याय स्तंभों की सुंदरता-शास्त्रीयता पर सवाल खड़ा कर सकती है।

1989 में शिलापूजन का कार्यक्रम देश के पौने तीन लाख गांवों आयोजित हुआ था और शिलापूजन के बाद ही मंदिर आंदोलन का ज्वार शिखर की ओर उठने लगा था।

अयोध्या में राम मंदिर के प्रत्येक स्तंभ पर ऐसी 16 मूर्तियां उत्कीर्ण की जानी हैं। जीतू निषाद

इस प्रारूप पर विकसित होगी स्मार्ट राम नगरी

- अयोध्या शहर में स्मार्ट रोड और रामलला दर्शन मार्ग पर स्मार्ट स्ट्रीट
- हैरिटेज वॉक और सिटी वॉक
- 12 प्रमुख चौराहों का सुंदरीकरण
- कुंडों का सुंदरीकरण
- अयोध्या शहर के एंट्री प्वाइंटों का सुंदरीकरण
- सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन
- अयोध्या शहर के प्रमुख स्थानों पर स्मार्ट टॉयलेट
- धार्मिक कार्यों के प्रचार-प्रसार के लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर डिजिटल स्क्रीन
- साकेत पेट्रोल पंप से नयाघाट की ओर आधुनिक/हैरिटेज लुक देते हुए वेंडिंग जोन की स्थापना

केंद्र व राज्य सरकार का पूरा फोकस अयोध्या के विकास पर है। गरिमा व मर्यादा के अनुरूप राम नगरी को विकसित किया जाएगा।

-ऋषिकेश उपाध्याय, महापौर अयोध्या

चंपत राय ने कहा, एलएंडटी ही बनाएगी राम मंदिर

रमाशरण अवस्थी, अयोध्या

राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ही करेगी। यह जानकारी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव व विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने दी। 24 घंटे के भीतर ही दिल्ली से अयोध्या लौटे राय ने कारसेवकपुरम में 'जागरण' से विशेष बातचीत में यह जानकारी दी।

उन्होंने ट्रस्ट का स्थानीय कार्यालय व वैकल्पिक गर्भगृह में रामलला की शिफ्टिंग को फिलहाल प्राथमिकता बताया। संकेत दिया कि ट्रस्ट की अगली बैठक रामलला की शिफ्टिंग के बाद अप्रैल माह में हो सकती है। राय ने बताया कि एलएंडटी ने लगभग 10 वर्ष पहले राममंदिर निर्माण का कार्य सेवाभाव से करने की मंशा विहिप के तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष अशोक सिंहल से जताई थी। इधर, मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कंपनी ने अपने इस संकल्प को फिर दोहराया।

कंपनी तकनीकी दक्षता व संयंत्र आदि के मामले में भी बेजोड़ है। ऐसे में उसे मंदिर निर्माण के लिहाज से सर्वाधिक उपयुक्त माना जा रहा है। 29 फरवरी को हुए निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के दौरे में भी कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण समिति समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद ही इस संबंध में निर्णय लेगी।

दिल्ली से शीघ्र वापसी के प्रश्न पर ट्रस्ट महासचिव ने कहा कि अब हमें देश को यथाशीघ्र मंदिर निर्माण होते हुए दिखाना है, इसलिए तैयारियों को युद्धस्तर पर अंजाम देना होगा। राय ने बताया कि ट्रस्ट के स्थानीय कार्यालय का चयन हो गया है, जिससे जुड़ी औपचारिकताएं पूर्ण की जानी हैं। उन्होंने बताया कि गर्भगृह की भूमि की मिट्टी की जांच के लिए नमूने लिए जाने का काम भी शीघ्र शुरू होगा। इस प्रक्रिया में दो दिन और रिपोर्ट आने में लगभग एक महीने का समय लगेगा। यह कार्य आइआइटी रुड़की की सिविल इंजीनियरिंग शाखा करेगी।

- वैकल्पिक गर्भगृह में शिफ्टिंग के बाद अप्रैल में होगी ट्रस्ट की अगली बैठक
- आइआइटी रुड़की के विशेषज्ञ करेंगे मिट्टी की जांच

चंपत राय फाइल

इटली और ईरान समेत 12 देशों से आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- देश में इस वायरस के फैलने को रोकने के लिए बढ़ाई गई सतर्कता
- 21 एयरपोर्ट, 12 बड़े व 65 छोटे बंदरगाहों पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था

एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए का कहना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए इटली और ईरान समेत दस देशों से आने वाले सभी यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से अनिवार्य रूप से गुजरना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश में इस वायरस के फैलने को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाई गई है।

उन्होंने सोमवार को कहा कि अब चीन, सिंगापुर, थाइलैंड, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, नेपाल, इंडोनेशिया, ईरान और इटली से आने वाले सभी यात्रियों की एयरपोर्ट, बंदरगाह और चेकपोस्ट पर अनिवार्य स्क्रीनिंग की जा रही है। देश में कुल 21 एयरपोर्ट, 12 बड़े व 65 छोटे बंदरगाहों के साथ-साथ नेपाल सीमा पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों अनुसार अभी तक एयरपोर्ट पर 5,57,431 और बंदरगाहों पर 12,431 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। नेपाल की सीमा से भारत आने वाले 10,24,922 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। सीमा पर 3,695 ग्राम सभाओं के माध्यम से लोगों को वायरस के प्रति सचेत किया जा रहा है। कुल 3,222 सैंपल को कोरोना वायरस की जांच के लिए भेजा गया, जिनमें 3,217 सैंपल निगेटिव पाए गए।

सिंगापुर, द. कोरिया, ईरान और इटली जाने से बचें

सोमवार को कोरोना वायरस पर मंत्रिमंडलीय समूह की बैठक की जानकारी देते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि इससे निपटने के लिए दवाइयों व अन्य सामान की पर्याप्त मात्रा देश में उपलब्ध है और सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे यदि जरूरी नहीं हो तो सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ईरान और इटली जाने से बचें। 10 फरवरी के बाद इटली, दक्षिण कोरिया और ईरान की यात्रा करने वालों को भारत आने के बाद 14 दिनों तक अलग-थलग रखने की व्यवस्था की जा रही है। ताकि उनमें कोरोना वायरस होने की आशंका को पूरी तरह खत्म किया जा सके। पूरे देश में 25,738 लोगों को विशेष निगरानी में रखा गया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 19 नए टेस्टिंग लैब की सुविधा चालू करने का फैसला किया गया।

राम मंदिर निर्माण के साथ देश होगा राममय

जागरण संवाददाता, अयोध्या

राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की तैयारियों के साथ देश को राममय बनाने की कोशिश चल रही है। इसके पीछे विहिप है और यह कोशिश राम महोत्सव के रूप में बयां होगी। राम महोत्सव चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी 25 मार्च से चैत्र पूर्णिमा यानी आठ अप्रैल तक संयोजित है। राम महोत्सव कार्यक्रम के तहत विहिप गांव-गांव में भगवान राम का पूजन करेगी। मंदिर निर्माण शुरू होने की खुशी मनाएगी और मंदिर निर्माण की मुहिम के लिए शक्ति, समर्थन और समर्पण हासिल करेगी। आठ अप्रैल को राम महोत्सव का तो समापन हो जाएगा, पर इस महोत्सव के माध्यम से जिन केंद्रों पर भगवान राम का पूजन किया जाएगा, वे अक्षुण्ण रहेंगे। विहिप प्रवक्ता शरद शर्मा कहते हैं कि भगवान राम आस्था के केंद्र तो हैं ही, देश की एकता-अखंडता और उत्कर्ष के पर्याय भी हैं। ऐसे में गांव-गांव में उनसे जुड़ी आस्था के केंद्र राष्ट्रवाद की चेतना को भी धार देंगे।

शिला पूजन की तर्ज पर हो रही तैयारी : राम महोत्सव के लिए विहिप व्यापक तैयारी कर रही है। मंदिर निर्माण शुरू होने की प्रेरक बेला में वातावरण भी उसके अनुकूल है और मंदिर आंदोलन की भावभूमि पुख्ता करने वाले शिलापूजन कार्यक्रम का प्रेरक दृष्टांत भी है। विहिप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री बगैर लाग-लपेट के स्पष्ट करते हैं, रामजन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण से पूर्व देश में रामशिला पूजन की भांति श्रीराम महोत्सव मनाया जाएगा।

राम नगरी में भी है 27 तीर्थों का जल

नवनीत श्रीवास्तव, अयोध्या

यहां राम जन्मभूमि के पार्श्व में प्रवाहित उत्तरावाहिनी मां सरयू हैं। आग्नेय कोण पर हनुमानजी विराजमान हैं। इन सबके बीच राम मंदिर के शिलान्यास में देश की सभी पवित्र नदियों व समुद्र का जल लाने की योजना भी बन रही है। कम ही लोगों को मालूम होगा कि राम नगरी अयोध्या में ही 27 तीर्थों का जल है। सप्तपुरियों में अग्रणी अयोध्या के निकट ही भरत की तपोभूमि भरतकुंड है। भगवान राम के वनवास के दौरान भरतजी ने राज सिंहासन पर उनकी चरण पादुका रखकर यहीं 14 वर्ष तक तप किया था। यहीं वह कूप है, जिसमें 27 तीर्थों का जल है। खास बात यह है कि भरत कूप आज भी जस का तस विद्यमान है और इसमें पानी भी है, जिसे भरतकुंड आने वाले श्रद्धालु श्रद्धावनत भाव से शिरोधार्य करते हैं। वनवास के बाद जब भरतजी भगवान राम को मनाने के लिए चित्रकूट गए थे, तो अपने साथ 27 तीर्थों का जल भी लेकर गए थे। जब भरतजी भगवान की चरण पादुका लेकर वापस आने लगे तो 27 तीर्थों का आधा जल चित्रकूट के एक कूप में स्थापित किया और आधा भरतकुंड स्थित कूप में। त्रेताकाल से लेकर अब तक नंदीग्राम में यह कूप विद्यमान है। इसी स्थान पर भगवान राम व हनुमानजी से भरत के मिलाप का मंदिर भी है। साथ ही भरत तपस्थली भी। भरतकुंड स्थित रामजानकी मंदिर के व्यवस्थापक रामभूषणदास कृपालु बताते हैं कि भरत जी इसी जल से पूजन व जलपान करते थे। नंदीग्राम आने वाले श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से इस कूप के जल का सेवन करते हैं। अयोध्या में ही सात सागरों का जल भी है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब वनवास से लौटे तो उनके राज्याभिषेक के लिए सात सागरों का जल भी लाया गया था। छोटी देवकाली के पार्श्व में एक कुंड में सात सागरों के जल को स्थापित किया गया था, हालांकि अब इस सप्तसागर कुंड का वजूद लगभग समाप्त है।

अयोध्या में स्थित भरतकूप। जागरण

मणिपुर के आतंकी संगठन का मुखिया साथी समेत गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मणिपुर के प्रतिबंधित आतंकी संगठन कंगलिपक कम्युनिस्ट पार्टी-पीपुल्स वार ग्रुप (केसीपी-पीडब्लूजी) के चेयरमैन लाइशराम मंगोलजाओ सिंह उर्फ लामिंबा खुमान और उसके साथी हिजबुर रहमान उर्फ इत्तेमा लोचन को गिरफ्तार किया है। दोनों राजधानी में ठिकाना बनाने के लिए जगह की तलाश में आए थे। इनके खिलाफ मणिपुर में हत्या, गोलीबारी, बम फेंकने और फिरौती मांगने के पांच मुकदमे दर्ज हैं। लाइशराम मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को जान से मारने की धमकी देने के मामले में भी आरोपित है। उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित है। हालिया हिंसा में इनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है।

स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव कुमार यादव ने बताया कि मणिपुर पुलिस ने इस संबंध में सूचना दी थी। एक मार्च को पता चला कि लाइशराम मंगोलजाओ सिंह और हिजबुर रहमान बुराड़ी इलाके में आने वाले हैं। पुलिस टीम ने बुराड़ी स्थित निरंकारी सत्संग मैदान के समीप से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से आतंकी संगठन केसीपी का लेटरहेड और मोबाइल बरामद हुए।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीपुल्स वार ग्रुप (केसीपी) का गठन लाइशराम रंजीत मीतेई द्वारा कई चरमपंथी समूहों को मिलाकर किया गया था।

उप्र सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, 49 हजार 568 सफल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- योगी सरकार में अब तक हो चुकी है एक लाख 37 हजार 253 पदों पर भर्ती

उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में सोमवार का दिन बेहद खास रहा और युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया। उप्र पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने 49568 पदों पर सिपाही भर्ती का परिणाम घोषित किया है, जो अब तक की सबसे बड़ी सिपाही भर्ती है। पुरुष अभ्यर्थियों में गाजीपुर निवासी गुलशन कुमार व महिला अभ्यर्थियों में हरदोई की अंतिमा सिंह सर्वाधिक अंक हासिल कर अव्वल रहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देने के साथ ही जल्द उनका प्रशिक्षण शुरू कराए जाने का निर्देश दिया है। योगी सरकार में अब तक पुलिस में 137253 पदों पर भर्ती हो चुकी है।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की क्षमता दोगुनी की गई है। इसे लगातार और बढ़ाया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों के प्रशिक्षण केंद्रों में भी चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों में 1809 अभ्यर्थी दूसरे राज्यों के हैं। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष/डीजी राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि आरक्षी नागरिक पुलिस व पीएसी के 49568 पदों पर सीधी भर्ती-2018 अक्टूबर की लिखित परीक्षा के लिए करीब 23 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। मेरिट के आधार पर एक लाख 23 हजार अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जांच व शारीरिक मानक परीक्षा में शामिल किया गया। अंतिम रूप से चयनित 49568 का परिणाम घोषित किया गया। इनमें आरक्षी नागरिक पुलिस के 31360 (25394 पुरुष व 5966 महिला) तथा आरक्षी पीएसी के 18208 अभ्यर्थी शामिल हैं। इनमें 1567 भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हैं।

प्रतीकात्मक

नौ अन्य राज्यों के भी अभ्यर्थियों ने मारी बाजी

सिपाही भर्ती में उत्तर प्रदेश के 47759 तथा दूसरे राज्यों के 1809 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इनमें सबसे अधिक बिहार के 831 अभ्यर्थी हैं। गैर राज्यों में उत्तराखंड के 27, बिहार के 831, मध्य प्रदेश के 179, राजस्थान के 409, दिल्ली के 108, महाराष्ट्र के 24, झारखंड के 21, पंजाब के 36 व हरियाणा के 174 अभ्यर्थी शामिल हैं।

शिवसेना नेता पर फायरिंग में पुलिस का कमांडो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर : शिवसेना हिंदुस्तान के यूथ विंग के पंजाब प्रधान हनी महाजन पर फायरिंग मामले में पुलिस ने सोमवार को पंजाब पुलिस के कमांडो प्रिंस कुमार को गिरफ्तार किया है। इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। आरोपित कमांडो गुरदासपुर के गांव तिब्बड़ का रहने वाला है। वह पटियाला में सेकेंड कमांडो में तैनात था और हमलावरों को कारतूस मुहैया कराए थे। उसके पास से भी पांच कारतूस बरामद हुए हैं। प्रिंस की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अब इस केस में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) भी लगा दिया है। उसको शक है कि इस मामले में विदेश से भी फंडिंग हुई है। पुलिस मान रही है कि तरनतारन के जिस गन हाउस से कारतूस लिए गए थे, उसमें भी जल्द अहम सुबूत हाथ लगेंगे। उधर, एसपीडी हरविंदर सिह संधू का कहना है कि प्रारंभिक जांच में आरोपित सिमरनजीत सिंह के खालिस्तान समर्थकों के साथ संबंध सामने आए हैं। पुलिस ने अब इस एंगल से भी जांच शुरू कर दी है।

हनी पर हमला करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों औजला कालोनी के सनी और बटाला के गांव कंडियाल के सिमरजीत सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सोमवार को आरोपित सनी व सिमरनजीत सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपितों को छह दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।

इंटरव्यू के बाद बढ़ाए गए छह अभ्यर्थियों के अंक

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज

पेपर लीक, अंकों में हेर-फेर के लिए विवादों में रही पीसीएस 2015 परीक्षा एक बार फिर चर्चा में है। सीबीआइ जांच में परीक्षा की अनियमितता सामने आ रही है। ओएमआर शीट जलाने, स्केलिंग व मॉडरेशन प्रक्रिया में अनियमितता के बाद सीबीआइ को इंटरव्यू में गड़बड़ी मिली है। जांच में सीबीआइ को पता चला है कि छह अभ्यर्थियों का चयन कराने के लिए उनके अंक इंटरव्यू के बाद बढ़ाए गए। इंटरव्यू लेने वाले पैनल ने उन्हें जितने अंक दिए थे, उसमें 10 से 25 नंबरों की बढ़ोतरी कर अभ्यर्थियों को पास किया गया। सीबीआइ ऐसा करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की पहचान करने में जुटी है। साथ ही उन छह अभ्यर्थियों को तलब करने की तैयारी है।

उप्र लोकसेवा आयोग ने 29 मार्च, 2015 को पीसीएस प्री 2015 की परीक्षा कराई थी। प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान लखनऊ में पेपर लीक हो गया। लखनऊ के कृष्णानगर थाने में एसटीएफ ने पेपर लीक होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पेपर लीक होने पर 30 मार्च को अभ्यर्थियों ने लोकसेवा आयोग पर उग्र प्रदर्शन किया। दबाव बढ़ने पर आयोग ने प्री परीक्षा निरस्त कर 10 मई 2015 को दोबारा परीक्षा कराई थी। उसमें पांच लाख के लगभग अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

सीबीआइ 25 जनवरी, 2018 से यूपीपीएससससी की 550 भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही है। पीसीएस 2015 की जांच एक वर्ष से चल रही है। जांच की शुरुआत में सीबीआइ को स्केलिंग व मॉडरेशन प्रक्रिया के जरिये अंकों में हेर-फेर करने की जानकारी मिली। आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रक से जून 2019 से लगातार पूछताछ चल रही है। इधर, पिछले माह सीबीआइ ने विदेश में रह रहे आयोग के एक पूर्व अधिकारी को पूछताछ के लिए बुलाया था। सीबीआइ जल्द ही पूर्व परीक्षा नियंत्रक व विदेश से बुलाए गए अधिकारी का आमना सामना कराएगी।

पीसीएस परीक्षा 2015

- कुल पद : 530 (एसडीएम के 22 पद)
- 29 मार्च 2015 : प्री परीक्षा हुई, प्रथम पाली का पेपर लीक हुआ। फिर भी दूसरी पाली की परीक्षा कराई गई।
- 10 मई 2015 : दोबारा प्रारंभिक परीक्षा कराई गई।
- छह जून 2015 : प्री परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ। मुख्य परीक्षा के लिए 9164 अभ्यर्थी सफल।
- 29 जून से 16 जुलाई 2015 : मुख्य परीक्षा हुई।
- एक दिसंबर 2015 : मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ। इंटरव्यू के लिए 1578 अभ्यर्थी सफल हुए।
- 22 जनवरी से 24 फरवरी 2016 : इंटरव्यू चला।
- एक मार्च 2016 : अंतिम रिजल्ट घोषित।

रांची में उग्रवादी प्रेम सागर को गोलियों से भूना

जागरण संवाददाता, रांची

रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित होटल पार्क प्राइम के पास तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (टीएसपीसी) के उग्रवादी प्रेम सागर मुंडा को गोलियों से छलनी कर दिया गया। सोमवार शाम करीब सात बजे पांच से छह अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। प्रेम चतरा जिला के टंडवा का रहने वाला था। वह एक पूर्व सीएम क ा करीबी था। प्रेम कोयला कारोबार और उग्रवादी संगठन के बीच लेवी के पैसा के लिए लाइजनिंग का काम भी करता था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) उसकी संपत्ति की जांच कर रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्रेम सागर अपनी फॉर्च्यूनर (जेएच01बीटी-0009) से मोरहाबादी स्थित पार्क प्राइम होटल के पास रुका हुआ था। इसी दौरान बाइक सवार दो अपराधियों ने उसको गोली मार दी और भाग निकले। स्थानीय लोगों की मदद से मुंडा को रिम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

जांच एजेंसी खंगाल रही थी संपत्ति : प्रेम सागर मुंडा के खिलाफ एनआइए भी जांच में जुटी थी। टेरर फंडिंग के मामले में चतरा के पिपरवार (कांड संख्या 36-19) में प्रेम सागर मुंडा समेत 77 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बताया गया है कि प्रेम ने रांची स्थित मोरहाबादी, कांके सहित कई इलाके में संपत्ति खरीदी थी।

भाई टीएसपीसी का करोड़ों रुपये लेकर है फरार : पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रेम सागर मुंडा टीएसपीसी के लिए लेवी वसूलने का भी काम करता था। इसी मामले में वह जेल गया था। चार दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था। पुलिस को सूचना है कि प्रेम सागर मुंडा का भाई बबलू मुंडा टीएसपीसी उग्रवादी संगठन का करोड़ों रुपये लेकर फरार हो गया है। इसके बाद से ही टीएसपीसी रुपयों को लेकर प्रेम सागर मुंडा पर दबाव बना रहा था। आशंका है कि हत्या की वजह यह हो सकती है।

चतरा में प्रेम सागर मुंडा पर उग्रवादी संगठन के लिए लेवी वसूलने समेत कई मामले दर्ज हैं। हत्यारों का पता लगाया जा रहा है। जांच के लिए दो एसपी व पांच डीएसपी को लगाया गया है। जल्द ही हत्यारे पकड़े जाएंगे।

- अनीश गुप्ता, एसएसपी रांची।

दैनिक जागरण

सुख और दुख प्रभु द्वारा कर्मों के अनुरूप प्रदत्त कर्म-प्रसाद हैं

दंगों पर सियासी दंगल

बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन संसद में वही हुआ जिसका अंदेशा था। दोनों सदनों में दिल्ली दंगों पर कोई धीर-गंभीर चर्चा होने के बजाय जमकर हल्ला-हंगामा हुआ। चूंकि जोर हंगामा मचाने पर ही था इसलिए हैरत नहीं कि पक्ष-विपक्ष के सांसदों के बीच हाथापाई होते-होते बची। यह तो गनीमत रही कि हाथापाई की नौबत आने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती रही, अन्यथा वहां मारपीट भी हो सकती थी। समझना कठिन है कि जब सरकार दिल्ली दंगों पर चर्चा करने और विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सहमत थी तब फिर विपक्ष ने नारेबाजी करना जरूरी क्यों समझा? कहीं इसलिए तो नहीं कि दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए वह भी जिम्मेदार है? आखिर यह किससे छिपा है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ लोगों को भड़काने में विपक्ष ने कोई कसर नहीं उठा रखी? यह राजनीतिक बेशर्मी के अलावा और कुछ नहीं कि सीएए के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले विपक्षी नेता सीएए के समर्थन में ऐसे ही बयान देने वाले सत्तापक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में दंगा किसी धार्मिक मसले पर नहीं, बल्कि सीएए रूपी राजनीतिक मसले पर हुआ। इस मसले पर विपक्षी दलों के साथ-साथ वामपंथी बुद्धिजीवियों ने जैसा विष वमन किया उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है।

सीएए का किसी भारतीय नागरिक से कोई लेना-देना नहीं, फिर भी विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस ने दुष्प्रचार का सहारा लेकर यह माहौल बनाया कि यह देश के मुसलमानों के खिलाफ है। अब तो यह भी साबित हो रहा है कि मुस्लिम समुदाय को भड़काने के साथ ही उसे अमेरिकी राष्ट्रपति के दिल्ली आगमन के अवसर पर सड़कों पर उतारने की सुनियोजित साजिश रची गई ताकि केंद्रीय सत्ता को असहज करने के साथ ही दुनिया को यह दिखाया जा सके कि सीएए ने भारत में किस तरह उबाल पैदा कर दिया है? किसी को इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान दिल्ली में हुए दंगे उस कुत्सित राजनीति का ही नतीजा हैं जिसके आयोजक और प्रायोजक हमारे अपने विपक्षी दल थे। ये दल अभी भी ऐसा रवैया अपनाए हुए हैं जैसे उन्हें शरणार्थियों से ज्यादा चिंता घुसपैठियों की है। चूंकि वे अभी भी आग से खेल रहे हैं इसलिए उन्हें वैसे ही बेनकाब किया जाना चाहिए जैसे दिल्ली के दंगों के गुनहगारों को। इससे इन्कार नहीं कि पुलिस दिल्ली के बिगड़ते हालात को भांप नहीं सकी और सरकार भी समय रहते सक्रियता का परिचय नहीं दे पाई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि विपक्षी दल दूध के धुले हैं। वास्तव में उनकी ही लगाई गई आग से दिल्ली जली।

गैस पर मनमानी

सरकार जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाने की लिए कई योजनाएं बनाती है। यही प्रयास होता है कि लोगों को घर-द्वार पर ही सुविधाएं मिलें। रसोई गैस की डिलीवरी भी लोगों के घर-द्वार पर करने की व्यवस्था है। शहरी क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध भी करवाई जा रही है, लेकिन दूरदराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से पैसे तो होम डिलीवरी के वसूले जाते हैं, पर घर तक गैस सिलेंडर नहीं पहुंचाया जाता है। इतना ही नहीं, उपभोक्ताओं को कैश एंड कैरी नियम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी का फायदा उठाकर गैस एजेंसी संचालक उन्हें चूना लगाकर जेब भर रहे हैं। इस नियम के तहत गोदाम से सिलेंडर लेने पर उपभोक्ता को कुछ छूट दी जाती है, लेकिन प्रदेश में गोदाम से सिलेंडर लाने पर भी उपभोक्ता को पूरे पैसे का भुगतान करना पड़ता है। यह सही है कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में यह संभव भी नहीं है, लेकिन कई जगह गैस एजेंसी संचालक हर जगह एक ही दाम वसूल करते हैं। कई जगह शहरी क्षेत्रों में भी ऐसी ही स्थिति है। गैस एजेंसी संचालक एक जगह गाड़ी खड़ी कर देते हैं जहां से लोगों को खुद सिलेंडर घर तक पहुंचाना पड़ता है। कई जगह तो लोगों को सिलेंडर घर तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त भुगतान भी करना पड़ता है। नियम है कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी देते समय उसका भार भी चेक किया जाए, लेकिन डिलीवरी करने वाले ऐसा नहीं करते हैं। उपभोक्ता भी यह सोचकर शिकायत नहीं करते कि भविष्य में उनके लिए समस्या हो सकती है, इस कारण शिकायत भी नहीं करते। डिलीवरी करने वाले लोग खुले पैसे न होने पर भी दो-तीन रुपये रख लेते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि खुले पैसे किसी उपभोक्ता को वापस किए जाते हों। गैस एजेंसियों की मनमानी रोकने के लिए जरूरी है कि लोग डिलीवरी के नियमों के बारे में पूरी तरह जागरूक रहें। उन्हें पता होना चाहिए कि गैस के गोदाम, सड़क एवं घर पर डिलीवरी लेने के अलग-अलग दाम तय हैं और उसी के अनुसार भुगतान करना चाहिए। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को इस संबंध में पहल करनी चाहिए और शिविर लगाकर लोगों को जगाना चाहिए। लोग सजग होंगे तो कोई भी उनके साथ छल नहीं कर पाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो उसे सक्षम अधिकारियों के समक्ष उजागर करना चाहिए।

आसान नहीं अफगानिस्तान की राह

विवेक काटजू

भले ही अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता हो गया हो, लेकिन उसकी राह में तमाम मुश्किलें कायम हैं

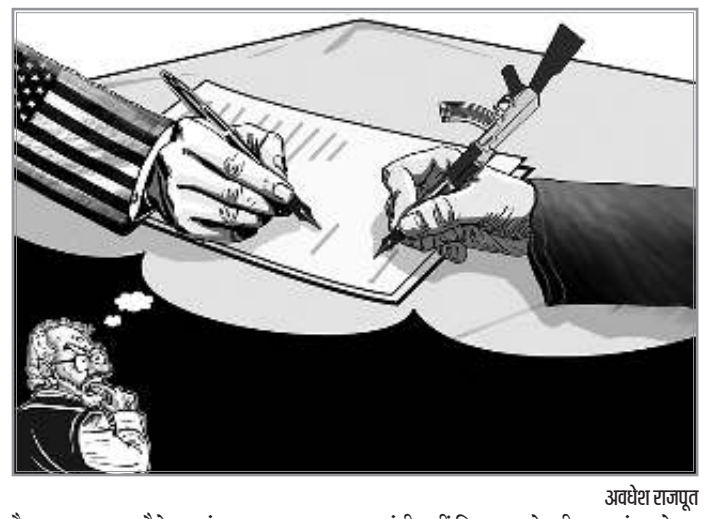

अवधेश राजपूत

करीब डेढ़ साल की कशमकश और कई दौर की वार्ता के बाद आखिरकार अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो ही गए। गत शनिवार को कतर की राजधानी दोहा में हुए समझौते पर अमेरिका की ओर से जालमेई खलीलजाद ने हस्ताक्षर किए। वहीं तालिबान की तरफ से यह काम उसके राजनीतिक कार्यालय के मुखिया मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने किया। खलीलजाद खुद अफगानी मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। वह अफगानिस्तान में राजदूत भी रह चुके हैं। हालांकि इस बहुप्रचारित समझौते से अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता की राह कुछ खुलती दिख रही है, लेकिन वास्तव में यह अमेरिकी सेनाओं को स्वदेश बुलाने का एक जरिया ही अधिक है। तालिबान ने केवल इतनी प्रतिबद्धता दिखाई है कि वह अपनी नियंत्रित भूमि पर किसी भी ऐसे अंतरराष्ट्रीय आतंकी गुट को घुसने नहीं देंगे जिससे अमेरिका और उसके साथी देशों को कोई खतरा उत्पन्न हो। इस समझौते के मूल में दो उद्देश्य हैं। जहां तालिबान की प्रमुख मांग यह थी कि अफगानिस्तान से सभी अंतरराष्ट्रीय सेनाएं बाहर चली जाएं वहीं अमेरिका यह मांग करता आ रहा था कि अफगानिस्तान से उसे कोई खतरा न रहे। यदि ये दो उद्देश्य पूरे हुए तभी यह करार सफल माना जाएगा। समझौते में तालिबान इस पर भी सहमत हुआ है कि अफगानिस्तान के राजनीतिक भविष्य के लिए वह सभी अफगानी पक्षों से बातचीत के लिए तैयार है। यह बातचीत 10 मार्च से शुरू होगी। इसमें कुछ खाका खिंचने के बाद ही वह पूर्ण युद्धविराम पर मुहर लगाएगा। इस वार्ता के लिए अमेरिका ने सही माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उसने आश्वासन दिया है कि उसकी कोशिश होगी कि वार्ता से पहले अफगान सरकार की गिरफ्त में पांच हजार तालिबानी और तालिबान की कैद में एक हजार अफगानी सैनिकों की रिहाई हो सके।

जिस दिन यह समझौता हुआ उसी दिन काबुल में अफगान सरकार और अमेरिका के बीच एक संयुक्त बयान जारी हुआ। इसमें अफगान सरकार ने अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते की पुष्टि की। अमेरिका ने स्पष्ट किया कि वह अफगान सरकार को भविष्य में हरसंभव सहायता देना जारी रखेगा। इसमें सामरिक मदद भी शामिल होगी। इससे भी महत्वपूर्ण अमेरिका की ऐसी मंशा है कि वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत में भी मदद करेगा ताकि दोनों देशों की भूमि से एक दूसरे के लिए कोई खतरा उत्पन्न न हो। एक लिहाज से यह बयान अफगान सरकार की प्रतिष्ठा कायम रखने लिए दिया गया प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि अमेरिका द्वारा तालिबान के साथ समझौता करने से तालिबान की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ी है। अब इस समझौते पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मुहर लगवाने की कोशिश होगी। भले ही यह समझौता हो गया हो, लेकिन इसकी राह में बड़ी मुश्किलें अभी भी कायम हैं। समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं कि अफगान सरकार ने कहा कि उसने तालिबान बंदियों को छोड़ने का कोई आश्वासन नहीं दिया। इस सूरत में क्या 10 मार्च से विधिवत बातचीत शुरू हो पाएगी? इसमें एक राजनीतिक पेच भी है और वह यह कि हाल में अफगान चुनाव आयोग ने अशरफ गनी को दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया है, मगर उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने हार स्वीकार नहीं की। उन्होंने समांतर सरकार गठित करने की बात की है। इस हालात में तालिबान से वार्ता के लिए सभी पक्षों को साथ लाने में मुश्किल होगी। गनी चाहते हैं कि वह गैर-तालिबान पक्ष का नेतृत्व करें, पर क्या अन्य समूह उनके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। तालिबान के साथ यह आशंका जुड़ी हुई है कि वह हिंसा कम तो कर देगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वह उसे पूरी तरह बंद करेगा।

दोहा में इस समझौते पर हस्ताक्षर के मौके पर कतर में भारतीय राजदूत भी उपस्थित थे। उसी दिन विदेश सचिव काबुल में थे जहां उन्होंने राष्ट्रपति गनी, डॉ. अब्दुल्ला अब्दुल्ला और अन्य अफगान नेताओं से बातचीत की। इस दौरान विदेश सचिव ने आश्वासन दिया कि भारत अपनी परंपरागत नीतियों को आगे बढ़ाएगा। यानी वह अफगानिस्तान को सहायता देता रहेगा और उसके आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। जहां तक समझौते का सवाल है तो भारत सरकार ने इस पहलू पर जरूर गौर किया कि अफगानिस्तान का प्रत्येक राजनीतिक पक्ष इस करार के पक्ष में हो। अब सवाल यह है क्या भारत तालिबान से बातचीत करेगा? एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भारत को तालिबान से पहले ही संबंध स्थापित कर लेने चाहिए थे? यह समझना आवश्यक है कि राजनयिक दृष्टि से बातचीत करना या संबंध स्थापित करने से दूसरे पक्ष की नीतियों या विचारधारा को वैधानिकता नहीं मिलती। 1990 के दशक में भारत ने तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी की सरकार का समर्थन किया था। तब भारत के साथ ईरान और रूस भी रब्बानी सरकार के साथ थे, लेकिन 2020 उस दौर से बहुत अलग है। कई वर्षों से विश्व की बड़ी शक्तियों ने तालिबान से संबंधों की पींगें बढ़ाई हैं। इनमें चीन और यूरोपीय संघ के देश भी शामिल हैं। यहां तक कि ईरान और रूस ने भी अपने द्वार तालिबान के लिए खोले। इसके साथ-साथ अफगान सरकार का भी यह प्रयास रहा कि तालिबान उससे बातचीत करने के लिए राजी हो। वहीं तालिबान अफगान सरकार की इन कोशिशों को यह कहते हुए नकारता रहा कि वह अमेरिका की पिट्ठू है। इस बदलते घटनाक्रम में बेहतर होता कि भारत सरकार भी कुछ लचीला एवं व्यावहारिक रवैया अपनाकर बातचीत की तालिबानी पहल पर सकारात्मक रुख दिखाती। इसमें संदेह नहीं कि पाक और तालिबान के संबंध बहुत घनिष्ठ हैं और तालिबान इस्लामाबाद पर निर्भर भी है, लेकिन उन्होंने भारतीयों को यह संदेश देने की कोशिश भी की है कि उन्हें पाकिस्तान का पिट्ठू कतई न समझें।

भारत को अफगानिस्तान की बदलती सूरत पर कड़ी नजर रखनी होगी। वहां के घटनाक्रम से भारत के सामरिक समीकरणों पर भी असर पड़ सकता है, हालांकि ऐसी आशंका कम ही है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए बेहतर यही होगा कि वह अफगानिस्तान में सभी राजनीतिक पक्षों के साथ सार्थक संवाद एवं सहायता जारी रखे। अफगानिस्तान में भारत जो भी सहायता कर रहा है, उसका वहां बहुत सकारात्मक प्रभाव है। इन गतिविधियों को और धार देकर आगे बढ़ाने की दरकार है।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

विरोध के बहाने विद्रोह को हवा

संसद से नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पारित होने के बाद उसके अंधविरोध की चिंगारी ने जो हिंसक रूप धारण किया उसके चलते देश की राजधानी दिल्ली में 40 से अधिक लोगों की जान चली गई और अरबों रुपये की संपत्ति स्वाहा हो गई। सीएए के विरोध में हैरान करने वाली बात यह है कि विरोधी सीएए में किसी आपत्तिजनक प्रावधान को इंगित न कर कानून वापस लेने की जिद पर अड़े हुए हैं। इस कानून के साथ एनआरसी के स्वकल्पित भय को जोड़कर उन्होंने हिंसा का बहाना बनाया। इस स्थिति को बनाने में कई पत्रकारों, नेताओं, बुद्धिजीवियों एवं कलाकारों ने नकारात्मक ही नहीं, बल्कि घातक भूमिका निभाई। विरोध की अगुआई कर रहे स्वर सीएए के किसी प्रावधान पर बात न कर केवल भारतीय नेतृत्व के प्रति भावनाएं भड़का रहे हैं। बतौर उदाहरण पत्रकार सबा नकवी ने विरोधियों से अदालतों के सहारे न रहकर सड़कों पर उतरने का आह्वान किया वहीं एआइएमआइएम नेता वारिस पठान ने 15 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद सौ करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ने की धमकी दी। जब छात्र नेता शर्जील इमाम असम को भारत से काटने की बात कर रहा था तब कवि हुसैन हैदरी सीएए को राज्य प्रायोजित हिंदू आतंकवाद बता रहा था। छोटे-बड़े राजनीतिक दलों ने भी आग में घी डालने का काम किया। खुद सोनिया गांधी ने अस्तित्व का हवाला देकर वर्ग विशेष को घरों से बाहर निकलने की आवाज दी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने भारत को अपने मतावलंबियों की पैतृक जागीर बताया। विपक्ष और वामपंथी बुद्धिजीवियों द्वारा समर्थित जहरीले विरोध का आलम यह था कि खुलकर जिन्ना वाली आजादी के नारे लगाए गए। कई मंचों से संख्या बल बदलने पर बहुसंख्यक समुदाय को देख लेने की धमकी भी दी गई।

इसमें कोई संदेह नहीं कि सीएए विरोधी आंदोलन की आड़ में जो कुछ हुआ और हो रहा है वह विरोध नहीं, बल्कि एक तरह का विद्रोह है। इन्हीं विद्रोही तेवरों के चलते संसद, संविधान और न्यायिक प्रक्रिया को धता बताकर यह एलान किया जा रहा है कि शाहीन बाग ने फैसला ले लिया है और उससे पीछे हटने का सवाल नहीं। हिंसा और उग्र प्रदर्शनों में अपना दृष्टिकोण समझाने की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को संख्या बल और हिंसा के दम पर झुकाने का प्रयास है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पर भड़काई गई हिंसा इस बात का सबूत है कि विद्रोह की चिर परिचित प्रोपेगेंडा शैली में भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संघर्ष क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। तथाकथित विरोध के क्रम में आजादी के नारों को भले ही चतुराई के साथ गांधी और निज अधिकारों के साथ जोड़ा जा रहा हो, लेकिन उनका सांप्रदायिक तेवर विघटनकारी उन्माद के रूप में ही सामने आ रहा है। बड़ी धूर्तता के साथ भूख-प्यास से आजादी के साथ-साथ कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों की आजादी के नारे भी सरका दिए गए। कागज नहीं दिखाने का एलान बगावत का वह रूप है जिसके तहत अंग्रेजी शासनकाल में नागरिक अवज्ञा का झंडा उठाया गया था।

विकास सारस्वत

सीएए विरोधी इसके कानूनी पहलू पर बात न कर केवल भारतीय नेतृत्व के प्रति भावनाएं भड़का रहे हैं

सीएए विरोध में अन्य स्थानों पर हुई हिंसा की ही भांति दिल्ली दंगों में भी पुलिस और सुरक्षाबलों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। इन हमलों में एक पुलिसकर्मी और एक गुप्तचर कर्मी की मौत हो गई और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को गंभीर चोटें आईं। एक अन्य स्थान पर अर्धसैनिक बलों के ऊपर तेजाब फेंका गया। पुलिस और सुरक्षाबलों को निशाना बनाना क्षणिक भावावेश न होकर एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा ही था।

वास्तव में वह नक्सली विचारधारा जो पिछले पांच दशकों से भारत में व्यापक जन विद्रोह खड़ा करने का प्रयास कर रही है और जिस पर सीएए के विरोध को हवा देने के आरोप लगते हैं, भारतीय जनतंत्र को धोखा बताती रही है। नक्सलवाद के शीर्ष विचारक चारू मजूमदार का कहना था कि क्रांतिकारियों को ऐसा सजग नेतृत्व देना होगा जो नौकरशाहों, पुलिस कर्मियों और सैन्य अधिकारियों पर वार कर सके। हमारी लड़ाई थानों और इमारतों से नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों और अधिकारियों से है। क्रांतिकारियों को ध्यान रखना होगा कि हमला सिर्फ हमले के लिए नहीं बल्कि अधिकारी और पुलिसकर्मियों को खत्म करने के लिए होना चाहिए। दिल्ली में पुलिसकर्मियों पर लगातार हुए हमलों में इस नक्सली विचार की स्पष्ट झलक मिलती है। यह भी ध्यान रहे कि जहां फिल्मी दुनिया से जुड़े कुछ लोगों ने पुलिस को दंगाइयों के समकक्ष बताने की भद्दी कोशिश की वहीं कई तथाकथित बुद्धिजीवियों ने अंकित शर्मा की जघन्य हत्या को आत्मरक्षा से जोड़ने में देर नहीं की।

जहां पुराने वामपंथियों का मानना था कि भारतीय सत्ता सामंतवादी और उपनिवेशवादी है, वहीं आज के विद्रोही सत्ता पर फासीवाद के आरोप लगा रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में भारतीय जनतंत्र को अनैतिक और अवैध ठहराने का प्रयास जारी है। हां, एक बड़ा परिवर्तन वाहक समूह को लेकर हुआ है। पहले विद्रोह की कल्पना किसान क्रांति और वर्ग संघर्ष के भरोसे रही वहीं अब समुदाय विशेष का सहारा लेने का प्रयास हो रहा है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर पीएफआइ जैसी संस्थाओं और स्थानीय स्तर पर अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के छात्र संगठनों के साथ गठजोड़ बनाए जा रहे हैं। शरिया-नक्सल गठजोड़ की यह बगावत राष्ट्र के सामने एक भीषण चुनौती बन गई है। सीएए विरोध और दिल्ली दंगा इस गठजोड़ का वह प्रयोग ही है जिसकी तरफ प्रधानमंत्री ने हाल में इशारा किया था। उम्मीद करनी चाहिए कि दिल्ली दंगों के बाद विपक्षी दल विरोध के नाम पर विद्रोह को हवा देना बंद कर तनिक गंभीरता का परिचय देंगे।

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य और स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

पहला कदम

किसी गांव से थोड़ी दूरी पर एक मंदिर था। दूर-दूर से लोग वहां दर्शन के लिए आते थे, किंतु उसी गांव का एक युवक कभी उस मंदिर को देखने नहीं जा सका। उसे हमेशा यही लगता था कि मंदिर बहुत दूर है और वहां जाते-जाते अंधेरा हो जाएगा और फिर उसे घर वापस आने में तकलीफ होगी।

एक शाम सूरज अस्त होने को था तभी उस युवक को दूर से एक बूढ़ा हांफते हुए मंदिर के रास्ते चलता हुआ दिखाई दिया। वह हैरत में पड़ गया कि दूरी के भय के कारण जिस मंदिर का वह अभी तक दर्शन नहीं कर पाया था, उसी के दर्शन के लिए वह वृद्ध व्यक्ति दिन ढलने की भी परवाह नहीं कर रहा था। उसने बुझे मन से पूछा, 'बाबा, यह कैसे संभव है? एक-एक कदम चलकर आप उतनी दूर मंदिर का दर्शन करने कैसे जा सकते हैं? भला एक-एक कदम चलकर कोई कैसे इतना बड़ा सफर तय कर सकता है?' युवक के ऐसे नजरिये से हैरान बाबा थोड़ी देर रुके और बोले, 'बेटा, इंसान तो हमेशा एक बार में एक कदम ही चलता है। फिर घबराना किस बात का? यही एक अकेला कदम हमारी जीवन यात्रा का सबसे अहम कदम होता है जो हमारे जीवन को गति प्रदान करता है।' बाबा की बातों से जीवन के एक अनमोल रहस्य के प्रति युवक का ज्ञान-चक्षु खुल चुका था।

मानव अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण कार्य इसीलिए नहीं कर पाता है कि वह पहला कदम उठाने से ही डरता है। उसे हमेशा असफल होने की आशंका सताती रहती है जो उसके पांव की सबसे बड़ी बेड़ी होती है। कदाचित मानव की इससे बड़ी कोई हार नहीं हो सकती। कहते हैं कि इस दुनिया की सबसे लंबी यात्रा की शुरुआत पहले कदम से ही होती है। पहला कदम गर्भनाल सरीखा होता है जिससे गर्भ में पल रहे किसी शिशु का जीवन बंधा होता है। फिर जीवन में अपने सपनों को साकार करने की राह में पहला कदम उठाने से भय कैसा?

श्रीप्रकाश शर्मा

वन्य जीवों को बचाने की जरूरत

प्रमोद दीक्षित 'मलय'

वन्यजीव संकट में हैं जिन्हें बचाने की महती आवश्यकता है, ताकि नीले ग्रह पर मानव की पदचाप सुनाई पड़ती रहे

संकटग्रस्त वन्यजीवों के महत्व के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और उनको विलुप्त होने से बचाने एवं संरक्षित करने की पहल के रूप में संयुक्त राष्ट्र प्रति वर्ष 3 मार्च को 'विश्व वन्यजीव दिवस' मनाता है। यह आयोजन प्रत्येक वर्ष एक थीम पर केंद्रित होता है। 'पृथ्वी पर जीवन रखना है' वर्तमान वर्ष का थीम विषय है जो वन्य जीवों के महत्व को दर्शाता है। एक अध्ययन के अनुसार दुनिया के तीन अरब लोगों का जीवन और जीविका समुद्र एवं तटीय जैव विविधता एवं संसाधनों पर आश्रित है। समुद्री एवं तटीय संसाधनों पर केंद्रित उद्योग धंधों का मूल्य 3 खरब डॉलर से कहीं अधिक है जो विश्व की जीडीपी का 5 प्रतिशत है, लेकिन आज यह समुद्र और समुद्री जीव जगत जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण दुर्दशा के शिकार हैं। समुद्री जीवों की बहुत सारी प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं।

इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के एक अध्ययन के अनुसार जीवों की 2500 से अधिक प्रजातियां संकट में हैं। साथ ही 1975 से अधिक वनस्पतियां अस्तित्व से संघर्ष कर रही हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार पिछली एक सदी में 60 से 80 लाख जीव एवं वनस्पतियां लुप्त हो चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि भारत ने भी वन्यजीवों के संरक्षण के लिए शुरुआती कदम बहुत पहले ही उठा लिए थे। 1927 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार वन्यजीवों के शिकार एवं वनों की अवैध कटाई को दंडनीय अपराध घोषित किया गया था।

विकास के नाम पर प्रकृति के साथ की गई छेड़छाड़ और शोषण के दुष्परिणाम दिखाई पड़ने लगे हैं। बढ़ते शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण जंगलों की कटान की जा रही है। अवैध खनन के द्वारा प्रकृति की जीवन रेखा नदियां मारी जा रही हैं। प्लास्टिक आज जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा संकट बनकर खड़ा है। लाखों टन प्लास्टिक समुद्र में पहुंच चुका है जो समुद्री जीवन के लिए खतरा है।

स्मरणीय है कि विश्व के कार्बन उत्सर्जन का 80 प्रतिशत समुद्र एवं जंगल सोखते हैं। अभी धरती के फेफड़े कहे जाने वाले अमेजन एवं ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से जैव विविधता को भारी नुकसान हुआ है। बढ़ते वैश्विक ताप के कारण पहाड़ों की बर्फ पिघलने से समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है जो समुद्र तटीय देशों के अस्तित्व पर एक संकट के रूप में खड़ा है। मनुष्य की अधिकाधिक भौतिक संसाधनों को जुटाने की लालसा ने जीव-जंतुओं एवं वनस्पतियों का अंधाधुंध शोषण किया है। साफ है कि वन्यजीव संकट में हैं जिन्हें बचाने की महती आवश्यकता है, ताकि नीले ग्रह पर मानव की पदचाप सुनाई पड़ती रहे और प्रकृति के विशाल आंगन में वन्य जीव निर्भय विचरण करते रहें।

(लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं)

सीएए विरोध के पीछे साजिश

दुष्प्रचार की भारी कीमत चुकाता देश शीर्षक से युक्त अपने लेख में संजय गुप्त ने यह ठीक ही कहा है कि सीएए का अराजक विरोध किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसका अनुमान लगा पाने में शायद मोदी सरकार विफल रही। इतना ही नहीं मोदी सरकार विपक्ष की इस नीयत को भी नहीं भांप सकी कि वह अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सीएए की ओट में देश के मुस्लिम वर्ग को भड़काकर केंद्र सरकार के विरुद्ध भी खड़ा कर सकता है। मोदी सरकार अभी तक यह भी नहीं समझ पाई है कि अल्पसंख्यकों का देश के संसाधनों पर पहला हक बताकर बहुसंख्यक वर्ग को दोयम दर्जे का नागरिक सिद्ध करना ही जिस कांग्रेस की नीयत रही हो वह भला इस देश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? शायद इन सबसे असावधान रहने का ही दुष्परिणाम है दिल्ली का भीषण दंगा, जिसमें अभी तक 43 लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग घायल अवस्था में जीवन-मृत्यु के संघर्ष से जूझ रहे हैं। यह देखने वाली बात है कि एक साजिश के तहत दिल्ली को दंगों की आग में तब झोंका गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत के मेहमान थे। केंद्र सरकार शाहीन बाग जैसे धरनों के प्रति जो सख्ती अब बरतना चाहती है यह सख्ती शुरुआती दौर में ही दिखाने की जरूरत थी। लेकिन दिल्ली चुनाव के राजनीतिक नफा-नुकसान के मद्देनजर वह ऐसा नहीं कर सकी। दिल्ली चुनाव के चलते शाहीन बाग धरने के पीछे पकने वाली साजिश का अंदाजा भी मोदी सरकार नहीं लगा पाई, लेकिन भविष्य में अब इस तरह की देशविरोधी साजिशें

मेलबाक्स

परवान न चढ़ पाएं इसके लिए दिल्ली दंगों के सभी साजिशकर्ताओं को बेनकाब कर, विपक्ष के मंसूबों को धराशायी करने की जरूरत है। यदि मोदी सरकार इस काम में चूक गई और सीएए विरोध के पीछे छुपी साजिश का ठीक से पर्दाफाश नहीं हुआ तो दिल्ली दंगों के बदनुमा दाग और गहरे हो जाएंगे।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

बेरोजगार युवा

हृदय नारायण दीक्षित का लेख, जहर घोलती सांप्रदायिकता, में लेखक ने समाज के प्रबुद्ध वर्ग से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का आह्वान भी किया है, लेकिन अपने लेख में वो सबसे अहम कारक युवाओं को भूलते नजर आए। देखा जाए तो भारत युवाओं का देश है और कुछ युवाओं के सहारे ही अलगाववादी व चरमपंथी ताकतें देश में सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने को कोशिश करती हैं। देश में बड़ी संख्या में युवाओं के पास रोजगार नहीं है। इसी का फायदा विघटनकारी ताकतें उठाती हैं। सरकार को सबसे पहले युवाओं को रोजगार मुहैया कराना चाहिए।

पवन कुमार मुरली, कादीपुर, गुरुग्राम

नफरत को हराएं

हम यह बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत अनेकता में एकता का देश है। यहां सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन अभी दिल्ली में जो हुआ वह इस बात पर सवाल उठाता है। दिल्ली के बहुत से इलाकों में हिंसा व आगजनी हुई। हालांकि अब धीरे-धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं। हालात को सामान्य करने में उन लोगों का ज्यादा सहयोग है जिन्होंने इस नफरत के बीच प्रेम व भाईचारे का उदाहरण पेश किया है। दंगों को भड़काने में सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल हुआ है। इसी सोशल मीडिया से अमन व चैन स्थापित करने की अपील भी की जा सकती है।

पारस गौर, दिल्ली विवि

दंगाइयों से भरपाई हो

बीता कुछ वक्त दिल्ली के लिए दहशत भरा रहा। ऐसा भी माना जा रहा है कि हिंसा को ज्यादा भड़काने में बाहर से आए तत्वों का हाथ था। इन दंगों में सबसे ज्यादा नुकसान बेकसूर लोगों को हुआ। सरकार को चाहिए कि सीसीटीवी फुटेज खंगालकर दंगाइयों की पहचान करे और उप्र सरकार की तर्ज पर दंगाइयों की निजी संपत्ति से नुकसान की भरपाई करे। दंगाइयों को ये सबक मिलना चाहिए।

उपासना, दिल्ली विवि

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

1957 में महबूब खान की मदर इंडिया से ऑस्कर में भारतीय फिल्मों के प्रवेश की शुरुआत हुई थी। वह ऑस्कर की 'सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म' की श्रेणी में नामित होने में कामयाब रही थी, लेकिन पुरस्कार नहीं प्राप्त कर सकी।

आजकल

चीन की पोल खोलने वाली आपदा

कोरोना संकट दुनिया को सेहत से जुड़ी आपदा के साथ ही इस पहलू से भी परिचित कराता है कि तथाकथित चीनी मॉडल वैसा नहीं है जैसी उसकी खुशनुमा तस्वीर पेश की जाती है। अब देर-सबेर इस विपदा पर भी काबू पा लिया जाएगा। यह चीन और शी चिनफिंग की बड़ी सफलता मानी जाएगी। मगर इसके साथ यह भी स्पष्ट होता जाएगा कि चीनी साम्यवादी पार्टी यानी सीपीसी और शी चिनफिंग को सत्ता में बनाए रखने की आम चीनियों को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है

हर्ष वी पंत
प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज, लंदन

वुहान में जिस बीमारी ने दस्तक दी वह अब वैश्विक महामारी बन गई है। भारत में भी इसके तीन नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के कहर से चीन में मृतकों की संख्या तकरीबन 2900 का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहां करीब 80,000 से अधिक लोग इस वायरस की चपेट में बताए जा रहे हैं। तमाम जहाज समंदर तटों पर जस से तस खड़े हैं, क्योंकि बंदरगाह पर खौफ पसरा हुआ है कि कहीं जहाज से उतरने वाले कोरोना वायरस के वाहक न हों। हर एक गुजरते दिन के साथ यह वायरस वैश्विक आवाजाही और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सेहत भी बिगाड़ रहा है। इससे चीनी साम्यवादी पार्टी यानी सीपीसी पर दबाव और बढ़ा है।

चीन में अब तक दो हजार से अधिक लोगों की जिंदगी कोरोना वायरस की भेंट चढ़ चुकी है। ऐसे हालात में राष्ट्रपति शी चिनफिंग खुद मास्क पहनकर एक अस्पताल में अपनी हालत का परीक्षण कराने के लिए पहुंचे और उन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए और 'निर्णायक' कदम उठाने का आह्वान किया। इस बीमारी के शुरुआती चरण में शी एक तरह से परिदृश्य से बाहर ही रहे और इससे निपटने का जिम्मा उन्होंने प्रधानमंत्री ली कछ्यांग को सौंपा हुआ था। हालांकि इस पर हुए जनाक्रोश के बाद शी को हाल में खुद ही कमान संभालनी पड़ी। चूंकि कोरोना का प्रकोप वर्ष 2002-03 के दौरान फैले सार्स से कहीं ज्यादा हो गया है तो यह न केवल आम चीनियों, बल्कि सीपीसी और शी के लिए भी एक बेहद गंभीर खतरे के रूप में उभरा है। तब भी वैश्विक महामारी बन चुके सार्स को लेकर सूचनाएं छिपाने के मामले में चीन को अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के कोप का भाजन बनना पड़ा था।

ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं कि कोरोना से निपटने के मामले में चीन सरकार ने अप्रत्याशित रूप से कदम उठाए। इनके तहत हुबेई प्रांत के तमाम शहरों को एक तरह से बंद कर दिया गया। वुहान इसी प्रांत का हिस्सा है। इस सूबे से परिवहन को रोक दिया गया है। सैलानियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। करोड़ों लोगों को घर में रहने की हिदायत मिली है। बीजिंग, कनमिंग, ग्वांगझू और शेनझेन जैसे बड़े शहरों में जनजीवन थम गया है जिसकी तपिश उद्योग-धंधों को झेलनी पड़ रही है। तकरीबन 5.6 करोड़ लोगों को अस्थायी एकांत स्थानों पर रखा गया है।

चीनी सरकार ने ये कदम जरूर उठाए, लेकिन इसमें काफी देर कर दी। इसके कारण चीनी मॉडल की खामियां एक बार फिर उजागर हो गईं। सरकार ने जो कदम उठाए, उनमें पारदर्शिता का भी अभाव था। वुहान के स्थानीय निकाय प्रशासन ने शुरुआत में सूचनाएं बाहर ही नहीं आने दीं। इसके चलते वायरस पर समय रहते अंकुश नहीं लग पाया और एक अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा की आशंका मजबूत होती गई। इसका ही परिणाम रहा कि चीनी सरकार के खिलाफ जनाक्रोश बेहद तीखा हो चला है। सीपीसी और शी की साख पर सवालिया निशान लगे हैं। जिन सरकारी अधिकारियों ने निहित स्वार्थों और जनता के प्रति अपने कर्तव्यों के ऊपर पार्टी के प्रति वफादारी को वरीयता दी, उनकी इस उद्दंडता ने लोगों को एक बड़े खतरे की ओर धकेल दिया। शी की पेशानी पर बल डालने वाली इस समय तमाम वजहें हैं। चीन की अर्थव्यवस्था पहले ही सुस्ती की शिकार हो चुकी है तिस पर इस महामारी के कारण उसकी हालत और खराब होगी। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस साल चीन की जीडीपी वृद्धि दर में एक से दो प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। यह सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब कई मोर्चों पर चीन के लिए चुनौतियां बढ़ी हैं। हांगकांग में हो रहे विरोध-प्रदर्शन को लेकर वह पहले से ही हमले झेल रहा है। ताइवान में भी चीन विरोधी सरकार दोबारा सत्ता में आ गई है। अमेरिका ने भी उस पर शिकंजा कड़ा किया है। चीन के साथ होने वाले व्यापार में 74 अरब डॉलर की कमी दर्शाती है कि चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले कुछ असर दिखाने लगे हैं।

किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए चीन द्वारा त्वरित और नाटकीय फैसले लेने की उसकी क्षमता को उसके 'अधिनायकवादी लाभ' के तौर पर रेखांकित किया जाता है। अब कोरोना वायरस से निपटने के लिए भी उसी जांची-परखी तिकड़म का सहारा लिया जा रहा है। असल में कम्युनिस्ट पार्टी की यही परिपाटी रही है कि वह किसी भी समस्या का ठीकरा स्थानीय स्तर पर फोड़ती है और संसाधन जुटाकर यह आभास कराती है कि वह हालात से निपटने में गंभीरता से जुटी है। ताजा मामले में भी यही हुआ। मौतों का आंकड़ा बढ़ने के साथ ही सीपीसी ने त्वरित कदम उठाते हुए कोरोना के केंद्र बने हुबेई प्रांत में कई वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टी कर दी है।

सीपीसी के लिए महत्वपूर्ण है कि वह इस रूप में नजर आए कि कोरोना वायरस जैसी आपदा से निपटने में वह प्रभावी रूप से मुस्तैद है। तानाशाही सरकारों की बुनियाद अमूमन इसी धारणा पर टिकी होती है कि वे सुरक्षा एवं स्थायित्व प्रदान करती हैं। चीन में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए सीपीसी इसी धारणा का सहारा लेती आई है। हालांकि कोरोना वायरस से निपटने में प्रत्यक्ष हुए कुप्रबंधन इस धारणा को मिथ्या ही साबित करता है। साथ ही यह इस बात को भी दर्शाता है कि विपरीत हालात में सीपीसी प्रभावी प्रशासन के मामले में भला कैसे अपनी छवि बचा पाएगी। यह संकट दुनिया को इसी पहलू से परिचित कराता है कि तथाकथित चीनी मॉडल वैसा नहीं है जैसी उसकी खुशनुमा तस्वीर पेश की जाती है।

देर-सबेर इस विपदा पर भी काबू पा लिया जाएगा। यह चीन और शी चिनफिंग की बड़ी सफलता मानी जाएगी। मगर इसके साथ यह भी स्पष्ट होता जाएगा कि सीपीसी और शी को सत्ता में बनाए रखने की आम चीनियों को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है।

कोरोना के मूल स्रोत की तलाश

मुकुल व्यास

कोरोना वायरस जानवरों से मनुष्य में कैसे पहुंचा, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। दुनिया के वैज्ञानिक इस वायरस के असली स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक थ्योरी यह है कि चीन में किसी जगह उड़ते हुए चमगादड़ ने जंगल में बीट गिराई जिसमें कोरोना वायरस था। एक जानवर वहां पत्तों में कीड़े-मकोड़े खोजते हुए उस बीट के संपर्क में आया और वायरस से संक्रमित हो गया। यह जानवर संभवतः पैंगोलिन था। यह वायरस वन्य जीवन में प्रसारित होता रहा। संभवतः इससे कोई व्यक्ति वायरस की चपेट में आ गया और उसने जंगली जानवरों की मंडी में दूसरे कर्मचारियों को भी संक्रमित कर दिया। इस तरह एक महामारी का जन्म हुआ।

वैज्ञानिक अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह कहानी सच है। वे उन जंगली जानवरों की तलाश कर रहे हैं जो इस वायरस के वाहक हैं। जूलॉजिकल सोसाइटी लंदन के एंड्रयू कनिंघम का कहना है कि कई जानवर इस वायरस के मेजबान हो सकते हैं। इनमें खास तौर से चमगादड़ का जिक्र किया जा सकता है। यह उड़ने वाला स्तनपायी जीव कई तरह के कोरोना वायरसों की मेजबानी करता है। चमगादड़ लंबी दूरियों तक उड़ानें भरते हैं। बड़ी-बड़ी कॉलोनियां बना कर रहते हैं। हर महाद्वीप पर चमगादड़ मौजूद हैं। ये खुद संक्रमित नहीं होते, लेकिन अपने रोगाणुओं से दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। यह भी अपने आप में आश्चर्यजनक है कि चमगादड़ खुद वायरस का शिकार नहीं बनते। चूंकि वह खुद स्तनपायी जीव है, ऐसे में इस बात की संभावना है कि कुछ चमगादड़ मनुष्य को सीधे या किसी अन्य जीव के जरिये संक्रमित करते हों। इस पहेली का दूसरा हिस्सा उस जानवर की पहचान करना है जिसने अपने शरीर में इस वायरस को विकसित किया और वुहान की जानवर मंडी में पहुंचा।

सबसे ज्यादा शक पैंगोलिन पर जाता है। चींटियां खाने वाला यह जानवर अपनी अनोखी त्वचा के लिए जाना जाता है। चीनी औषधियों में इसका उपयोग होता है। कुछ लोग पैंगोलिन के मीट को बड़े शौक से खाते हैं। इस जानवर की तस्करी बहुत होती है, जिसकी वजह से इसके विलुप्त होने का भी खतरा है। पैंगोलिन में कोरोना वायरस पाया गया है और कुछ का दावा है कि यह मनुष्य में मिले कोरोना वायरस से काफी मैच खाता है।

मीट-मछली की मंडियों में पैंगोलिन और चमगादड़ों की कुछ प्रजातियां भी बेची जाती हैं। इससे वायरसों को एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में प्रविष्ट करने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। इस तरह की मंडियां प्रजातियों के बीच रोगाणुओं की अदला-बदली के लिए आदर्श होती हैं।

हाल के वर्षों में जितने भी खतरनाक वायरस हमारे सामने आए हैं उनमें सभी का उद्गम जंगली जानवरों से हुआ है। इनमें इबोला, सार्स, एचआइवी और नीपा वायरस शामिल हैं। प्रो. जोंस का मानना है कि वन्य जीवन से संक्रामक रोगों के फैलने के पीछे एक मुख्य कारण यह है कि वन्य जीवों के पर्यावास में हमारा अतिक्रमण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से परिदृश्य बदल रहे हैं और हमारा सामना ऐसे नए वायरसों से हो रहा है जिन्हें मानव आबादियों ने पहले नहीं देखा था। प्रो. कनिंघम का कहना है कि यदि हमें रिस्क फैक्टर पता लग जाएं तो हम भविष्य में जानवरों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोक सकते हैं।

चीन में 2002 में इसी तरह के कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद जंगली जानवरों की मंडियों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था, लेकिन कुछ समय बाद चीन, वियतनाम और दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे देशों में इनके बाजार वापस खुल गए। अब नए कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद चीन ने पुनःवन्य जीव उत्पादों की खरीदारी और बिक्री पर रोक लगा दी है। वायरस के वर्तमान प्रकोप के असली कारणों का शायद कभी पता नहीं चले, फिर भी वैज्ञानिकों को इस तरह की दूसरी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस उपाय सोचने पड़ेंगे।

खरी-खरी

आम जनजीवन से जुड़ी ठेला संस्कृति

हेमंत कुमार पारीक

कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है, वरना लाइफ इतनी बेजार और नीरस न होती। वे गली-कूंचे और खपरैल वाले मकान न जाने कहां खो गए? अब सब बदला-बदला सा है। सामने छोटा-सा खपरैल वाला एक और मकान पिछले दिनों धराशायी हो गया। उसकी जगह नए मकान का कांक्रीट वाला ढांचा तैयार हो रहा है। यहां-वहां खपरैल का ढेर लगा है। और ठेलेवाले लगे हैं, उसे अन्यत्र कहीं ले जा रहे हैं। हमें इस मौके पर याद आ रहे हैं वे पुराने दिन, जब मुन्ने मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। कभी फाख्ता, खपरे और ठेले का गहरा संबंध हुआ करता था। ठेलेवाला शाम को आवाज लगाता था, हर माल छह आने! कभी ये ठेले हमारा राष्ट्रीय वाहन हुआ करते थे। एकबार अंग्रेजी के मास्साब के पेट में सूल उठी तो उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए ठेला ही काम आया। और साहब की उठा-धरी के लिए वही ठेले वाला खड़ा था!

हम तो शुरू से ही ठेलों के प्रशंसक रहे हैं। जब ठेला सामने हो तो एंबुलेंस की भली चलाई। पर आजकल ठेले दिखते नहीं। वरना तो कभी चौराहे पर लाइन से खड़े मिलते थे। कोई माने या न माने, भारतीय संस्कृति में इनका अहम रोल है। हर माल छह आने की आवाज सुनने को कान तरस गए हैं। अब वे गली-कूंचे न रहे, इसलिए ठेले भी न रहे। अब तो विकास बनाम अस्सी फीट के सवाल हर जगह खड़े हैं। अस्सी फीट ने दस फुटा गली-कूंचों को निगल लिया है। वरना तो कभी वहीं गिल्ली-डंडा खेला जाता था। भाईचारा पनपता था। बगल वाली इंस्पेक्टर की बीवी आंगन में खड़ी आवाज लगाती-अरे ओ मुन्न, फत्तू की दुकान से दो रुपये का नमक ले आ। मुन्न भी कम नहीं थे। हर दूसरा लड़का मुन्न हुआ करता था और हर तीसरा लड़का पप्पू!

अब तो अस्सी फुट की सड़क के कारण इधर की आवाज उधर सुनाई नहीं देती। अस्सी फुट के कारण मुन्न न रहा, मुन्नभाई हो गया है। घर की महिलाएं मोबाइल से सीधे दुकानदार से बात कर लेती हैं। आजकल ठेले दिन में दिखाई नहीं दे रहे। चोरी छिपे कांक्रीट और पत्थर के मकान के लिए रात में रेत ढो रहे हैं। हर माल छह आने वाला ब्रह्मवाक्य न जाने कहां खो गया।

ट्वीट-ट्वीट

ईरान और इटली जैसे देशों में कोरोना का फैलना किसी पहेली से कम नहीं। चीन से लगे हांगकांग, कोरिया और जापान का इससे प्रभावित होना समझ में आ सकता है। वहीं इटली में भी सैलानियों की भारी आवक होती है, लेकिन ईरान क्यों?
यशवंत देशमुख@YRDeshmukh

उमर खालिद का एक वीडियो सामने आया है। इसमें 17 फरवरी को अमरावती में दिया उनका भाषण है जिसमें वह लोगों से अपील कर रहे हैं कि ट्रंप के दौरे के समय भारी संख्या में सड़कों पर उतरें। सवाल यही है कि बीते दिनों दिल्ली में जो हुआ क्या उसकी पहले से ही तैयारी हो रही थी?
आशीष सिंह@AshishSinghNews

निर्भया के माता-पिता के लिए मामला फिर लटक गया। इस मामले में दोषियों की एक बार फिर टली फांसी इस बात की उम्दा मिसाल है कि अपराधी कैसे हमारे कानून की खामियों को जानते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। इससे पूरे न्यायिक तंत्र का ही मखौल उड़ता है।
मारिया शकील@maryashakil

कोहली की कप्तानी में भारत ने विदेशों में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेल लिए, पर मौजूदा सीरीज कुछ अलग थी। इसमें भारत ने केवल भाग लिया। लचर बल्लेबाजी और न्यूजीलैंड के निचले क्रम को जल्दी न निपटा पाने की अक्षमता भारत को भारी पड़ी।
आकाश चोपड़ा@cricketaakash

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या अमेरिका-तालिबान के बीच हुए समझौते से अफगानिस्तान में शांति एवं स्थिरता का रास्ता साफ होगा?

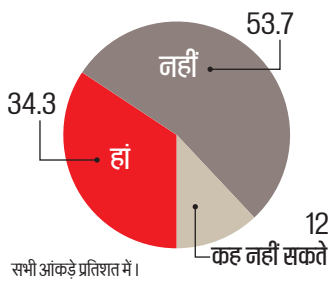

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या दिल्ली हिंसा के लिए कुछ दलों द्वारा गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगना उचित है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

फिर से फांसी टल गई दैत्य रहें आबाद,
ऐसे में क्यों होय ना घटित हैदराबाद??
घटित हैदराबाद हार कर बैठे हैं यम,
पीड़ित के अधिकार जहां हो जाते दोयम।
ऐसा अद्भुत न्याय गुजरता जाए सिर से,
जहां दैत्य से मौत हारती फिर से फिर से!
- ओमप्रकाश तिवारी

कुशल कोठियाल
स्थानीय संपादक, उत्तराखंड

उत्तराखंड डायरी

कांग्रेस लालटेन लेकर खोज रही विकास

उत्तराखंड गठन के बाद से सबसे बुरे हालात से गुजर रही कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस रही है। प्रदेश के आला नेता जगह-जगह भरी दोपहर में लालटेन जुलूस निकाल रहे हैं। संदेश यह है कि जिस विकास का प्रदेश की भाजपा सरकार ढोल पीट रही है वह तो लालटेन से खोज कर भी नहीं मिल रहा है। उधर भाजपाइयों का कहना है कि कांग्रेस बुढ़ापे के दौर में है, दृष्टिदोष होना स्वाभाविक है। कांग्रेस के ही एक और दिग्गज नेता मंत्री प्रसाद नैथानी राज्य में देव याचना यात्रा निकाल रहे हैं। उद्देश्य धार्मिक नहीं, बल्कि घोषित रूप से राजनीतिक है। वह देव यात्रा निकाल कर भाजपा सरकार को कोस रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड के देवी-देवताओं से सरकार के पतन की याचना कर रहे हैं। इस पर भाजपाई कांग्रेस पर धार्मिक भावनाओं का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। वैसे यह आरोप पारंपरिक तौर पर कांग्रेस वाले भाजपा पर लगाते थे, लेकिन अब कांग्रेस भाजपा को यह मौका दे रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव को अभी दो साल बचे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के बड़े एवं बुजुर्ग नेता हरीश रावत अभी से चारा फेंकने लगे हैं। दिल्ली में केजरीवाल की सफलता का राज जानने के बाद से हरदा ने अभी से भारी-भरकम चुनावी चारा जनता के बीच फेंक दिया है। कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश में बिजली, पानी फ्री। क्या बात है, हरदा के इस पासे से तो कांग्रेसी भी सकते में हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीमत सिंह कह रहे हैं, पहले सरकार तो आने दो फिर बताएंगे क्या-क्या फ्री हो सकता है।

कार्यकारिणी का फर्क : आजकल राजनीतिक गलियारों में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी चर्चा में है। जहां विधानसभा में 11 सदस्य वाली कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में 280 सदस्य हैं वहीं 57 विधायकों वाली भाजपा ने केवल 28 सदस्यीय कार्यकारिणी घोषित की है। छोटी एवं सक्रिय कार्यकारिणी बनाने का दावा तो कांग्रेस ने किया था, लेकिन बना डाला भाजपा ने। अब भाजपाई चुटकी लेते कह रहे हैं कि कांग्रेस केवल कहती है एवं भाजपा कर डालती है। गौरतलब है कि कांग्रेस को पिछले माह घोषित कार्यकारिणी बनाने में वर्षों लगे।

सरकार फिर चली गैरसैंण : प्रदेश सरकार विधानसभा का बजट सत्र इस बार गैरसैंण में करा रही है। तीन मार्च से शुरू हो रहे इस सत्र के लिए सारा सरकारी अमला बजटरी लाव-लश्कर के साथ गैरसैंण पहुंच गया है। करोड़ों रुपये की लागत से गैरसैंण में बने विधानसभा भवन की प्रासंगिकता को दिखाने के लिए साल भर में सरकारें एक सत्र वहां पर करती हैं, भले तीन दिनों का ही क्यों न हो। विशुद्ध रूप से पहाड़ की भावनाओं से खेलने के लिए करोड़ों खर्च कर यह आयोजन किया जाता रहा है। सांकेतिक महत्व के इस आयोजन पर होने वाले खर्च को अगर पहाड़ के गांवों पर लगा दिया जाता तो अब तक कई गांवों की शक्ल ही बदल गई होती। राजधानी पर पिछले लगभग बीस सालों से खेले जा रहे इस सियासी खेल के चलते अभी तक छोटे से उत्तराखंड राज्य को स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई। 70 सदस्यीय विधानसभा में 57 विधायकों का ऐतिहासिक बहुमत होने के बावजूद भाजपा सरकार भी इस पर कोई फैसला नहीं ले पा रही है। इस विषय पर जस्टिस दीक्षित आयोग ने कई एक्सटेंशन के बाद जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी उसे देखने की हिम्मत भी कांग्रेस एवं भाजपा की सरकारें नहीं जुटा पाईं। सवाल जब वोटों की खातिर जनता को भरमाने का हो तो दोनों दल एक ही साथ खड़े नजर आते हैं।

फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में घपला : उत्तराखंड वन महकमे में वन आरक्षी पदों पर भर्ती परीक्षा में घपले का प्रकरण एक बार फिर से सुर्खियों में है। भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े की परतें धीरे-धीरे खुल रही हैं और दो सरकारी कार्मिकों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ऐसे में परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं और साथ ही जोर-शोर से उठने लगी है इस परीक्षा को रद करने की मांग। हालांकि अभी सरकार ने इस बारे में फैसला नहीं लिया है, लेकिन परीक्षा की शुचिता को लेकर उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है, जब वन आरक्षी पदों पर भर्ती का मसला विवादों में हो। पूर्व में भी इन पदों पर भर्ती के प्रयास हुए, लेकिन तब इसके मानकों को लेकर युवाओं में उबाल रहा था। नतीजतन मानकों के शिथिलीकरण के नाम पर पूर्व में यह परीक्षा रद की गई थी। अब नए मानकों के आधार पर भर्ती परीक्षा हुई तो दोबारा विवादों में आ गई।

मंथन

ऑस्कर और भारतीय सिनेमा

हमारे फिल्मकारों को भारतीय समाज में मौजूद नए विषयों को चिन्हित करते हुए न केवल वर्तमान, बल्कि भविष्य दृष्टि के साथ उन पर नए तरीकों से फिल्म बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए

पीयूष द्विवेदी
कला-संस्कृति मामलों के जानकार

गत 31 जनवरी को भारतीय थिएटरों में लगभग सौ स्क्रीन पर दक्षिण कोरियाई फिल्म 'पैरासाइट' प्रदर्शित हुई थी। तब इस फिल्म पर भारत में बहुत अधिक कोई चर्चा नहीं हुई। स्क्रीन कम होने के कारण न तो दर्शकों के बीच इसे लेकर कोई रुझान दिखा और न ही फिल्म समीक्षकों का ही इसपर ध्यान गया। लेकिन दस फरवरी को जब यह घोषणा हुई कि इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा का ऑस्कर दिया गया है तो फिर भारत सहित दुनिया भर में इसे लेकर लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई। बांग जून हो निर्देशित 'पैरासाइट' पहली गैर-अंग्रेजी एशियाई फिल्म है, जिसे ऑस्कर प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही संभव है कि ऑस्कर निर्णायकों पर लगने वाले इस आरोप पर कुछ विराम लगे कि यह पुरस्कार देने में गैर-अंग्रेजी फिल्मों के साथ भेदभाव किया जाता है।

पैरासाइट दो परिवारों की कहानी है। एक परिवार अमीर है और दूसरा गरीब। फिर कुछ नाटकीय घटनाक्रमों के साथ गरीब परिवार के सदस्य अपने संबंध को अप्रकट रखते हुए अमीर परिवार में अलग-अलग भूमिकाओं में नौकरी करने लगते हैं। इस नौकरी के साथ उनका जीवन बेहतर चलने लगता है, लेकिन जीवन-स्तर में आया ये बदलाव उनके व्यवहार और सोच में भी बदलाव लाता है। हम देखते हैं कि वे जरा-सी बेहतर स्थिति में पहुंचते ही अपने जैसे गरीबों के प्रति कटु व्यवहार करने लगते हैं। इसके बाद हम धीमे-धीमे गरीबी-अमीरी के द्वंद्व की आंतरिक जटिलताओं से भी परिचित होते हैं। झूठ बोलकर नौकरी पाने वाले तरीके पर बॉलीवुड में भी फिल्में बनी हैं, लेकिन उनकी सीमा का विस्तार हास्य तक ही रहा है और अंत आदर्शवादी ढंग से हो गया है, जबकि पैरासाइट इस बिंदु पर ही बड़ी फिल्म बन जाती है। इसमें थोपा गया कोई आदर्शवाद नहीं है और न ही बनावटी यथार्थ। इसके गरीब पात्रों के प्रति न तो कभी सहानुभूति होती है, न ही अमीरों के प्रति घृणा पैदा करने की कोशिश ही फिल्म में की गई है। इसके सभी रंग स्वाभाविक होते हुए भी समग्र कैनवस पर आर्थिक असमानता और पूंजी की समस्या को लेकर एक अनूठा चित्र खींचने में कामयाब रहते हैं।

भारत की तरफ से अबकी ऑस्कर में गली बॉय को भेजा गया था। ऑस्कर में भारतीय फिल्मों के प्रवेश की शुरुआत 1957 महबूब खान की मदर इंडिया से होती है जो ऑस्कर की 'सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म' की श्रेणी में नामित होने में कामयाब भी रही थी, लेकिन पुरस्कार नहीं प्राप्त कर सकी। इसके तीन दशक बाद 1988 में दूसरा मौका आया जब मीरा नायर की 'सलाम बॉम्बे' को ऑस्कर में नामित किया गया, लेकिन पुरस्कार इसे भी नहीं मिला। फिर 2001 में आमिर खान की लगान के साथ भी यही हुआ। इसके अलावा विधु विनोद चोपड़ा की 'एन एनकाउंटर विद फेसेस', आश्विन कुमार की 'लिटिल टेररिस्ट', रायका जेहताबची की 'पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस' भारत की कुछ डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्में भी ऑस्कर में जा चुकी हैं। इनमें 'पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस' को ऑस्कर मिला भी था। लेकिन भारतीय भाषाओं की फीचर फिल्में आज भी ऑस्कर की प्रतीक्षा में हैं।

गांधी और स्लमडॉग मिलिनेयर भारतीय पृष्ठभूमि और कहानी पर आधारित विदेशी निर्देशकों की वे दो फिल्में हैं, जिन्होंने ऑस्कर में झंडा गाड़ा था। इन दोनों फिल्मों ने विभिन्न श्रेणियों में आठ-आठ ऑस्कर जीते थे और इनके लिए दो भारतीयों भानु अथैया और एआर रहमान को भी ऑस्कर मिला था। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों है कि भारतीय नायक या भारतीय पृष्ठभूमि की कहानी पर विदेशी निर्देशक ऑस्कर विजेता फिल्में बना लेते हैं, जबकि बॉलीवुड नहीं बना पाता। क्या इस सवाल का बॉलीवुड फिल्म निर्माता-निर्देशकों के पास कोई जवाब है कि बॉलीवुड में गांधी पर अबतक कोई अच्छी फिल्म क्यों नहीं बन पाई? ऐसे ही स्लमडॉग मिलिनेयर की कहानी उस मुंबई की गरीबी पर है, जिस मुंबई में पूरा बॉलीवुड बसता है। लेकिन इसपर फिल्म बनाने के लिए डैनी बॉयल को आना पड़ता है।

देश में एक राय यह मिलती है कि हमें ऑस्कर के प्रमाणपत्र की जरूरत क्या है। बात किसी प्रमाणपत्र की नहीं है, लेकिन फिल्म पुरस्कारों में ऑस्कर की वैश्विक प्रतिष्ठा से इन्कार नहीं किया जा सकता। अब अगर हम अपने फिल्म सम्मानों को भी वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने में कामयाब होते तो जरूर हमें ऑस्कर की परवाह करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को छोड़ दें तो हमारा कोई फिल्म पुरस्कार विश्व में तो दूर की बात है, देश में भी विश्वसनीय और सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा जाता। अभी हाल ही में घोषित फिल्मफेयर पुरस्कारों को लेकर मचा बवाल इसी का उदाहरण है। सो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे भारतीय फिल्मकारों को भारतीय समाज में मौजूद नए विषयों को चिन्हित करते हुए न केवल वर्तमान, बल्कि भविष्य दृष्टि के साथ उनपर नए तरीकों से फिल्म बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। ऐसे प्रयास ही भारतीय सिनेमा को वैश्विक प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। अंततः बात यह भी है कि साहसिक प्रयास ही सम्मान का संधान करते हैं।

3 प्रजातियों को भारत ने संयुक्त राष्ट्र संरक्षण संधि के तहत नामित किया है जो विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं। ये हैं एशियाई हाथी, गोडावण पक्षी और बंगाल पेलिकन।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 3 मार्च 2020

बंगाल

अभियान पर अभियान

बंगाल में तृणमूल एवं भाजपा के बीच घमासान जारी है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के शहीद मीनार मैदान से सीएए के समर्थन में एक रैली की जिससे उन्होंने एक ममता सरकार के खिलाफ एक बड़ा अभियान 'और नहीं अन्याय' शुरू किया है जिसके सहारे भाजपा सूबे पांच करोड़ वोटरों तक पहुंचने की योजना बनाई है। ऐसे में तृणमूल भी कहां पीछे रहने वाली थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बना रहे प्रशांत किशोर ने इसके अगले ही दिन यानी सोमवार को ममता के लिए एक नया अभियान शुरू कर दिया है। अमित शाह की रैली को 2021 में होने वाले बंगाल के विधानसभा चुनाव के आगाज के तौर पर भी देखा जा रहा है। ठीक उसी के अगले दिन यानी सोमवार बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल ने चुनाव से पहले 'बंगाल का गौरव ममता' के नाम से बड़े कैंपेन की शुरुआत कर दी है।

यहां बताते चलें कि ठीक इसी तरह से 2015 में बिहार में नीतीश कुमार के लिए प्रशांत किशोर ने बिहारी अस्मिता से जोड़ते हुए अभियान छेड़ा था। अब उन्होंने ममता के लिए यह अभियान शुरू किया है। आज से शुरू होकर 10 मई तक चलने वाले 75 दिनों के इस बड़े कैंपेन के तहत तृणमूल कांग्रेस बंगाल के हर हिस्से को कवर करने की योजना बनाई है। 75 दिनों के इस कैंपने में तृणमूल के 75 हजार से ज्यादा नेता, पांच लाख के करीब जमीनी कार्यकर्ता कुल 21 हजार से ज्यादा मीटिंग करेंगे और इस दौरान तकरीबन 41 हजार किलोमीटर की यात्रा पूरे बंगाल में की जाएगी। पार्टी का अनुमान है कि इस दौरान सवा लाख के करीब नए लोग तृणमूल से जुड़ेंगे और ये कैंपेन ढाई करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा।

तृणमूल ने चुनाव से पहले 'बंगाल का गौरव ममता' के नाम से बड़े कैंपेन की शुरुआत कर दी है। यह कैंपेन आज से शुरू होकर 10 मई तक चलेगा।

भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल काफी महत्वपूर्ण राज्य है। इसीलिए 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा लगातार बंगाल में मेहनत कर रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आगामी दो दिन माह में बंगाल में नगर निकाय चुनाव भी होने वाले हैं और तृणमूल का ये कैंपेन निकाय चुनाव पर भी काफी असर डाले इसी को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनावों से ही आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीतिक स्थिति का हाल पता चलेगा, परंतु अभियान पर अभियान से सियासी टकराव आने वाले समय में बंगाल में बढ़ने के पूरे आसार दिख रहे हैं। क्योंकि अब भाजपा भी एक इंच जमीन छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। इसीलिए अप्रैल से माह में तीन दिन और अक्टूबर से माह में सात दिन शाह बंगाल में रहेंगे। बंगाल में भाजपा बहुत मेहनत कर रही है। इसकी वजह भी है। उसे लगता है कि प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां उसके अनुकूल हैं। बीते लोकसभा चुनाव के नतीजों ने उसके इस भरोसे को और बढ़ाया है। वह ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरी है। बंगाल में कांग्रेस और वाममोर्चे की हालत खस्ता है। ऐसे में प्रदेश के मतदाताओं ने सत्ता में बदलाव की जरूरत समझी तो इसमें कोई दोराय नहीं कि इसका सबसे ज्यादा लाभ भाजपा को ही मिलेगा। इसीलिए पार्टी अपने को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने के लिए हरसंभव कोशिश करती नजर आ रही है।

उत्तराखंड

पलायन को रोकने की चिंता

उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है, मगर तस्वीर के दूसरे पहलू भी हैं। बदलाव के पक्षधरों और इसे धरातल पर उतारने वालों की कमी नहीं है, जिन्होंने उस धारणा को तोड़ा है कि पहाड़ में रहकर कुछ नहीं हो सकता। तरक्की की इबारत लिखने वाले यही 'चैंपियन्स ऑफ चेंज' अब सरकार को बताएंगे कि पलायन कैसे रुकेगा। प्रदेश सरकार ने उनके अनुभवों को एक अप्रैल से सर्वाधिक पलायनग्रस्त 245 गांवों में पलायन थामने को शुरू की जाने वाली कार्ययोजना में शामिल करने की ठानी है। इस कड़ी में 23 मार्च को देहरादून में पलायन आयोग के तत्वावधान में 'चैंपियन्स आफ चेंज' का सम्मेलन आयोजित करने को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी है।

जाहिर है चैंपियंस ऑफ चेंज के माध्यम से पलायन पर अंकुश लगाने की राज्य सरकार की सोच को सकारात्मक रूप में लिया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर यह एक अच्छा विचार है। उत्तराखंड में पलायन की स्थिति कितनी भयावह है, यह किसी से छिपी नहीं है। कहने में कतई संकोच नहीं कि राज्य में पलायन बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इसकी भयावहता का अंदाजा सरकारी आंकड़ों को देखकर लगाया जा सकता है। उत्तराखंड बनने के बाद अब तक सत्रह सौ से ज्यादा गांव पूरी तरह निर्जन हो चुके हैं। पांच सौ से ज्यादा गांव ऐसे हैं, जहां से

पलायन को लेकर सरकार का चिंतित होना स्वाभाविक है। सामरिक दृष्टि से भी इसको लेकर समय रहते प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।

प्रतीकात्मक फोटो

पचास फीसद से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं। वहां खड़े रह गए हैं सिर्फ उनके खंडहर में तब्दील आशियाने। चिंताजनक यह कि सिलसिला अभी थमा नहीं है। कोई शक नहीं कि पलायन आयोग के आंकड़े माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहे हैं। कारणों की तह में झांके तो मूलभूत सुविधाओं का टोटा मुख्य रूप से सामने आ रहा है। ऐसे में अगर सरकार पलायन को लेकर कुछ विचार कर रही है तो इसे अच्छी पहल के रूप में देखा जाना चाहिए।

सरकार कह रही है कि वह उन लोगों के माध्यम से, जो अपनी जड़ों से जुड़ कर कारोबार और रोजगार दोनों मोर्चों पर तरक्की की इबारत लिख रहे हैं, पलायन पर अंकुश लगाने का प्रयास करेगी। चार सौ से ज्यादा ऐसे लोग चिह्नित किए गए हैं, जिन्होंने अपनी कर्मठता और दृढ़निष्ठा के बूते अपना मुकाम बनाया है। ये वे लोग हैं जो सुविधाओं के अभाव में अपने घरों से दूर चले गए थे, लेकिन जड़ों से जुड़े रहे। अब वे रिवर्स पलायन कर पर्वतीय क्षेत्रों की आर्थिकी को संवार रहे हैं।

यही नहीं सरकार के एजेंडे में डेढ़ हजार से ज्यादा ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने पहाड़ में रहकर ही कामयाबी की नजीर पेश की। इन लोगों के माध्यम से पहाड़ में रोजगार की राह प्रशस्त करने की है सोच और विचार दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन सरकार को इस बात पर भी दृढ़ता दिखानी होगी कि केवल शुरुआत कर देने मात्र से पलायन नहीं रुकेगा। इन प्रयासों को शिद्दत के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसमें कोई बड़ी मुश्किल नजर नहीं आती है, बस इच्छाशक्ति जरूरी है। उम्मीद है सरकार चैंपियनों के बूते पलायन पर विराम लगाने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ेगी। नासूर बन रही इस समस्या का स्थायी समाधान तलाश करने के लिए सभी बुनियादी पहलुओं पर गौर करेगी।

पंजाब

मौत के मैनहोल

सड़क हादसों के मामले में पंजाब देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। इससे हर साल बहुत से लोगों की जान चली जाती है। इन हादसों के पीछे तेज गति, लापरवाही, नशे में वाहन चलाना जैसे कारण तो हैं ही, साथ ही खराब सड़कें भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। इससे भी भयावह यह है कि प्रदेश के लगभग हर जिले में कहीं न कहीं मैनहोल तक खुले पड़े रहते हैं। आए दिन इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है।

गत दिवस तो लुधियाना में एक निर्माणाधीन मैनहोल में बाइक समेत एक युवक गिर गया। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। निश्चित रूप से इसके लिए जो महकमा सबसे अधिक जिम्मेदार है वह नगर निगम ही है। जहां यह हादसा हुआ वहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। ऐसे में नगर निगम को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि निर्माणाधीन मैनहोल खुला न रहे, लेकिन शायद किसी को यह चिंता नहीं थी कि इसमें गिरकर किसी की जान भी जा सकती है। ऐसा तब है जबकि ऐसे कई हादसे प्रदेश भर में हो चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निगम को न तो किसी की चिंता है और न ही कानून का भय।

प्रतीकात्मक फोटो

लुधियाना में हुई घटना के बाद पुलिस ने निगम ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इतने भर से काम चलने वाला नहीं है। यह देखना होगा कि आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा?

कदाचित यही कारण है कि प्रदेश भर में जीटी रोड से लेकर मोहल्लों तक में क्षतिग्रस्त मैनहोल आसानी से देखे जा सकते हैं। लुधियाना में हुई घटना के बाद पुलिस ने निगम ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इतने भर से काम चलने वाला नहीं है। निगम को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीरता बरतनी होगी। जब भी कोई हादसा होता है तो कुछ दिन सक्रियता दिखाई देती है, लेकिन इस समस्या के स्थायी हल की शायद किसी को कोई चिंता नहीं है। निगम को चाहिए कि वह ठेकेदारों पर सख्ती बरते और उनके काम की कड़ी निगरानी करे।

सरकार को भी यह देखना होगा कि आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? उसे निगम के साथ मिलकर इसका हल ढूंढना चाहिए, साथ ही निगम कर्मियों को जिम्मेदार व जवाबदेह बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाना चाहिए।

झारखंड

सरकारी अस्पताल में प्रसव

आमतौर पर राजनीतिक-प्रशासनिक अमले से एक शिकायत यह भी होती है कि वे स्वयं सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग से परहेज करते हैं। इस धारणा के उलट झारखंड के गोड्डा सदर अस्पताल में जिले की उपायुक्त द्वारा अपना प्रसव कराना चर्चा में है। यह बहुत स्वाभाविक भी है। ऐसा इसलिए, क्योंकि सरकारी अस्पताल की सेवा पर भरोसा जताकर जहां उन्होंने नजीर पेश की है, वहीं आम लोगों को यह संदेश भी दिया है कि अगर सरकारी अस्पताल में सुविधाएं मौजूद हैं तो अंधी दौड़ में शामिल होकर महंगे निजी अस्पतालों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। झारखंड के लोगों के लिए यह संदेश इसलिए भी अहम है, क्योंकि आधे से अधिक लोग गरीब हैं और 37 फीसद लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करते हैं। इलाज के चक्कर में कई बार उनके घर-बार तक बिक जाते हैं। इससे भी बड़ी आपदा उन पर तब आती है जब सब कुछ दांव पर लगाने के बावजूद वे प्रियजनों की जिंदगी बचाने में कामयाब नहीं हो पाते।

सरकारी अस्पतालों की गुणवत्ता सुधारकर ही हम इनके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा सकते हैं। शासन-प्रशासन को इसे चुनौती के रूप में लेना चाहिए।

गरीबी के अलावा अशिक्षा और जागरूकता का अभाव भी लोगों का अहित करता है। शिक्षित और जागरूक न होने की वजह से भोले-भाले लोग आसानी से किसी की भी बातों में आ जाते हैं और कभी दलालों के तो कभी झोलाछाप डॉक्टरों और कभी निजी नर्सिंग होम संचालकों के चंगुल में फंस जाते हैं। हालांकि कई और भी पहलू हैं जिन पर हमें विचार करना होगा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि रसूखदार और संपन्न होने के बावजूद डीसी किरन कुमारी पासी ने सरकारी अस्पताल में अपना प्रसव कराकर एक उदाहरण पेश किया है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सरकारी अस्पतालों की सेवा पर एक बड़ा तबका भरोसा क्यों नहीं कर पाता। बजट का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करने के बाद भी हम अपने अस्पतालों की व्यवस्था और सेवा-सुविधा को इतना सुदृढ़ और गुणवत्तापूर्ण क्यों नहीं बना पाए हैं कि लोगों को निजी क्षेत्र की ओर रुख ही न करना पड़े।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि नेता, मंत्री, अधिकारी और अन्य सक्षम एवं प्रभावशाली लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने लगेंगे तो आम लोगों की भी इस ओर रुचि बढ़ेगी, साथ ही व्यवस्था भी सुधरेगी। यह भरोसा गुणवत्ता से जुड़ा है और इस कसौटी पर सरकारी अस्पतालों को खरा उतरना होगा। शासन-प्रशासन सबको इसके प्रति गंभीर होना होगा। हमारे ही देश के कई शहरों में ऐसे भी शानदार सिविल अस्पताल मौजूद हैं, जहां की सेवा पर लोगों को भरोसा है। अमीर-गरीब सभी वहां इलाज कराते हैं। हमें भी अपनी सेवा और गुणवत्ता के स्तर को वहां तक पहुंचाना होगा। इसके लिए कई स्तरों पर प्रयास करने होंगे। प्रशासन की जवाबदेही के साथ ही जनता में भी जागरूकता का प्रसार करना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल महज मजबूर लोगों के ठिकाने बनकर रह जाएंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह स्थिति न बने और सरकारी स्कूल एवं अस्पताल अपनी सार्थकता को सिद्ध करें।

झारखंड के पूर्व सीएम मरांडी के बेटे समेत 37 की हत्या में कोई 'कसूरवार' नहीं

दिलीप सिन्हा, गिरिडीह

तेरह साल गुजर चुके हैं। गिरिडीह जिले के चिलखारी गांव में झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बेटे अनूप मरांडी समेत 20 निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करने के मामले में अभी तक कोई कसूरवार साबित नहीं हो सका है। यह सिर्फ एक बानगी है। 15 साल पहले भेलवाघाटी नरसंहार में 17 लोगों को बेरहमी से मारा गया था। अदालत से कोई दोषी घोषित नहीं हुआ है अब तक। सीएम के बेटे की हत्या में जीतन मरांडी समेत चार लोगों को गिरिडीह की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। आरोपित पक्ष अपील में झारखंड हाईकोर्ट गए। सबूतों को पर्याप्त नहीं मानते हुए हाईकोर्ट ने फांसी की सजा रद कर आरोपितों को रिहा कर दिया। दोनों नरसंहार में पुलिस एक दर्जन से अधिक आरोप पत्र अदालत में दे चुकी है। दरअसल, माओवादियों की ओर से अंजाम दी गई ऐसी वारदातों में पुलिस तगड़े साक्ष्य तक इकट्ठा नहीं कर पाती है।

गिरिडीह जिले के चिलखारी में 26 अक्टूबर 2007 को संथाली यात्रा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी समेत 20 लोगों की

चिंताजनक

- **निचली अदालत ने चार लोगों को सुनाई थी फांसी, हाईकोर्ट से बरी**
- **17 लोगों की हत्या में भी कोई अभी तक घोषित नहीं हुआ दोषी**

केस का अभी भी अनुसंधान हो रहा है। पुलिस दोषियों को सजा दिलाने की कोशिश में लगी है।
नवीन कुमार, एसडीपीओ, खोरीमहुआ।

हत्या हुई थी। इससे पहले भेलवाघाटी में 11 सितंबर 2005 को घरों से निकालकर 17 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया गया था। चिलखारी कांड में रंगकर्मी जीतन मरांडी समेत चार को गिरिडीह की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने इन चारो को रिहा किया था। हालांकि कुछ माओवादियों पर अभी भी मुकदमा चल रहा है। इस कांड में शामिल चिराग दा समेत कई नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। एक अभियुक्त सिदो कोड़ा की पुलिस हिरासत में मौत हो चुकी है। एक अभियुक्त नक्सली नेता सुरंग यादव ने बिहार में सरेंडर किया है। सहदेव मांझी उर्फ परवेज दा उर्फ अनुज दा, नेमचंद महतो उर्फ साकेत को पुलिस ने इस कांड में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हालांकि किसी को भी पुलिस दोषी नहीं ठहरा सकी।

गवाहों के होस्टाइल होने से हो गए बरी : चिलखारी कांड में जिन गवाहों के भरोसे अभियोजन पक्ष था, उनमें अधिकांश अदालत में होस्टाइल हो गए। नतीजा चिलखारी नरसंहार के 10 अभियुक्त बरी हो गए हैं। इनमें जीतन मरांडी, मनोज रजवार, छत्रपति मंडल, अनिल राम, हाफिज, टूपलाल यादव, सीताराम तुरी, रामसहाय दास, मांगू किस्कू एवं किशुन रजवार शामिल हैं। इसके अलावा विवेक यादव, विनोद उर्फ अल्बर्ट हांसदा, सुनील उर्फ बड़का एवं जीतन किस्कू को जमानत मिल चुकी है। जमानत पर जेल से बाहर निकलने पर विवेक की हत्या भी हो चुकी है। भेलवाघाटी नरसंहार में भी किसी को अभियोजन पक्ष सजा नहीं दिला सका है, क्योंकि इस मामले में भी सटीक साक्ष्य पुलिस नहीं इकट्ठा कर सकी।

चिलखारी नरसंहार को गिरिडीह की अदालत ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की श्रेणी का माना। कुछ स्थानीय लोगों ने चार आरोपितों की पहचान की थी। उस आधार पर सजा दी गई थी।

समान नागरिक संहिता केंद्र से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने सुनवाई 23 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

मालूम हो कि इससे पहले पीठ ने इस संबंध में संसद को कोई निर्देश जारी करने से इन्कार कर दिया था। कहा था कि यह मामला विधान मंडल से जुड़ा है और अदालत इसमें हस्तक्षेप करने नहीं करेगी। हालांकि, मुख्य पीठ ने अब सभी याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि वह सभी की जिरह सुनेगी।

अधिवक्ता व याचिकाकर्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने सबसे पहले यूसीसी बनाने संबंध में जनहित याचिका दायर करने के संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की थी। इसके अलावा देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के पड़पोते व मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू यूनिवर्सिटी के कुलपति फिरोज बख्त अहमद, सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार अंबर जैदी ने भी जनहित याचिका दायर की है। इनकी दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी के पक्ष में कई फैसले दिए हैं, लेकिन सरकार ने इस दिशा में आज तक कुछ नहीं किया।

सुखना कैचमेंट के नुकसान की भरपाई को हरियाणा-पंजाब करें सौ-सौ करोड़ जमा

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि हरियाणा व पंजाब सरकार की नीतियों के कारण सुखना कैचमेट को नुकसान हुआ है। इसलिए दोनों राज्य इस नुकसान की भरपाई के लिए सौ-सौ करोड़ रुपये तीन महीने में केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय को जमा कराएं। कोर्ट ने इस राशि को सुखना लेक और कैचमेंट एरिया के संरक्षण पर खर्च करने को कहा है। जस्टिस राजीव शर्मा एवं जस्टिस एचएस सिद्धू की खंडपीठ ने हाई कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान का निपटारा करते हुए यह आदेश दिए। अपने 148 पेज के आदेश में कोर्ट ने 21 सितंबर 2004 में सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में तय कैचमेंट एरिया को स्वीकार करते हुए पूरे एरिया में हुए सभी निर्माणों को तीन महीने में गिराने के भी आदेश दिए हैं।

नया गांव और मनसा देवी का मास्टर प्लान रद : हाई कोर्ट ने कहा कि जिन्होंने यहां निर्माण की स्वीकृति ली हुई थी, उसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ किसी अन्य वैकल्पिक जगह पर बसाएंगे। इन सभी को 25-25 लाख मुआवजा भी संबंधित सरकारों को देना होगा। इसके साथ ही

फैसले के अंत में श्री गुरुग्रंथ साहिब के शबद का हवाला

जस्टिस राजीव शर्मा ने श्री गुरुग्रंथ साहिब के शबद पवन पानी धरती आकाश घर मंदर हर बानी के साथ अपने फैसले का समापन किया जिसके अनुसार वायु, जल, पृथ्वी और आकाश यह ईश्वर का घर है और यही मंदिर है। अपने फैसले में जस्टिस राजीव शर्मा ने कहा कि सुखना लेक एक कानूनी व्यक्ति/हैसियत है जिसके अपने अधिकार हैं और जिसे संरक्षित किया जाना जरूरी है और चंडीगढ़ का प्रत्येक निवासी इसका अभिभावक है, जिसे सुखना लेक का संरक्षण करना है।

हाई कोर्ट ने नया गांव और मनसा देवी के मास्टर प्लान को रद करते हुए सर्वे ऑफ इंडिया में तय कैचमेंट एरिया को स्वीकार कर लिया है।

हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दे दिए हैं कि वह सुखना लेक के एक किलोमीटर के दायरे को ईको-सेंसेटिव जोन घोषित करे। यह एरिया जो पंजाब और हरियाणा दोनों में पड़ता है। वहीं, चंडीगढ़ प्रशासन को तीन महीने में सुखना लेक को वेटलैंड घोषित किए जाने के आदेश दिए हैं। साथ ही पंजाब और हरियाणा को भी अपने एरिया में पड़ने वाले कैचमेंट एरिया को सुखना वेटलैंड घोषित कर तीन महीनों में नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए हैं।

अधिकारियों पर गिरेगी गाज : हाई कोर्ट के इस आदेश से उन अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है जिन्होंने मार्च 2011 में हाई कोर्ट की रोक के बावजूद यहां निर्माण की इजाजत दी है। हाई कोर्ट ने दोनों सरकारों को एसआइटी गठित कर ऐसे अधिकारियों की पहचान कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

सुखना लेक का दायरा 100 से 150 हेक्टेयर करने के आदेश : हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दे दिए हैं कि वह सुखना लेक का दायरा बढ़ाकर 100 से 150 हेक्टेयर करे, इसके लिए चाहे और खोदाई की जरूरत हो तो वह की जाए और लगातार री-सिल्टिंग की जाए ताकि सुखना लेक को बचाया जा सके। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा को आदेश दिए हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि कांसल, कैंबवाला और सकेतड़ी की ओर से लेक तक सीवर का पानी न आने दे। साथ ही सुखना से जलीय वनस्पति को छह महीनों में साफ करने के आदेश दे दिए हैं।

अब बनारस में भी होगा गोकाष्ठ से दाह संस्कार

धनंजय प्रताप सिंह, भोपाल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से शुरू हुआ गोकाष्ठ (गाय के गोबर की लकड़ी) से दाहसंस्कार और होलिका दहन का चलन अब बनारस भी अपनाएगा। भोपाल की पर्यावरण प्रेमी एक समिति के प्रयासों से अब तक नौ हजार दाह संस्कार गोकाष्ठ से हो चुके हैं। इससे 50 एकड़ की हरियाली बचाए जाने का अनुमान है। गौरतलब है कि यदि दाहसंस्कार में लकड़ी का उपयोग होता तो पेड़ों पर आरी चलती।

समिति के मुताबिक बीते साल भोपाल में तीन हजार होलिकाएं गोकाष्ठ से दहन की गई थीं। इस बार पांच हजार होलिकाओं का दहन गोकाष्ठ से किया जाएगा। समिति की यह पहल बनारस व दिल्ली नगर निगम को भी रास आ रही है। दोनों शहरों में समिति के सदस्यों को आमंत्रित किया गया है।

समिति चला रही है अभियान : भोपाल के पर्यावरण प्रेमियों द्वारा गठित 'गोकाष्ठ संवर्द्धन एवं पर्यावरण संरक्षण समिति ' गत 16 माह से इसमें जुटी है। समिति मप्र के कई जिलों में इस गोकाष्ठ का उपयोग बढ़ाने के लिए अभियान चला रही है।

गो काष्ठ समिति के अध्यक्ष अरुण चौधरी (बाएं), डॉ. योगेंद्र सक्सेना (बीच में)। फोटो : सौजन्य

पिता की अंत्येष्टि से ली प्रेरणा : डॉ. योगेंद्र कुमार सक्सेना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। दो साल पहले उनके पिताजी की मृत्यु हुई तब उन्होंने उनका लकड़ी से दाह संस्कार किया। यहीं से उन्हें प्रेरणा मिली कि क्यों न दाह संस्कार के लिए गाय के गोबर से बनी लकड़ियों का उपयोग किया जाए।

चंदा कर गोशाला में लगाई मशीन : डॉ. सक्सेना ने भोपाल के श्मशान घाट में संपर्क किया। उन्हें विश्रामघाट समिति से जुड़े समाजसेवी अरुण चौधरी, प्रमोद चुघ, हेमंत अजमेरा सहित कुछ लोग मिले। यहीं से गोकाष्ठ का सफर शुरू हुआ। सभी ने 10-10 हजार रुपये का चंदा इकट्ठा किया और नजदीक स्थित रामकली गोशाला में गोकाष्ठ बनाने की मशीन लगा दी। यह प्रयोग सफल रहा और पिछले साल ही इस गोशाला को विश्रामघाट समिति ने 27 लाख रुपये का भुगतान किया।

एक दाह संस्कार में एक पेड़ की बलि : वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. सक्सेना कहते हैं कि एक दाह संस्कार के लिए चार से पांच क्विंटल लकड़ी लगती है, जिसके लिए एक हरे-भरे पेड़ की बलि दी जाती है। लेकिन, गोकाष्ठ से अंत्येष्टि में मात्र ढाई क्विंटल में ही दाह संस्कार हो जाता है। यह लकड़ी की तुलना में ज्यादा होती है और सस्ती भी पड़ती है। भोपाल की तर्ज पर काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट समेत गंगा किनारे के अन्य श्मशान घाटों पर दाह संस्कार के लिए लकड़ी के बजाय गोकाष्ठ का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए बनारस नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी है। वाराणसी नगर निगम आयुक्त गौरांग राठी ने भोपाल की समिति के सदस्यों को होली के बाद बनारस बुलाया है। उनसे चर्चा कर गोकाष्ठ से दाह संस्कार का ब्लू प्रिंट तैयार किया जाएगा।

बनारस की महापौर मृदुला जायसवाल ने कहा कि इस दिशा में पहले से नगर निगम ने कदम बढ़ा दिया है। कान्हा उपवन में गोवंशों के गोबर से गोकाष्ठ बनाने का प्लांट लगा दिया गया है।

बघेल की करीबी उपसचिव के घर की सील तोड़कर की जांच

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया रायपुर स्थित अपने आवास पर छापा मारने पहुंची आयकर की टीम से बात करती हुईं। .नई दुनिया

नईदुनिया, रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकार के करीबी नेताओं, वरिष्ठ नौकरशाहों और शराब व रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों पर आयकर विभाग की छापेमारी से राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। छापेमारी को लेकर सोमवार को विधानसभा में हंगामा भी हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तीखी नोकझोंक के बीच पांच मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस बीच तीन बाद सामने आईं मुख्यमंत्री की करीबी उपसचिव सौम्या चौरसिया के यहां आयकर टीम ने घर की सील तोड़कर जांच की। दोपहर करीब बारह बजे पहुंची टीम ने उनके सामने ही जांच शुरू की। इस दौरान सौम्या के घरेलू सहायकों और वाहन चालक से अलग से पूछताछ भी की गई।

सौम्या के बंगले की जांच करने 16 अधिकारियों की टीम पहुंची। जांच टीम अपने साथ स्कैनर भी लेकर आई थी।

मुंबई में कल तय होंगी आईफा अवार्ड समारोह के टिकटों की कीमतें

नईदुनिया, इंदौर: मध्य प्रदेश में होने वाले प्रतिष्ठित आईफा अवार्ड समारोह के टिकटों की कीमतें बुधवार को तय होंगी। इसके लिए आयोजक कंपनी विजक्राफ्ट की मुंबई में बैठक बुलाई गई है। बैठक के ठीक बाद कीमतों की घोषणा होगी। दर्शक बुक माय शो के जरिये ऑनलाइन टिकट खरीद सकेंगे।

समारोह में बॉलीवुड की कौन-कौन बड़ी हस्तियां शामिल होंगी, उनके नाम भी कंपनी बताएगी। बड़ी फिल्म हस्तियों में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, शाह रुख खान, काजोल, शाहिद कपूर के नाम शामिल होने की उम्मीद। अमिताभ बच्चन भी समारोह में आ सकते हैं। समारोह के होस्ट सलमान खान और जैकलिन फर्नांडीस हैं, जबकि शो के बीच में कुछ हास्य कलाकार दर्शकों को गुदगुदाएंगे। चार मार्च को मुंबई में बैठक के बाद टिकटों की बिक्री भी शुरू हो सकती है। अलग-अलग श्रेणी के हिसाब से टिकट की दरें रहेंगी। आईफा अवार्ड समारोह को लेकर सोशल मीडिया पर आयोजक कंपनी विजक्राफ्ट ने ब्रांडिंग शुरू कर दी है।

33 लाख टन अनाज की पैदावार कावेरी डेल्टा की 28 लाख एकड़ भूमि पर सालाना होती है और तमिलनाडु राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है।

हरियाणा में16 एकड़ के खेत से कमा रहे 45 लाख रुपये

प्रेरणा... ▶ जींद निवासी किसान सतबीर की सफलता की कहानी, जिन्हें अब लोग 'बेर वाले अंकल' कहते हैं

विजेंद्र मलिक, जींद

हरियाणा के गांव अहिरका निवासी किसान सतबीर पूनिया को अब लोग बेर वाले अंकल के तौर पर पहचानते हैं। पानी की किल्लत से जूझ रहे जींद जिले के इस इलाके में अतिरिक्त आय के लिए उन्होंने जो उपाय किया, वह क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन गया है। अपनी सूझबूझ से उन्होनें उपलब्ध पानी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए बागवानी में हाथ आजमाए। पारंपरिक कृषि के मुकाबले अब सतबीर कई गुना अधिक अर्जित कर रहे हैं। सालाना कमाई 45 लाख रुपये तक पहुंच गई है। अब तो दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं।

गरीबी उन्मूलन

57 साल के सतबीर के पास 16 एकड़ जमीन है। पारंपरिक कृषि करते आए थे। लेकिन पानी की कमी, लागत अधिक और मुनाफा मनमाफिक न होने के कारण उन्होंने खेती करना छोड़ दिया।

वैकल्पिक कृषि से पाई समृद्धि

- अतिरिक्त आय के लिए लगाए गए बाग ने बदल दी सतबीर की किस्मत
- पानी की किल्लत वाले इलाके में सूझबूझ से पाई सफलता

अपने खेत ठेके पर दे देने लगे और आजीविका के लिए खुद दूसरा व्यवसाय करते। लेकिन जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहते सुना कि फलों और बागवानी इत्यादि के जरिये कृषि के वैकल्पिक उपायों को आजमाकर किसान समृद्धि की राह पकड़ सकते हैं। तब सरकार के कृषि जागरूकता कार्यक्रमों में उन्होंने इस बारे में विस्तार से जाना। तय किया कि पारंपरिक कृषि के इतर अतिरिक्त मुनाफा कमाने के लिए वह भी अपने खेत में बागवानी शुरू करेंगे।

सतबीर बताते हैं, अप्रैल 2017 में पांच एकड़ में थाई एप्पल प्रजाति के बेर, आठ एकड़ में उन्नत किस्म के अमरूद और दो एकड़ में नींबू लगाए। फसल अच्छी आई और बाजार भी अच्छा मिल गया। अब तो बागवानी से साल भर में 45 लाख रुपये तक कमा रहे हैं। बाग के अंदर ही सब्जियों की भी खेती करते हैं।

अपने बाग के बेर दिखाते सतबीर। जागरण

सतबीर ने बताया, जब बेर का बाग लगाना शुरू किया, तब परिवार और आसपास के लोग कहते कि खेत में यह क्या झाड़-झंखाड़ लगा दिए, इससे क्या होगा। लेकिन आज आसपास के गांवों के किसान भी मेरे बाग को देखने के लिए आते हैं...।

सतबीर के उत्पादों की मांग जींद सहित आसपास के जिलों और कुछ दूरस्थ बड़ी मंडियों-बाजारों तक भी है। बागवानी के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए बीते साल हरियाणा के कृषि मंत्री उन्हें सम्मानित कर चुके हैं।

ऐसे किया पानी का इंतजाम...

जींद में भूमिगत पानी की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। इससे निपटने के लिए सतबीर ने नहर के पानी को स्टोर करने के लिए 21 लाख लीटर पानी क्षमता का टैंक बनाया। सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम से पूरे खेत में सिंचाई करते हैं। महीने में एक बार ही नहर का पानी आता है। टैंक में स्टोर पानी से पूरे महीने सिंचाई का काम चल जाता है। इससे सिंचाई की लागत का खर्च भी न के बराबर है।

20 को दिया रोजगार

सतबीर ने 20 लोगों को रोजगार भी दिया है। खेत में पौधों की छंटाई, निराई का काम गांव व आसपास के गांवों की महिलाएं करती हैं। वहीं बाजार में लगाए गए अपने स्टाल पर फल बेचने के लिए भी उन्होंने लोगों को काम दिया है।

केवल मंडी पर निर्भर नहीं

सतबीर फल बेचने के लिए केवल मंडी पर निर्भर नहीं हैं। उन्होंने शहर में खुद भी पांच-छह जगह स्टाल लगाए हैं। सतबीर बताते हैं कि आमतौर पर बेर 15 मार्च के आसपास बाजारों में आता है, मगर थाई एप्पल बेर का उत्पादन जनवरी में ही शुरू हो जाता है। जींद व आसपास के बाजारों में सतबीर का ही माल बिक रहा है। प्रतिस्पर्धा न होने के कारण 50 रुपये किलो तक दाम मिल रहे हैं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

रणथंभौर सेंचुरी के लिए फिर शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग

जागरण संवाददाता, जयपुर : वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान के रणथंभौर एवं सरिस्का सेंचुरी के साथ ही जयपुर स्थित झालाना नेचर पार्क के लिए ऑनलाइन बुकिंग सोमवार से फिर शुरू कर दी गई है। पिछले सप्ताह 15 दिन के लिए बुकिंग बंद कर दी गई थी, लेकिन वन्यजीव प्रेमियों एवं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के दबाव के बाद इस निर्णय को बदल दिया गया है।

वन विभाग ने पिछले सप्ताह दो से 16 मार्च तक ऑनलाइन बुकिंग पर रोक लगा दी थी। अधिकारिक रूप से तो यह कहा गया था कि मार्च के दूसरे सप्ताह में जयपुर में वन एवं पर्यावरण से जुड़ी बड़ी कांफ्रेंस होने के कारण बड़ी संख्या में देशी-विदेशी प्रतिनिधि रणथंभौर एवं सरिस्का भ्रमण के लिए आएंगे, जिनके लिए वाहनों को आरक्षित रखना जरूरी होगा।

वन विभाग प्रति पारी 36 वाहनों को भ्रमण की अनुमति देता है। ऐसे में इतने वाहनों की आवश्यकता तो अकेले प्रतिनिधियों के लिए ही होगी। इस कारण पर्यटकों को भ्रमण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस वजह से ऑनलाइन बुकिंग पर रोक लगाई गई थी। जिसे सोमवार को फिर खोल दिया गया है।

निजी स्कूलों को मात दे रहा है धनवार का सरकारी विद्यालय

- अभिभावकों के साथ जिला उपायुक्त भी हुए बदलाव के कायल
- इस मॉडल स्कूल की प्रबंधन समिति, बाल संसद व शिक्षकों को सोशल मीडिया में मिल रही हैं बधाइयां
- स्कूल की दीवारों पर स्वच्छता का संदेश देती चित्रकारी के साथ-साथ यहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी है उपलब्धता

स्कूल बैग के साथ गिरिडीह के धनवार के मध्य विद्यालय डोरंडा के विद्यार्थी। जागरण

दिलीप सिन्हा, धनवार (गिरिडीह)

हर अभिभावक की चाहत होती है कि उनके बच्चे गुणात्मक शिक्षा हासिल कर जिंदगी में सफलता के परचम लहराएं। सामान्य तौर पर ऐसे हजारों अभिभावक अपने बच्चों को अपनी क्षमता के हिसाब से सरकारी स्कूलों की बजाए निजी स्कूलों दाखिला दिलाते हैं। शिक्षा को लेकर ऐसे अभिभावकों के मन में सरकारी विद्यालयों के प्रति धारणा कुछ अच्छी नहीं होती। गिरिडीह के धनवार स्थित मध्य विद्यालय, डोरंडा इस मिथक को तोड़ रहा है।

यह स्कूल किसी भी मायने में निजी स्कूल से कम नहीं है। कई मामलों में यह निजी विद्यालयों को भी मात दे रहा है। मॉडल स्कूल का स्वरूप ले चुके इस विद्यालय के कायल न सिर्फ बच्चों के अभिभावक हैं, बल्कि गिरिडीह के उपायुक्त ने भी इसकी जमकर प्रशंसा की है। उन्होंने ट्विटर पर स्कूल की प्रबंधन समिति, बाल संसद व शिक्षकों को इसके लिए बधाई भी दी है।

इस विद्यालय में अन्य विद्यालयों से क्या है अलग : इस विद्यालय का अपना दो मंजिला भवन है, जहां छात्र-छात्राओं के लिए चार-चार साफ-सुथरा शौचालय, शानदार गार्डेनिंग, स्कूल की दीवारों पर स्वच्छता का संदेश देती चित्रकारी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, शुद्ध पेयजल, हैंड वाश यूनिट सहित जगह-जगह पर डस्टबीन की उपलब्धता है।

मॉडल रसोई, पीने को मिनरल वाटर : इस विद्यालय की रसोई आसपास के विद्यालयों के लिए आदर्श है। मध्याह्न भोजन तैयार करने में जुटी द्रौपदी देवी, अर्चना देवी एवं नीतू देवी कुकिंग ड्रेस पहनकर कुकिंग गैस पर भोजन तैयार करती है, जिसमें स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाता है। भोजन से पूर्व और भोजन के बाद साबुन से हाथ धोना विद्यालय प्रबंधन ने अनिवार्य कर रखा है। भोजन के लिए टेबल और पीने के लिए मिनरल वाटर की यहां उपलब्धता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आस-पास के क्षेत्र में इस तरह का कोई सरकारी स्कूल नहीं है। यह स्कूल के शिक्षकों की मेहनत का कमाल है कि आज यह स्कूल की ख्याति इतनी बढ़ गई है कि दूर-दूर से लोग इसे देखने आते हैं।

283 बच्चे, आठवीं का परिणाम शत फीसद

विद्यालय में कुल 283 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। लगभग हर विषयों के शिक्षक यहां उपलब्ध हैं। आठवीं तक की यहां पढ़ाई होती है। विद्यालय में कुल 10 कमरे और सात शिक्षक हैं। परिणाम की बात करें तो पिछले साल आठवीं के सभी छात्र सफल हुए थे।

एक युवा शिक्षक ने बदल दी तस्वीर : मौजूदा प्रभारी प्रधानाध्यापक पवन कुमार का पदस्थापन 24 मार्च 2018 को यहां हुआ था। उन दिनों स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसे में धनवार के तत्कालीन एरिया अफसर एमके पांडेय ने सबसे जूनियर शिक्षक पवन कुमार को इस विद्यालय का प्रभार सौंपा। आज विद्यालय की स्थिति बदली-बदली सी है।

खुलेंगे सिनेमाघर, कश्मीर में गूंजेगा लाइट-कैमरा-एक्शन...

जागरण विशेष ▶ सरकारी प्रयास तेज, फिल्मों की शूटिंग इसी साल से शुरू हो जाने की उम्मीद

रजिया नूर, श्रीनगर

कश्मीर को बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग का हब बनाने के सरकारी प्रयास तेज हो चुके हैं। साथ ही कश्मीर के बंद पड़े सिनेमाघरों को भी जल्द खोले जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इसी साल यह प्रयास रंग लाते दिखेंगे। इसका सबसे अधिक लाभ स्थानीय युवाओं को देने का खाका बन चुका है।

बीते दिनों केंद्र सरकार के आउटरीच कार्यक्रम में कश्मीर दौरे पर पहुंचे गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने घोषणा की थी कि कश्मीर को फिल्म उद्योग के जरिये भी रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान मुंबई का दौरा कर फिल्म निर्माताओं को जम्मू कश्मीर आने का न्योता दे चुके हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मामलों के केंद्रीय राज्यमंत्री मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय ने भी जनवरी में कश्मीर दौरे पर स्थानीय युवाओं को फिल्म निर्माण से जुड़ी विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित करने का यकीन दिलाया। उनके आश्वासन के बाद केंद्रीय मंत्रालय से जुड़े दो वरिष्ठ अधिकारी कश्मीर घाटी का दौरा भी कर चुके हैं। उन्होंने उत्तरी कश्मीर में सेना द्वारा संचालित कौशल विकास केंद्र का भी दौरा किया जहां स्थानीय युवक फिल्म निर्माण से जुड़े काम सीख रहे हैं।

तारीफ करूं क्या उसकी...

- प्रशासन ने मुंबई जाकर फिल्म निर्माताओं को प्रदेश में आने का दिया है न्योता
- कश्मीर में बंद पड़े सिनेमाघरों को भी खोले जाने के हो रहे हैं प्रयास
- बॉलीवुड और टॉलीवुड ही नहीं पंजाबी फिल्म उद्योग से जुड़े लोग भी दिखा रहे हैं दिलचस्पी

स्थानीय लोगों में फिल्मों को लेकर क्रेज रहा है। वादी में डेढ़ दर्जन सिनेमाघर थे। आतंकी हिंसा के चलते बॉलीवुड कश्मीर से दूर हो गया, लेकिन स्थानीय लोगों का फिल्मों से मोह बना रहा। स्थानीय फिल्मकारों ने सीमित साधनों से कश्मीर में फिल्में बनाईं। कश्मीर के कई युवा फिल्मों में अपना भाग्य आजमाने मुंबई भी पहुंचे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद घाटी के माहौल में आए सकारात्मक माहौल के बीच फिर बॉलीवुड और टॉलीवुड ही नहीं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्रीज से जुड़े लोग कश्मीर में फिल्म शूटिंग के लिए आगे आने लगे हैं। एक साल के दौरान कश्मीर में तीन फिल्मों की शूटिंग हुई भी।

फिलहाल कश्मीर में सिनेमाघर भी बंद पड़े हैं। राज्य प्रशासन इन्हें खोलने के प्रयास में भी जुटा है। कुलमिलाकर, यदि सब कुछ ठीक रहा तो इसी वर्ष कई नामी प्रोडेक्शन हाउस बड़े फिल्मी सितारों के साथ कश्मीर में शूटिंग करते दिखेंगे। कश्मीर के फिल्म निर्माता-निर्देशक मुश्ताक अली अहमद खान खुश हैं कि कश्मीर में फिल्म संस्कृति को फिर जिंदा करने की जरूरत समझी गई है। बंद सिनेमाघरों के ताले खोले जाएंगे। लोगों को रोजगार और मनोरंजन मिलेगा।

युवा फिल्म निर्माता बिलाल जान का भी कहना है कि श्रीनगर में बंद पड़े सिनेमाघरों को शुरू करने में सरकार को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिनेमा शुरू होने से और शूटिंग से संबंधित संसाधन मुहैया हो जाने से श्रीनगर अपने आप में फिल्म सिटी बन जाएगा।

कश्मीर में हाईवे फिल्म की शूटिंग के दौरान ली गई एक तस्वीर। ट्विटर

स्थानीय फिल्म निर्माता अरशद ने कहा कि काफी कम व्यवसाय होने के बावजूद भी स्थानीय फिल्म निर्माता और निर्देशक क्षेत्रीय फिल्में बना रहे हैं। सरकार की योजना में वह भी भरपूर सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि घाटी के हजारों विद्यार्थियों ने मास कम्यूनिकेशन व फिल्म प्रोडेक्शन में डिग्री ले रखी है, लेकिन यहां इस क्षेत्र में बेहतर संसाधन उपलब्ध न होने से वह या तो देश के अन्य राज्यों में चले जाते हैं या फिर दूसरे क्षेत्र में रोजगार तलाशते हैं।

राज्य प्रशासन की तैयारियां तेज... : मुंबई में 21 फरवरी को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एसके मुर्मू के नेतृत्व में हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन में कश्मीर में फिल्म सिटी बनाने पर निवेशकों और फिल्म निर्देशकों ने रुझान दिखाया। इसके अलावा सिनेमा से संबंधित एक कंपनी की कश्मीर के हर जिले में सिनेमाघर खोलने की योजना है। इस संबंध में एक कंपनी से एमओयू भी साइन हुआ है। ये कंपनी मल्टीप्लेक्स सिनेमा खोलेगी। हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता-निर्देशक मधुर भंडारकर जम्मू कश्मीर में प्रोडक्शन हाउस और फिल्म इंस्टीट्यूट खोलने पर सहमति जता चुके हैं। हाल ही में फिल्म निर्माता साजिद नाडियावाला ने भी उपराज्यपाल मुर्मू से मुलाकात कर शूटिंग से संबंधित विषयों पर चर्चा की। टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी एक कंपनी भी यहां स्टूडियो खोलने की तैयारी में है। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद कश्मीर के युवाओं को रोजगार देना और भटकने से रोकना है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

बिहार में पानी को आर्सेनिक से मुक्ति का विकल्प बनेगा 'जलकल्प'

अजय पांडेय, समस्तीपुर

- फिल्टर में प्रयुक्त आयरन कील या छीलन आर्सेनिक को अवशोषित करने में सहायक

बिहार के आर्सेनिक प्रभावित इलाकों में जल शुद्धिकरण के लिए प्लांट लगाने की योजना तो बनी, मगर मूर्तरूप नहीं पा सकी। इन इलाकों में यह देसी तकनीक किसी वरदान से कम नहीं। इसका नाम है 'जलकल्प'। चार हजार कीमत वाला यह फिल्टर एक घंटे में 30 से 35 लीटर पानी साफ कर सकता है। बक्सर जिले में इसका सफल ट्रायल हो चुका है। आर्सेनिक प्रभावित समस्तीपुर में भी इसके उपयोग की तैयारी है।

सूबे के समस्तीपुर, भागलपुर, दरभंगा, बांका, पटना और बक्सर आर्सेनिक प्रभावित हैं। बिहार के कई जिलों में जलकल्प के परीक्षण का काम देख रहे धर्मेंद्र कुमार बताते हैं कि पिछले छह महीने से विभिन्न जिलों में ट्रायल चल रहा है। हाल ही में सबसे ज्यादा आर्सेनिक प्रभावित बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड में ट्रायल हुआ था। वहां पानी में 1750 पीपीबी (पार्ट पर बिलियन) तक आर्सेनिक पाई गई। जलकल्प से पानी साफ किया गया तो पीने योग्य हो गया। उसकी जांच आर्सेनिक पर काम करनेवाली बेंगलुरु केंद्रित संस्था साकी वाटर से कराई गई थी। यह संस्था महावीर कैंसर अस्पताल, पटना के साथ मिलकर आर्सेनिक प्रभावित जिलों में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसकी मदद से अब पूरे बिहार में पानी को पीने योग्य बनाया जा सकता है।

30 पीपीबी के बाद पड़ती लौह कील की जरूरत

पानी में अगर 30 पीपीबी तक आर्सेनिक की मात्रा है तो यह सामान्य तकनीक पर ही दूर हो जाती है। लेकिन, इससे ऊपर जाने पर लौह कील या छीलन की जरूरत पड़ती है। इसमें अनुपात का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए, मशीन लगाने से पहले आर्सेनिक की मात्रा की किट से जांची जाती है। फिलहाल, बक्सर में सफल ट्रायल के बाद इसे बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा।

कैसे हटाता है आर्सेनिक

जलकल्प को विकसित करनेवाले दिल्ली निवासी ललित मोहन शर्मा बताते हैं कि यह तकनीक बालू, जीरा रोड़ी, कॉपर प्लेट और आयरन के छिलके या कील पर आधारित है। स्टील के बॉक्स में इन्हें रखा गया है।

जलकल्प में जैविक, रासायनिक व भौतिक क्रियाएं पानी को जीवाणु रहित करती हैं। यह प्रक्रिया तीन लेयर पर काम करती है। आर्सेनिक हटाने के लिए इसमें छलनी के लेयर में लोहे की कील या छीलन को रखा जाता है। यह आर्सेनिक को अवशोषित कर लेता है।

आधी बची डल झील पर ड्रोन से रखेंगे नजर

डल झील। फाइल

- भू-माफिया, बढ़ती आबादी, सरकारी उदासीनता के कारण सिकुड़ रही झील
- अतिक्रमण के चलते 22 वर्ग किलोमीटर की झील अब रह गई है 11 वर्ग किलोमीटर की
- अतिक्रमण रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों का भी होगा इस्तेमाल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर की पहचान डल झील दुनियाभर की खूबसूरत झीलों में गिनी जाती है। भू-माफिया, अनियोजित शहरीकरण, बढ़ती आबादी और सरकारी उदासीनता के कारण यह झील लगातार सिकुड़ रही है। इसके संरक्षण को सुनिश्चित बनाने को अब ड्रोन से एरियल सर्वे किया जाएगा। झील के भीतरी और बाहरी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं।

झील का क्षेत्रफल जो कभी 22 वर्ग किलोमीटर था अब 11 वर्ग किलोमीटर ही रह गया है। हाउसबोटों, होटलों व लोगों के घरों से निकलने वाली गंदगी का अधिकांश हिस्सा इसी झील में समा रहा है, जिससे इसका पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गया है। डल का पानी पीने लायक नहीं रहा है। डल के संरक्षण को लेकर जम्मू-कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार ने भी कई योजनाएं शुरू, लेकिन उन्हें सिरे नहीं चढ़ते देख कई समाजसेवी संगठन अदालत पहुंचे। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय भी डल के संरक्षण को लेकर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है।

अदालत के हस्ताक्षेप के बाद संबधित प्रशासन झील के संरक्षण के लिए सक्रिय नजर आ रहा है। उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश पर डल संरक्षण के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लेक एंड वॉटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी (लावडा) ने झील के एरियल सर्वे का फैसला किया है। यह सर्वे लगभग एक माह चलेगा। सर्वे में डल के भीतरी और बाहरी हिस्सों को शामिल किया जाएगा।

अत्याधुनिक सेंसरों से लैस होंगे ड्रोन : लावडा के अधिकारियों ने बताया कि डल और नगीन झील के संरक्षण और प्रबंधन की समग्र योजना को अंतिम रूप देने के लिए एरियल सर्वे किया जाएगा। इसके लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी। यह ड्रोन में अत्याधुनिक वीडियो व डिजीटल कैमरों से लैस होगा। यह झील की मौजूदा स्थिति और झील के भीतर व साथ सटे इलाकों में जारी निर्माण गतिविधियों का रिकार्डिंग करेंगे। यह फोटोग्रमेटिक सर्वे होगा और इसके जरिए कंप्यूटर के माध्यम से एक डिजाइन एंड जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम मैप तैयार किया जाएगा। इस सर्वे के बाद हर छह महीने बाद ड्रोन के जरिए झील के भीतरी और बाहरी इलाकों में किसी प्रकार के नए निर्माण का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। इससे प्राप्त होने वाले डाटा का इस्तेमाल झील में होने वाले किसी भी नए परिवर्तन का पता लगाने के लिए होगा। डल के एरियल सर्वे के अलावा डल के भीतर और उसके साथ सटे प्रतिबंधित इलाकों में किसी प्रकार के निर्माण को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी इस्तेमाल किए जा जाएंगे। पहले चरण में पांच सीसीटीवी कैमरे झील के आसपास चिह्नित जगहों पर लगाए जाएंगे। बाद में इनकी संख्या बढ़ायी जाएगी।

असर

कैंपिंग साइट व बुग्यालों में रात्रि प्रवास पर हाई कोर्ट की रोक के बाद घटी पर्यटकों की आमद, वर्ष 2018 से पहले पहुंचते थे दस हजार से अधिक पर्यटक, वर्ष 2019 में यह संख्या घटकर 2725 रह गई

चमोली में लॉर्ड कर्जन ट्रैक पर जाने से परहेज कर रहे पर्यटक

रणजीत सिंह रावत, जोशीमठ (चमोली)

नैनीताल हाई कोर्ट के कैंपिंग साइट और बुग्यालों में रात्रि प्रवास पर रोक लगाए जाने के बाद पर्यटकों की तादाद में भारी कमी आई है। इसकी बानगी है चमोली जिले का लॉर्ड कर्जन ट्रैक। देश के दस खूबसूरत डेस्टिनेशन में शामिल क्वारी पास (कौरी पास) के इस ट्रैक पर वर्ष 2018 से पहले दस हजार से अधिक पर्यटक पहुंचते थे। लेकिन, वर्ष 2019 में यह संख्या घटकर 2725 रह गई, जो कि वर्ष 2018 के मुकाबले 2793 कम है। वर्ष 2018 में यह संख्या 5418 थी। इस ट्रैक पर पर्यटकों की आमद घटने का असर जिले के पर्यटन व्यवसाय पर भी पड़ा है।

चमोली जिले में वैसे तो कई पर्यटन स्थल हैं, लेकिन इनमें क्वारी पास से गुजरने वाले लॉर्ड कर्जन ट्रैक का खास महत्व है। ग्वालदम से तपोवन तक 200 किमी लंबा यह पैदल ट्रैक अपनी खूबसूरत लोकेशन और प्राकृतिक सुंदरता के कारण दुनियाभर में प्रसिद्ध है। इस ट्रैक पर पहले सालभर पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता था। लेकिन, अगस्त 2018 में उच्च हिमालय ने बुग्याली क्षेत्रों में रात्रि प्रवास को प्रतिबंधित कर दिया। तब से इस ट्रैक पर पर्यटक काफी कम संख्या में जा रहे हैं।

चमोली जिले में क्वारी पास के लार्ड कर्जन ट्रैक में पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार गिर रही है, जबकि यह देश के दस खूबसूरत डेस्टिनेशन में शामिल है। जागरण आर्काइव

पर्यटन विशेषज्ञ संजय कुंवर कहते हैं कि पर्यटन प्रदेश का सपना दिखाने वाली सूबे की सरकार अब तक इस मसले पर चुप्पी साधे हुए है। इसका खामियाजा पर्यटन कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि, जिला पर्यटन अधिकारी विजेंद्र पांडेय का दावा है कि हाई कोर्ट की रोक के बाद भी उच्च हिमालयी क्षेत्र के पर्यटन पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। नजदीकी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही लगातार हो रही है।

ये पर्यटन स्थल भी हैं पर्यटकों की खास पसंद : लॉर्ड कर्जन ट्रैक के अलावा चमोली जिले में ढकवाणी, सेनातोली, कालीघाट, झींझी, सेमखर्क, खुलारा, ताली, गेलगाड़, गोरसों कैंप जैसे बेहतरीन पर्यटन स्थल भी मौजूद हैं। इन पर्यटन स्थलों में बुग्यालों की खूबसूरती तो है ही, अधिकांश समय बर्फ जमी होने से पर्यटक यहां जहां सबसे ज्यादा पसंद करते हैं।

लॉर्ड कर्जन ने 1902 में बनवाया था यह ट्रैक : लॉर्ड कर्जन ट्रैक को विकसित करने का श्रेय ब्रिटिश भारत के वायसराय रहे लार्ड कर्जन को जाता है। कर्जन वर्ष 1902 में उत्तराखंड भ्रमण पर आए थे। यहां की सुंदरता से वे इस कदर अभिभूत हुए कि ग्वालदम से तपोवन पैदल ट्रैक का निर्माण करवा दिया। इसके पीछे उनका उद्देश्य देशी-विदेशी पर्यटकों को चमोली जिले के खूबसूरत पर्यटन स्थलों के करीब लाना था।

दिव्यांगों के कौशल विकास के लिए जल्द आएगी योजना

नई दिल्ली : सरकार दिव्यांगों के कौशल विकास के लिए नई योजना लाने की तैयारी में है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस योजना के जरिये दिव्यांग लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके उत्पादन को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। हस्तशिल्प और हाथ-करघे से निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी में गडकरी ने कहा कि यह योजना सामाजिक न्याय और आधिकारिता व कपड़ा मंत्रालय की देखरेख में कार्य करेगी। इस दौरान उन्होंने दिव्यांग जनों को बिना किसी गारंटी के कर्ज उपलब्ध कराने का वादा भी किया। (प्रेट्र)

एयर इंडिया जैसी कंपनी को खरीदने में किसी की भी रुचि स्वाभाविक है। विस्तारा एक संयुक्त उपक्रम है और उसी के तहत बोली लगाने पर विचार किया जाएगा।

— भास्कर भट
चेयरमैन, टाटा एसआइए

सेंसेक्स	38,144.02 ▼ 153.27	निफ्टी	11,132.75 ▼ 69	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 42,616 ▲ ₹391	चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 46,213 ▲ ₹713	$ डॉलर	₹ 72.74 ▲ ₹0.50	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 50.53

फिच ने देश का आर्थिक विकास दर अनुमान घटाया

- चालू वित्त वर्ष में 4.9 प्रतिशत वृद्धि दर की संभावना
- अगले वित्त वर्ष के लिए भी 5.4 प्रतिशत विकास दर का अनुमान

नई दिल्ली, प्रेट्र: फिच सॉल्यूशंस ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का आर्थिक विकास दर अनुमान घटाकर 4.9 प्रतिशत कर दिया। पहले इस एजेंसी ने 5.1 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया था। फिच ने कहा है कि कोरोना वायरस के असर से आपूर्ति गड़बड़ाने और घरेलू मांग कमजोर पड़ने के कारण आर्थिक वृद्धि घटने की आशंका है।

फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भी विकास दर का अनुमान 5.9 से घटाकर 5.4 प्रतिशत कर दिया है। एजेंसी ने भारत के परिदृश्य पर अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है, 'फिच सॉल्यूशंस वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि का अनुमान पहले घोषित 5.1 प्रतिशत से घटाकर 4.9 प्रतिशत कर रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भी इसे पहले के 5.9 प्रतिशत से घटाकर 5.4 प्रतिशत कर दिया गया है।

भारत की जीडीपी वृद्धि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर--दिसंबर, 2019) में घटकर 4.7 प्रतिशत रह गई। दूसरी तिमाही के संशोधित अनुमानों में यह 5.1 प्रतिशत बताई गई। हालांकि शुरुआती अनुमानों में दूसरी तिमाही की वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत बताई गई थी। सरकार के स्तर पर खपत धीमी रहने, सकल स्थायी पूंजी निर्माण में बड़ी गिरावट आने और शुद्ध निर्यात योगदान मामूली रहने की वजह से जीडीपी वृद्धि धीमी पड़ी है।

कुछ उम्मीदें भी

फिच सॉल्यूशंस ने 2020-21 में मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में सुधार आने की उम्मीद जताई है। एजेंसी ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि कृषि क्षेत्र में संभावनाएं बेहतर होने और अगले वित्त वर्ष के बजट में दिए गए वित्तीय समर्थन से आर्थिक गतिविधियों में सुधार आएगा।'

कई कच्चे माल के आयात शुल्क में कटौती की तैयारी

राहत ▶ जरूरी कच्चे माल के आयात शुल्क में कमी पर विचार जारी

फार्मा, ऑटो, टेक्सटाइल व मेडिकल उपकरण जैसे क्षेत्रों को राहत संभव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश में जरूरी चीजों की कमी एवं उनके दाम में बढ़ोतरी की आशंका को टालने के लिए सरकार कई कच्चे माल के आयात शुल्क में कटौती कर सकती है। चीन में फैले कोरोना वायरस की वजह से कई जरूरी वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल की कमी होने की आशंका है। इस वजह से उन वस्तुओं के दाम भी बढ़ सकते हैं। इनमें फार्मा, ऑटो पार्ट्स, खाद एवं उर्वरक, मेडिकल उपकरण, अकार्बनिक रसायन एवं टेक्सटाइल क्षेत्र के आइटम शामिल हैं। इन क्षेत्रों के लिए 60-70 फीसद कच्चे माल की आपूर्ति चीन से होती है।

उद्यमियों ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से चीन में अभी उत्पादन सुचारू नहीं हुआ है। अगर अगले महीने तक चीन कोरोना वायरस से उबर भी लेता है तब भी सामान्य गति से उत्पादन आरंभ होने

प्रतीकात्मक

में एक माह लग जाएगा। फिर, चीन से भारत तक कच्चे माल की आपूर्ति होने में कम से कम एक माह और लग जाएगा। उद्यमियों ने बताया कि वे कच्चे माल के लिए चीन के अलावा अन्य देशों से आयात के विकल्प तलाश रहे हैं। लेकिन दूसरे देशों से कच्चे माल का आयात चीन के मुकाबले 20-25 फीसद तक महंगा होगा। कच्चे माल की कीमत अधिक होने पर तैयार वस्तुओं की कीमत भी अधिक होगी। इससे घरेलू स्तर पर महंगाई बढ़ने के साथ निर्यात भी प्रभावित होगा। उद्यमियों ने बताया कि उन्होंने सरकार से जरूरी एवं रोजगारपरक क्षेत्र की वस्तुओं से जुड़े कच्चे माल के आयात शुल्क में कटौती की गुजारिश की है और सरकार की तरफ से उन्हें इस दिशा में मदद का आश्वासन दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए करीब 15 दिन पहले विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक की थी। मंगलवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल निर्यातकों के साथ कच्चे माल की आपूर्ति एवं अन्य मसलों पर बैठक करने वाले हैं।

बाक्स

औद्योगिक संगठन सीआइआइ ने भी आयात शुल्क में कटौती की सिफारिश सरकार से की है। सीआइआइ ने कहा है कि हाल के समय में सरकार की तरफ से कई आइटम के आयात शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। संगठन का कहना है कि मौजूदा हालात में आयात शुल्क में कमी करना आवश्यक हो गया है। सीआइआइ ने सरकार से एनपीए रेगुलेशन में भी छूट देने की मांग की है।

सीआइआइ ने अपनी सिफारिश में कहा है कि सप्लाई चेन के बाधित होने से कई उद्यमियों को कार्यशील पूंजी की दिक्कत हो जाएगी और वे समय पर उधार नहीं चुका पाएंगे। ऐसी स्थिति में उन्हें एनपीए करार देने से दूर रखा जाए।

कर्ज बांटने में तेजी की सलाह पर बैंक बोले - लेने वाले नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ देश में कर्ज बांटने की स्थिति पर आरबीआइ व सरकारी बैंक प्रमुखों की हुई बैठक

आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रमुखों को देश में कर्ज के हालात में सुधार के लिए बुलाया था। लेकिन सोमवार को तकरीबन तीन घंटे तक मुंबई स्थित आरबीआइ मुख्यालय में चली बैठक का कोई नतीजा निकला हो, ऐसा नहीं लगता है। बैठक में दास ने बैंकों से कहा कि वे ब्रांच स्तर पर अपनी गतिविधियों को और तेज करें व ग्राहकों से मिल कर उन्हें कर्ज लेने के लिए प्रोत्साहित करें। अधिकांश बैंकों ने आरबीआइ से कहा कि वे कर्ज देने को तैयार हैं लेकिन बाजार में कर्ज लेने वालों की कमी है। एक बैंक प्रमुख ने तो यहां तक अंदेशा जताया कि आने वाले महीनों में कर्ज की रफ्तार और घट सकती है।

आरबीआइ ने पिछले शुक्रवार को जनवरी, 2020 के कर्ज वितरण के आंकड़े जारी किए थे। उस महीने कर्ज वितरण में 8.5 फीसद की वृद्धि हुई थी जबकि जनवरी, 2019 में यह वृद्धि 13.5 फीसद की थी। सबसे ज्यादा खराब स्थिति सर्विस सेक्टर की है जिसमें कर्ज की रफ्तार इस अवधि में 24 फीसद से घटकर नौ फीसद रह गई है। इन आंकड़ों के जारी होने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आरबीआइ और बैंक प्रमुखों की अलग से बैठक की थी। सीतारमण ने बैंकों से कहा था कि उन्हें ब्रांच स्तर की बैंकिंग फिर से शुरू करने की जरूरत है ताकि ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संपर्क

प्रतीकात्मक

हो और वो कर्ज लेने के लिए आगे आएं। आरबीआइ गवर्नर ने एक तरह से यही संदेश को बैंक प्रमुखों को दिया। लेकिन बैंकों के रवैये से साफ है कि असल समस्या उनकी तरफ से नहीं है, बल्कि बाजार में कर्ज लेने वाले ही नहीं है।

इस बैठक में भाग लेने वाले एक अधिकारी ने कहा कि असली समस्या मांग की है। बाजार में मांग नहीं है और उद्योग जगत को ऐसा लग रहा है कि अभी मांग बढ़ने वाली नहीं है। ऐसे में उद्योग जगत नया कर्ज लेने के लिए आगे नहीं आ रहा है। अभी स्थिति यह है कि समूचे बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त पूंजी पड़ी हुई है जिसका वह कर्ज देने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन मांग नहीं होने की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। एक बैंक प्रमुख ने बैठक में साफतौर पर कहा कि कर्ज वितरण की रफ्तार आने वाले दिनों में और कम हो सकती है।

मैन्यूफैक्चरिंग की रफ्तार घटी, फिर भी 31 महीनों से पॉजिटिव

नई दिल्ली, प्रेट्र : दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस फैलने का असर फरवरी के दौरान भारत में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियों पर देखा गया। सोमवार को जारी एक मासिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बीते माह मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियों में कुछ नरमी देखी गई।

आइएचएस मार्किट इंडिया के मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआइ) फरवरी 2020 में 54.5 पर रहा। जनवरी में यह पिछले आठ साल के सबसे ऊंचे स्तर 55.3 पर था। वैसे यह लगातार 31वां महीना है, जब भारत में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर का पीएमआइ 50 से ऊपर बना रहा। पीएमआइ 50 अंक से ऊपर रहना विस्तार और इससे नीचे आना गिरावट दर्शाता है।

आइएचएस मार्किट की प्रधान अर्थशास्त्री पॉलियाना डि लीमा ने कहा, 'भारत के कारखानों में फरवरी के दौरान बेहतर ऑर्डर मिलने की वजह से गतिविधियां बेहतर रहीं। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों बाजारों से ऑर्डर प्राप्त हुए। इसका मतलब यह है कि कारखानों में उत्पादन बढ़ेगा और कच्चे माल की खरीदारी भी ऐतिहासिक रूप से काफी ऊंची दर से होगी।'

बंदरगाहों पर सड़ रहा करोड़ों का आयातित प्याज

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

▶ दो सौ करोड़ रुपये का प्याज टर्की समेत कई देशों से हुआ आयात

▶ दिसंबर और जनवरी के बीच 90 फीसद प्याज की विदेशी बाजारों से हुई खरीद

पहले प्याज की कमी ने उपभोक्ताओं को परेशान किया, तो अब आयातित प्याज की हजारों टन की खेप सरकारी खजाने को प्रभावित कर सकती है। तुर्की समेत कई और देशों से आयातित प्याज की बड़ी खेप विभिन्न बंदरगाहों पर सड़ रही है। दिसंबर से जनवरी के बीच कुल आयातित प्याज का 90 फीसद हिस्सा घरेलू बंदरगाहों पर पहुंचा था, जिसकी कोई पूछ नहीं है। लिहाजा प्याज की इन खेप को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। इस बीच, सरकार घरेलू प्याज के निर्यात की अधिसूचना भी 15 मार्च तक जारी करने वाली है। ऐसे में आयातित प्याज की बिक्री की कोई उम्मीद नहीं बची है।

विदेश से मंगाए प्याज की क्वालिटी और कीमतें दोनों ठीक नहीं हैं, जिसके चलते इसे न घरेलू व्यापारी पसंद कर रहे हैं और न उपभोक्ता। बड़े आकार और रंग-रूप के साथ फीके स्वाद के चलते घरेलू उपभोक्ता इसे पंसद नहीं कर रहे हैं। आयातित प्याज 50 से 58 रुपये किलो की दर से बंदरगाह तक पहुंचा है। इस हिसाब से लगभग दो सौ करोड़ रुपये का प्याज बंदरगाहों पर पड़ा हुआ है।

सरकार इसे राज्यों को 22 रुपये किलोग्राम तक पर बेचने को राजी है। इसके बावजूद इसकी खरीद को कोई तैयार नहीं हुआ। दरअसल, घरेलू प्याज की खेप सब्जी बाजार में पहुंच चुकी है, जिसका थोक भाव 17 से 20 रुपये किलो बोला जाने लगा है। ऐसे में बेस्वाद और महंगा आयातित प्याज खरीदने को कोई तैयार नहीं है।

खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कुल 41,500 टन प्याज के आयात का सौदा किया गया था। लेकिन बाद में 5,300 टन प्याज के निर्यात सौदे रद कर दिए गए। कुल शुद्ध आयात 36,200 टन का हुआ है। आयातित प्याज में से मात्र 2000 टन प्याज ही विभिन्न राज्य सरकारों ने उठाया है। ऑनलाइन पोर्टल पर आयातित प्याज की कीमत 11 रुपये किलो तक बोली गई है। प्याज आयात करने वाले प्रबंधकों का नया प्रस्ताव इस प्याज को जैसे-तैसे ऑनलाइन पोर्टल के साथ केंद्रीय एजेंसियों के हाथ बेचने का है। आयातित प्याज में से 32,000 टन से ज्यादा अभी भी बंदरगाहों पर पड़ा हुआ है।

प्याज के आयात का फैसला तब लिया गया था, जब घरेलू बाजार में प्याज की भारी किल्लत हो गई थी, जिससे कीमतें 150 रुपये किलो के स्तर तक पहुंच गई थीं। सब्जी बाजार में प्याज की आवक सप्ताह दर सप्ताह बढ़ रही है।

प्याज आयात करने के फैसले को लेकर अब सरकार के मंत्रालयों के बीच तनातनी चल रही है। प्याज आयात करने के समय, मात्रा और क्वालिटी को लेकर अंदरुनी तौर पर विवाद शुरू हो गया है। यह मसला बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद में भी उठ सकता है। वैसे तो तत्कालीन सचिवों की समिति के फैसले से प्याज का आयात किया गया।

उड़ान में इंटरनेट उपयोग की मिली इजाजत, कॉल पर रोक जारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ पायलट की अनुमति से वाई-फाई के उपयोग के लिए एयरक्राफ्ट रूल्स में संशोधन

▶ मगर पेसमेकर जैसी चुनिंदा डिवाइस को छोड़ बाकी डिवाइस पर रोक जारी

सरकार ने एयरलाइनों को उड़ान के दौरान यात्रियों को इंटरनेट के उपयोग के लिए वाई-फाई सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए 1937 के वायुयान नियमों में संशोधन किया गया है।

संशोधित नियमों के अनुसार अब डीजीसीए किसी भी एयरलाइन को उड़ान के दौरान विमान में वाई-फाई सेवाएं प्रदान कर सकता है। किसी उड़ान विशेष में मुख्य पायलट या कमांडर को वाई-फाई चालू करने तथा यात्रियों को इंटरनेट के लिए उसके उपयोग की अनुमति देने का अधिकार होगा। लेकिन वाई-फाई का उपयोग करने से पहले यात्री को अपना लैपटॉप, स्मार्ट फोन, टेबलेट, स्मार्ट वॉच, ई-रीडर अथवा प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण फ्लाइट या एयरप्लेन मोड में लाना आवश्यक होगा।

विमान में वाई-फाई के लिए एयरक्राफ्ट रूल्स में संशोधन की अधिसूचना सरकार ने शुक्रवार को जारी की। इससे पहले पिछले वर्ष 14 अगस्त के दिन सरकार ने इस संबंध में मसौदा अधिसूचना निकालकर जनता से सुझाव व आपत्तियां मांगी थीं। परंतु कहीं से कोई सुझाव या आपत्ति प्राप्त न हुई। इसलिए अब सरकार ने फाइनल अधिसूचना के जरिए विमानो में उड़ान के दौरान वाई-फाई सुविधा की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसके लिए वायुयान अधिनियम 1934 के तहत वायुयान नियम 1937 के नियम 29 ख के उपनियम (1) में संशोधन किया गया है।

सरकार की ओर से अनुमति मिलने के साथ भारतीय एयरलाइनों ने उड़ानों में वाई-फाई सुविधा देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए वाई-फाई सुविधा के साथ ही नए विमानों की खरीद की जा रही है। विस्तारा की ओर से पिछले शुक्रवार को हासिल किए गए बोइंग 737-9 विमान में यह सुविधा देने की व्यवस्था है। विमान की डिलीवरी प्राप्त करते हुए विस्तारा के सीईओ ने कहा था वाई-फाई सुविधा देने वाली यह भारत की पहली विमानन कंपनी होगी। विदेशी एयरलाइन कंपनियां अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यह सुविधा पहले से दे रही हैं।

विमान में उड़ान के दौरान मोबाइल फोन से कॉल करने या रिसीव करने की सुविधा अभी भी नहीं दी गई है। अधिसूचना में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि विमान में उड़ान के दौरान किसी भी व्यक्ति को भी किसी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। कमांडर पायलट भी इसकी अनुमति नहीं दे सकेगा।

हालांकि यह नियम पोर्टेबल वॉइस रिकॉर्डर, हियरिंग डिवाइस, हार्ट पेसमेकर, इलेक्ट्रॉनिक शेवर अथवा ऐसी ही किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर लागू नहीं होगा, जिससे विमान की संचार प्रणाली पर कोई असर नहीं पड़ता हो और जिनके उपयोग की एयरलाइन ने डीजीसीए से पहले से अनुमति ले रखी हो।

विवाद से विश्वास बिल लोकसभा में पेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ 4.83 लाख प्रत्यक्ष कर विवाद का होगा निपटान, सदन से जल्द पारित कराना होगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में विवाद से विश्वास बिल पेश कर दिया। इस बिल के पारित होने पर प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट) टैक्स से जुड़े 4.83 लाख विवादों को इस महीने के अंत तक निपटाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे सरकार को 9.32 लाख करोड़ रुपये का राजस्व हासिल होगा। इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी पहले मिल चुकी है।

संसद की मंजूरी मिलते ही इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आवेदन फॉर्म जारी कर दिए जाएंगे। इस स्कीम का लाभ 31 मार्च तक उठाया जा सकेगा। उसके बाद 10 फीसद जुर्माने के साथ इस स्कीम का लाभ लिया जा सकेगा।

विवाद से विश्वास स्कीम के तहत अपने कर विवाद के निपटान के इच्छुक उम्मीदवार को अपने विवादित टैक्स का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उन्हें टैक्स पर लगने वाले ब्याज एवं पेनाल्टी का कोई भुगतान नहीं करना होगा। अगर 31 मार्च के बाद वे भुगतान करते हैं तो उन्हें विवादित टैक्स का 10 फीसद अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यह नियम तब लागू होगा जब टैक्स विवाद को लेकर टैक्सपेयर्स की ओर से अपील दायर की गई हो। अगर यह अपील सरकार की ओर से दायर की गई है तो उन्हें विवादित राशि का सिर्फ 50 फीसद देना होगा।

योजना के मुताबिक मामला अगर टैक्स पर लगने वाले ब्याज एवं जुर्माने से जुड़ा है तो 31 मार्च तक विवादित ब्याज या पेनाल्टी की 25 फीसद राशि देनी होगी। 31 मार्च के बाद और 30 जून तक ऐसे मामले में 30 फीसद राशि देनी होगी।

31 जनवरी, 2020 तक अपील या याचिका दाखिल कर चुके टैक्सपेयर्स की इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। अगर पहले से दायर अपील या याचिका की मियाद 31 जनवरी, 2020 को समाप्त चुकी है तो उन्हें स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।

एयर इंडिया को खरीदने के लिए विस्तारा गंभीर

नई दिल्ली, प्रेट्र : संकट से गुजर रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया की खरीद में कई कंपनियां रुचि दिखा रही हैं। निजी विमानन कंपनी विस्तारा भी इस सौदे के लिए गंभीर नजर आ रही है। कंपनी ने कहा है कि वह एयर इंडिया का विश्लेषण कर रही है। टाटा एसआइए के चेयरमैन भास्कर भट ने बताया कि फिलहाल एयर इंडिया का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके बाद बोली में भाग लेने पर फैसला किया जाएगा।

भट ने बोली के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भला कौन सी कंपनी एयर इंडिया में रुचि नहीं दिखाएगी। टाटा और विस्तारा में से किसी एक की रुचि के सवाल को नकारते हुए उन्होंने कहा कि विस्तार दोनों कंपनियों का साझा उपक्रम है। गौरतलब है कि सरकार ने इसी वर्ष जनवरी में एयर इंडिया में 100 परसेंट हिस्सेदारी बेचने की कवायद शुरू की थी। इसके साथ ही कंपनी के एयरपोर्ट कारोबार में 50 परसेंट हिस्सेदारी बेचने की तैयारी है।

एयर इंडिया की खरीद में रुचि दिखाने वाली कंपनियां 17 मार्च तक अपनी बोली जमा कर सकती हैं। इसके लिए उनकी नेटवर्थ कम से कम 3,500 करोड़ रुपये होनी चाहिए। सरकार को अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही तक इसकी बिक्री प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली में सोमवार को विस्तारा बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर की लांचिंग के दौरान केबिन क्रू से बात करते टाटा एसआइए एयरलांइस लि. के चेयरमैन भास्कर भट (बीच में)। निजी विमानन कंपनी विस्तारा, टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस का संयुक्त उपक्रम है। प्रेट्र

एटीएफ के भाव में 10 परसेंट की गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र : कच्चे तेल की गिरती कीमत का असर विमान ईंधन (जेट फ्यूल) पर भी देखने को मिल रहा है। सोमवार को जेट फ्यूल 10 परसेंट सस्ता हो गया। पिछले दो महीनों के दौरान यह दूसरी कटौती है। सोमवार को जेट फ्यूल के भाव में 6,590 .62 रुपये प्रति किलोलीटर की कटौती हुई। इसके साथ ही अब दिल्ली में इसकी कीमत 56,859 .01 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है। इससे पहले फरवरी में जेट फ्यूल का भाव 874 .13 रुपये प्रति किलोलीटर गिरा था।

चिंता

सेंसेक्स 153 अंक और निफ्टी 69 अंक टूटकर हुआ बंद, कारोबारी सत्र में देखने को मिला भारी उतार-चढ़ाव

कोरोना की भेंट चढ़ी शेयर बाजारों की शुरुआती तेजी

मुंबई, प्रेट्र : सप्ताह के पहले कारोबारी सत्र के दौरान देश के प्रमुख शेयर बाजारों में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला। इंट्रा-डे में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 786 अंक चढ़ने के बाद नीचे लुढ़क गया। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश में कोरोना के दो नए मामले सामने आने की पुष्टि के बाद सेंसेक्स ने ऊपरी स्तर से 1,300 अंकों का गोता लगा दिया। हालांकि अंत में कुछ संभलते हुए यह 153.27 अंकों की गिरावट के साथ 38,144.02 पर रहा। एनएसई के निफ्टी में भी 69 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। यह 11,132.75 के स्तर पर बंद हुआ।

शुक्रवार को घरेलू बाजारों में बड़ी गिरावट के बाद सोमवार के शुरुआती सत्र में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। लेकिन दिन चढ़ने तक यह लगातार सातवें सत्र में गिरावट का शिकार हुए। इस दौरान सेंसेक्स पैक में एसबीआइ के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। टाटा स्टील, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ओएनजीसी और इंडसइंड बैंक के शेयर भी नीचे खिसक गए। हालांकि एचसीएल टेक, नेस्ले इंडिया, आइसीआइसीआइ बैंक और इन्फोसिस के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए।

जानकारों के मुताबिक चीन समेत कई देशों में पहले से महामारी का रुप ले चुके कोरोना वायरस के देश में दो नए मामले सामने आने के बाद निवेशकों का मनोबल टूटा है। सोमवार को एशिया के अन्य बाजारों में कुछ सुधार देखने को मिला। इस दौरान शंघाई, हांगकांग, सियोल और टोक्यो के शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए।

प्रतीकात्मक

रुपया 15 महीनों के निचले स्तर पर

मुंबई, प्रेट्र : सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में 50 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते रुपया 15 महीने के निचले स्तर तक लुढ़क गया। हालांकि शुरुआती कारोबार में रुपये का प्रदर्शन बेहतर रहा। लेकिन देश में कोरोना के दो नए मामले सामने आने के बाद रुपये ने शुरुआती तेजी खो दी और डॉलर के मुकाबले 50 पैसे गिरकर 72 .74 रुपये के भाव पर बंद हुआ। कारोबारी सत्र की शुरुआत में डॉलर के मुकाबले रुपया 72 .09 पर रहा और बाद में 72 .04 के स्तर तक गया। पिछले सप्ताह शुक्रवार को रुपया 72 .24 के स्तर पर बंद हुआ था।

इन शेयरों में रही गहमागहमी

टीवीएस मोटर : बीते महीने बिक्री में गिरावट की सूचना आने के बाद कंपनी के शेयरों में चार परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को बीएसई में इसके शेयर 3 .55 परसेंट लुढ़ककर 420 .10 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए। वहीं एनएसई में यह 4 .29 परसेंट तक लुढ़क गए। इससे पहले कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया था कि फरवरी में इसकी बिक्री 15 .39 परसेंट नीचे रही है।

बजाज ऑटो : सोमवार को इस ऑटो कंपनी के शेयर तीन परसेंट तक की गिरावट के साथ बंद हुए। कंपनी के शेयरों में गिरावट की वजह बीती फरवरी के दौरान बिक्री में कमी रही। दिन के कारोबार में बीएसई में कंपनी के शेयर 3 .21 परसेंट की गिरावट के साथ 2,797 .70 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए। वहीं एनएसई में यह 3 .21 परसेंट नीचे आकर 2,774 रुपये पर बिके।

सोना-चांदी के भाव में उछाल

नई दिल्ली, प्रेट्र : सोमवार को स्थानीय सराफा बाजारों में तेजी देखने को मिली। इस दौरान सोना 391 रुपये सुधरकर 42,616 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। इस दौरान चांदी के भाव में भी 713 रुपये का उछाल देखने को मिला। यह 46,213 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकी। जानकारों के मुताबिक ग्लोबल मार्केट में सोने के भाव में सुधार का असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में सोना 1,604 डॉलर और चांदी 17 डॉलर प्रति औंस के हिसाब से बिके।

एपल का दावा, ट्रंप ने भारत में की पैरवी

नई दिल्ली, आइएएनएस : दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी कंपनियों में एक एपल इंक ने पहली बार दावा किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की हालिया यात्रा में उसकी पैरवी की थी। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने कहा है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार भारत में एपल की पैठ बनाने-बढ़ाने में अमेरिकी प्रशासन ने बड़ी मदद की है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले 24-25 फरवरी को भारत यात्रा पर आए थे और यहां मिले सत्कार को अभूतपूर्व बताया था। उनके अमेरिका लौटने के बाद ही कुक ने कहा था कि एपल अगले वर्ष भारत में पहला एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर खोलेगी। कंपनी ने इसी वर्ष एक ऑनलाइन एक्सक्लूसिव स्टोर खोलने की भी बात कही थी। गौरतलब है कि अमेरिकी कंपनियों द्वारा भारत में उनके विकास और विस्तार के लिए अलग-अलग तरह से लॉबिंग की खबरें आती रही हैं।

कोरोना से दुनिया में तीन हजार से ज्यादा की मौत

महामारी का प्रकोप ▶ 70 से अधिक देशों में फैला यह जानलेवा वायरस, 88 हजार से ज्यादा लोग हैं संक्रमित

22 जनवरी के बाद पहली बार संक्रमण के नए मामलों में दर्ज की गई है कमी

बीजिंग, एजेंसियां : महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस से दुनियाभर में जान गंवाने वालों की संख्या तीन हजार के पार हो गई है। जबकि संक्रमित लोगों की संख्या 88 हजार के आंकड़े को पार कर गई है। अब तक इस बीमारी के 70 से ज्यादा देशों में मामले सामने आ चुके हैं।

चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचसी) ने रविवार को बताया कि देश में 42 और लोगों के मरने का पता चला है। इस तरह देश में मृतकों की संख्या 2912 हो गई है। संक्रमण के 202 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमित लोगों की 80,026 हो गई है। 22 जनवरी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब संक्रमण के इतने कम मामले सामने आए हैं। संक्रमण के नए मामलों में गिरावट आने के बाद त्वरित इलाज के लिए बनाए गए 16 अस्थायी अस्पतालों में से वुहान स्थित पहले अस्पताल को बंद कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने मी फेंग ने कहा कि संक्रमण के नए मामलों में कमी आने के चलते यह निर्णय लिया गया है।

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग (दाएं से दूसरे) ने बीजिंग में स्थित एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंसेज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस पर जारी शोध और वैक्सीन विकसित करने के प्रयासों की जानकारी हासिल करने के साथ जरूरी निर्देश दिए। चिनफिंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी की ओर से शोधकर्ताओं और चिकित्साकर्मियों का उनके प्रयासों के लिए आभार जताया। एपी

ईरान में खामनेई के करीबी की मौत : कोरोना वायरस से ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की सलाहकार परिषद के सदस्य मुहम्मद मीर मुहम्मदी की मौत हो गई। वह 71 वर्ष के थे। यह खबर ईरान में कई शीर्ष अधिकारियों के वायरस से पीड़ित होने की सूचना के बीच आई है। कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए ईरान ने सोमवार को अपने विदेश मंत्रालय की ओर से ऑनलाइन ब्रीफिंग कार्यक्रम का आयोजन किया, क्योंकि ब्रिटेन ने वहां से अपने गैरजरूरी कर्मचारियों और उनके परिजनों को हटाना शुरू कर दिया है। ईरान में अभी तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है और 978 लोग संक्रमित हैं।

ईरान ने अमेरिका की पेशकश ठुकराई : अमेरिका ने कोरोना वायरस से जूझते ईरान की मदद की पेशकश की है, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्बास मौसवी ने कहा, हम ऐसी किसी मदद पर ना ही गौर करते हैं और ना ही इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ईरान को हमेशा अमेरिकी मंशा पर शक होता है।

दक्षिण कोरिया में चर्च के प्रमुख ने माफी मांगी : दक्षिण कोरिया में कोरोना से अब तक चार हजार से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। जो लोग संक्रमित हैं उनमें 50 फीसद से ज्यादा शिन्चेओनजी चर्च ऑफ जीसस की देगू शाखा से जुड़े हैं। सोमवार को चर्च के प्रमुख ली मैन ही ने बीमारी के प्रसार के लिए माफी मांगी। सियोल के अधिकारियों ने इस महामारी को रोकने में मदद नहीं करने पर उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की शिकायत दी है। चीन के बाहर कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले दक्षिण कोरिया में आए हैं।

अमेरिका में दूसरी मौत : अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार रात कोरोना वायरस से एक और व्यक्ति की मौत होने की जानकारी दी। यह अमेरिका में इस वायरस से मौत का दूसरा मामला है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ग्रेटर सिएटल इलाके में कई हफ्तों से फैल रहे कोरोना वायरस का समय पर पता नहीं लगाया जा सका। अमेरिका में जिन दो लोगों की मौत हुई है उनका पूर्वी सिएटल के किर्कलैंड के अस्पताल में इलाज किया गया था। अमेरिका में अब तक संक्रमण के 12 मामले सामने आ चुके हैं।

जांच चौकी पर दो की हत्या में चीनी को मृत्युदंड

बीजिंग, एएफपी : चीन की अदालत ने कोरोना वायरस के लिए बनाई गई एक जांच चौकी पर दो अधिकारियों की चाकू मारकर हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। चीन में वायरस की रोकथाम के लिए कई गांवों और समुदायों ने भी जांच चौकियां बना रखी हैं।

यह वारदात गत छह फरवरी को दक्षिण-पश्चिम युन्नान प्रांत में होंग इलाके के लुओ मेंग गांव में हुई। मा जियांगू नामक 23 साल के मिनीबस ड्राइवर ने जांच चौकी पर सहयोग करने से इन्कार कर दिया था। उसने चाकू से हमला कर दो अधिकारियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। दोनों की बाद में अस्पताल में मौत हो गई थी। मौके पर तैनात कुछ अन्य अधिकारियों ने अपने मोबाइल फोन से इस घटना का वीडियो बना लिया था।

तुर्की से यूरोप पहुंचे 80 हजार से ज्यादा शरणार्थी

इस्तांबुल, आइएएनएस : अब तक 80 हजार से ज्यादा शरणार्थी तुर्की की उत्तर-पश्चिमी सीमाओं के जरिये यूरोप पहुंच चुके हैं। तुर्की सरकार ने सोमवार को कहा कि आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ सकती है। उधर, लेसबोस के ग्रीक आइसलैंड में शरणार्थियों को लेकर आ रही एक नाव के डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि तुर्की ने बीते गुरुवार को एलान किया था कि वह अब शरणार्थियों को अपनी सीमा के जरिये यूरोप जाने से नहीं रोकेगा।

तुर्की के संचार निदेशक फहार्तिन अल्तुन ने कहा, मानवीय पीड़ा, सीरिया में पलायन की चुनौती और अभूतपूर्व विस्थापन ना केवल तुर्की बल्कि यूरोप और पूरी दुनिया के लिए समस्या बना हुआ है। शरणार्थी संकट से निपटने के लिए तुर्की मजबूती से काम कर रहा है, लेकिन अन्य देशों को भी इस मुद्दे पर काम करना चाहिए। सीमा पर मौजूद स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक, ज्यादातर शरणार्थी एवरोस नदी के जरिये मछली पकड़ने वाली नावों से यूरोपीय देश ग्रीस की सीमा तक पहुंच रहे हैं। तुर्की के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग शरणार्थियों को मछली पकड़ने वाली नावों से नदी के दूसरी ओर ले जा रहे हैं। इसके एवज में वे लोग शरणार्थियों से 2200 रुपये से पांच हजार रुपये तक वसूल रहे हैं। बच्चों से हालांकि किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा। आलम यह है कि नदी के किनारे सैकड़ों शरणार्थी एकत्र हैं और नदी पार कराने के लिए मछुआरों से मोलभाव कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जिन शरणार्थियों को ग्रीक सुरक्षा बल पकड़ने में कामयाब हो रहे हैं, उन्हें वापस तुर्की भेजा जा रहा है। शरणार्थी ग्रीस में नहीं आ सकें, इसके लिए सुरक्षा बलों ने नदी के किनारों पर कंटीले तार लगा दिए हैं। इदलिब में कुछ दिनों पहले सीरियाई बलों द्वारा की गई बमबारी से भयभीत होकर करीब 15 लाख सीरियाई शरणार्थी तुर्की की सीमा की तरफ भागे हैं। तुर्की ने हालांकि उन्हें अपनी सीमा में घुसने की अनुमति नहीं दी है। तुर्की में पहले से ही कई लाख शरणार्थी रह रहे हैं, इनमें बड़ी संख्या सीरियाई नागरिकों की है।

ग्रीस सुरक्षाबलों की कार्रवाई में मारा गया एक व्यक्ति : दो तुर्की अधिकारियों ने बताया है कि शरणार्थियों को ग्रीस में घुसने से रोकने के लिए सुरक्षाबलों द्वारा की गई कार्रवाई में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। हालांकि एथेंस ने तुर्की के इस दावे को गलत बताया है। बताया जाता है कि दस हजार से अधिक शरणार्थी ग्रीस और बुल्गारिया से लगती तुर्की की सीमा पर पहुंच गए हैं। इन शरणार्थियों में अधिकांश सीरियाई हैं।

शरणार्थियों को लेकर आ रही नाव के डूबने से एक बच्चे की मौत

न्यूज गैलरी

फिलीपींस के मॉल में गार्ड ने 30 लोगों को बनाया बंधक

मनीला : फिलीपींस की राजधानी मनीला के एक मॉल में नौकरी से निकाले गए सुरक्षा गार्ड ने एक व्यक्ति को गोली मार दी और करीब 30 लोगों को बंधक बना लिया। पुलिस बंधकों को बचाने में जुटी है। गार्ड मीडिया से बात करने की मांग कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, मध्य मनीला में स्थित वी-मॉल में सोमवार सुबह गोलियां चलने की आवाज सुनी गई। मॉल से कई कर्मचारियों और ग्राहकों को निकाल लिया गया। घटना के समय मॉल में भीड़-भाड़ थी। गार्ड की पहचान आर्ची पेरे के रूप में की गई है। मॉल में सुरक्षा मुहैया कराने वाली कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। शहर के मेयर सान जुआन ने कहा, 'गार्ड के पास एक पिस्टल और ग्रेनेड होने की खबर है। उसने मॉल के प्रशासनिक दफ्तर में बंधकों को बंद कर रखा है। एक व्यक्ति को गोली लगी है। उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है।' बता दें कि मनीला में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। 2010 में एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने एक मॉल में कुछ लोगों को बंधक बना लिया था। इस दौरान आठ लोगों की मौत हो गई थी। (एजेंसियां)

ब्रिटेन से शरीफ के प्रत्यर्पण का अनुरोध करेगी इमरान सरकार

लाहौर : पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित करने के बाद पाकिस्तान की इमरान खान सरकार उन्हें प्रत्यर्पित करने के लिए ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखेगी। पिछले सप्ताह पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने शरीफ की जमानत अवधि बढ़ाने से इन्कार कर दिया था। अपने फैसले में सरकार ने कहा था कि ऐसा करने के लिए किसी प्रकार का न्यायिक, नैतिक और मेडिकल आधार नहीं है। इमरान खान की विशेष सहायक फिरदौस आशिक अवान ने रविवार को यहां कहा, ब्रिटिश सरकार से पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के शीर्ष नेता नवाज शरीफ के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाएगा। इसके लिए इसी सप्ताह वहां की सरकार को पत्र लिखा जाएगा। शरीफ अपने इलाज के लिए पिछले साल 19 नवंबर को लंदन गए थे, लेकिन वहां के किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए। उनका ऐसा करना दर्शाता है कि स्वास्थ्य को आधार बनाकर शरीफ, उनकी पार्टी और मीडिया के एक वर्ग ने मिलकर उन्हें देश से बाहर जाने में मदद पहुंचाई। अवान ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री और उनके छोटे भाई शहबाज अपने बच्चों के कारोबार को बचाने के लिए लंदन गए हैं। (प्रेट्र)

डेमोक्रेटिक उम्मीदवारी की दौड़ से हटे बटीगीग, बिडेन की बढ़ी उम्मीद

वाशिंगटन, एएफपी : इंडियाना के साउथ बेंड शहर के पूर्व मेयर और युवा नेता पीट बटीगीग अमेरिका की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी में चल रही राष्ट्रपति उम्मीदवारी की होड़ से हट गए हैं। उनका यह फैसला हैरान करने वाला है क्योंकि वह आयोवा के प्राइमरी चुनाव में विजेता बनकर उभरे थे। उनके हटने से पूर्व उप राष्ट्रपति जो बिडेन को फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

आयोवा के प्राइमरी चुनाव में बटीगीग ने 77 वर्षीय बिडेन और 79 साल के बर्नी सैंडर्स जैसे दिग्गज नेताओं को मात दी थी। लेकिन वह तीन अन्य राज्यों के प्राइमरी चुनाव में सैंडर्स से थोड़ा पिछड़ गए थे। शनिवार को साउथ कैरोलिना प्राइमरी में वह तीसरे स्थान पर रहे थे। साउथ कैरोलिना में जीत के साथ बिडेन ने वापसी की है। 38 वर्षीय बटीगीग ने सोमवार को अपने समर्थकों के बीच राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने का एलान किया।

आज 14 राज्यों में प्राइमरी चुनाव : डेमोक्रेटिक पार्टी में मंगलवार को कैलिफोर्निया समेत 14 राज्यों में प्राइमरी चुनाव कराए जाएंगे। पार्टी के इन आंतरिक चुनावों में विजेता बनने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। इस साल तीन नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वह डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देगा।

सांसद तुलसी गबार्ड समेत छह दावेदार बचे

डेमोक्रेटिक पार्टी में अब महज छह दावेदार रह गए हैं। बिडेन और सैंडर्स के अलावा अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड, सीनेटर एजिलाबेथ वारेन, एमी क्लोबुशर और न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर माइकल ब्लूमबर्ग मुकाबले रह गए हैं। इस विपक्षी दल में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए 20 से ज्यादा नेताओं ने दावेदारी पेश की थी।

इजरायल में सालभर में तीसरी बार हुए चुनाव, नतीजे आज

यरुशलम, प्रेट्र : इजरायल में सालभर के अंदर सोमवार को तीसरी बार संसदीय चुनाव कराए गए। नतीजे मंगलवार को आने की उम्मीद है। सर्वे में हालांकि इस चुनाव में भी किसी दल को फिर बहुमत नहीं मिलने का अनुमान है। पिछले दो चुनावों में भी किसी को बहुमत नहीं मिला था और गठबंधन सरकार बनाने पर बात नहीं बन पाई थी। यह चुनाव प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सियासी करियर के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुकदमों में उन्हें आरोपित किया गया है। इन मुकदमों की सुनवाई अगले दो हफ्ते बाद शुरू होने वाली है।

▶ **सर्वे में किसी भी दल को फिर बहुमत नहीं मिलने का अनुमान**

इजरायल में स्थानीय समयानुसार सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ। करीब 65 लाख मतदाताओं के लिए 10,631 मतदान केंद्र बनाए गए। कोरोना वायरस के डर से अलग-थलग रह रहे लोगों के लिए 14 विशेष मतदान केंद्र भी बनाए गए थे। रात दस बजे मतदान बंद होने के बाद मतों की गिनती शुरू कर दी गई। इजरायल में सबसे लंबे समय से प्रधानमंत्री पद पर काबिज 70 वर्षीय बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि उनके नेतृत्व वाली लिकुड पार्टी बहुमत पाने में सफल होगी। उनका चुनाव प्रचार व्यक्तिगत साख पर ज्यादा केंद्रित रहा। जबकि मुख्य विपक्षी दल ब्लू एंड ह्वाइट के नेता बेनी गेंट्ज ने चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नेतन्याहू को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू मुकदमे से बचने के लिए किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से उनके खिलाफ मत प्रयोग की अपील की थी।

इजराइल में सोमवार को एक साल में तीसरी बार हुए संसदीय चुनाव में कोरोना वायरस ने भी असर दिखाया। एकांतवास में रह रहे कोरोना वायरस के संभावित संक्रमितों के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए गए थे। अश्कलोन शहर की तस्वीर में एक मतदाता मतदान प्रक्रिया पूरी कर रहा है। एएफपी

गठबंधन सरकार बनाने में भी विफल रहे थे दोनों दल

इजरायल में पिछले साल अप्रैल और सितंबर में भी 120 सदस्यीय संसद के चुनाव कराए गए थे। इन दोनों ही चुनाव में लिकुड पार्टी और ब्लू एंड ह्वाइट को बहुमत नहीं मिला था। दोनों दल गठबंधन सरकार बनाने में भी विफल रहे थे।

किसी को बहुमत नहीं मिला तो जटिल होगी स्थिति

चुनाव पूर्व कराए गए सर्वे में नेतन्याहू की पार्टी को मामूली बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन उनके नेतृत्व वाला गठबंधन बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटों का आंकड़ा भी छूता नजर नहीं आ रहा। अगर इस चुनाव में भी किसी दल को बहुमत नहीं मिला तो इजरायल की सियासत में एक साल से जारी गतिरोध और जटिल हो सकता है।

तालिबान और गनी सरकार के बीच बातचीत सबसे अहम : भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **अफगानिस्तान में किस तरफ जा रहा बातचीत का रुख, भारत रखेगा नजर**
- **जयशंकर बोले, फिल्म पाकीजा की तरह लंबित हुआ अमेरिका-तालिबान समझौता**

काबुल में तालिबान की तरफ से अमेरिका से किए गए समझौते से पीछे हटने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में भारत ने कहा है कि वह पूरे हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है। भारत ने यह भी कहा है कि अमेरिका-तालिबान समझौते के बाद तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच होने वाली बातचीत सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही भारत की तरफ से इस बात के भी साफ संकेत दिए गए हैं कि उसने पिछले 17-18 वर्षों में अफगानिस्तान में लोकतंत्र बहाली और विकास के लिए जो मदद की है उस पर आसानी से पानी फेरने नहीं दिया जाएगा। भारत की तरफ से कुछ ऐसे ही उद्गार विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यहां एक सेमिनार को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

जयशंकर ने कहा कि, 'सही मायने में अफगानिस्तान में बातचीत का दौर अब शुरू होगा। यह देखना होगा कि तालिबान लोकतांत्रिक व्यवस्था में आता है या मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को तालिबान के हिसाब से बदला जाता है। इस बातचीत में पड़ोसी देशों की क्या भूमिका होती है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। भारत को इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। वैसे भारत इस बात को मानता है कि अफगानिस्तान में पिछले 18 वर्षों में काफी विकास हुआ है। यह वर्ष 2001 का अफगानिस्तान नहीं है। हमने अमेरिका को भी बताया है कि जो विकास किया गया है उसे खत्म नहीं किया जाना चाहिए खास तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में। लेकिन भारत को अभी इंतजार करना होगा और देखना होगा कि परिस्थितियां किस तरह से बदलती हैं।' पिछले शनिवार को अमेरिका और तालिबान के बीच ऐतिहासिक समझौता होने के बाद पहली बार विदेश मंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। जब इस समझौते पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने इसकी तुलना आठवें दशक की मशहूर फिल्म पाकीजा से की जिसके बनने में काफी वक्त लग गया था और कई बार नए ट्रेलर आने के बाद फिल्म का प्रदर्शन हो पाया था।

दिखने लगा भारत के बढ़ते कद का असर

जयशंकर ने दुनिया के भौगोलिक और कूटनीतिक परिदृश्य में हो रहे बदलाव पर कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान देखा जाए तो भारत के बढ़ते कद का असर दिखने लगा है। इस संदर्भ में उन्होंने चीन का नाम लिए बगैर कनेक्टिविटी परियोजनाओं को लेकर भारत के विरोध का उदाहरण दिया और कहा कि जब दुनिया इसको लेकर संशय में थी तो भारत ने इस पर बहस को दिशा दी। दूसरी तरफ हमने कई देशों में इस तरह की परियोजनाओं को समर्थन भी दिया। इसी तरह से आतंकवाद के खिलाफ भारत ने एक वैश्विक माहौल बनाया। यही वजह है कि दूसरे देश भारत को भी एक महत्वपूर्ण शक्ति के तौर पर देखने लगे हैं। कई बार भारत को एक प्रतिद्वंदी के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में हमारी कूटनीति का एक अहम लक्ष्य अभी यह है कि किस तरह से पसंद करने वाले देशों की संख्या बढ़ाई जाए और नापसंद करने वाले देशों की संख्या घटाई जाए।

ओसामा का पता लगाने वाला डॉक्टर पाक की जेल में भूख हड़ताल पर

इस्लामाबाद, एएफपी : अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन का पता लगाने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर शकील अफरीदी अन्याय के खिलाफ जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनकी ही मदद से अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए ने ओसामा को खोज निकाला था। बाद में अमेरिकी सील कमांडो ने मई, 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर उसे ढेर कर दिया था। इस घटना से पाकिस्तान को काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि वह अपने यहां ओसामा की मौजूदगी से इन्कार करता रहा था।

ओसामा के मारे जाने के बाद से ही डॉ शकील सलाखों के पीछे हैं। उनके फर्जी टीकाकरण कार्यक्रम की मदद से सीआइए एजेंटों ने ओसामा का पता लगाया था। शकील से मुलाकात के बाद उनके भाई जमील अफरीदी ने सोमवार को कहा, 'वह उनके और परिवार पर हो रहे अन्याय व अमानवीय बर्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है।' उन्हें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक जेल में रखा गया है। शकील के वकील कमर नदीम ने भी भूख हड़ताल की पुष्टि की। उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें और पारिवारिक सदस्यों को सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है।

गृह मंत्री प्रीति पटेल के समर्थन में उतरे ब्रिटिश पीएम जॉनसन

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रीति पटेल को शानदार गृह मंत्री बताया है। पटेल के स्थायी सचिव रहे सर फिलिप रुथनम के इस्तीफे के बाद पीएम की इस टिप्पणी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रुथनम ने कुछ दिनों पहले एक भावुक टीवी संबोधन के दौरान इस्तीफे का एलान करते हुए आरोप लगाया था कि पटेल के इशारों पर उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था।

कोरोना वायरस की बढ़ती आशंकाओं को दूर करने के लिए ब्रिटिश पीएम रविवार को उत्तरी लंदन पहुंचे थे। इसी दौरान मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या वह अब भी प्रीति पटेल पर भरोसा करते हैं। इस पर जॉनसन ने कहा, बिल्कुल, वह शानदार गृह मंत्री हैं। जो कोई भी इस पद पर रह चुका है वह इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि गृह मंत्रालय में काम करना कितना कठिन है।

स्वास्थ्य मंत्री ने भी किया प्रीति का बचाव : रुथनम के इस्तीफे के मुद्दे पर प्रीति पटेल ने तो अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री मैट हनकॉक उनके बचाव में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि प्रीति दृढ़ निश्चयी होने के साथ ही बहुत विनम्र भी हैं। बता दें कि ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी ने वरिष्ठ नौकरशाह के इस्तीफे के बाद गृहमंत्री प्रीति पटेल से उनके खिलाफ अधिकारियों को धमकाने के लगे आरोपों पर संसद में बयान देने की भी मांग की थी। गृह मंत्रालय में स्थायी सचिव के वरिष्ठ पद से शनिवार को फिलिप रुथनम ने इस्तीफा दे दिया था। रुतनम पटेल के खराब व्यवहार के आरोपों को लेकर उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन गृह मंत्री ने उनके बात नहीं की।

पटेल के स्थायी सचिव के इस्तीफे से ब्रिटेन में बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी

संसद में आकर बयान दें पटेल : लेबर पार्टी

विपक्षी लेबर पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पर गृह मंत्री से संसद में आकर बयान देने की मांग की है। पार्टी नेता सर किएर स्टारमर ने कहा, कुछ जरूरी सवाल हैं जिनका जवाब हरहाल में दिया जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि प्रीति पटेल को जांच का भी सामना करना पड़ सकता है क्योंकि रुथमन ने इस मुद्दे पर कोर्ट जाने की धमकी दी है।

चिंताजनक

तालिबान ने कहा- पांच हजार लड़ाकों की रिहाई से पहले नहीं करेंगे वार्ता, अफगान सुरक्षा बलों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान

अमेरिका-तालिबान समझौता खटाई में पड़ने के संकेत

काबुल, रायटर : समझौते के 48 घंटे के भीतर ही अमेरिका और तालिबान के बीच हुआ शांति समझौता खटाई में पड़ने की आशंका पैदा हो गई है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि अपने पांच हजार लड़ाकों की रिहाई से पहले वह अफगान सरकार से कोई वार्ता नहीं करेगा। रविवार को राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा था कि लंबे संघर्ष के बाद पकड़े गए लड़ाकों को सरकार रिहा नहीं करेगी। जबकि समाचार एजेंसी एएफपी से तालिबान प्रवक्ता ने अफगान सुरक्षा बलों के खिलाफ अभियान जारी रहने की बात कही है। कहा कि अमेरिका के साथ उनका समझौता विदेशी बलों पर हमला न करने का है लेकिन अफगान बलों से संघर्ष को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है।

शनिवार को कतर की राजधानी दोहा में हुए शांति समझौते में भरोसा बढ़ाने वाले उपायों के तहत एक-दूसरे के कैदियों को छोड़ने की सहमति बनी थी। लेकिन इस समझौते में अफगानिस्तान सरकार शामिल नहीं है। उसकी ओर से यह सहमति अमेरिका ने जताई थी। समझौते के अनुसार दस मार्च तक अफगान सरकार की जेलों में बंद पांच हजार तालिबान लड़ाके छोड़े जाने हैं, बदले में तालिबान अपनी कैद से एक हजार अफगान सरकारी सैनिकों और अन्य को रिहा करेगा। लेकिन अफगान राष्ट्रपति ने तालिबान की इस मांग को मानने से इन्कार कर दिया है। गनी ने रविवार को कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैदियों की रिहाई के बारे में उनसे कुछ नहीं कहा है। यह मसला आपसी बातचीत में तय होना है। सोमवार को तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने कहा, हम अफगान सरकार से अंदरूनी मसलों पर बात करने को तैयार हैं लेकिन इससे पहले उन्हें हमारे पांच हजार बंदियों को रिहा करना होगा। जब तक यह रिहाई नहीं होगी, तब तक बातचीत शुरू नहीं होगी। प्रवक्ता ने कहा, ये लोग अमेरिकी सैनिकों ने पकड़े थे और उन्हें अफगान जेलों में रखा था। अब अमेरिका से समझौता हो गया, तो इन बंदियों को छोड़ा जाना चाहिए। इनमें तमाम बीमार और बुजुर्ग हैं। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि दोनों पक्षों में जल्द वार्ता शुरू हो जाएगी। इस वार्ता से अफगानिस्तान में समस्याओं के स्थायी समाधान और युद्धविराम की स्थिति बनेगी। लेकिन पश्चिमी देशों के राजनयिक और विश्लेषक भविष्य में बड़ी चुनौतियों के आड़े आने की आशंका जता रहे हैं।

अफगानिस्तान में शांति समझौते के बाद लगमन प्रांत के अलिंगार जिले में तालिबान लड़ाकों ने इसका जश्न मनाया। एएफपी

सैन्य गतिविधियां बंद नहीं करेगा तालिबान : तालिबान प्रवक्ता ने कहा, शांति समझौते के बाद हिंसा कम हो जाने पर लोग खुशी मना रहे हैं। हम उनकी खुशी को कम करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी सामान्य सैन्य गतिविधियां बंद कर देंगे। हम अपनी सैन्य ताकत पहले जैसी ही बनाए रहेंगे। इससे हम जरूरत के समय कभी भी कार्रवाई करने में सक्षम रहेंगे।

ईरान ने कहा-अफगानिस्तान हो या सीरिया समस्या की जड़ है अमेरिका

तेहरान, एएनआइ : ईरान ने आतंकी संगठन तालिबान के साथ शनिवार को शांति समझौता करने वाले अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने समझौते पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि अफगानिस्तान हो या सीरिया समस्या की जड़ अमेरिका है।

ईरानी विदेश मंत्री ने रविवार को ट्विटर पर लिखा, 'अमेरिका को अफगानिस्तान में धावा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा किया और नतीजों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराया। अपमान के 19 साल बाद अब अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है। अफगानिस्तान, सीरिया, इराक या यमन चाहे कहीं भी हो अमेरिका एक समस्या है। वे भारी गड़बड़ी के बाद हर जगह से चले जाएंगे।' अमेरिका और ईरान के बीच पिछले करीब दो साल से तनातनी का दौर चल रहा है। दोनों के संबंध मई, 2018 में उस समय बेहद खराब हो गए थे, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते से अमेरिका के हटने का एलान कर दिया था। साथ ही ईरान पर कई सख्त प्रतिबंध थोप दिए थे। पिछले करीब एक वर्ष के दौरान दोनों देशों में कई बार सैन्य टकराव की नौबत आ चुकी है।

जुकाम से परेशान पोप नहीं ले रहे लेंटन रिट्रीट में हिस्सा

वेटिकन सिटी, एपी : प्रत्येक रविवार को होने वाली पारंपरिक प्रार्थना सभा में पोप फ्रांसिस ने श्रद्धालुओं के समक्ष घोषणा की कि वह जुकाम की वजह से हफ्तेभर तक चलने वाले आध्यात्मिक लेंटन रिट्रीट में हिस्सा नहीं लेंगे। पोप बनने के बाद सात साल में पहली बार वह इस आध्यात्मिक आयोजन में हिस्सा नहीं लेंगे।

83 वर्षीय पोप फ्रांसिस को अपनी युवावस्था में श्वास संबंधी बीमारी की वजह से अपने फेफड़े का एक हिस्सा गंवाना पड़ा था। जुकाम की वजह से उन्होंने इस हफ्ते होने वाले कई आधिकारिक कार्यक्रम भी रद कर दिए हैं। श्रद्धालुओं के समक्ष आने से पहले बुधवार को भी उन्हें खांसी से परेशान देखा गया था। रविवार को श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए पोप ने खुद यह घोषणा की कि वह जुकाम से पीड़ित हैं और लेंटन रिट्रीट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

विश्व की नंबर वन टीम हुई धड़ाम

शर्मनाक हार ▶ न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम को सात विकेट से हराया

दो मैचों की सीरीज में मेहमान टीम का किया सूपड़ा साफ

क्राइस्टचर्च, प्रेट्र : सितारों से सजी भारतीय टीम एक बार फिर कागजी शेर साबित हुई जिसे न्यूजीलैंड की अनुशासित टीम ने दूसरे और अंतिम टेस्ट में तीन दिन के भीतर सोमवार को यहां सात विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 से सूपड़ा साफ किया। भारत के 132 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 36 ओवर में तीन विकेट पर 132 रन बनाकर जीत दर्ज की।

एक घंटे में पवेलियन लौटे भारतीय : भारतीय टीम सोमवार सुबह छह विकेट पर 90 रन से आगे खेलने उतरी और एक घंटे के अंदर ही उसकी दूसरी पारी 124 रन पर सिमट गई। बल्लेबाजी करते हुए मुहम्मद शमी को गेंद से चोट लगी और वह गेंदबाजी करने नहीं उतरे जिससे न्यूजीलैंड की राह आसान हो गई।

ब्लंडेल-लाथम ने आसान बनाया लक्ष्य : सलामी बल्लेबाजों टॉम ब्लंडेल (113 गेंद में 55 रन) और टॉम लाथम (74 गेंद में 52 रन) ने पहले विकेट के लिए 103 रन की साझेदारी करके आसान जीत की नींव रखी। इस सीरीज को जीतकर न्यूजीलैंड ने आइसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 120 अंक हासिल किए और उसके कुल 180 अंक हो गए हैं। भारत हालांकि वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश को हराकर 360 अंक के साथ शीर्ष पर चल रहा है।

स्विंग के सामने टेके घुटने : भारत ने न्यूजीलैंड दौरे पर टी-20 सीरीज 5-0 से जीती थी लेकिन इसके बाद विराट कोहली की टीम को वनडे सीरीज में 0-3 और टेस्ट सीरीज में 0-2 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। भारत के इस प्रदर्शन से एक बार फिर साबित हो गया कि कागजों पर उसका रिकॉर्ड भले ही कितना अच्छा हो लेकिन जब गेंद स्विंग और सीम करती है तो उसके बल्लेबाज धराशायी हो जाते हैं। इंग्लैंड में 2014 और 2018 तथा अब न्यूजीलैंड में टीम को ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। सीरीज के हार के अंतर से अधिक समस्या यह है कि भारतीय बल्लेबाजों ने बिना संघर्ष किए घुटने टेक दिए। पहले विदेशी दौरों पर देखा गया था कि भारतीय टीम ने चुनौती का डटकर सामना किया, लेकिन इस दौरे पर ना तो उनके बल्लेबाज कोई कमाल दिखा सके और ना ही गेंदबाज। चिंता का विषय यह भी रहा कि इशांत शर्मा और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी चोटिल भी हो गए।

सिर्फ लगे चार अर्धशतक : दो मैचों की सीरीज की चार पारियों में भारत की ओर से सिर्फ चार अर्धशतक लगे और इस दौरान सीम और स्विंग लेती गेंद के खिलाफ अजिंक्य रहाणे, मयंक अग्रवाल, कोहली, चेतेश्वर पुजारा और पृथ्वी शॉ सहित लगभग सभी खिलाड़ियों की तकनीक पर सवाल उठे। भारत के लिए सबसे बड़ा झटका कप्तान कोहली का प्रदर्शन रहा जो चार पारियों में सिर्फ 38 रन बना सके।

पंत भी नहीं चले : सोमवार को भारत का निचला क्रम एक बार फिर नाकाम रहा और टीम ने 34 रन जोड़कर बाकी चार विकेट भी गंवा दिए। रिद्धिमान साहा पर तरजीह देकर रिषभ पंत को मौका दिया गया लेकिन उन्होंने एक बार फिर निराश किया। टिम साउथी (तीन विकेट) और ट्रेंट बोल्ट (चार विकेट) की तूफानी गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हनुमा विहारी (09) सुबह आउट होने वाले पहले बल्लेबाज रहे। उन्होंने लेग साइड से बाहर जाती गेंद पर विकेट के पीछे कैच थमाया। पंत भी इसके बाद बोल्ट की गेंद पर विकेटकीपर बीजे वाटलिंग को कैच दे बैठे। वह इस सीरीज के दौरान 19, 25, 12 और चार रन की पारियां ही खेल पाए। मुहम्मद शमी (05) को साउथी ने पवेलियन भेजा जबकि जसप्रीत बुमराह (04) रन आउट हुए।

नहीं दिखा लड़ने का माद्दा : भारतीय टीम 2018 में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड में भी हारी थी लेकिन तब उसने हर मैच में विपक्षी टीमों को उसके घर में टक्कर दी थी लेकिन यहां पांच टी-20 मैचों की सीरीज जीतने के बाद कोहली की टीम पटरी से उतर गई। उसने तीन वनडे तो हारे ही उसके बाद दोनों टेस्ट दान में विपक्षी टीम को दे दिए। पिछले दौरों में देखा गया कि विराट की टीम अंत तक हार नहीं मानती थी लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऐसा लगा कि यह टीम जीतना ही नहीं चाहती है। सीरीज के दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन प्रशंसकों को उम्मीद थी कि पंत और विहारी स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाएंगे लेकिन भारत में लोगों के सोकर उठने से पहले ही पूरी टीम पवेलियन पहुंच गई।

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान निराश खड़े भारतीय कप्तान विराट कोहली। एएनआइ

विराट कोहली के लिए बुरा सपना रहा न्यूजीलैंड दौरा

क्राइस्टचर्च : भारतीय कप्तान विराट कोहली के लिए न्यूजीलैंड दौरा किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। चार टी-20, तीन वनडे और दो टेस्ट की कुल 11 पारियों में कोहली के बल्ले से सिर्फ 218 रन ही निकल पाए। वहीं टेस्ट सीरीज में उनका औसत 9.50 का रहा है, जिसमें उन्होंने 2, 19, 3, 14 का स्कोर किया। यह किसी भी सीरीज में उनका दूसरा सबसे खराब औसत है। कोहली का सबसे खराब औसत 2016-17 बॉर्डर-गावस्कर सीरीज में है, जहां उन्होंने पांच पारियों में 9.20 के खराब औसत से मात्र 46 रन बनाए थे। वहीं 10वीं बार घर से बाहर किसी सीरीज में भारतीय कप्तान का औसत 10 से कम का रहा है। इन 10 सीरीज में भारत को नौ में हार मिली जबकि एक सीरीज ड्रॉ रही।

स्कोर बोर्ड

टॉस : न्यूजीलैंड (गेंदबाजी) मैन ऑफ द मैच : काइली जेमिसन मैन ऑफ द सीरीज : टिम साउथी

भारत (पहली पारी) : 242 रन (63 ओवर) न्यूजीलैंड (पहली पारी) : 235 (73.1 ओवर)

भारत (दूसरी पारी) (90/6 से आगे) 124 (46 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
हनुमा विहारी का. वाटलिंग बो. साउथी	09	18	02	00
रिषभ पंत का. वाटलिंग बो. बोल्ट	04	14	00	00
रवींद्र जडेजा नाबाद	16	22	01	01
मुहम्मद शमी का. ब्लंडेल बो. साउथी	05	11	00	00
जसप्रीत बुमराह रन आउट	04	08	01	00

अतिरिक्त : (बा-9, लेबा-12) 21

कुल : 46 ओवर में 124 रन पर सभी आउट

विकेट पतन : 7-97 (विहारी, 38.4), 8-97 (पंत, 39.3), 9-108 (शमी, 42.4)

गेंदबाजी :
टिम साउथी 11-2-36-3
ट्रेंट बोल्ट 14-4-28-4
काइली जेमिसन 8-4-18-0
कोलिन डि ग्रैंडहोम 5-3-3-1
नील वैगनर 8-1-18-1

न्यूजीलैंड (दूसरी पारी) 132/3 (36 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
टॉम लाथम का. पंत बो. यादव	52	74	10	00
टॉम ब्लंडेल बो. बुमराह	55	113	08	01
विलियमसन का. रहाणे बो. बुमराह	05	08	01	00
रॉस टेलर नाबाद	05	09	01	00
हेनरी निकोल्स नाबाद	05	13	01	00

अतिरिक्त : (बा-1, लेबा-8, नोबॉ-1) 10

कुल : 36 ओवर में तीन विकेट पर 132 रन

विकेट पतन : 1-103 (लाथम, 27.6), 2-112 (केन, 30.6), 3-121 (ब्लंडेल, 32.5)

गेंदबाजी :
जसप्रीत बुमराह 13-2-39-2
उमेश यादव 14-3-45-1
मुहम्मद शमी 3-1-11-0
रवींद्र जडेजा 5-0-24-0
विराट कोहली 1-0-4-0

परिणाम : न्यूजीलैंड सात विकेट से जीता

242 रन भारतीय टीम का इस सीरीज में सर्वोच्च स्कोर रहा। 2002-03 में न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर 161 रहा था

34.61 के औसत से न्यूजीलैंड के आठवें से 10वें नंबर के बल्लेबाजों ने बनाए। दो पारियों में आखिरी तीन विकेट के लिए छह साझेदारियां हुईं, जिसमें 205 रन बने। वहीं भारत की ओर से निचलेक्रम के बल्लेबाजों ने सिर्फ 124 रन बनाए, जिसमें एक भी अर्धशतकीय साझेदारी नहीं थी

58 रन मयंक अग्रवाल की ओर से खेली गई पारी सीरीज में किसी भारतीय की ओर से सर्वोच्च रन की पारी रही। यह दो या उससे ज्यादा टेस्ट की सीरीज में भारत की ओर से न्यूनतम निजी स्कोर है

2002-03 के बाद दो या उससे ज्यादा मैचों की टेस्ट सीरीज में किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया है। तब से लेकर अब तक भारत ने 60 सीरीज खेली हैं

2011-12 के बाद भारतीय टीम ने दो या उससे ज्यादा टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप झेला है। यह पहली बार है जब भारतीय कप्तान विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने क्लीन स्वीप झेला है

14 विकेट न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी ने इस सीरीज में झटके। वह अपने करियर में दूसरी बार टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज चुने गए

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका

टीम	मैच	जीत	हार	अंक
भारत	9	7	2	360
ऑस्ट्रेलिया	10	7	2	296
न्यूजीलैंड	7	3	4	180
इंग्लैंड	9	5	3	146
पाकिस्तान	5	2	2	140
श्रीलंका	4	1	2	80
द. अफ्रीका	7	1	6	24
वेस्टइंडीज	2	0	2	0
बांग्लादेश	3	0	3	0

सीरीज में रन बनाने वाले शीर्ष पांच बल्लेबाज

बल्लेबाज	पारी	रन	सर्वश्रेष्ठ	औसत
टॉम लाथम	4	122	52	40.66
टॉम ब्लंडेल	4	117	55	39.00
मयंक	4	102	58	25.50
पुजारा	4	100	54	25.00
पृथ्वी शॉ	4	98	54	24.50

सीरीज में विकेट लेने वाले शीर्ष पांच गेंदबाज

गेंदबाज	पारी	विकेट	सर्वश्रेष्ठ	औसत
साउथी	4	14	5/61	13.14
ट्रेंट बोल्ट	4	11	4/28	19.36
जेमिसन	4	9	5/45	16.33
बुमराह	4	6	3/62	31.66
इशांत	2	5	5/68	15.20

18.05 रन के औसत से भारत ने विकेट गंवाए। यानी औसतन भारत का प्रत्येक विकेट 18.05 रन बाद गिरा। यह भारतीय बल्लेबाजों का किसी भी टेस्ट सीरीज में तीसरा सबसे खराब औसत है। 2002-03 में न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में 13.37 और 1969-70 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत में 16.61 रन के औसत से टीम इंडिया के विकेट गिरे थे

गेंदबाजों को आक्रमण के लिए रन नहीं मिले : कोहली

क्राइस्टचर्च, प्रेट्र : बल्लेबाजी क्रम के एक बार फिर विफल रहने के कारण 0-2 से सीरीज गंवाने के बाद कप्तान विराट कोहली ने कहा कि इस प्रदर्शन के लिए कोई बहाना नहीं है। कोहली ने मैच के बाद कहा कि टेस्ट मैचों में हम वैसा क्रिकेट नहीं खेल पाए जैसा खेलना चाहते थे। बल्लेबाजों ने इतने रन नहीं बनाए कि गेंदबाज प्रयास और आक्रमण करते। गेंदबाजी अच्छी थी, मुझे लगता है कि वेलिंगटन में हमने अच्छी गेंदबाजी की।

कोहली ने कहा कि पहले मैच में हम पर्याप्त जज्बा नहीं दिखा पाए जबकि यहां हम मैच को खत्म नहीं कर पाए। हम लंबे समय तक सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी नहीं कर पाए। उन्होंने काफी दबाव बनाया। हम अपनी योजना को अमलीजामा नहीं पहना पाए और न्यूजीलैंड ने अपनी योजना को लागू किया। यह निराशाजनक है। हमें बैठकर विचार करना होगा और चीजों को सही करना होगा। यह पूछने पर कि क्या टॉस हारने का भी असर पड़ा, कोहली ने कहा कि टॉस एक मुद्दा हो सकता है लेकिन हम शिकायत नहीं करेंगे।

न्यूजीलैंड के पत्रकारों के सवालों से नाराज हुए कोहली : कोहली सोमवार को नाराज हो गए जब उनसे विपक्षी कप्तान केन विलियमसन के आउट होने पर उनके आक्रामक जश्न पर सवाल किए गए। एक स्थानीय पत्रकार ने विलियमसन के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्दों के इस्तेमाल पर कोहली की प्रतिक्रिया पूछी तो भारतीय कप्तान नाराज हो गए। कोहली के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था और उन्होंने पूछा, आपको क्या लगता है? मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं। कोहली ने कहा कि आपको जवाब खोजने की जरूरत है और अगली बार बेहतर सवाल के साथ आइये। जो हुआ उसे लेकर आप यहां आधी-अधूरी जानकारी और आधे-अधूरे सवाल के साथ नहीं आ सकते। अगर आपको विवाद पैदा करना है तो यह सही जगह नहीं है। मैंने मैच रेफरी रंजन मदुगले से बात की और जो हुआ उससे उन्हें कोई समस्या नहीं है। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह ने जब विलियमसन को आउट किया तो कोहली ने हर बार की तरह जमकर जश्न मनाया। कोहली ने स्थानीय दर्शकों को चुप रहने का इशारा भी किया था। विलियमसन से जब कोहली के जश्न के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे हंसकर टाल दिया। उन्होंने कहा कि विराट ऐसे ही हैं। वह मैदान पर जुनूनी हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरुरत है।

क्या कोई बता सकता है कि न्यूजीलैंड ने दुनिया की नंबर एक टीम पर पूरी तरह से दबदबा कैसे बनाया? मैं सही कारण नहीं समझ पा रहा हूं। क्या किसी व्यक्ति को अपमानित किए बगैर कोई मेरी मदद कर सकता है। धैर्य रखने, शांत चित्त रहने और प्रतिबद्धता दिखाने के लिए न्यूजीलैंड की सराहना कीजिए।
- बिशन सिंह बेदी

भारत को हराने और टेस्ट सीरीज आसानी से जीतने के लिए न्यूजीलैंड को बधाई। भारत जरूरी अनुशासन नहीं दिखा पाया और यह बेहद निराशाजनक है।
- वीवीएस लक्ष्मण

2018 के इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका दौरों के विपरीत इस सीरीज में कोहली की टीम प्रतिस्पर्धा भी पेश नहीं कर पाई। कोहली के नेतृत्व में भारत ने विदेशी सरजमीं पर अधिकतर टेस्ट मैच में अच्छी प्रतिस्पर्धा पेश की है लेकिन यह सीरीज अलग थी। भारत ने सिर्फ हिस्सा लिया। बल्लेबाजी और न्यूजीलैंड के निचले क्रम को आउट करने में विफलता ने भारत को निराश किया।
- आकाश चोपड़ा

सिर्फ पंत को दोषी नहीं ठहरा सकते : कोहली

क्राइस्टचर्च : कोहली ने कहा कि आलोचनाओं के शिकार विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत को 'काफी मौके मिले' लेकिन फिलहाल टीम इस युवा क्रिकेटर की जगह किसी और को परखने के बारे में नहीं सोच रही। उन्होंने साथ ही कहा कि टीम की सामूहिक विफलता का दोष किसी एक खिलाड़ी पर नहीं मढ़ा जा सकता। प्रदर्शन में निरंतरता नहीं होने के कारण पंत पिछले एक साल से लोगों के निशाने पर हैं।

पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ चार पारियों में सिर्फ 60 रन बना सके जिससे रिद्धिमान साहा पर उन्हें तरजीह देने के फैसले को लेकर बहस शुरू हो गई है। कप्तान कोहली ने पंत का बचाव किया। कोहली ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज की शुरुआत से हमने घरेलू सत्र में भी उन्हें (पंत) काफी मौके दिए। इसके बाद वह कुछ समय के लिए नहीं खेले। उन्होंने इसके बाद कड़ी मेहनत की। आपको तय करना होगा कि किसी और को मौका देने का सही समय कौन सा है। अगर आप लोगों को काफी जल्दी बदल दोगे तो वह आत्मविश्वास खो सकता है। यह पूछने पर कि क्या उनका मानना है कि पंत ने टीम में अपनी जगह पक्की मान ली है, कोहली ने स्पष्ट किया कि टीम की संस्कृति किसी भी खिलाड़ी को ऐसा सोचने को प्रेरित नहीं करती।

केन विलियमसन बोले, 50 रन और होते तो हमारे लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण होती

क्राइस्टचर्च : न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने कहा कि दूसरे टेस्ट मैच में तीन दिन के अंदर जीत दर्ज करना सही मायने में यह नहीं दिखाता कि यह मुकाबला कितना प्रतिस्पर्धी था और अगर भारतीय टीम ने 50 रन और बनाए होते तो हमारे लिए स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण होती।

विलियमसन ने मैच के बाद कहा कि यह शानदार प्रदर्शन था लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस नतीजे से यह पता नहीं चलता है कि मैच कितना प्रतिस्पर्धी था। भारत ने अगर 50 रन और बनाए होते तो यह मुकाबला बराबरी का लगता। उपमहाद्वीप से उलट यहां दोनों टेस्ट मैचों की पिच से गेंद और बल्ले के बीच बराबरी का मुकाबला था जहां रन बनाना थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने कहा कि पिच के लिहाज से दोनों मैचों में गेंद और बल्ले का बराबरी का मुकाबला था और रन बनाना आसान नहीं था। आपको थोड़ी किस्मत का साथ चाहिए था और गेंदबाज पर दबाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पिछले दो मैचों में टीम के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है दोनों पिचें तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा मददगार थी। ऐसी परिस्थितियों में भी वेलिंगटन में जिस तरह से हमने पहली पारी में बल्लेबाजी कर प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया वह देखना शानदार था।

दो चयनकर्ताओं के लिए नामों की छंटनी करेगी सीएसी

मुंबई, प्रेट्र : बीसीसीआइ की क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) मंगलवार को यहां अपनी पहली बैठक करेगी, जिसमें दो राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। बीसीसीआइ के संविधान के अनुसार चयनकर्ताओं के चयन की जिम्मेदारी तीन सदस्यीय सीएसी की है, लेकिन 31 जनवरी को नियुक्ति के बाद से इस समिति ने कोई बैठक नहीं की।

पूर्व भारतीय क्रिकेटरों मदन लाल, आरपी सिंह और सुलक्षणा नाइक की समिति निजी साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की छंटनी करेगी। मदन लाल ने सोमवार को पुष्टि की कि वह बैठक के लिए मुंबई जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हां, मैं बैठक के लिए जा रहा हूं लेकिन मेरे पास अब तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। बीसीसीआइ के एक सूत्र ने पुष्टि की कि बैठक का आयोजन उम्मीदवारों की छंटनी के लिए किया जा रहा है।

चयन समिति के प्रमुख एमएसके प्रसाद और उनके साथी सदस्य गगन खोड़ा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और समिति इन्हीं के विकल्पों का चयन करेगी। कोरोना वायरस के खतरे के कारण एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) की बैठक के लिए दुबई नहीं जाने वाले बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली के मंगलवार को बीसीसीआइ मुख्यालय में मौजूदा रहने की संभावना है। जनवरी में बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा था कि नई चयनसमिति पैनल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम का चयन करेगा।

कोरोना वायरस की वजह से अजलन शाह कप आगे खिसका

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

असर
- अप्रैल की जगह इस बार सितंबर-अक्टूबर में होगा आयोजन
- इस बार भारत की हॉकी टीम नहीं ले रही है भाग

दुनिया भर में फैल रहे भीषण कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए सोमवार को अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के 29वें सत्र को अप्रैल की जगह सितंबर-अक्टूबर में आयोजित कराने का फैसला किया गया।

आयोजकों के अनुसार, अजलन शाह कप का आयोजन मलेशिया के इपोह में 11 से 18 अप्रैल तक होना था, लेकिन अब यह टूर्नामेंट 24 सितंबर से तीन अक्टूबर तक होगा। इसमें नियमित तौर पर खेलने वाले और चार बार के चैंपियन भारत के इस साल इस टूर्नामेंट में भाग लेने का कार्यक्रम नहीं है। आयोजन समिति के अध्यक्ष डेतो हाजी अब्द रहीम बिन मुहम्मद ने कहा, 'यह खिलाड़ियों, अधिकारियों और सभी पक्षों के सर्वश्रेष्ठ हित में है कि सुल्तान अजलन शाह कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2020 को स्थगित कर दिया जाए।'

आयोजन समिति ने इसके कारण होने वाली असुविधा के लिए माफी मांगी है, लेकिन कहा कि दुनिया भर में मौजूदा संकट को देखते हुए यह फैसला किया गया है। आयोजन समिति के अनुसार, 'एफआइएच (अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ), एएचएफ (एशियाई हॉकी महासंघ), एमएचसी (मलेशिया हॉकी महासंघ) और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों को इस फैसले की जानकारी दे दी गई है।' इस बार अजलन शाह कप में 10 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मेजबान मलेशिया, पाकिस्तान और गत चैंपियन द. कोरिया की टीमों को भाग लेना था। वायरस के कारण इससे पहले भी कई खेल प्रतियोगिताएं रद, स्थगित या स्थानांतरित हो चुकी हैं। वायरस से अब तक दुनिया भर में 3000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 86000 से अधिक संक्रमित हुए हैं।

एशियाई पैदल चाल चैंपियनशिप रद

नई दिल्ली : जापान में 15 मार्च को प्रस्तावित एशियाई पैदल चाल चैंपियनशिप को कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए रद कर दिया गया। इस स्पर्धा में 13 भारतीय खिलाड़ियों को भाग लेना था।

टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली भावना जाट को नोमी शहर में होने वाली इस स्पर्धा में भारतीय चुनौती की अगुवाई करनी थी। एशियाई एथलेटिक्स महासंघ (एएए) ने जापान के महासंघ के निवेदन पर इसे रद करने का फैसला किया। एएए के अध्यक्ष दहलान अल हमद ने कहा, 'एएए परिषद से विचार विमर्श और अनुमोदन के बाद मैं पुष्टि करता हूं कि एशियाई 20 किमी पैदल चाल चैंपियनशिप रद कर दी गई है।' जापान में इस बीमारी के लगभग 100 मामले दर्ज किए गए हैं।

आइपीएल डायरी

पिछले साल वनडे विश्व कप के बाद से ही धौनी के संन्यास के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि पूर्व भारतीय कप्तान ने तब से कोई मैच नहीं खेला है

चेन्नई के पहले अभ्यास सत्र में धौनी का शानदार स्वागत

चेन्नई, प्रेट्र : महेंद्र सिंह धौनी का सोमवार को चेन्नई सुपरकिंग्स की तरफ से पहले अभ्यास सत्र के दौरान एमए चिदंबरम स्टेडियम में जोरदार स्वागत किया गया। धौनी अपने करियर को लेकर लगाए जा रहे कयासों के बीच अभ्यास के लिए पहुंचे। पिछले साल वनडे विश्व कप के बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि इस पूर्व भारतीय कप्तान ने तब से कोई मैच नहीं खेला है लेकिन आइपीएल में वह वापसी करेंगे। धौनी जब स्टेडियम में पहुंचे तो 'धौनी-धौनी' के नारे गूंजने लगे।

उन्होंने कुछ जोरदार शॉट लगाकर अपने प्रशंसकों को प्रसन्न किया। चेन्नई के खिलाड़ियों का अभ्यास देखने के लिए यहां कुछ सौ दर्शक उपस्थित थे। चेन्नई के जिन खिलाड़ियों ने सोमवार को अभ्यास में भाग लिया उनमें अंबाती रायुडू, मुरली विजय, पीयूष चावला, कर्ण शर्मा, आर साई किशोर और एन जगदीशन शामिल थे। आइपीएल का उद्घाटन मैच 29 मार्च को चेन्नई और मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस के बीच मुंबई में खेला जाएगा।

राजस्थान रॉयल्स ने नागपुर में शुरू किया अभ्यास

जयपुर : आइपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने सोमवार को बॉडिंग सत्र से आगामी आइपीएल सत्र की शुरुआत की। नागपुर में लगे कैंप में म्यूजिक के साथ शुरुआत हुई। खिलाड़ियों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया, जिसमें उनका फोकस और ध्यान का टेस्ट लिया गया। इस सत्र में खिलाड़ियों को एक दूसरे को जानने का मौका मिला। इस दौरान खिलाड़ियों ने चित्रकला में भी हाथ आजमाए। इस सत्र का मकसद था कि खिलाड़ी एक दूसरे से घुलमिल जाएं और बिना किसी दबाव के अपनी बात रख पाएं। इस सत्र से खिलाड़ियों को मानसिक रूप से भी मजबूत होने में मदद मिलेगी। खिलाड़ियों में आकाश सिंह, कार्तिक त्यागी, रॉबिन उथप्पा, मनन वोहरा, मयंक मार्कंडेय, वरुण आरोन, महिपाल लोमरोर, अनुज रावत, शशांक सिंह शामिल रहे।

चेन्नई में अभ्यास सत्र के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धौनी। प्रेट्र

दो एशियाई स्क्वॉश अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट स्थगित

चेन्नई : स्क्वॉश के दो टूर्नामेंट मलेशिया में होने वाली एशियाई टीम चैंपियनशिप और चीन में होने वाली एशियाई जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप को कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया है। एशियाई टीम चैंपियनशिप 25 से 29 मार्च के बीच कुआलालंपुर में, जबकि एशियाई जूनियर चैंपियनशिप चीन के क्विंगदाओ में 29 जून से तीन जुलाई के बीच होनी थी। यह फैसला एशियाई स्क्वॉश महासंघ की वार्षिक आम बैठक में किया गया। इन दोनों टूर्नामेंटों की नई तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी।

कतर और थाइलैंड मोटो जीपी रद

दोहा, आइएएनएस : कतर की राजधानी दोहा में आगामी आठ मार्च को प्रस्तावित मोटो जीपी सत्र की पहली रेस कोरोना वायरस के कारण रद कर दी गई है। अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल महासंघ (आइएमएफ) ने कहा, 'इटली, कतर सहित कई देशों के बीच यात्रा प्रतिबंधों के कारण लोसैल सर्किट पर होने वाली रेस आयोजित नहीं की जाएगी।' आइएमएफ ने आगे कहा कि मोटो 2 और मोटो 3 विश्व चैंपियनशिप रेस तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। वहीं, कोरोना वायरस के कारण थाइलैंड मोटो जीपी को भी स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 20 से 22 मार्च के दौरान बुरीराम में होना था।

सानिया व अंकिता के साथ भारत चुनौती के लिए तैयार

दुबई, प्रेट्र : शानदार लय में चल रही अंकिता रैना और अनुभवी सानिया मिर्जा की मौजूदगी से भारतीय टीम मंगलवार से यहां शुरू हो रहे छह देशों की फेड कप प्रतियोगिता में प्लेऑफ में जगह पक्की करने की कोशिश करेगी। अंकिता इस सत्र की शुरुआत से शानदार लय में है। उन्होंने आइटीएफ प्रतियोगिता के दो सिंगल्स खिताब जीतने के साथ दो डबल्स खिताब भी अपने नाम किए हैं।

बंगाल के गेंदबाज इशान पोरेल इस समय इतनी अच्छी लय में है कि वह कोहली को भी आउट कर सकते हैं।
– अरुण लाल, बंगाल के कोच

रीयल मैड्रिड के नाम हुआ एल क्लासिको

एल क्लासिको ▶ ला लीगा मुकाबला मैड्रिड ने 2-0 से जीता, विनिसियस जूनियर और मारियानो डियाज ने दागे गोल

मैड्रिड, एएफपी : ईबर के खिलाफ चार गोल करने वाले कप्तान लियोन मेसी ने सोमवार (भारतीय समयानुसार) को स्पेनिश लीग ला लीगा के सबसे बड़े मुकाबले एल क्लासिको के पहले हाफ में एक जोरदार शॉट जड़ा तो लगा कि वह इस महामुकाबले में बार्सिलोना को जीत दिलाकर ही मानेंगे लेकिन किस्मत इस बार रीयल मैड्रिड के कप्तान सर्जियो रामोस के साथ थी जो अंतिम सीटी बजने के बाद अपनी बाहों को फैलाकर जश्न मना रहे थे। उनकी प्रतिक्रिया इस जीत के महत्व का प्रतीक थी, ना सिर्फ तालिका के लिहाज से, बल्कि खिताब की दौड़ के लिहाज से भी। इस जीत के साथ ही रीयल मैड्रिड ला लीगा की अंक तालिका में बार्सिलोना को पछाड़कर नंबर एक पर पहुंच गया है।

गोल करने के बाद जश्न मनाते रीयल मैड्रिड के विनिसियस जूनियर। एएफपी

रीयल मैड्रिड ने बार्सिलोना को 2-0 से हराकर अपने खराब दौर का ना सिर्फ शानदार तरीके से अंत किया, बल्कि ला लीगा की तालिका में भी फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया। इस तरह रीयल मैड्रिड ने एल क्लासिको मुकाबला भी जीता और संभवतः अपना सत्र भी बचा लिया। रीयल मैड्रिड की टीम अब ला लीगा की तालिका में 26 मैचों में 16 जीत, आठ ड्रॉ व दो हार से 56 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है। उसने बार्सिलोना पर अब एक अंक की बढ़त बना ली है, जो अब 26 मैचों में 17 जीत, चार ड्रॉ एवं पांच हार से 55 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई है।

सैंटियागो बर्नबू स्टेडियम में हुए अत्यंत तेज मुकाबले में विनिसियस जूनियर के अलावा स्टॉपेज टाइम में मारियानो डियाज ने गोल दागा और चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी के हाथों मिली हार के बाद संकट के दौर से गुजर रहे रीयल मैड्रिड को नया जीवनदान दिया। बार्सिलोना की टीम पहले हाफ में कई मौकों को भुना नहीं पाई। रीयल मैड्रिड के करीम बेंजमा के पास भी पहले हाफ में कुछ मौके आए, लेकिन वह उन्हें गोल में नहीं बदल सके। करीम पिछले पांच मैचों से एक भी गोल नहीं कर सके हैं। पहला हाफ गोलरहित रहने के बाद रीयल मैड्रिड ने दूसरे हाफ में आक्रमण तेज कर दिया। 70वें मिनट तक दोनों ही टीमें एक-दूसरे के डिफेंस में सेंध नहीं लगा पाईं थीं। रीयल मैड्रिड की ओर से इस मैच का पहला गोल विनिसियस जूनियर ने किया। उन्होंने 71वें मिनट में बार्सिलोना के डिफेंडर जेरार्ड पीक को चकमा देकर गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। बेहतरीन गोलकीपरों में शुमार आंद्रे टेर स्टेगन भी विनिसियन को गोल करने से नहीं रोक सके।

मैच का दूसरा गोल भी रीयल मैड्रिड की ओर से हुआ, जिसे मारियानो डियाज ने दागा। मैनेजर जिनेदिन जिदान ने डियाज को निर्धारित समय खत्म होने के बाद इंजुरी टाइम में मैदान पर उतारा और उन्होंने अपने मैनेजर को निराश नहीं किया और मैदान पर उतरने के अगले ही मिनट में (90+2वें मिनट में) गोल दाग दिया। डियाज इस सत्र में जिदान की टीम की तरफ से एक भी मैच नहीं खेले थे और उन्हें अधिकतर समय बेंच पर ही बैठना पड़ा था। लेकिन, जिदान ने इस मैच में उन्हें उतारने का फैसला किया और उन्होंने अपनी टीम को यादगार जीत दिला दी।

विनिसियस ने तोड़ा मेसी का रिकॉर्ड : 19 साल 233 दिन की उम्र में रीयल मैड्रिड के विनिसियस जूनियर ने मैच का पहला गोल दागा। इसी के साथ वह एल क्लासिको में गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। उन्होंने बार्सिलोना के ही दिग्गज लियोन मेसी का रिकॉर्ड तोड़ा। मेसी 2007 में 19 साल 259 दिन की उम्र में एल क्लासिको में गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे।

रोनाल्डो भी रहे मौजूद : कभी रीयल मैड्रिड का हिस्सा रहे और फिलहाल जुवेंटस की ओर से खेलने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी एल क्लासिको का यह मुकाबला देखने के लिए सैंटियागो बर्नबू स्टेडियम में मौजूद थे। उन्होंने एक्जिक्यूटिव बॉक्स में बैठकर यह मैच देखा।

यह सप्ताह काफी मुश्किलों भरा रहा। हमने बात की थी कि इस सप्ताहांत हम किस तरह मौके को भुना सकते हैं और हमने ऐसा कर दिखाया।
– जिनेदिन जिदान, मैनेजर, रीयल मैड्रिड

सच्चाई यह है कि हमने गेंद के साथ अपना विश्वास खो दिया। हम नर्वस स्पैल में चले गए और तभी गोल हो गया।
– क्विक सेतियान, मैनेजर, बार्सिलोना

07 पिछले मैचों में बार्सिलोना की टीम रीयल मैड्रिड से हारी नहीं थी। बार्सिलोना ने चार मुकाबले जीते थे और तीन मुकाबले ड्रॉ रहे थे

02 अप्रैल 2016 के बाद रीयल मैड्रिड ने बार्सिलोना को पहली बार हराया

04 मैचों में अजेय रहने के बाद बार्सिलोना को पहली हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान उसने तीन मैच जीते थे और चैंपियंस लीग में नापोली के खिलाफ उसका पिछला मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा था

01 जीत ही पिछले चार मैचों में हासिल कर पाई थी रीयल मैड्रिड। इस दौरान उसने दो मैच हारे थे और उसका एक मुकाबला ड्रॉ रहा था

बंगाल के खिलाफ कर्नाटक की टीम का शीर्ष क्रम लड़खड़ाया

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए कर्नाटक ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल के तीसरे दिन सोमवार को यहां शीर्ष क्रम के अपने तीन महत्वपूर्ण विकेट जल्दी गंवा दिए। बंगाल ने अपनी दूसरी पारी में 161 रन बनाए लेकिन पहली पारी की बड़ी बढ़त के दम पर उसने कर्नाटक के सामने 352 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा।

कर्नाटक ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट पर 98 रन बनाए हैं और वह लक्ष्य से अब भी 254 रन पीछे है। न्यूजीलैंड दौरे में वनडे में शानदार प्रदर्शन करने वाले केएल राहुल (शून्य) को ईशान पोरेल ने पारी की दूसरी गेंद पर ही एलबीडब्यू कर दिया। देवदत्त पडिक्कल (नाबाद 50) और आर समर्थ (27) ने दूसरे विकेट के लिए 57 रन जोड़े, लेकिन इसके बाद 19 रन के अंदर समर्थ और कप्तान करुण नायर (छह) पवेलियन लौट गए। समर्थ को आकाशदीप ने जबकि नायर को मुकेश कुमार ने पवेलियन भेजा। अनुभवी मनीष पांडे (नाबाद 11) ने इसके बाद दिन का खेल समाप्त होने तक कर्नाटक को आगे कोई झटका नहीं लगने दिया। पडिक्कल ने अपनी अर्धशतकीय पारी में अब तक 109 गेंदों का सामना करके छह चौके लगाए हैं। इससे पहले सुबह बंगाल ने अपनी दूसरी पारी चार विकेट पर 72 रन से आगे बढ़ाई।

सौराष्ट्र को मिली बढ़त

राजकोट : चिंतन गजा के ऑलराउंड प्रदर्शन से गुजरात ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र के खिलाफ तीसरे दिन सोमवार को पहली पारी में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की। सौराष्ट्र के 304 रन के जवाब में इस पांच दिवसीय मुकाबले में गुजरात ने पहली पारी में 252 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने तक सौराष्ट्र ने दूसरी पारी में पांच विकेट पर 66 रन बना लिए जिससे उनकी कुल बढ़त 118 रन की हो गई। तीसरे दिन का खेल पूरी तरह से गजा के नाम रहा जिन्होंने 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 61 रन की पारी खेल गुजरात को संकट से उबारने के बाद सौराष्ट्र की दूसरी पारी के सभी पांच विकेट झटके। इससे पहले गुजरात ने दिन की शुरूआत पहली पारी में छह विकेट पर 119 रन से की। दूसरे दिन के नाबाद बल्लेबाज रुजुल भट्ट (71) और अक्षर पटेल (27) ने सातवें विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी कर टीम के स्कोर को 150 के पार पहुंचाया। भट्ट को इसके बाद गजा का अच्छा साथ मिला और दोनों ने नौवें विकेट के लिए 87 रन जोड़कर टीम को संकट से उबारा। भट्ट ने 212 गेंद की पारी में छह चौके लगाए जबकि गजा ने 103 गेंद खेली।

जॉर्ज लिंडे दक्षिण अफ्रीका टीम में नया चेहरा फाफ डुप्लेसिस और डुसेन की हुई वापसी

जोहानिसबर्ग, प्रेट्र : बायें हाथ के स्पिनर जॉर्ज लिंडे धर्मशाला में 12 मार्च से भारत के खिलाफ शुरू हो रही तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम में एकमात्र नया चेहरा होंगे जबकि पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसिस की टीम में वापसी हुई है। लिंडे ने पिछले साल भारत दौरे के दौरान टेस्ट पदार्पण किया था।

डुप्लेसिस और रेसे वान डेर डुसेन दोनों की टीम में वापसी हुई है। डुसेन को पिछली सीरीज में आराम दिया गया था। डुप्लेसिस की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका की टीम निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए विश्व कप के पहले चरण से ही बाहर हो गई जिसके बाद से उन्होंने कोई वनडे

वनडे सीरीज

मैच नहीं खेला है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि चयन में दक्षिण अफ्रीका के अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों की खोज का रास्ता निकाला गया है। ऐसी टीम चुनने का प्रयास किया गया है, जिससे 2023 विश्व कप के लिए टीम तैयार की जा सके। यह खिलाड़ियों के लिए अच्छा मौका है कि वह अच्छा प्रदर्शन करके टीम में अपनी जगह को पक्की कर सकें। टीम में स्पिनर तबरेज शम्सी को नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि उनकी पत्नी खदीजा पहले बच्चे को जन्म देने जा रही हैं। तेज गेंदबाज कैगिसो रबादा भी चोट के कारण टीम में नहीं है। चयनकर्ता लिंडा जोंडी ने कहा कि हम भारत के चुनौतीपूर्ण दौरे के लिए टीम चयन से संतुष्ट हैं। पिछले वर्ष टी-20 सीरीज में कुछ खिलाड़ियों ने भारत में अच्छा प्रदर्शन किया था। हमने जॉर्ज लिंडे को एक और मौका देने का फैसला किया है।

टीम इस प्रकार है : क्विंटन डिकॉक (कप्तान), तेंबा बावुमा, रेसे वान डेर डुसेन, फाफ डुप्लेसिस, काइल वेरीने, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, जान-जान स्मट्स, आंदिले फेलुकवायो, लुंगी नगिदी, लुथो सिपामला, ब्युरेन हेंड्रिक्स, एनरिक नोर्त्जे, जॉर्ज लिंडे और केशव महाराज।

न्यूजीलैंड को हरा ऑस्ट्रेलिया भी सेमीफाइनल में

मेलबर्न, प्रेट्र : मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने महिला टी-20 विश्व कप के अपने करो या मरो मैच में सोमवार को यहां न्यूजीलैंड को चार रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। ग्रुप-ए के इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बेथ मूने की 60 रन की पारी के दम पर पांच विकेट पर 155 रन बनाने के बाद न्यूजीलैंड को सात विकेट पर 151 रन पर रोक दिया।

इस ग्रुप से भारत ने पहले की सेमीफाइनल के लिए जगह पक्की कर ली है जबकि ग्रुप-बी से दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड ने अंतिम चार का टिकट कटाया है। दक्षिण अफ्रीका का अभी एक मैच बचा है और उसके बाद ही तय होगा कि अंतिम-चार में किसकी भिड़ंत किससे होगी। जहां

महिला टी-20 विश्व कप

तक इस मैच की बात है तो लेग स्पिनर जार्जिया वेयरहम ने चार ओवर में महज 17 रन देकर तीन विकेट चटकाकर न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया। कैटी मार्टिन ने हालांकि 18 गेंद में चार चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 37 रन की पारी खेल न्यूजीलैंड की उम्मीदों को अंत तक जीवंत रखा लेकिन उनका प्रयास टीम के लिए नाकाफी साबित हुआ। इससे पहले मूनी ने 50 गेंद की पारी में छह चौके और दो छक्के लगाए। उन्हें मेग लैनिंग (21), एशलिघ गार्डेनर (20) का अच्छा साथ मिला हेंस ने आखिरी ओवरों में आठ गेंद में नाबाद 19 रन बनाए।

बांग्लादेश पर श्रीलंका की जीत में श्रीवर्दना चमकीं

मेलबर्न : शशिकला श्रीवर्दना ने अपने अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच में चार विकेट चटकाए जिससे श्रीलंका ने सोमवार को यहां अंतिम ग्रुप मैच में बांग्लादेश को नौ विकेट से हरा दिया। श्रीवर्दना (चार विकेट) के विश्व कप के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और अचिनी कुलसूर्या के दो विकेट के सामने बांग्लादेश की टीम आठ विकेट पर 91 रन ही बना सकी। बांग्लादेश की ओर से निगार सुल्ताना ने सर्वाधिक 39 रन की पारी खेली। उनके अलावा संजीदा इस्लाम (13) और फरगाना हक (13) ही दोहरे अंक में पहुंच सकी।

अपनी कमियों पर काम करने से जीत मिली : लैनिंग

मेलबर्न : ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मेग लैनिंग ने महिला टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने के बाद सोमवार को कहा कि उनकी टीम सही समय पर अपने खेल के स्तर में सुधार कर रही है। लैनिंग ने कहा कि सोमवार का प्रदर्शन हमारा अभी तक का टूर्नामेंट का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। मुझे नहीं लगता कि हम इससे बेहतर स्थिति में सेमीफाइनल में जा सकते थे। उन्होंने कहा कि एक अच्छी टीम के खिलाफ जीत हासिल करना अच्छी बात है। मुझे लगता है कि यह शानदार प्रदर्शन था। ह

विविध

नेपाली महिलाओं ने किसान को पीट-पीटकर मार डाला

जासं, मधुबनी : बिहार के मधुबनी जिले के लदनियां थाना क्षेत्र के पिपरारी गांव में बकरी चराने के विवाद में सोमवार को महिलाओं ने एक किसान को पीट-पीटकर मार डाला। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने चारों महिलाओं को पकड़कर एक घर में बंद कर दिया। सभी महिलाएं नेपाली बताई जा रही हैं। ग्रामीणों के मुताबिक, पिपराही निवासी डोमी पंडित (68) के खेत में सीमावर्ती नेपाल के कचनारी गांव की दर्जनभर बकरियां चर रही थीं।

डोमी पंडित जब खेत पर गए तो बकरी को चरने के लिए छोड़ने वाली महिलाओं को डांटा। इससे खफा नेपाल के कचनारी गांव की दस महिलाओं ने डोमी से पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने उसे डंडे से पीट-पीटकर मार डाला। इसकी सूचना मिलते ही किसान के स्वजन व ग्रामीण खेत पर गए। तब महिलाएं भागने लगीं। लेकिन, ग्रामीणों ने चार महिलाओं को पकड़ कर पिपराही ले आए। सभी को एक कमरे में बंद कर दिया।

उमर अब्दुल्ला की नजरबंदी के खिलाफ याचिका पर पांच मार्च को होगी सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह नेशनल कांफ्रेंस के नेता एवं जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत नजरबंदी को चुनौती देने वाली सारा अब्दुल्ला पायलट की याचिका पर पांच मार्च को सुनवाई करेगा।

शीर्ष कोर्ट ने कहा, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी की पीठ ने कहा, 'मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता का है।' पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह सारा अब्दुल्ला पायलट की याचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से जवाब दाखिल करेंगे। अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने शीर्ष कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नजरबंदी के मामले में याचिकाकर्ता को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। पीठ ने इस याचिका को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर प्रशासन के जवाब पर अपना जवाबी हलफनामा दायर कर सकती हैं।

उमर की बहन सारा ने शीर्ष कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपने भाई की जन सुरक्षा कानून के तहत नजरबंदी के पांच फरवरी के प्रशासन के आदेश को चुनौती दी है। सारा ने यचिका में कहा है कि नजरबंदी का आदेश गैरकानूनी है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में उनके भाई से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है।

राज्य प्रशासन ने नजरबंदी का किया बचाव

उमर की नजरबंदी का जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शीर्ष कोर्ट में बचाव किया और कहा कि उनके 'पूर्व आचरण' के कारण ही उनको पीएसए के तहत नजरबंद रखा गया है। प्रशासन ने कहा कि अगर उनको रिहा किया जाता है तो वह पुनः 'पूर्व आचरण' शुरू कर सकते हैं जिससे राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

उमर को अनुच्छेद 370 खत्म करने का धुर विरोधी बताते हुए प्रशासन ने कहा कि उनके कृत्य पूरी तरह से लोक व्यवस्था के दायरे में आते हैं, क्योंकि इसका मकसद सार्वजनिक शांति और सद्भाव को भंग करना था। जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दाखिल जवाब के बारे में बताया।

प्रशासन ने कहा कि याचिकाकर्ता यह बताने में विफल रही हैं कि वह पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गईं। यह याचिका खारिज करने का अनुरोध करते हुए शीर्ष कोर्ट से कहा गया कि इस पर विचार करने से ही यहां ऐसी याचिकाओं का अंबार लग जाएगा।

भोपाल में 48 घंटे लगातार किया नाटक विश्व रिकॉर्ड का दावा

नईदुनिया, भोपाल : भोपाल में बीएसएस कॉलेज के विद्यार्थियों ने सोमवार को यहां के ऑडिटोरियम में लगातार 48 घंटे तक नाटक 'कथा-ए-हिंद' का मंचन किया। प्रस्तुति की विश्व रिकॉर्ड के लिए दावेदारी की जाएगी। नाटक में भारत के स्वर्णिम इतिहास की झलक दिखाई गई। सोमवार दोपहर 12.47 बजे नाटक के 48 घंटे पूरे हुए तो हॉल में मौजूद विद्यार्थियों ने तालियां बजाकर कलाकारों का अभिवादन किया। इससे कलाकार काफी उत्साहित दिखे।

चेन्नई का रिकॉर्ड टूटने का दावा : आयोजकों का दावा है कि रविवार को यह नाटक चेन्नई में 28 घंटे तक चलने वाले सबसे लंबी अवधि के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। नाटक के आयोजकों की ओर से मंजू मेहता एवं समन्वयक धर्मेंद्र बहादुर के मुताबिक इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे 48 घंटे तक की गई है। अब इस रिकार्डिंग को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के पास भेजा जाएगा। नाटक में 60 विद्यार्थियों ने प्रस्तुति दी।

डीएसपी देविंदर से जुड़ रहे आइएएस राजीव रंजन के तार

कुलदीप शुक्ला, चंडीगढ़

- कुपवाड़ा में डीएम रहते फर्जी दस्तावेज पर 30 हजार आर्म्स लाइसेंस जारी करने का आरोप
- सीबीआइ कर रही पूछताछ, एनआइए से भी मदद मांगेगी जांच एजेंसी

फर्जी दस्तावेज और बिना सत्यापन के के करीब 30 हजार आर्म्स लाइसेंस जारी करने के मामले में गिरफ्तार कश्मीर कैडर के आइएएस अधिकारी राजीव रंजन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूत्रों के अनुसार राजीव रंजन का कनेक्शन पिछले दिनों आतंकियों के साथ गिरफ्तार डीएसपी देविंदर सिंह से जुड़ रहा है। सीबीआइ ने राजीव रंजन को जम्मू कश्मीर में कोर्ट में पेशकर दस दिन के रिमांड पर लिया है।

सीबीआइ इस मामले में राजीव रंजन और दूसरे आरोपित इतरत हुसैन से भी पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी का कहना है कि वह जल्द ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) से भी संपर्क करेगी। दरअसल, एनआइए देविंदर सिंह मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राजीव रंजन और इतरत हुसैन के कुपवाड़ा के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) पद पर कार्यरत रहने के दौरान फर्जी दस्तावेजों पर हजारों की संख्या में आर्म्स लाइसेंस जारी किए हैं।

तीन आइएएस और दो आइपीएस की भूमिका भी संदिग्ध : सीबीआइ के अनुसार 2016 से 2017 तक कुपवाड़ा में तैनाती के दौरान राजीव रंजन ने करीब 30,000 आर्म्स लाइसेंस जारी किए। इस काम के लिए उन्होंने प्रति लाइसेंस आठ से दस लाख रुपये लिए। पता चला है कि चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के लोगों को भी फर्जी कागजातों पर कश्मीरी बताकर लाइसेंस जारी किए गए थे। इस मामले में राजीव के बैच के दो और उसके सीनियर बैच के एक आइआएस के अलावा दो आइपीएस की भूमिका भी सामने आ रही है।

फर्जी हथियार लाइसेंस के साथ पकड़ा गया था राजीव का भाई

2017 में राजस्थान पुलिस ने राजीव रंजन के भाई ज्योति रंजन को फर्जी हथियार लाइसेंस के साथ गिरफ्तार किया था। तब राजस्थान के तत्कालीन डीजीपी ओपी गिल्होत्रा ने जांच के बाद राजीव रंजन पर भी शक जाहिर किया था। श्रीगंगानगर में 2007 में फर्जी आर्म्स लाइसेंस के मामले सामने आने के बाद करीब आधा दर्जन केस दर्ज किए गए थे। तब जांच में दो-तीन तत्कालीन आइएएस की सुपरविजन मामले में लापरवाही मानी गई थी। यही नहीं, संबंधित शाखा के दो लिपिकों और एक सहायक कर्मचारी पर भी विभागीय कार्रवाई की गई थी।

जगदलपुर के नक्सली इलाकों में एयर एंबुलेंस की तरह काम करेंगे हेलीकॉप्टर

नईदुनिया, जगदलपुर

- सीआरपीएफ ने मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टॉफ की शुरू की ट्रेनिंग
- हवा में ही किया जा सकेगा उपचार, जवानों को बचाने में मिलेगी मदद

रायपुर और जगदलपुर एयर बेस में एक समय में कम से कम चार हेलीकॉप्टर हमेशा उपलब्ध होते हैं। जरूरत पड़ने पर और हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं। अब सीआरपीएफ की ओर से हेलीकॉप्टरों को एयर एंबुलेंस बनाने की पहल की जा रही है।
– सुंदरराज पी, आइजी, बस्तर

नक्सल इलाकों में जवानों को एयर लिफ्ट कराने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले हेलीकॉप्टरों को एयर एंबुलेंस बनाया जाएगा। इसी कड़ी में सीआरपीएफ ने सोमवार को जगदलपुर के सीआरपीएफ कैंप में फोर्स में पदस्थ डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टॉफ के लिए विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल की शुरुआत की।

एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगे वायुसेना और बीएसएफ के हेलीकॉप्टरों में अब एयर एंबुलेंस की सभी सुविधाएं रहेंगी। इससे घायल जवानों का उपचार आसमान में ही शुरू हो जाएगा। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में वर्तमान में करीब आधा दर्जन हेलीकॉप्टर एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगे हुए हैं। जंगल में मुठभेड़ के दौरान घायल जवानों को बाहर निकालने में इनकी मदद ली जाती है।

सीआरपीएफ के नए चीफ एपी माहेश्वरी ने निर्देश जारी किए हैं कि देशभर में एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगे एक दर्जन हेलीकॉप्टरों को एयर एंबुलेंस में तब्दील किया जाए। इस पर काम शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि आम हेलीकॉप्टरों में सिर्फ प्राथमिक उपचार की सुविधा होती है। गोलीबारी के बीच हेलीकॉप्टर को लैंड कराना भी चुनौती होता है। हेलीकॉप्टर से घायल को निकालने के बाद अस्पताल तक पहुंचने में भी वक्त लगता है। इस बीच ज्यादा खून बहने से कई बार जवानों की जान पर बन आती है। इसे देखते हुए हेलीकॉप्टरों को एयर एंबुलेंस में बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

एयर एंबुलेंस के तौर पर काम करने वाले हेलीकॉप्टर, वहीं उतर सकते हैं जहां हवाई पट्टी हो, जबकि नक्सल इलाकों में विषम जगहों पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करानी होती है। इसीलिए यह जरूरत महसूस की जा रही थी कि आम हेलीकॉप्टरों को ही एयर एंबुलेंस की सुविधाओं से लैस कर दिया जाए। बस्तर में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की सेवाएं ली जा रही हैं।

झारखंड में भी सुविधा : सीआरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि इसी तरह की सुविधा झारखंड के रांची में भी विकसित की जा रही है। रांची से ही दुर्गम क्षेत्रों में फंसे घायल जवानों को एयर लिफ्ट कराया जाता है।

कच्छ और सूरत में हाई प्रोफाइल शराब पार्टी पकड़ी

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

- शराब के नशे में झूमते हुए युवकों का वीडियो वायरल
- इन दो घटनाओं से राज्य में शराबंदी कानून पर खड़े हुए सवाल

कच्छ के मुंद्रा व सूरत में शराब पार्टी की दो घटनाओं ने राज्य में शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में कच्छ के मुंद्रा में युवक नशे में डांस करते व एक दूसरे को शराब से नहलाते नजर आ रहे हैं। सूरत में हाई प्रोफाइल शराब पार्टी पकड़ी गई है।

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि राज्य में शराब पार्टी जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य में शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन होगा। शराब की तस्करी करने व इसका सेवन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शराब एक सामाजिक बुराई है जिसे जागरूकता से ही रोका जा सकता है।

सूरत में बीती रात पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल शराब पार्टी पर छापा मारकर कई युवकों को गिरफ्तार किया था। सोशल मीडिया पर कोडवर्ड के साथ मैसेज चलाकर पार्टी के लिए युवकों को आमंत्रित किया गया था। यहां शराब, बीयर, गांजा, कोकीन की आपूर्ति की गई।

कच्छ में एक शादी समारोह में युवकों को शराब के नशे में डांस करते व एक दूसरे को शराब से नहलाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद सरकार हरकत में आ गई। मुख्यमंत्री रूपाणी ने गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा, पुलिस महानिदेशक शिवानंद झा व सीएमओ के आला अधिकारियों की बैठक बुलाई जिसमें इन घटनाओं की जानकारी ली। पुलिस ने इस मामले में 50 से अधिक युवकों को गिरफ्तार किया है जिन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

मौसम विशेष

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में सुबह के समय हल्का कोहरा व कुहासा छा सकता है। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में आंशिक बादल छाये रहेंगे। इन राज्यों में एक दो स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा व बर्फबारी संभव है। रात के तापमान में हल्की गिरावट संभव है।

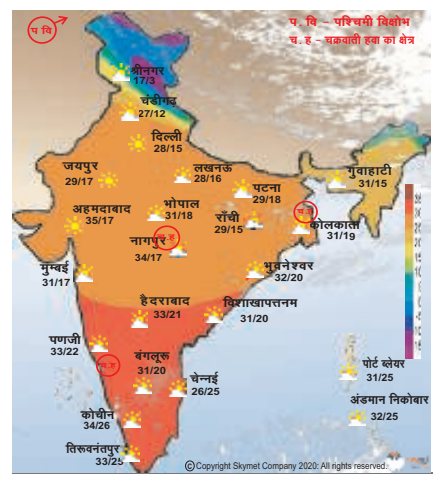

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/16/आंबा	अहमदाबाद	34/16/आंबा
कोलकाता	31/18/च	बड़ोदा	30/13/आंबा
चेन्नई	33/25/आंबा	नागपुर	33/16/आंबा
हैदराबाद	32/20/आंबा	इन्दौर	32/17/आंबा
बंगलूरू	31/19/आंबा	रांची	30/16/आंबा
त्रिवेन्द्रम	33/24/आंबा	पटना	28/17/आंबा
गुवाहाटी	31/19/आंबा	जमशेदपुर	33/19/आंबा
गंगटोक	19/09/आंबा	पुणे	31/13/आंबा

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 3 मार्च 2020
आजकल
16
www.jagran.com

विमान में दोबारा ईंधन भरे बिना अकेले लगाया दुनिया का चक्कर

आज ही 2005 में अमेरिकी अरबपति स्टीव फॉसेट ने अकेले विमान उड़ाकर पहली बार दुनिया का चक्कर लगाया। 67 घंटे और 23 हजार मील की यात्रा के दौरान विमान में दोबारा फ्यूल (ईंधन) नहीं भरा। 100 से अधिक रिकार्ड बनाए हैं। 2002 में अकेले बैलून से भी दुनिया का चक्कर लगाया था।

टाइम पत्रिका का प्रकाशन न्यूयॉर्क से शुरू हुआ

आज ही 1923 में साप्ताहिक अमेरिकी पत्रिका टाइम का प्रकाशन न्यूयॉर्क से शुरू हुआ। एक वक्त यह दुनिया की सर्वाधिक प्रसार संख्या वाली पत्रिका थी और इसकी करीब ढाई करोड़ प्रतियां प्रकाशित होती थीं। हालांकि इसमें काफी कमी आई है, लेकिन विश्वसनीयता बरकरार है।

टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल का जन्म

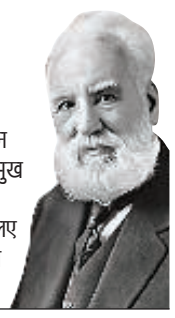

आज ही के दिन आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म 1847 में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ। 12 साल की उम्र में पहला आविष्कार किया। 1865 में संगीत शिक्षक बने। उन्होंने 1872 में बधिरों के लिए स्कूल शुरू किया। वर्ष 1876 में उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया और 1877 में अपनी टेलीफोन कंपनी शुरू की। प्रमुख रूप से उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन, बेल व डेसीबल यूनिट तथा मेटल डिटेक्टर का आविष्कार किया। उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें विभिन्न देशों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया। 2 अगस्त 1922 को उनका निधन हो गया।

विज्ञान की इन प्रेरणाओं को सरकार का सम्मान

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय ने बीसवीं सदी की 11 उन भारतीय महिलाओं की पहचान की है, जिन्होंने अपनी मेधा से लोगों का कल्याण करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (आठ मार्च) से ठीक पहले सरकार की इस पहल का मकसद इन प्रेरक व्यक्तित्व का लोगों के बीच ठीक से पहचान कराना है और विज्ञान के क्षेत्र में किए गए उनके उत्कृष्ट काम को सम्मान देना है। देश भर के संस्थानों में इन महिला वैज्ञानिकों के नाम पर 11 चेयर स्थापित की जाएंगी। इनके नाम पर सुरक्षित सीटों पर सिर्फ महिला शोधार्थियों को ही लिया जाएगा और रिसर्च के लिए एक करोड़ का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक सिर्फ मदर टेरेसा के नाम पर ही ऐसी सीट सुरक्षित थी।

कई शोध संस्थानों में किया काम

दर्शन रंगनाथन, रसायन शास्त्री : दर्शन रंगनाथन का जन्म चार जून 1941 को दिल्ली में हुआ था। वे दिल्ली में पली बढ़ीं और दिल्ली विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में पीएचडी किया। वे मिरांडा कॉलेज में कई सालों तक रसायन विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष भी रहीं। उन्होंने यूरिया चक्र, प्रोटीन संरचना पर काफी काम किया। जून 2001 में स्तन कैंसर के चलते उनका निधन हो गया।

मौसम के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान

अन्ना मणि, मौसम विज्ञानी : मशहूर भारतीय मौसम वैज्ञानिक अन्ना मणि का जन्म 23 अगस्त 1918 को केरल के त्रावणकोर में हुआ था। उन्होंने चेन्नई के प्रेसीडेंसी कॉलेज से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया।

इसके बाद बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में रिसर्च करने पहुंची। यहां रूबी और हीरों के स्पेक्ट्रम पर अध्ययन किया। फिर मौसम विज्ञान के उपकरण से जुड़ी जानकारी सीखने के इच्छुक शोधकर्ताओं के लिए सरकार ने एक स्कॉलरशिप का एलान किया। अन्ना चयनित हुईं और लंदन पहुंचीं। तीन साल बाद स्कॉलरशिप पूरी करके भारत आईं और पुणे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में नौकरी करने लगीं। अपने कार्यकाल के दौरान उनके कई शोध पत्र प्रकाशित हुए। उन्होंने मौसम विज्ञान उपकरणों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सौर विकिरण, ओजोन और पवन ऊर्जा माप के विषय में उल्लेखनीय कार्य किया। 16 अगस्त 2001 में उनका निधन हो गया।

जन्म शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित

रमन परिमाला, गणितज्ञ : बीजगणित की दुनिया में रमन परिमाला बड़ा नाम है। 21 नवंबर 1948 में तमिलनाडु में जन्मीं रमन ने चेन्नई में शारदा विश्वविद्यालय गर्ल्स हाई स्कूल और स्टेला मैरिस कॉलेज से पढ़ाई की। उन्होंने एमएससी मद्रास विश्वविद्यालय से और पीएचडी मुंबई विश्वविद्यालय से किया। वह एमोरी विश्वविद्यालय में गणित के कला और विज्ञान की प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। इससे पहले वह कई सालों तक वह मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में प्रोफेसर भी रहीं। 1987 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया गया। 2003 में उन्हें श्रीनिवास रामानुजम जन्म शताब्दी पुरस्कार से नवाजा गया।

होमी जहांगीर भाभा के साथ किया काम

बिभा चौधरी, भौतिक विज्ञानी : कोलकाता में 1913 में पैदा हुईं बिभा चौधरी ने होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई के साथ काम किया। 1936 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में एमएससी करने वाली पहली महिला बनीं। उन्होंने देबेन्द्र मोहन बोस के साथ मिलकर बोसॉन कण की खोज की। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से पीएचडी की और अवपरमाणुक कणों पर काम किया। उनका आखिरी शोध पत्र 1990 में उनकी मृत्यु (1991) से साल भर पहले इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में प्रकाशित हुआ।

चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा गया

कमल रणदिवे, चिकित्सा विशेषज्ञ : 8 नवंबर 1917 को पुणे में जन्मीं कमल रणदिवे ही वह महिला हैं, जिन्होंने स्तन कैंसर और आनुवंशिकता में संबंध के बारे में बताया था। उनके अभूतपूर्व काम की वजह से ही भारत सरकार ने उन्हें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में 1982 में पद्म भूषण से नवाजा था। उन्होंने फर्गुसन कॉलेज से वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में स्नातक किया। पुणे में एग्रीकल्चर कॉलेज से परास्नातक के बाद बॉम्बे विश्वविद्यालय से पीएचडी की। 2001 में उनका निधन हुआ।

पहली वनस्पति विज्ञानी

जानकी अम्माल, वनस्पति विज्ञानी : वनस्पति विज्ञान में पीएचडी करने वाली पहली भारतीय महिला जानकी अम्मल का जन्म 4 नवंबर 1897 को केरल के कुन्नुर जिले के तेल्लीचेरी में हुआ था। वो चेन्नई में पढ़ाई करने के बाद मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, अमेरिका चली गईं। 1931 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से बॉटनी में पीएचडी भी की। उन्होंने गन्नों की हाइब्रिड प्रजाति खोजी। फूलों व बैंगन की क्रॉस ब्रीडिंग पर काफी शोध किया। 7 फरवरी 1984 को उनका निधन हो गया।

साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित

इरावती कर्वे, मानव विज्ञानी : जन्म 15 दिसंबर 1905 में बर्मा (म्यांमार) में हुआ था, लेकिन उनकी पढ़ाई पुणे में हुई। उन्होंने दर्शनशास्त्र से स्नातक किया और 1928 में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में परास्नातक किया। वह पुणे के डेक्कन कॉलेज के समाजशास्त्र और मानव विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष भी रहीं। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में कई विषयों पर लिखा है। उनकी रचना युगान्त के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 11 अगस्त 1970 में उनकी मृत्यु हो गई।

दूसरी महिला फिजीशियन

डॉ. कादंबिनी गांगुली : भारत की दूसरी महिला फिजीशियन कादंबिनी गांगुली का जन्म 18 जुलाई को बिहार के भागलपुर में हुआ था। बंगा महिला विद्यालय से उन्होंने शिक्षा प्रारंभ की। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास करने वाली पहली महिला रहीं। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से स्नातक किया। 1892 में ब्रिटेन गईं और वापस लौटकर डफरिन अस्पताल में कुछ समय काम करने के बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। 3 अक्टूबर 1923 में उनका निधन हो गया।

इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन में रहा योगदान

राजेश्वरी चटर्जी, इंजीनियर : कर्नाटक से पहली महिला इंजीनियर रहीं राजेश्वरी चटर्जी 24 जनवरी 1922 में कर्नाटक में पैदा हुई थीं। उनकी शुरुआती शिक्षा उनकी दादी द्वारा शुरू किए गए स्पेशल इंग्लिश स्कूल से हुई। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने सेंट्रल कॉलेज ऑफ बेंगलुरु में दाखिला लिया। वहां से राजेश्वरी ने बीएससी और एमएससी की डिग्री ली। अमेरिका से पीएचडी की और 1953 में भारत लौटीं। वह बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर रहीं और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग की अध्यक्ष भी रहीं। माइक्रोवेव तकनीक के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। 3 सितंबर 2010 को उनकी मृत्यु हो गई।

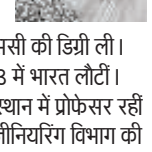

चार सौ रिसर्च पेपर हुए प्रकाशित

अर्चना शर्मा, वनस्पति शास्त्री : प्रख्यात वनस्पति विज्ञान शास्त्री अर्चना शर्मा का जन्म 16 फरवरी 1932 को पुणे में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में एमएससी की। 1955 में वनस्पति शास्त्र में पीएचडी की। 1967 से बतौर प्रोफेसर काम किया और वनस्पति शास्त्र की विभागाध्यक्ष भी रहीं। उनकी 10 किताबें और करीब 400 शोध पत्र प्रकाशित हुए। 14 जनवरी 2008 को उनका निधन हो गया।

विज्ञान में पहली डॉक्टरेट उपाधि

आसिमा चटर्जी, रसायन शास्त्री : 23 सितंबर 1917 में कोलकाता में जन्मीं आसिमा चटर्जी ने एंटी मलेरियल ड्रग्स पर काफी काम किया। विज्ञान में डॉक्टरेट प्राप्त करने वाली पहली महिला थीं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से रसायन विज्ञान में स्नातक और जैविक रसायन में डॉक्टरेट की। उन्होंने दवाओं पर काफी काम किया। आसिमा का निधन 22 नवंबर 2006 में हो गया।

इधर-उधर की

'कमजोर को दे दो मेरे अंक'

न्यूयॉर्क, एजेंसी : परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं में अंक बढ़ाने की याचना के बारे में आपने कई बार देखा सुना होगा। हालांकि अमेरिका में याचना नहीं बल्कि त्याग का ऐसा ही मामला सामने आया है। केंटुकी के एक स्कूली छात्र ने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखा कि जिसने भी सबसे कम अंक हासिल किए हों, उसे मेरे पांच बोनस अंक दे दिए जाएं। इसके बाद फेसबुक यूजर विंस्टन ली ने पोस्ट शेयर की है। जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके एक ए प्लस पाने वाले छात्र ने अपने 5 बोनस अंक सबसे कम अंक लाने वाले कोदेने के लिए कहा है। मैंने ऐसी ईमानदारी कभी नहीं देखी है। हालांकि छात्र का नाम सामने नहीं आया है लेकिन उसने कक्षा के सबसे कमजोर छात्र की मदद के बारे में सोचा।

एक्सोप्लैनेट पर तलाशी जीवन की संभावनाएं

रहस्यमय ब्रह्मांड ▶ पृथ्वी से दो गुना बड़ा है 'के2-18बी' का आकार

हमारे ग्रह से 124 प्रकाश वर्ष दूर है इसकी मौजूदगी

लंदन, एजेंसियां : भारतवंशी खगोलविद के नेतृत्व वाली टीम ने पृथ्वी के दो गुने से भी ज्यादा बड़े आकार वाले एक ऐसे एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है, जहां जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। सौरमंडल से बाहर के ग्रह को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है।

कैंब्रिज यूनिवर्सिटी की टीम ने के2-18बी नामक इस एक्सोप्लैनेट के द्रव्यमान (मास), त्रिज्या (रेडियस) और वायुमंडलीय (एटमोस्फेयरिक) डाटा के अध्ययन में पाया कि वहां पानी और जीवन लायक स्थितियां हो सकती हैं। हालांकि, ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन की अधिकता है। इसकी रिपोर्ट एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुई है।

नए एक्सोप्लैनेट का द्रव्यमान पृथ्वी से 8.6 गुना ज्यादा है। प्रतीकात्मक

यह एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष दूर है। इसकी त्रिज्या पृथ्वी से 2.6 गुना, जबकि द्रव्यमान 8.6 गुना ज्यादा है। यह तारे की परिक्रमा करता है। इसका तापमान ऐसा है कि वहां पानी की उपलब्धता हो सकती है। पिछले साल भी इसके बारे में मीडिया में खूब चर्चा हुई थी, जब दो टीमों ने दावा किया था कि वहां के वायुमंडल में वाष्प पाया गया है। हालांकि, तब उसकी वायुमंडलीय और आंतरिक स्थिति का पता नहीं चल पाया था।

आंतरिक वायुमंडलीय स्थिति को समझना है जरूरी : खगोलविदों का नेतृत्व करने वाले कैंब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के डॉ. निक्कू मधुसूदन ने कहा था, 'कई एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में वाष्प के कण पाए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वहां जीवन की संभावनाएं हैं। जीवन की संभावनाओं के लिए जरूरी है कि वहां की आंतरिक और वायुमंडलीय स्थितियों को समझा जाए। खासकर वहां, जहां वायुमंडल के नीचे पानी हो सकता है। पृथ्वी से बड़े और नेपच्यून से छोटे हाइड्रोजन की बहुलता वाले इस एक्सोप्लैनेट पर पानी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन का आवरण गाढ़ा हुआ तो तापमान और पानी के सतह का दबाव जीवन की संभावनाओं के लिए उपयुक्त होगा।

लौह अयस्कों की है भरमार : वैज्ञानिकों ने इसे मिनी नेपच्यून जैसा बताया है। उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि इस ग्रह पर हाइड्रोजन और पानी के अलावा चट्टानें और लौह अयस्क भारी मात्रा में मौजूद है।खगोलशास्त्रियों ने इस ग्रह पर दूसरे रसायनों जैसे- मीथेन और अमोनिया की सतहें भी पाई हैं लेकिन वो अपेक्षाकृत बहुत कम है लेकिन ये सतहें जैवकीय प्रक्रिया में कितना योगदान दे सकती हैं, इसका अंदाज अभी लगाया जाना शेष है। हालांकि शोधकर्ताओं ने पाया कि जिस अधिकतम हाइड्रोजन की जरूरत ग्रह के द्रव्यमान के अनुपात में होना चाहिए, वो 06 फीसदी है। पृथ्वी पर भी इसका अनुपात यही है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि हमारा ब्रह्मांड कई रहस्यों और अचरजों से भरा पड़ा है। इसके बारे में खगोलविद हर दिन नई-नई जानकारियां साझा करते हैं। नए एक्सोप्लैनेट में अब जीवन की संभावनाएं तलाशी गई है।

पृथ्वी जैसा ग्रह -कैल्पर

इससे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से लगभग 40 गुना बड़ा और 1200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित कैल्पर 62एफ नामक ग्रह की खोज की थी, जिसके बारे में कहा गया कि वहां जीवन की प्रबल संभावनाएं हैं। वैज्ञानिकों का कहना था कि कैल्पर और पृथ्वी के बीच ऐसी कई समानताएं हैं जो यहां जीवन की संभावनाओं को पुख्ता करती हैं। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हाकिंग ने अपने एक अध्ययन में ऐसी आशंका जताई थी कि पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी चीजें अगले 100 वर्षों में खत्म हो सकती हैं। इसका तापमान भी बढ़ेगा और ये रहने लायक नहीं रहेगी। तब मनुष्यों को किसी नए ग्रह की जरूरत होगी। इसलिए हमें अभी से उसकी तलाश शुरू कर देनी चाहिए।

समय से पूर्व जन्म के जोखिम का पता लगाएगा एप

लंदन, आइएएनएस : शोधकर्ताओं ने एक ऐसा मोबाइल एप विकसित किया है जो प्री-मैच्योर बर्थ यानी समय से पूर्व जन्म के जोखिम का पता लगाने के साथ-साथ यह भी बताएगा कि महिला को किस समय विशेष देखभाल और इलाज की जरूरत है। इससे लोगों का भावनात्मक और वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिल सकती है।

क्यूयूआइपीपी वी2 नामक यह मोबाइल फोन एप डॉक्टरों को प्री-मैच्योर बर्थ के जोखिम के प्रति आगाह करने के साथ-साथ जिन महिलाओं को इसकी संभावना कम होगी उन्हें आश्वस्त भी करेगा।

शोधकर्ताओं ने कहा कि जिन शिशुओं का जन्म 37 सप्ताहों से पहले हो जाता है, उनमें ज्यादातर की मौत होने की संभावना रहती है। जो जिंदा रह जाते हैं उन्हें भविष्य में शारीरिक विकास की समस्यों से जूझना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप परिवारों को एक बड़ा भावनात्मक और वित्तीय बोझ झेलना पड़ सकता है।

दुबई लॉटरी में भारतीय ने जीती लक्जरी बीएमडब्ल्यू कार

दुबई, प्रेट्र : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में बीते शनिवार को संपन्न हुई दुबई ओपन टेनिस चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले के बाद निकाले गए लॉटरी के ड्रा में भारतीय नागरिक सैयद एनएसवाई ने लक्जरी कार बीएमडब्ल्यू जीती। सैयद ने लॉटरी का टिकट दुबई ओपन के सेमीफाइनल मैच के दौरान खरीदा था। बीएमडब्ल्यू कार जीतने की खबर मिलने पर सैयद की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा।

हर साल आयोजित होने वाली दुबई ओपन टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल के बाद भाग्यशाली लॉटरी विजेता की घोषणा की जाती है। इस साल के दुबई चैंपियनशिप

फाइल

के विजेता नोवाक जोकोविक ने जैकपॉट लॉटरी का चयन किया, जो सैयद के नाम निकली। मूल रूप से चेन्नई के रहने वाले सैयद पिछले 30 वर्षों से दुबई में रह रहे हैं। वह यहां कार्गो के क्षेत्र में कारोबार करते हैं।

एंटीबायोटिक्स का सेवन बना सकता है बीमार

शोध अनुसंधान

बुखार, खांसी या जुकाम कोई भी समस्या अगर जल्दी ठीक ना हो तो लोग एंटीबायोटिक दवाओं की ओर रुख कर लेते हैं। सामान्य संक्रमण हो तो आमतौर पर एंटीबायोटिक्स की तीन से पांच दिन की खुराक में परेशानी ठीक भी हो जाती है। लेकिन बार-बार ऐसा करना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। हालिया शोध के मुताबिक, कम समय अंतराल पर कई बार एंटीबायोटिक्स का कोर्स आपको ज्यादा बीमार बना सकता है। यहां तक कि अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ सकता है।

शोध के मुताबिक, तीन साल के भीतर किसी एक जैसे संक्रमण के लिए नौ या इससे ज्यादा बार एंटीबायोटिक्स का सेवन करने वालों में कुछ ही महीने के भीतर किसी अन्य संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने की आशंका 2.26 गुना तक हो जाती है। वहीं दूसरी ओर पांच से आठ बार एंटीबायोटिक्स ले चुके लोगों में यह खतरा 1.77 गुना और तीन से चार बार एंटीबायोटिक्स लेने वालों में 1.33 गुना रहता है।

- आइएएनएस

एआइ की मदद से दूर होंगी नींद से जुड़ी परेशानियां

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद से जुड़ी परेशानियां होना बहुत आम हो गया है। वैज्ञानिक इनके इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रभावी और सटीक दवा ईजाद करने की दिशा में प्रयासरत हैं। हालिया अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) की मदद से इन परेशानियों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझना और दवाओं को ज्यादा कारगर बनाना संभव हो सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि विभिन्न प्रयोगशालाओं और अध्ययन केंद्रों में नींद से जुड़े डाटा बड़े पैमाने पर हैं। अगर इन सभी डाटा को एआइ की मदद से परखा जाए तो परेशानियों को समझना ज्यादा आसान हो सकता है। इससे मिली जानकारियों की मदद से नींद से जुड़ी दिक्कतों को सही ढंग से समझने और उनके इलाज के लिए ज्यादा सटीक और प्रभावी दवा विकसित करने का रास्ता भी खुल सकता है।

- प्रेट्र

स्क्रीन शॉट

सम्मान पाने के लिए आत्मसम्मान लाना होगा : काजोल

इन दिनों महिलाओं से जुड़े मुद्दों को सिनेमा में प्रमुखता से उठाया जा रहा है। अभिनेत्रियां इन फिल्मों को अपने अभिनय से सपोर्ट भी कर रही हैं। यही वजह है कि वे शॉर्ट फिल्म का हिस्सा बनने से भी गुरेज नहीं कर रही हैं। शॉर्ट फिल्म 'देवी' इसकी बानगी है। बलात्कार का शिकार हुई नौ महिलाओं की इस कहानी के जिस सेटअप में पिरोया गया है, वह सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म केवल 13 मिनट की है। सोमवार को

मुंबई में इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर नेहा धूपिया को छोड़कर बाकी सभी अभिनेत्रियां काजोल, श्रुति हासन, नीना कुलकर्णी, मुक्ता भरवे, संध्या म्हात्रे, शिवानी रघुवंशी और यशस्विनी दायमा मौजूद रहीं। फिल्म का निर्देशन प्रियंका बनर्जी ने किया है। काजोल की यह पहली शॉर्ट फिल्म है। इसे करने की वजह बताते हुए काजोल ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी थी। महिला सशक्तीकरण पर काजोल ने कहा कि इसे केवल महिलाएं ही ला सकती हैं, उनके लिए कोई और आवाज नहीं उठा सकता है। उनका यह भी मानना है कि पितृसत्तात्मक समाज में सम्मान पाने के लिए खुद में आत्मसम्मान होना चाहिए। दुनिया को आप जिस नजरिये से देखेंगे, दुनिया आपको वैसे ही देखेगी। काजोल का यह भी कहना है कि वह अपने बेटे को भी यह बात सिखाती हैं कि उनकी मां भी काम करती है। उन्होंने बताया कि जब मैं बाहर काम के लिए जाती हूं तो कई बार युग कहता है कि मत जाओ। मुझे उसे समझाना पड़ता है कि मैं काम करने के लिए बाहर जा रही हूं। अगर मैं उसे यह बातें अभी से सिखाऊंगी तो भविष्य में वह अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी के काम की इज्जत करेगा। वर्ष 2018 में मीटू के बाद इंडस्ट्री और दूसरे क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति पुरुषों के रवैये में आए बदलावों को लेकर काजोल का कहना है कि समाज में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं।

'कसौटी जिंदगी की' शो में करण सिंह ग्रोवर की हुई वापसी

सीरियल में नयापन लाने के लिए मेकर्स को कोई न कोई ट्विस्ट शो में लाना पड़ता है। अब 'कसौटी जिंदगी की' शो में भी एक ट्विस्ट आ रहा है। इस शो में मिस्टर बजाज की एंट्री होने वाली है। मिस्टर बजाज का किरदार करण सिंह ग्रोवर ने निभाया था। अब शो में उनकी वापसी हो रही है।

करण ने बताया कि उन्हें एकता कपूर की प्रोडक्शन कंपनी बालाजी से फोन आया था। दरअसल, शो में मुख्य किरदार प्रेरणा का मुश्किल समय आने वाला है। मिस्टर बजाज ने प्रेरणा से कहा था कि अगर उसे कभी कोई दिक्कत होगी, तो वह हमेशा उसका साथ देंगे। शो को छोड़ने की वजहों के बारे में करण ने कहा, 'मुझे पता था कि मुझे शो से बाहर होना होगा। यह स्क्रिप्ट में पहले से ही लिख दिया गया था। तब मेरे लिए भी एक ब्रेक जरूरी था, क्योंकि मेरी पेंटिंग्स की एग्जिबिशन होने वाली थी, जिसके लिए मुझे वक्त भी चाहिए था।' करण का कहना है कि शो को छोड़ने का निर्णय उनका कभी नहीं था। उन्होंने बताया कि ये सारे निर्णय एकता कपूर लेती हैं। उन्हें पता है कि कब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बजाज का किरदार शो छोड़कर अगर वापसी करेगा, तो उसका असर ज्यादा पड़ेगा। किरदार में दोबारा वापसी करने को लेकर करण ने कहा कि शो की शुरुआत में किरदार को सेट करने में दिक्कत होती है, लेकिन जब आप किरदार को समझ जाते हैं, तो वह किरदार भले ही छह महीने बाद क्यों न करना पड़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। शो में करण अपनी उम्र से बड़ी उम्र वाले व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं।

कट्रीना के हुस्न के फैन थे अक्षय अब प्रतिभा के कायल हैं

अक्षय कुमार और कट्रीना कैफ लगभग दस साल बाद एकसाथ फिल्म 'सूर्यवंशी' में नजर आएंगे। लगभग आधा दर्जन फिल्मों में दोनों एकसाथ काम कर चुके हैं। इसके बावजूद अक्षय को कट्रीना के अभिनय में कुछ खास नहीं दिखा। लेकिन फिल्म 'सूर्यवंशी' में कट्रीना के अभिनय की तारीफ करने से वह खुद को रोक नहीं पाए। सोमवार को 'सूर्यवंशी' के ट्रेलर लांच पर अजय देवगन, रणवीर सिंह, कट्रीना के साथ फिल्म के निर्माता करण जौहर और निर्देशक रोहित शेट्टी भी उपस्थित थे। अक्षय ने कट्रीना की तारीफ करते हुए कहा, 'इस फिल्म में कट्रीना ने एक ऐसा सीन किया है, जिससे मैं उनका फैन बन गया हूं।' इस पर अजय ने चुटकी ली कि क्या वह पहले कट्रीना की प्रतिभा के फैन नहीं थे? तो अक्षय ने कहा कि पहले वह कट्रीना के हुस्न के फैन थे, लेकिन अब उनकी प्रतिभा के भी फैन हो गए हैं।

दिशा ने अनोखे अंदाज में दीं टाइगर को जन्मदिन की शुभकामनाएं

टाइगर श्रॉफ ने सोमवार को अपना 30वां जन्मदिन मनाया। दो मार्च 1990 को जन्मे टाइगर को उनकी मां आयशा श्रॉफ समेत कई हस्तियों ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर उनकी कथित गर्लफ्रेंड दिशा पटानी द्वारा अनोखे अंदाज में दी गईं शुभकामनाओं ने सभी का ध्यान खींचा। दिशा ने टाइगर के साथ फिल्म 'बैंग बैंग' के टाइटल सांग पर डांस करते हुए पुराना वीडियो साझा कर लिखा, 'यह एकसाथ हमारा पहला डांस ब्लॉक था। मैं तुम्हारे साथ डांस करते वक्त नर्वस थी और मुझे शर्म आ रही थी। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम्हारे साथ डांस करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। इतना जटिल मैच बनने के लिए शुक्रिया।' साथ ही दिशा ने टाइगर को आगामी फिल्म 'बागी 3' के लिए भी शुभकामनाएं दीं। टाइगर ने भी दिशा के इस अंदाज को प्यारा बताकर शुक्रिया अदा किया।

ताजमहल में दिलजीत दोसांझ के संग इवांका ट्रंप !

दिलजीत दोसांझ का दिल विदेशी हसीनाओं पर आया है। अमेरिकी मॉडल व टीवी पर्सनैलिटी कायली जेनर और अभिनेत्री गैल गैजोट के सोशल मीडिया पेज पर दिलजीत यह प्यार जाहिर कर चुके हैं। इस बार दिलजीत ने अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी इवांका ट्रंप को चुना है। इवांका बीते दिनों अपने पिता के भारत दौरे पर उनके साथ आई थीं। उन्होंने ताजमहल में फोटो खिंचाई थी। इस तस्वीर को दिलजीत ने एडिट करके खुद को इवांका के साथ बिठा दिया है। खास बात यह है कि इवांका ने दिलजीत की पोस्ट पर जवाब भी दिया है। दिलजीत ने पोस्ट के साथ लिखा, 'मैं और इवांका। पीछे ही पड़ गई। कहती है ताजमहल जाना है। मैं ले गया, क्या करता।' इवांका ने रीट्वीट करते हुए लिखा, 'मुझे ताजमहल दिखाने के लिए धन्यवाद। इस अनुभव को नहीं भूल पाऊंगी।' दोबारा दिलजीत ने लिखा, 'ओ माई गॉड। अतिथि देवो भवः। शुक्रिया इवांका। मैंने सबको समझाने की बहुत कोशिश की कि यह फोटोशॉप नहीं है। जल्द ही मिलूंगा। अगली बार लुधियाना में पक्का। ...'

शाह रुख के बेटे ने बनाई पापा की ड्रॉइंग

किंग खान शाह रुख अक्सर सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ तस्वीरें साझा करते रहते हैं। सोमवार को उन्होंने अपने छोटे बेटे अबराम की बनाई एक ड्रॉइंग सोशल मीडिया पर साझा की। इस ड्रॉइंग में अबराम ने दो लोगों के चित्र बनाकर लिखा है -'अबराम और पापा'। इसे साझा करते हुए शाह रुख ने लिखा, 'तीन बच्चों का पिता होना मेरे लिए गर्व की बात है। यह मेरे लिए प्रेरणा और उपलब्धि भी है। इसने मुझे जीवन के हर पहलू में स्मार्टनेस की जगह मासूमियत और ईमानदारी का चुनाव करना सिखाया है। अपनी ड्रॉइंग के माध्यम से मेरे छोटे बेटे ने बताया कि मैं उससे सुंदर लग रहा हूं, क्योंकि मैं अकारण ही मुस्कुरा रहा हूं।' शाह रुख इससे पहले भी अपने बच्चों की उपब्धियां सोशल मीडिया पर साझा कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अबराम के ताइक्वांडो में पदक जीतने और येलो बेल्ट हासिल करने की तस्वीरें भी साझा की थीं। आखिरी बार शाह रुख साल 2018 में फिल्म 'जीरो' में नजर आए थे।